खण्ड-06 — सत्र -07 (भाग-01) / अंक-73

मंगलवार — 27 मार्च, 2018 / 06 चैत्र, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

R;eso t;rs

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lph

सत्र-7 भाग (1) सोमवार, 26 मार्च, 2018/05 चैत्र, 1940 (शक) अंक-75

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2	तारॉकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर(121 122, 124, 125, 127,129,131, 133, 134 एवं 135)	3—55
3	तारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर(123, 126, 128, 130, 136 से 140)	55—76
4	अतारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर(323 से 368) (347,348, 350 एवं 367 को छोड़कर)	76—214
5	विशेष उल्लेख (नियम—280)	214—232
6.	ध्यानाकर्षण (नियम—54)	232—243
7	सदन पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज	243—252
8.	वित्त वर्ष 2018—19 हेतु अनुदान मॉगों पर विचार तथा पारण।	252—335
9.	विनियोजन (संख्या—02) विधेयक, 2018का पुरःस्थापन, विचार तथा पारण	335—338

fnYyh fo/kku lHkk
dh
dk;Zokgh

सत्र-7 भाग (1) मंगलवार, 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) अंक-73

fnYyh fo/kku lHkk

lnu vijkgu 2%00 cts leor gqvkA
lnu esa mifLFkr lnL;ksa dh lwph%

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचंद्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह

23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री नरेश बाल्यान
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. श्री गुलाब सिंह
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री अमानतुल्लाह खान
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री नितिन त्यागी
45. श्री ओम प्रकाश शर्मा
46. श्री एस.के. बग्गा
47. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
48. श्रीमती सरिता सिंह
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) मंगलवार, 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) अंक-73

Inu vijkgu 2-05 cts leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए ।*

rkjkfdr i'uk d ekf[kd mRrj

v/;{k egkn;% सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्टार्ड क्वैश्चन प्रश्न संख्या 121, अखिलेशपति त्रिपाठी जी। (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या 122, श्री ओम प्रकाश शर्मा।

Jh vke idk'k 'kek% अध्यक्ष महोदय, क्या लोक निर्माण मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित एलिवेटिड बीआरटी कॉरीडोर्स का विवरण क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट और वास्तव में आबंटित की गइ राशि का विवरण क्या है;

(ग) अब तक कितने कॉरिडोर्स पूर्ण हो चुके हैं तथा अगले दो वर्षों में कितने पूर्ण हो जाएंगे;

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(घ) पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण कॉरीडोर के क्रियान्वयन में क्या कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इसे दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाएगा?

v/;{k egkn;% मंत्री जी।

ykd fuekZ.k ea=h (श्री सत्येन्द्र जैन)% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 122 का उत्तर निम्न प्रकार है:

(क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एलिवेटिड बीआरटी कॉरीडोर्स बनाने के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है;

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है;

(घ) एलिवेटिड पूर्व–पश्चिम और उत्तर–दक्षिण कॉरीडोर की योजनाएं यूटी पैक के अनुमोदन के लिए लंबित है। ये बीआरटी कॉरीडोर्स के भाग नहीं है; और

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

vu|yXud

विषयः वर्ष 2015–16 से आगे के वर्षों में डीएसआईआईडीसी की औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन एवं पुर्नविकास के लिए आवंटित किए गए फण्डस एवं खर्च का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त आवंटित फण्ड				कुल खर्च का विवरण			
		2015–16	2016–17	2017–18	कुल	2015–16	2016–17	2017–18	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों का पुर्नविकास	1250.00	0.00	0.00	1250.00	148.38	1248.22	770.61	2167.21
2.	उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों का पुनर्विकास	375.00	0.00	0.00	375.00	449.06	404.47	66.12	919.65
3.	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–II में सड़कों एवं नालियों का पुर्नविकास	290.00	0.00	0.00	290.00	790.88	236.30	0.00	1027.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों का पुर्नविकास	496.00	0.0	0.00	496.00	574.82	402.36	0.00	977.18
5.	गुणवत्ता जांच, आकस्मिक व्यय एवं अतिरिक्त कार्य के लिए आवंटित फण्ड	289.00			289.00				
	(क) लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र								
	(ख) उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र								
	(ग) मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–II								
	(घ) कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र								
	कुल	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1963.14	2291.35	836.73	5091.22

v/;{k egksn; % ऐनी सप्लीमेंटरी।

Jh vke izdk'k 'kekZ % माननीय मंत्री महोदय, मयूर विहार तक जो आर्म्स जानी है, जो पुल आता है मूलचंद से लेकर इधर उसके बारे में, वो कब तक पूरा होगा, कुछ बताने का कष्ट करेंगे?

ykd fuekZ.k ea=h % अध्यक्ष महोदय, यह बारापुला फेज–III का काम चल रहा है। उसके अंदर जो लैंड डीडीए के द्वारा दिल्ली सरकार को दी गइ थी, उस लैंड के अंदर बाद में पता लगा कि लैंड के अंदर डिस्प्यूट है और उस लैंड के एक्वायर करने का मसौदा आदरणीय एलजी साहब देख रहे हैं। जैसे ही लैंड मिल जाएगी, तभी उसकी एग्जेक्ट डेट दी जा सकेगी।

v/;{k egksn; % एनी सप्लीमेंटरी? प्रश्न संख्या 123 श्री पवन कुमार शर्मा (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या 124 श्री नारायण दत्त शर्मा (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या– 125 श्री जगदीप सिंह।

Jh txnhi flag % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या – 125 प्रस्तुत हैः

(क) वर्ष 2015–16 से आगे के वर्षों में डीएसआइआइडीसी को आबंटित किए गए फंड्स का विवरण क्या है;

(ख) इन वर्षों के दौरान डीएसआइआइडीसी द्वारा वास्तव में खर्च किए गए फंड्स का विवरण क्या है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान डीएसआइआइडीसी द्वारा लिए गए कार्यों का विवरण क्या है?

v/;{k egkn;% मंत्री जी।

m|kx e=h ¼Jh lR;Un tu½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 125 उत्तर इस प्रकार है:

(क) वर्ष 2015–16 से आगे के वर्षों में डीएसआइआइडीसी को चार औद्योगिक क्षेत्रों, लॉरेन्स रोड, उद्योग नगर मायापुरी एवं कीर्ति नगर के विकास के लिए फंड्स आबंटित किया गया, सूची संलग्न है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 50.91 करोड़ की धनराशि खर्च की गयीहै। जिसका पूर्ण विवरण सलंग्न सूची में दर्शाया गया है;

(ग) इस वर्षो के दौरान चारों औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 30 किलोमीटर सड़कों एवं 45 किलोमीटर नालियों के विकास का कार्य कराया गया है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI - 02

No. P.3/3/2004-GAD/CN/2762-2773 Dated : 06-07-2006

Cabinet Decision No. 1091 Dated 04/07/2006

Sub.: Implementation of High Capacity Bus System (HCBS) project from Ambedkar Nagar to Delhi Gate (16 km.) (Transport Department)

The Cabinet decided as follows :-

(i) Approval was granted to the proposal to implement HCBS project at a cost of Rs. 153,05 crores.

(ii) Approval was granted for a Project Management Consultancy fee payable to M/s RITES @ 5% of the project cost subject to ceiling of Rs. 6 crorcs.

(iii) It was decided that the work relating to implementation of HCBS may be assigned to Delhi Integrated Multi-modal Transit Systems (DIMTS) as soon as DIMTS obtains a certificate of 'Commencement of Business'. Till then the Transport Department shall handle this work and accept various recommendations made by M/s RITES on engineering and other related matters.

(iv) It was decided that the Public Works Department shall handover the possession of the stretch of road (Ambedkar Nagar to Delhi Gate) to M/s RITES for undertaking the work.

(v) It was further decided that tha Environment Department shall grant clearance for cutting trees in a phased manner and provide assistance for compensatory afforestation as in case of DMRC.

Sd/-

(R. NARAYANASWAMI)
SECRETARY TO THE CABINET

v/;{k egkn;% सप्लीमेंटरी।

Jh txnhi flag% सर, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूॅगा कि मायापुरी में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी फण्ड अलाट नहीं किया गया और तीन सालों से वहॉ पर नालों का काम रूका हुआ है, नाले जाम हैं और सड़कें काफी बननी हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूॅगा कि क्या हम इस साल सड़के और नालों पर कुछ काम करने जा रहे हैं?

m|kx e=h% अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले बताया है कि इन चार औद्योगिक क्षेत्रों में 50.91 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था बजट के द्वारा। बजट के द्वारा उसके बाद अभी पैसा आबंटित नहीं किया गया है। जैसे ही बजट में आबंटित होगा, तभी इसके आगे कार्य हो पायेगा।

Jh vkeidk'k 'kek% अध्यक्ष जी...

v/;{k egkn;% अभी उनका हाथ उठा, वो पहले राजेश जी।

Jh jkt'k xlrk% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूॅगा कि जो नाले वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया के अंदर डीएसआइडीसी ने बनाये थे, उसमें सफाई की क्या प्रक्रिया है क्योंकि एमसीडी के पास तो फिर भी कर्मचारी होते हैं, डीएसआइडीसी बार बार ये कहती है कि उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है, तो टेंडर ही लगेंगे और उस पर पूरा अतिक्रमण है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है और दूसरी बात लाइट्स के लिए हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं जो डीएसआइडीसी का एरिया है उसमें जो लाइट्स हैं, डीएसआइडीसी के एरिया में बड़े इण्डस्ट्रियल एरियाज के अंदर उसका रख–रखाव बिलकुल भी नहीं हो पा रहा है, धन्यवाद।

m|kx e=h% अध्यक्ष महोदय, डीएसआइडीसी टेंडर के द्वारा ही नालों की सफाई कराता है। उनके पास रेग्यूलर स्टॉफ नहीं है जैसा कि एमसीडी के पास रेग्यूलर डिपार्टमेंटल स्टॉफ होता है जो पूरे साल के लिए होता है। डीएसआइडीसी ठेका देकर पूरे जितने भी इण्डस्ट्रियल एरिया; 22 इण्डस्ट्रियल एरिया हैं, सभी का ठेका देकर साल में एक बार डिसिल्टिंग कराते हैं, इस बारी भी कराई जाएगी।

v/;{k egkn;% जरनैल जी।

m|kx e=h% लाइट की मेन्टेनेंस के बारे में जो भी इण्डस्ट्रियल एरिया डीएसआइडीसी के अंदर आते हैं, उसको डीएसआइडीसी को मेन्टेन करना चाहिए और डीएसआइडीसी रेस्पेक्टिव जो बिजली कंपनियां हैं, उनके द्वारा उनको मेन्टेन कराती है और आगे भी करवाएगी।

Jh tjuSy flag% धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, डीएसआइडीसी के पूरी दिल्ली में इण्डस्ट्रियल शेड्स हैं तो इनके व्यापारियों को 31 जनवरी तक एक पेमेंट भुगतान करने का नोटिस दिये गये हैं, नहीं तो, वो शेड्स सील कर दिया जाएगा, ये नोटिस में लिखा है। उसमें मूल अमाउंट के साथ साथ बहुत हैवी इण्टरेस्ट लगा हुआ है तो कइ सारे व्यापारियों ने मेरे से पूछा, मैं मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या इण्टरेस्ट में कोई छूट देने की व्यवस्था की जा रही है, उसके पहले–पहले? धन्यवाद।

m|kx e=h% अध्यक्ष महोदय, इंटरेस्ट जहॉ तक मेरी जानकारी है 18 परसेंट का इण्टरेस्ट था जिसको कम करके 10 परसेंट करने का प्रपोजल है और आशा की जाती है कि जल्द ही एलजी साहब की अनुमति से इसका निवारण हो जाएगा।

v/;{k egkn;% नहीं, हो गया, अब।

Jh tjuSy flag% मंत्री सर, वो न करें पेमेंट, क्योंकि ऑर्डर नहीं हुए ना अभी तक। फिर वो सीलिंग का खतरा रह जाएगा उन पर भी।

v/;{k egkn;% भई सहीराम जी, अब एक क्वैश्चन पर इतने नहीं, प्लीज। अंतिम ओमप्रकाश जी।

Jh vkseizdk'k 'kekZ% मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि डीएसआइडीसी के द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में जो सड़कों के निर्माण के लिए जो एस्टीमेट बने और उसमें साथ साथ एक एजेंसी फ्लड इरिगेशन को भी जोड़ दिया गया तो अब तो वर्ष करीब करीब अंत हो गया, उसका तो वो जितने भी इस्टीमेट बने तो उनके विषय में कोई काम तो हुआ नहीं जी।

m|ksx ea=h% प्रश्न इस क्वैश्चन से संबंधित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात हो रही है, इससे संबंधित नहीं है।

Jh vkseizdk'k 'kekZ% ये डीएसआइडीसी का है।

v/;{k egkn;% नहीं, नहीं, वो अलग विषय है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी नहीं हैं। मैं अभी लूॅंगा जो लेट आए हैं, बाद में लूॅंगा थोड़ा रुक जाइये। चौ. फतेह सिंह जी, प्रश्न संख्या–127।

pkS- Qrg flag% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या – 127 प्रस्तुत हैः

(क) दिल्ली में बस रूटों को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(ख) इन अध्ययनों का, जिस वर्ष ये किए गए, जिस एजेंसी द्वारा किए गए और इनकी फाइडिंग्स सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या ये फाइडिंग्स और अनुशंसाएं सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित की गई;

(घ) यदि हॉ, तो किस हद तक इन्हें कार्यान्वित किया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) जब ये अध्ययन किए गए और इनकी रिपोर्ट सब्मिट की गई, उस समय परिवहन विभाग के सचिव कौन थे?

ifjogu ea=h ¼Jh dSyk'k xgyksr½% माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 127 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हॉ;

(ख) वर्ष 2010–12 में परिवहन विभाग द्वारा उस समय डीटीसी द्वारा परिचालित सभी 791 बस रूटों(जिनमें दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित 657 रूट सम्मिलित थे), का डिमट्स से वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया। उक्त विषय पर डिमट्स द्वारा की गयी फाइडिंग्स परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है;

(ग) जी नहीं;

(घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता;

(ङ) इन अनुसंशाओं को कार्यान्वित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः—

1. दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटिड द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के कार्यावयन पर आपत्तियां/।

2. डिमट्स द्वारा प्रस्ताविक सुझावों के अनुसार विभिन्न रूटो पर 100, 78 बसों का परिचालन प्रस्ताविक था। उस दौरान डीटीसी एवं कलस्टर सेवा के अनतर्गत उपर्युक्त संख्या में बसे ना होने के कारण रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझावों को परिचालन में लाने पर आनेवाली कठिनाइयों को विचार करते हुए उचित निर्णय नहीं लिया जा सका।

(च)

क्र.स.	अधिकारी का नाम	प्रधान सचिव/सचिव व आयुक्त के पद पर कार्य अवधि 01.1.2010
1	श्रीआर.के शर्मा	18.02.2008 से 01.07.2011
2	श्री एम.एम.कुटट्री	02.07.2011 से 11.08.2011
3	श्री चन्द्रमोहन	12.08.2011 से 31.10.2012
4	श्री राजेंद्र कुमार	01.11.2012 से 31.01.2013
5	श्री पुनीत कुमार गोयल	01.11.2012 से 31.01.2013

ifjf'k"V d

Rationalization of Bus Routes in Delhi **Final Report**

Based on analysis conducted, following conclusions and recommendations are made:

- 100 routes have been designed as feeder system to metro network in Delhi.
- 254 routes have been identified as "No Change" routes, for which no major structural change is proposed.
- 169 routes have been identified as "Modified", for which changes in alignment in terms of extension/curtailment and diversion have been proposed.
- 234 routes have been proposed to be merged.
- 22 new routes have been proposed to connect newly developed areas, important trip generation points etc.
- 43 additional routes have been identified for regular operation.
- A high frequency public transport network have been designed, consisiting of the metro rail network and nine direction oriented bus routes. This will provide a subtle intuitive grid network of public transport for Delhi, encouraging shift to public transport from private vehicle users.
- Frequency of operation and fleet size requirement has been estimated for all routes. The phasing plan of implementation of these routes have also been worked out.
- The total requirement of fleet to operate the routes at design frequency has been estimated to about 10,077 buses, including 8% reserve fleet

- The proposals of the study should be implemented on ground as soon as possible as the phased strategy of operation have been worked out, keeping in mind the present fleet available with DTC and in the Cluster Scheme.
- Review of the bus route system should be conducted from time to time after their implementation to ensure their suitability to the ground situation. This would enable the accommodation of any changes required in the routing pattern due to various factors such as development of a new area in the city, construction and operation of new transport infrastructure, changes in mobility patterns of the passengers, etc. This would make the public transport of Delhi more dynamic and demand responsive. The first review should be done after six months of operation, and subsequently once every year.

v/;{k egkn;% हॉ, सप्लीमेंटरी फतेह सिंह जी।

pk- Qrg flg% अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से क्लस्टर सेवा दिल्ली में दी गई और जो क्लस्टर सेवाओं के रूट तय किये गये, वो तो भारी मात्रा में राजस्व कमा रहे हैं और जो डीटीसी के रूट तय किये गये, उन पर हमेशा घाटा आता है। तो ऐसा कौन सा कारण है, क्या सरकार द्वारा जिस तरह से वो अध्ययन किया गया रूटों का, क्या दोबारा उनका अध्ययन करके ऐसे रूट तय किये जाएंगे जहॉ पर भीड़भाड़ है और जहॉ राजस्व ज्यादा आ सकता है, यातायात की सुविधा उन लोगों को मिल सकती है, जो इससे वंचित हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार क्या करने जा रही है? दोबारा रूटों का अध्ययन करने के बाद, दोबारा रूट तय करने की सरकार की कोई नीति है, है तो क्या है और कब तक इसको क्रियान्वित किया जाएगा?

ifjogu ea=h% अध्यक्ष महोदय, अभी 2017 में दिसंबर में दिल्ली सरकार ने फिर दोबारा एक बार सभी रूट्स का रेसनलाइजेशन की स्टडी करने का निर्णय लिया और केबिनेट डिसीजन आलरेडी इस पर हो चुका है तो बहुत जल्द दोबारा रूटों का, बिकॉज जितने भी रूट्स हैं, इन पर फ्रीक्वेंसी कई जगह जहॉ रूट डायवर्ट हो गये हैं, कई नई सड़कें बन गइ हैं तो उस प्रकार से रूट रेसनलाइजेशन और रूट्स की स्टडी एक डायनमिक स्टडी है तो फिर दोबारा दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि सभी रूट्स का दोबारा एक बार स्टडी की जाएगी।

v/;{k egksn;% एनी सप्लीमेंटरी? हॉ महेन्द्र जी।

Jh egUnz xks;y% धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे यहॉ पर मैंने बस रूट के लिए सर्वे भी करवा दिया और बस को लेकर भी घुमा दिया कि यहॉ से ये बसें जा सकती हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाइ नहीं हुई है और दो बार से तीन बार में मतलब ये सर्वे हो चुका है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जानकारी दे दें जो कि आपके संज्ञान में भी हम लेकर आए थे, ये आपसे आग्रह है।

v/;{k egksn;% देखिये, मंत्री जी, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए नहीं तो इस क्वैश्चन से रिलेटेड नहीं है मेरे ख्याल से।

ifjogu ea=h% फस्ट ऑफ आल रिलेटेड नहीं है, सेकेंड...

Jh egUnz xks;y% रूट से रिलेटेड है। रूट का ही इसके अंदर जिक्र किया गया है और उसी रूट के बारे में मैं बोल चुका हूॅ और अधिकारी यहॉ पर बैठे हैं, तो उसका वो जवाब दे सकते हैं।

ifjogu e=h% अगर आप ये मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक–एक रूट के बारे में ध्यान रखूंगा, तो मेरे ख्याल से माफी चाहता हूॅ मैं।

Jh egUnz xks;y% मैं मान रहा हूॅ।

ifjogu e=h% दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक स्पेसिफिक रूट के बारे में!

Jh egUnz xks;y% बुद्ध विहार के बारे में वहॉ से बस जा सकती।

ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता।

v/;{k egksn;% महेन्द्र जी, इसमें जवाब देना कठिन है क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है, प्लीज। हॉ, गर्ग साहब, बताइये।

Jh fotUnz xxZ% माननीय मंत्री जी, लास्ट माइल क्नेक्टिविटी के लिए क्या परिवहन विभाग की भविष्य में कोई मेट्रो फीडर बसें बढ़ाने की योजना है।

v/;{k egksn;% मंत्री जी।

ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, लास्ट माइल कनैक्टिविटी एक बड़ा और इम्पार्टेंट और सैंसिटिव टॉपिक है और अभी जो दिल्ली सरकार ने दोबारा रूट रेसनलाइजेशन की स्टडी जो डिम्स द्वारा की जा रही है, उसमें लास्ट माइल कनैक्टिविटी का भी एक अलग से चैप्टर रखा गया है। जहॉ तक मैट्रो की आप बात कर रहे है, डीएमआरसी से भी लगातार हमारी मिटिंग के दोरान भी ओर स्पेशल मिटिंग्स के दोरान भी हमने ये बार–बार रखा है कि जितनी डीएमआरसी की बसेज होनी चाहिए, उसके मुकाबले में 50

परसेंट बसें आज चल रही हैं और स्पेशली जो डीएमआरसी फीडर बेसज हैं, उनका डायरेक्ट संबंध जो है, वो लास्ट माइल कनैक्टिविटी से ही है। तो अभी डीएमआरसी ने बसों की संख्या भी बढ़ाने का वादा किया है। कुछ नई बसें जो इलैक्ट्रिक बसिज हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि डीएमआरसी के द्वारा भी नई बसें लायी जाएँगी और बहुत जल्द लायी जाएँगी।

v/;{k egksn;% नहीं विजेन्द्र जी, हो गया। अब इसमें दूसरा।

Jh fotsUnz xx% अध्यक्ष महोदय, क्या दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अपनी तरफ से मैट्रो स्टेशन पर बसें लगा सकता है?

ifjogu ea=h% अध्यक्ष महोदय, जहॉ तक बात छोटी बसें हैं, दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उसके बारे में लगातार सोच रहा है लेकिन रूट रेसनलाइजेशन स्टडी में से ही ये निकलेगा कि कहॉ पर कौन से रूट पर छोटी बसें लगायी जाएं। कहीं इन्क्रोचमेंट की वजह से जो रोड है, उसका उसकी विड्थ कम हो गयी है। जहॉ हमारी जो स्टैण्डर्ड बसिज हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। हमारे यहॉ पर भी जो काफी विधायकगण हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में भी स्टडी की जा रही है। तो जहॉ–जहॉ जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उचित और ठोस कदम उठाए जाएंगे।

v/;{k egksn;% प्रश्न संख्या – 129 श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

Jh lqjsUnz flag% अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न संख्या – 129 का जवाब जानना चाहता हूँ:

(क) क्या धौला कुऑ से एयरपोर्ट तक की सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रस्ताव का, इसके अनुमानित खर्च एवं इसके पूर्ण होने की अनुमानित तिथि सहित विवरण क्या है;

(ग) इस परियोजना का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(घ) क्या यह कार्य एनएचएआई की तरफ से लिया गया है; और

(ङ) यदि हॉ, तो इसका विवरण क्या है?

Ykkd fuek.k e=h ¼Jh lR;Un tu½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 129 का जवाब प्रस्तुत है:

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के आधीन प्रस्तावित नहीं है, परन्तु इस विभाग द्वारा निम्न मार्गो का सम्भावित अध्ययन करवाया जा रहा था:

1. उत्तरी महिपालपुर बाह्य रोड से हवाई अड्डा रोड के बीच फ्लाई ओवर/अंडरपास का कार्य; परन्तु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 35 दिनांक 13/10/2017, यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिनांक 2/11/2017 को स्थानांतरित कर दिया गया है;

2. (ए) मोड रोड (रिंग रोड जंक्शन से करियप्पा मार्ग/स्टेशन रोड और थिमाया जंक्शन तक);

(बी) करियप्पा मार्ग (जेल रोड):

यह कार्य भी परिवहन मंत्री, भारत सरकार, तथा मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भारत सरकार)को दिनांक 27/6/2016 को स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगा कि जो रिंग जंक्शन से करियप्पा मार्ग और स्टेशन रोड थिमाया जंक्शन हैं और दूसरा जो करियप्पा मार्ग जेल रोड का जो काम है, ये एनएचएआई कर रहा है इसको। इसका रीजन ये था कि वहॉ पर काफी आर्मी की जगह है। केन्द्रीय मंत्री का यह कहना था कि वो तो कर लेंगे, अगर दिल्ली सरकार करती है तो काम में बहुत बाधा पड़ेगी। तो इस वजह से उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में लिया। वैसे भी नेशनल हाई वे के अंडर आता है तो उनका पूर्ण अधिकार है, वह कर सकते हैं।

v/;{k egksn;% हॉ, सपलीमैंटरी

Jh lqjsUnz flag% अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये दिल्ली सरकार जो है, केन्द्र सरकार से डिपोजिट वर्क करा रही है तो इसमें जो बजट दिल्ली सरकार ने दिया है, वह कितना बजट हमने उनको अलाट किया है?

Ykkd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भी बजट दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। सारा का सारा बजट जो एनएचएआई है, वह लगा रही है।

v/;{k egkn;% प्रश्न संख्या 130 महेन्द्र यादव जी (अनुपस्थित)। आज बहुत लोग अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 131 रघुविन्द्र शोकीन जी।

Jh j?kfoUn 'kkdhu% क्या परिवहन मंत्री प्रश्न संख्या 131 का जवाब देने की कृपा करेंगे:

(क) निजी बस ऑपरेटर्स द्वारा अंतर्राज्जीय रूटों पर गैर कानूनी रूप से बसें चलाना रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले 10 वर्षों में गैर कानूनी अंतर्राज्जीय बस ऑपरेटर्स के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) पिछले 10 वर्षों में चलाए गए प्रवर्तन अभियानों का वर्षवार विवरण क्या है; और

(घ) कितनी बसें गैर कानूनी रूप से चलते हुए पाई गई, कितने चालान जारी किए गए, कितनी बसें जब्त की गई और इन ऑपरेटर्स के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दे?

ifjogu e=h ¼Jh dyk'k xgykr½% माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–131 का जवाब निम्न प्रकार से है:

(क) प्रवर्तन शाखा द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। गहन चैकिंग के दौरान जो भी ऐसी बसें मिलती है, उसका चालान किया जाता है व जब्त भी की जाती है;

(ख) गैर कानूनी अंतर्राज्जीय बस ऑपरेटर्स के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों का उपलब्ध वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैः—

वर्ष	प्राप्त शिकायत
2014	21
2015	24
2016	14
2017	21
2018	01

(ग) प्रवर्तन शाखा इस दिशा में निरंतर कार्रवाई कर रही है। जो भी ऐसे बसें मिलती हैं, उसका चालान किया जाता है व बसें जब्त भी की जाती हैं। विशेष अभियानों का कोई अलग से रिकार्डस नहीं रखा जाता; और

(घ) बसों के सम्बन्ध में उपलब्ध वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैः—

वर्ष	कुल बसें	कुल चालान	बसें जब्त
2012—13	334	648	65
2013—14	1033	1258	39
2014—15	4191	4584	87
2015—16	1388	1575	121

वर्ष	कुल बसें	कुल चालान	बसें जब्त
2016—17	2084	3010	748
2017—2018 फरवरी तक	7961	13962	5359

वर्ष 2017 से अब तक कुल 1267 गाड़ियों के विरुद्ध परमिट निरस्त करने की कार्रवाई के लिए एसटीए ब्रॉच को भेजा गया है। (अरुणाचल प्रदेश—04, बिहार—01, चंडीगढ—01, गुजरात—04, जम्मू एण्ड कश्मीर—07, कर्नाटका—01, महाराष्ट्र—01, मध्य प्रदेश—12, नागालैंड—03, पंजाब—22, राजस्थान—577, उत्तराखंड—01, उत्तर प्रदेश—591)

इससे पहले का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

एसटीए ब्रॉच ने सम्बन्धित राज्य की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को परिमिट निरस्त करने के लिए प्रेषित कर दिया है, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% स्पलीमैन्टरी। चौ. फतेह सिंह जी।

pk- Qrg flag% अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मंडौली से मध्य प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए रोजाना करीब 20—30 गाड़ियॉ जाती हैं और जो विदआउट परमिट हैं। उस पर माननीय मंत्री जी का कार्रवाई करने का कष्ट करें, ऐसी बसों को जब्त करें और सारा रोड रात के बारह बजे तक वो घिरा रहता है, ऐसी अवैध बसों से। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए।

ifjogu e=h% कार्रवाई की जाएगी।

v/;{k egkn;% सौरभ जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि कुल बसें का, क्या मतलब है। कुल बसें, कुल चालान, बसें जब्त।

ifjogu e=h% टोटल बसेज।

Jh lkjHk Hkkj}kt% टोटल बसेज, कहॉ की?

ifjogu e=h% दिल्ली में जिनके एगेंस्ट एक्शन किया गया।

Jh lkjHk Hkkj}kt% जैसे ये लिखा है कि कुल बसे 334 और कुल चालान 648 तो एक ही बस का रिपीटेड चालान है, इस तरह से है क्या?

ifjogu e=h% एक बस के मल्टीपल चालान हो सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑफेंसेज उसमें पाए जाते हैं तो मल्टीपल चालान भी है तो उसकी वजह से कुल बसें कम हो सकती हैं लेकिन कुल चालान ज्यादा हो सकते हैं।

Jh lkjHk Hkkj}kt% जैसे मैं एक ये छोटा सा समझना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। ये प्रश्न नहीं है सिर्फ, सभी हाउस के लिए समझने के लिए है कि 2017 में 7961 मतलब 7961 अलग–अलग बसें आई या इतनी यहॉ पर उनके चक्कर लगे। ये क्या है 7961, एक साल के अंदर?

ifjogu e=h% 7961 जो है, वहॉ बसों का काउंट है।

Jh lkjHk Hkkj}kt% टोटल बसेज।

ifjogu ea=h% टोटल बसेज और जो...

Jh lkjHk Hkkj}kt% अलग–अलग प्रकार की। मतलब अलग–अलग नम्बर की इतनी हजारों बसें आई दिल्ली में।

ifjogu ea=h% नहीं, same bus can be challan for same offence again also.

v/;{k egksn;% मंत्री जी, उनका क्वैश्चन बिल्कुल जायज लग रहा है। एक सैंकेड सौरभ जी, ये संख्या बसों की बाहर से आने वाली आठ हजार हो गई। आठ हजार संख्या बसों की जो गैर कानूनी ढंग से चल रही हैं। इतनी संख्या दिल्ली में आठ हजार ये मुझे लगता फिगर चैक करना पड़ेगा इसको देखना...

Jh lkjHk Hkkj}kt% अन्तर्राज्यीय हैं ये?

ifjogu ea=h% अध्यक्ष इन्टरस्टेट बसें हैं अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egksn;% हॉ, आठ हजार इन्टरस्टेट बसें अगर दिल्ली में आ जायेंगी।

ifjogu ea=h% दिस इज ओवर अ पीडियड ऑफ टाइम ये मतलब एक दिन की नहीं है ये। दिस इज ऑलमोस्ट 2017 फरवरी से लेके 18 तक मतलब मोर दैन ए इयर।

Jh lkjHk Hkkj}kt% नहीं, ये नहीं है। मंत्री जी, नहीं हो सकता क्योंकि पिछले साल से इस साल में चार गुना बसें नहीं बढ़ेंगी दिल्ली में आने वाली क्योंकि पिछले साल ये 2000 थीं इस साल ये 7961...

ifjogu ea=h% देखिए सर, बिकॉज ऑफ... आपको बिल्कुल याद होगा कि पॉल्यूशन के उस टाइम भी काफी इस बार आप देखें कि चालान्स के अंदर काफी इंक्रीज है। तो this is a conscious effort which was put in by the Transport Department और उसके चलते हुए but if you still want then we will have the figures verified again.

Jh lkjHk Hkkj}kt% ये बस, हमें ये क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या फिगर है, ये टोटल नं. ऑफ बसिज क्या है?

Ifjogu ea=h% मतलब आप कह रहे हैं कि वो उसकी डिटेल चाहिए आपको?

Jh lkjHk Hkkj}kt% नहीं, डिटेल नहीं चाहिए। जैसे 7961 का मतलब ये है कि इतनी टोटल बसेज दिल्ली में आई, एक साल में या इतनी आई उसके ऊपर?

ifjogu ea=h% दीज आर... नहीं–नहीं, ये बसें जो हैं, आपका जो सवाल है, वो गैरकानूनी रूप से है। तो ये जो इल्लीगल बसेज जो ट्रांसपोर्ट के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उनके चालान किये, पकड़ी गईं, ये उसका ब्यौरा है।

Jh lkjHk Hkkj}kt% वही मैं समझ रहा हूँ। अगर ये इल्लीगल बसें 7961 आई तो चालान 13 हजार कैसे हो सकते हैं?

ifjogu ea=h% भई same bus can be challaned for more than one offence.

v/;{k egksn;% चालान दोबारा हो सकता है। साल में दो बार आ सकती है। वो ठीक है।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी चीज समझना चाह रहा हूँ हाउस के लिए कि 7961 गलत तरीके की बसें आईं, 13 हजार चालान हुए और 5300 उसमें जब्त हो गयीं, तो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा।

दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बताई कि इतनी बसेज के लिए परमिट रद्द करने के लिए आपने एसटीए ब्रॉचेज को लिखा, ये सिर्फ इस साल के लिए क्यों उपलब्ध है, इससे पहले के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है डिपार्टमेंट का?

ifjogu ea=h% ये सवाल जो है, मैंने भी अधिकारियों से किया था तो इसका I would request Transport (Commissioner) who is here to give a detailed reply on this.

Jh lkjHk Hkkj}kt% इसको क्वैश्चन एंड रेफरेंस कमेटी में रेफर कर दें अध्यक्ष जी?

v/;{k egkn;% एक बार मुझे देख लेने दीजिएगा। अनिल बाजपेयी जी

Jh vfuy cktis;h % मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम कितने, कुछ भी मत कहिए सर। आइएसबीटी से लेकर और जो यूपी बॉर्डर है और आनंद विहार का जो हमारा बस अड्डा है, अगर उस पर ही अधिकारी सही तरीके से एक दिन अगर सख्ती करके अगर चेकिंग करके निकल जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 300 बसेज आपको इस रूट पे मिल जायेंगी जो उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, फर्रूखाबाद...

v/;{k egkn;% नहीं बाजपेयी जी, इसमें से क्वैश्चन बनाइए।

Jh vfut ckti;h% मैं वही कह रहा हूँ सर। तो उन पर सर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, हमने दिल्ली विधान सभा की जो मीटिंग है, उसके अंदर भी ऋतुराज जी वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, हमने जो हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, वो भी आई थी उस टाइम, हम लोगों ने उनको जगह के नाम भी लिखाए थे। हमने कहा कि प्लीज ये कराइए, जो हमारी एमसीडी की पार्किंग है, वहॉ सारी बसेज खड़ी रहती हैं। सारी शास्त्री पार्क की रेड लाइट पूरी जाम रहती है, सारी बसें लोग साइड पे खड़ी करते हैं, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी सर, कब तक होगी? पूरी जनता सफर कर रही है और आपका भी नुकसान हो रहा है सर, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू... उसका भी नुकसान हो रहा है।

ifjogu ea=h% अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही बात है कि इल्लीगल बसेज की प्रॉब्लम है। अलग अलग जगह से ये लोग इल्लीगली बसेज ऑपरेट करते हैं और इसी चीज को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो पिछले साल. .. अगर आप 2016–17 की फीगर देखेंगे तो कुल चालान 3010 हैं और उसी चीज को रोकने के लिए कि जितनी इल्लीगल बसेज ऑपरेट कर रहीं हैं, उनको रोकने के लिए अगर आप देखेंगे तो 17–18 में 13962 चालान्स हुए हैं टोटल। तो काफी बड़े लेवल पर इनके अगेंस्ट एक्शन हुआ है। लेकिन मैं सभी माननीय विधायकों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उसी प्रकार से जो इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसको हम और पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और ये एश्योर करेंगे कि इनके अगेंस्ट लगातार एक्शन होता रहे।

v/;{k egkn;% सौरभ जी, प्लीज इसमें चालान की राशि क्या है, कितनी है, क्या वो चालान की राशि एक बस रिपीटिड पकड़ी जाती है तो

क्या चालान की राशि बढ़ती है, दूसरी बार अपराध करने पर कितनी तीसरी बार करने पर कितनी? चौथा इसी में से प्रश्न निकल रहा है, ये बसें जो हमने जब्त की हैं, इनको किस आधार पर छोड़ दिया जाता है?

ifjogu e=h% जस्ट बाइ कॉमन नॉलेज आई... मतलब पक्का नहीं है बट आइ थिंक एक बार बस इंपाउंड हो जाती है, उसके बाद it has to be left only on giving surety या तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी छोड़ेंगे या थ्रू कोर्ट के थ्रू जो गाड़ी छूटती है। तो ये दो ही पॉसिबिल्टिीज हैं, अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egkn;% चालान की राशि क्या रहती है?

ifjogu e=h% चालान की राशि का अध्यक्ष महोदय, मैं पता करके सदन को...

Jh jkt'k xqIrk% अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि वो देना नहीं चाहते। लिख के तो दे रहे हैं हम लोग, देते हैं या नहीं?

v/;{k egkn;% मैं इसको... क्वैश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को दे देते हैं। भई हो गया, सुरेन्द्र जी, ये क्वैश्चन ही मैंने क्वैश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को दे दिया, मुझे इसमें बड़ा गड़बड़ लग रहा है।

ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है, सेकेण्ड चालान जो है, वो डबल किया जाता है लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो उस फाइन को कम भी कर सकती है और गाड़ी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट के द्वारा ही छोड़ी जाती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गाड़ी नहीं छोड़ता है।

v/;{k egkn;% चालिए, प्रश्न संख्या 132 विशेष रवि जी

Jh fo'k"k jfo% सर, इसका जवाब नहीं आया।

v/;{k egksn;% हॉ, इसका जवाब नहीं आया, वो ठीक है। वही विषय है जो कल वाला था।

Jh fo'k"k jfo% सर, इसमें मैं कुछ कहना चाहूॅगा सर, कि पिछले सेशन में भी हमने... ये प्रश्न मैंने खुद उठाया था थाना लेवल कमेटियों के बारे में कि जो एलजी साहब ने थाना लेवल कमेटियों को बदल के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाया है वहॉ पर कमेटियों में बिल्कुल काम नहीं हो रहा, उन मीटिंगों में कोई काम नहीं हो रहा है जो चेयरपर्सन है, वो माननीय सांसद होते हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट की लगभग 4–5 मीटिंग हुईं हैं, उसमें सिर्फ एक बार वो आए, चार मीटिंग में वो नहीं आए। चार मीटिंगों में मीटिंग सिर्फ हमने चाय पीने के लिए करी। उससे पहले जब थाना लेवल कमेटी की मीटिंग होती थी तो वहॉ पर हम क्षेत्र के आरडब्ल्युए संस्थायें और पुलिस के अधिकारी बैठते थे। वहॉ पर क्षेत्र की समस्याओं को डिस्कस करते थे और हर महीने उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे। तो एक तो एलजी साहब ने उन कमेटियों को जो काम कर रही थीं क्षेत्र के लिए, उनको खत्म कर दिया, उसके बाद जब डिस्ट्रिक लेवल थाना कमेटी बनाई तो उसमें वो काम नहीं कर रहे हैं और जब प्रश्न किया जा रहा है इस बात पे, तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

v/;{k egksn;% ठीक है, करते हैं इसमें कार्रवाई।

Jh fo'k"k jfo% लेकिन एक मिनट सर, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूॅगा कि इससे ठीक पहले प्रश्न के अंदर प्रश्न संख्या नं 130 में जहॉ परिवहन विभाग से प्रश्न पूछा गया ट्रैफिक पुलिस से संबंधित, तो ट्रैफिक

पुलिस के माध्यम से जवाब दिया है। जब ट्रैफिक पुलिस का जवाब आ सकता है तो पुलिस वाले क्यों जवाब नहीं दे सकते सर, उनको क्यों रोका गया है ?

v/;{k egkn;% जिस जवाब में इनको ये देखने में लगता है कि हमारी गर्दन फंस रही है, उसका जवाब एलजी का लेटर लेके नहीं देते। जिसमें इनकी गर्दन फंसती दिखाई देती है, उसका उत्तर एलजी के लेटर का बहाना लेकर नहीं दे रहे हैं।

Jh fo'k"k jfo% सर, इसमें मेरी एक प्रार्थना है कि जो होम सेक्रेटरी हैं, उनको क्वैश्चन एंड रेफरेंस कमेटी में बुलाया जाए और वहॉ पर सवाल जवाब किए जायें।

v/;{k egkn;% करेंगे... इसको कर रहे हैं।

Jh fo'k"k jfo % या सर, मंत्री जी जवाब दें सर, इसकर मंत्री जवाब दें कि जवाब क्यों नहीं आया इसका। सर, मंत्री जी जवाब दें कि इस प्रश्न का अब तक उत्तर क्यों नहीं आया है?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% देखिए, मैं अभी केवल इतना कहूॅगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। आज अखबारों ने कल को जितना वेटेज दिया; विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को लेकर, और उस अखबारों की चर्चा से जरा भी केन्द्रीय सरकार को थोड़ी भी शर्म और एलजी को... इस ऑर्डर को तुरंत वापस लें और नहीं लेंगे तो फिर आगे सदन जो भी तय करेगा, वो करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रैस ने कुल मिला के बहुत अच्छा रोल अदा किया है।

Jh vt; nRr% अध्यक्ष जी, ये पूरी विधानसभा दिल्ली के लोगों के प्रति उत्तरदायी है और जिस तरीके से दिल्ली में लॉ एंड आर्डर खराब हो रहा है, जिस तरीके से मेरे क्षेत्र में 17 मर्डर हो चुके हैं अब तक और रोज गोलियॉ और चाकूबाकी हो रही है, ये दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है और गृहमंत्री के जो सचिव हैं, उनकी जवाबदेही है और हमारी भी जवाबदेही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पुलिस कमिश्नर को और एलजी को आप हमारे माध्यम से लिख के भेजें कि दिल्ली की जो जनता है, जहॉ पे लॉ एंड आर्डर पूरा खराब है, जहॉ पे रोज रेप हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, उनकी जवाबदेही के लिए आप अपना आन्सर लिख के भेजें, ये गुजारिश है अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

Jh xqykc flag% अध्यक्ष महोदय, उनसे समय मांगिएगा गृहमंत्री जी से और हम सब विधायक मिलना चाहते हैं क्योंकि स्थिति ये होती है कि जो अभी सांसद महोदय जिस मीटिंग को ले रहे होते हैं, उसको इस तरह से उस मीटिंग को किया जाता है, विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, उसमें भाजपा के कुछ उनके जो स्थानीय नेता होते हैं, वो आते हैं और वहॉ जब पुलिस का जो रोल होता है, वो ऐसा होता है जैसे मतलब क्राइम हो ही नहीं रहा। वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सांसद महोदय एक्सेप्ट कर रहे हैं, हॉ भई क्राइम कुछ नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गृह मंत्री जी से आप मिलने का समय लें।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% बैठिये प्लीज।

Jh xqykc flag% सारे विधायक उनसे मिलना चाहते हैं, इस स्थिति से उनको अवगत कराना चाहते हैं

v/;{k egkn;% lkjh चर्चा हो गई हैं, कल अधिकांश चर्चायें हो गई हैं।

Jh iadt iq"dj% 23 मार्च को सदन के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल की डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस कमेटी रखी गई, मैंने तत्काल डीसीपी महोदय को सूचित किया। उन्होंने कहा ये तो मिनिस्टर महोदय के आफिस से तय होता है। मैंने कहा कि मिनिस्टर महोदय को इस बात का संज्ञान नहीं है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है इस टाइम। उन्होंने कहा उनका संसद भी चल रहा है। हमने कहा कि वो संसद तो खैर! जैसा चल रहा है, वो देश पूरा जानता है लेकिन जहॉ हम सात बजे तक विधानसभा में बैठ कर यहॉ काम कर रहे हैं, दिल्ली के जनता के हितों की बात कर रहे हैं, वहॉ पांच बजे सैन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग रखी जाती है, सब कुछ जानते बूझते और सवाल ना जाने... मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग नहीं होगी, थाना लेवल कमेटी आप बनने नहीं देंगे। वहॉ पर मीटिंग ऐसे रखवाएंगे कि आ न पाये। मीटिंग होने के अगले दिन सूचना आती है ऐसे ऐसे मेरे पास...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% बैठिये पुष्कर जी, बैठिये माननीय मंत्री जी भई, विशेष जी, आप कह चुके हैं ना अपनी बात।

...(व्यवधान)

नहीं भई, ऐसे नहीं। फिर ये सदन चलाना बड़ा कठिन हो जाता है।

Jh jkts'k _f"k% मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग के लिए रात को एक बजे पुलिस वाला आ के नोटिस दे के जाता है कि सुबह आपको जाना है, ये स्थिति है इनकी। इन्हें दिन में देने की फुरसत नहीं है। बोलते हैं कि पुलिस इतनी सक्रिय है कि रात को भी काम करती है, ये दिखाने आये थे आप को, ये स्थिति है।

v/;{k egksn;% बैठिये, प्लीज।

Jh jkts'k _f"k% हमारे एमपी महोदय होते हुए भी... वो खाली हॅसते रहते हैं। हमने जो उनको सवाल पूछे हैं, उसका कभी जवाब नहीं आता। हम जो काम के लिए कहते हैं, वो कभी काम नहीं होता। केवल एक माहौल बना होता है। वहॉ पर सारे के सारे इनके मंडल अध्यक्ष बैठे होते हैं या उनके पुराने पार्षद, वही सब की सब अपनी बातें रखते हैं और उन्हीं की बात पर हॉ, हॉ होती है।

v/;{k egksn;% चलिए।

...(व्यवधान)

Jh iadt iq"dj% जेएनयू में आठ लड़कियों के ऊपर बिल्कुल... वहॉ का प्रोफेसर करता है। हर घर की, हर थाने की ये स्थिति है उसको बहुत गंभीरता से लें।

v/;{k egksn;% पुष्कर जी, ये विषय रखा जा चुका है, आप द्वारा पहले भी रखा... माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

Jh iadt i'dj% तारांकित प्रश्न है, उसका जवाब नहीं आया। सीधा ये सवाल पूछा है कि आबादी के हिसाब से कितनी इसमें... ये सवाल का जवाब देते हुए ऐसी तैसी हो रही है, गंभीरता से लें।

x“g e=h% अध्यक्ष महोदय पहले तो मैं सदन के सामने ये कहना चाहूॅंगा कि ये दुर्भायपूर्ण है। जिन प्रश्नों के जवाब एक आरटीआई लगा के, दस रुपये से कोई भी नागरिक ले सकता है, उनके जवाबों को मना करना... ये बिल्कुल मुझे खुद दुःख हो रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट ने लिख के भेज दिया विधानसभा को कि इसका हम जवाब नहीं देंगे। बहुत ही दुःखद है।

v/;{k egksn;% आपसे साइन करवाये, आपके पास फाइल भेजी?

x`g e=h ¼Jh lR;sUnz tSu½ % जी नहीं, मुझे भी यहीं पर आने के बाद पता लगा, ये क्वैश्चन लगा था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूॅं... थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड बता दूॅं, ये जो थाना लेवल कमेटी है, इस सरकार के बनने से पहले कई सालों से बनी थी। अभी मेरे पीछे माननीय सदस्य राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि भई, पता करें कि क्या कहीं राजनीति से दुष्प्रभावित तो नहीं है। हो सकता है... क्योंकि सदन में सारे एमएलए लगभग एक पार्टी के आ गये तो उन्होंने कहा भई कि थाना लेवल कमेटी के चेयरमेन एमएलए हुआ करते थे, उसको खत्म कर दी। क्योंकि दूसरी पार्टी के सारे एमपी थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को बना दिया गया। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से प्रेरित हो के इस तरह से डिसीजन नहीं लेने चाहिये। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।

v/;{k egkn;% आज के भी प्रश्नों के उत्तर नहीं आये, कल की जानकारी के बाद भी, इसके विरोध में आधा घंटे के लिए मैं सदन स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।)

lnu vijkgu 3%20 ct iu% leor gvkA

v/;{k egkn; ¼Jh jke fuokl xk;y½ ihBklhu g,A

v/;{k egkn;% प्रश्न संख्या–133 श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nRr% माननीय मंत्री जी कृपया प्रश्न संख्या–133 का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) पिछले 5 वर्षों में सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण हेतु गए अधिकारियों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) इन प्रशिक्षणों का, इनकी अवधि, जिस एजेंसी द्वारा ये प्रशिक्षण प्रदान किए गए सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) पिछले पॉच वर्षों में अन्य विभागों /सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के जिन अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण लिया, उनका विवरण क्या है?

ifjogu ea=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 133 का जवाब इस प्रकार है:

(क) इस विभाग में उपलब्ध रिकॉर्डस/सूचना के अनुसार श्री एस.के. बाली.सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जो इस विभाग में नवगठित

सड़क सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी में विशेषज्ञ के तौर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा तैनात किये गए हैं, आइ.आर.टी.ई. द्वारा आयोजित रोड एक्सीडेंट इनवेस्टीगेशन ट्रेनिंग (5–9 मार्च 2018) में सम्मिलित हुए थे;

(ख) अवधि 5–9 मार्च 2018 एजेंसी –इंस्टि्टयूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आइआरटीई) बी–125–130,डीडीए शैडस्, ओखला औद्योगिक एरिया ,फेस–1, नई दिल्ली– 110020, वैन्यू ऑफ ट्रेनिंग–कालेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट सूरज कुंड बड़खल रोड, अरावली हिल्स, सेक्टर–43, फरीदाबाद,एनसीआर दिल्ली; और

(ग) अन्य विभागों/सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण से सम्बधित जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है तथापि जानकारी उपलब्ध करने हेतु शहरी विकास विभाग को अनुरोध किया गया है।

v/;{k egkn;% सप्लीमेंटरी।

Jh vt; nRr% मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रशिक्षण समिति का गठन कब हुआ क्योंकि इसकी कोई इसमें जानकारी नहीं है?

ifjogu ea=h% अध्यक्ष महोदय ये, सवाल अभी एक–दो दिन पहले भी आया था। उसमें पूरा बताया गया था कि रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग के दौरान जो ये लीड एजेंसी का गठन हुआ है और इसका गठन अभी हुआ है। जिसके तहत सारी रोड सेफ्टी पॉलिसी की भी जो फाइनल जो प्रिपरेषन है, वो चल रही है।

Jh vt; nRr% मंत्री जी कब, कौन सी डेट?

ifjogu ea=h % नहीं, एग्जेक्ट डेट मुझे याद नहीं है।

Jh vt; nRr% अच्छा एक और मेरा इसके साथ क्वेश्चन था इसमें जो ग) भाग है, इसमें क्यों अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की प्रशिक्षण विभाग को पूर्ण सूचना या जानकारी नहीं दी और अगर नहीं दी है तो उस पर क्या कार्रवाई बनती है?

ifjogu ea=h % नहीं, वो तो अध्यक्ष महोदय, जो डिफरेंट रोडिंग एजेंसी को; पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, डीडीए है, तो उनके जो आफिसर्स हैं, वो अलग–अलग ट्रेनिंग के लिए कहां जायेंगे, उसका आन्सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैसे देगा?

v/;{k egksn;% ऐनी सप्लीमेंटरी? बोलिए।

Jherh izfeyk Vksdl% मैं मंत्री से ये जानना चाहती हूॅं कि डीटीसी बसों के जो ड्राइवर है वो बसें बहुत रफली चलाते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग देने की योजना है?

ifjogu ea=h % अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन जो है कनेक्टिड नहीं है बट चूंकि प्रमिला बहन...

v/;{k egksn;% प्रमिला जी कभी–कभी पूछती हैं, जब पूछती हैं तो बड़ा भारी भरकम होता है।

ifjogu ea=h % मैं इसीलिए उसी पर आ रहा था पर चूंकि क्वेश्चन... वो बसें चाहे डीटीसी की हैं या जो कलस्टर की बसें हैं, अगर कोई भी ड्राइवर उसमें ठीक तरह से नहीं चला रहा है तो उसको एक रिफ्रेशर कोर्स

के लिए भेजा जाता है। जहॉ उसको सेंसिटाइज किया जाता है तो अगर आपके संज्ञान में ऐसे कोई ड्राइवर है या उसका अगर बस नंबर हो।

v/;{k egkn;% जो अनुपस्थित थे सदस्य, मैं आज दोहरा रहा हूॅं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान रखें। अखिलेशपति त्रिपाठी जी प्रश्न संख्या–121 बस, पढ़ दीजिए; प्रश्न संख्या–121 का उत्तर दीजिए।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh% माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रश्न संख्या–121 का जवाब देने का कष्ट करें।

(क) दिल्ली में बन रहे अस्पतालों और उनमें प्रस्तावित बिस्तरों की संख्या का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह निर्माण कार्य शेड्यूल के मुताबिक प्रगति कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना वार इस देरी के क्या कारण हैं;

(घ) कितने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं शैड्यूल के मुताबिक शुरू नहीं हुई हैं;

(ङ) प्रस्तावित अस्पतालों को कब तक कमिशन कर दिया जाएगा;

(च) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी में 800 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पिछले वर्ष पूरा हो गया था;

(छ) इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ज) बाबू जगजीवन राम अस्पताल में वेंटीलेटर्स खरीदे जाने के प्रस्तावों का विवरण क्या है; और

(झ) दीपचंद बंधु अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड, ऑपरेशन थियेटर्स और लेबर रूम कब तक खोल दिए जाऐंगे?

LokLF; ea=h ¼Jh lR;sUnz tSu½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–121 का उत्तर निम्न प्रकार है;

(क) निम्नलिखित तीन अस्पताल परियोजनाएं निर्माणाधीन है:

1. अम्बेडकर नगर अस्पताल परियोजना –600 बैड,
2. बुराड़ी अस्पताल परियोजना –768 बैड, और
3. द्वारका, सैक्टर–9 में इंदिरा गांधी अस्पताल परियोजना –1500 बैड

(ख) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है लेकिन बिस्तर संख्या में वृद्वि के कारण निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख शैडयूल समय से आगे बढ गई है;

(ग) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन बिस्तर संख्या में वृद्वि के कारण निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख शैडयूल समय से आगे बढ गई है।

(घ) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ङ) अस्पताल परियोजनाओं की पीडब्लूडी द्वारा भवन तैयार करने की तिथि निम्नलिखित है:

1. अम्बेडकर नगर अस्पताल परियोजना –फरवरी 2019(एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित),

2. बुराड़ी अस्पताल परियोजना –दिसम्बर 2018 (पीडब्लूडी द्वारा प्रस्तावित),

3. द्वारका सै.–9, दिसम्बर 2018 (पीडब्लूडी द्वारा प्रस्तावित),

(च) जी नहीं;

(छ) बुराड़ी अस्पताल परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन बिस्तर संख्या (220 से 768 बैड) में वृद्धि के कारण निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख शैडयूल समय से आगे बढ़ गयी है;

(ज) बाबू जगजीवन राम–सात वेंटीलेटर्स खरीदने का प्रस्ताव है। वेंटीलेटर्स के स्पेसिफिकेशन को अंतिम रूप देने के लिए मामला वर्तमान में अस्पताल एवं सी.पी.ए. के बीच विचाराधीन है; और

(झ) मैटरनिटी ओ.टी. एवं ऑपरेशन थियेटर्स मई माह, 2018 के अन्त तक आरम्भ कर दिये जाएंगे। अन्य ओ.टी. सुविधाएं छः माह के अन्दर आरम्भ कर दी जाएंगी।

v/;{k egksn;% हॉ जी, सप्लीमेंटरी।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh% माननीय मंत्री जी बताने का कश्ट करें कि सात वेंटीलेटर बाबू जगजीवन राम में आप कह रहे हैं कि खरीदे जाने का पिछले दो साल से चल रहा है, जहॉ तक मैं जान रहा हूॅ। वो कब मिल जाएगा अस्पताल को, जिसे लोग यूज कर पायेंगे?

LokLF; ea=h% अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने 150 वेंटीलेटर्स सभी अस्पतालों के लिए इकट्ठे लिए थे तो उस समय सभी अस्पतालों से पूछा गया था, जिस भी अस्पताल की जितनी भी कैपिसिटी थी वेंटीलेटर लेने

की, ये तो उल्टा हुआ था कि वेंटीलेटर ज्यादा हो गए थे और लेने वाले अस्पताल कम थे। तो उसके बाद जिस भी अस्पताल ने दो मॉगे, जिसने चार मॉगे, पॉच मॉगे, दस मॉगे, सबको दिए गए थे। ये उसके बाद इन्होंने लगता है, अपनी रिक्वायरमेंट बनाई है। इसलिए दोबारा से अलग से खरीदे जा रहे हैं।

Jh vf[kys'k'kifr f=ikBh% एक और सर, सप्लीमेंटरी मेरा है।

v/;{k egkn;% भइ देखिए ऐसे तो नहीं चल पाएगा। नहीं अब मैं कितने सप्लीमेंटरी लूॅगा आपसे पहले हाथ उठ चुके हैं।

-...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं, अखिलेश जी, बैठिए अब प्लीज। एक तो देर से आए हैं। नहीं, फतेह सिंह जी, आपके पीछे... मैं नाम... एकदम स्लिप हो रहा है माइंड से। करतार सिंह जी।

Jh djrkj flag roj% अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहॅूगा कि छतरपुर विधानसभा में पिछले करीब दस वर्ष से...

v/;{k egkn;% कौन–सी विधानसभा में?

Jh djrkj flag roj% छतरपुर विधानसभा। एक हॉस्पिटल का जो निर्माण प्रस्तावित है, उसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया किसी भी वजह से। इस बार बजट में फिर हमारे मंत्री जी ने जो है, प्रस्ताव किया है कि वहॉ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बजट में ही प्रावधान किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूॅ कि जो वहॉ पर एक रूकावट थी रिज का फॉरेस्ट

के लैंड की तो क्या उसको दूर करके वहीं पर बनाया जाएगा या उसको कहीं शिफ्ट करके कहॉ पर बनाया जाएगा, ये मैं जवाब जानना चाहता हूँ?

LokLF; ea=h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की रिक्वेस्ट के ऊपर ही इसको बजट में रखा गया है और उन्होंने कहा था कि जो जगह है, उसमें रिज की वजह से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा था कि हम सब लोग लगकर उस जगह को शिफ्ट करा लेंगे। जगह शिफ्ट हो जाएगी तो जरूर बनाया जाएगा।

v/;{k egksn;% प्रवीण जी बस, प्रवीण जी।

Jh izoh.k dqekj% अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि जो जयराम आश्रम ट्रस्ट में जहॉ पर उन्होंने विजिट भी किया था मॉर्निंग ओपीडी के लिए जो हॉस्पिटल के रूप में चालू होना था। उन्होंने विजिट भी किया था लेकिन उसके बाद फरदर उस पर क्या कार्रवाई हुई, मैं जानना चाहता था। इसके अलावा एक इसके अलग कस्तूरबा निकेतन में एक डूसिब की लैंड है, वहॉ पर ऑलरेडी हमने हॉस्पिटल का प्रपोजल दे रखा है। उसमें ज्वाइंट इंस्पैक्शन है जो अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।

v/;{k egksn;% उत्तर देंगे? वैसे इससे रिलेटिड नहीं है। फिर भी संभव है तो उत्तर दे दीजिए।

LokLF; ea=h% नहीं—नहीं, जो दूसरा नंबर प्रश्न है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पहले वाले के बारे में जानकारी है, उसको जगह देखकर आए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। उसके जब मैंने आदेश दिए

थे कि उनको चेक करके अगर पॉसिबल है तो उसको ओपीडी के लिए ले लें। मैं फिर से आदेश दूँगा कि उसको दोबारा देखें क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसे कई लोग हैं, बड़े गर्व की बात है हमारे सदस्य बैठे हैं, रघुविंद्र शौकीन जी बैठे हैं वो दो पॉलीक्लीनिक्स के लिए खुद की जगह देने को तैयार हैं। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को आदेष दिए हैं कि जो भी सरकार को दस साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देना चाहे तो उनके लिए एक एग्रीमेंट बनाकर लॉ डिपार्टमेंट से एप्रूव कराके हम उसको लेने के लिए तैयार है। मैं फिर से कहूँगा जितने भी इस तरह के इषूज हैं, जल्द से जल्द उनको क्लीयर किया जाएगा।

v/;{k egkn;% अमानतुल्लाह जी।

Jh vekurqYykg [kku% मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरिता विहार में पिछले साल भी अनाउंस किया था कि पॉच अस्पताल जो दिल्ली में बनने थे, उसमें से एक ओखला विधानसभा में सरिता विहार में बनना था जो 15 साल से वो ये ही सुनने में आ रहा है। कई बार उसका इनऑगरेशन हो गया है। तो उसमें क्या देरी हो रही है जो 318 बेड का अस्पताल सरिता विहार में बनना है?

LokLF; ea=h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब लगता है कि अबकी बारी जरूर बन जाएगा। अभी तक डिले चल रहा था तो अभी... इन्हीं के प्रयासों से मैं कहूँगा कि अमानतुल्लाह जी इसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे लिए तो शायद क्योंकि बड़े बड़े इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, शायद ये पीछे चलाया था, अब जरूर बने इनका।

v/;{k egkn;% चलिए। बस ये अंतिम पवन जी यहॉ उपस्थित हैं? नहीं, इसमें कुछ और नहीं, प्लीज। पवन कुमार शर्मा जी। कौन सा? मैं आ तो रहा हूँ दो मिनट तो रूक जाइए। पवन कुमार शर्मा नहीं उपस्थित। नारायण दत्त प्रश्न संख्या– 124।

Jh ukjk;.k nRr 'kekZ% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 124 का मंत्री साहब जवाब देने का कष्ट करें:

क) बीआरटी कॉरिडोर परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई, पूर्ण विवरण दें;

ख) इसकी उपयोगिता क्या थी;

ग) DIMTS के CMD के पद पर रहे अधिकारियों का विवरण क्या है;

घ) जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अम्बेडर नगर–दिल्ली गेट कॉरिडोर का कार्य हुआ, उनका विवरण क्या है;

ङ) इस परियोजना का प्रारम्भिक अनुमान क्या था और इस पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई; और

च) इस परियोजना में शामिल निजी कम्पनियों का विवरण क्या है?

ifjogu ea=h: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 124 का उत्तर इस प्रकार है:

क) बीआरटी कॉरिडोर परियोजना अंबेडकर नगर से दिल्ली गेट (16किलोमीटर) का निर्माण रुपया 153.05 करोड की लागत से कैबिनेट निर्णय संख्या 1091 दिनांक 4/7/2006 द्वारा होना तय हुआ था; इस कॉरिडोर

का निर्माण सन् 2006 में शुरू हुआ था व सन् 2008 तक अम्बेडकर नगर से मूलचंद (लंबाई 5.8 किलोमीटर) तक रू. 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार व संचालित हुआ था। (उपर्युक्त कैबिनेट निर्णय की प्रतिलिपी संलग्न है।);

ख) बीआरटी कॉरिडोर एक सार्वजनिक परिवहन प्रद्वति के रूप में सामान्य बस लाइन से ज्यादा तीव्र एवं कुशल सेवाएं प्रदान करता है जिसका उद्देश्य रेल ट्रांजिट की तरह की सेवा व गुणवत्ता,बस सेवा के रूप में प्रदान करना था;

ग) 1. वर्ष 2006 से जुलाई 2007 तक श्री बी.आई.सिंघल ओ.एस.डी.डिमट्स के पद पर रहे। (सर्वोच्च पद);

2. डिमट्स के एमडी और सीओ के पद पर श्री एस.एन.सहाय अगस्त 2007 से जुलाई 2014 तक कार्यरत थे।

3. श्री एम.रामशेखर अगस्त 2014 से 6/8/2017 तक ईडी एवं ज्वांइट सीओ के पद पर थे तथा 7/8/2017 से आज तक एमडी और सीओ के पद पर कार्यरत हैं;

घ) परिवहन विभाग के निम्न अधिकारियों के कार्यकाल में अम्बेडकर नगर–दिल्ली गेट का कार्य हुआः

आयुक्त का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री विजय एस मदान	29/05/2005	31/10/2006
श्री चंद्र मोहन	1/11/2006	07/08/2007

आयुक्त का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री डी.एम.सपोलिया	08/08/2007	17/02/2008
श्री आर.के वर्मा	18/02/2008	01/07/2011

ङ) इस परियोजना का प्रारंभिक अनुमान रुपये 153.05 करोड़ था और वास्तव में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

च) इस परियोजना में डिमट्स एवं M/S BSC C& C (JV) निजी कम्पनियॉ शामिल थी।

v/;{k egkn;% सप्लीमेंटरी, नारायण दत्त जी।

Jh ukjk;.k nRr 'kek% अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी साहब से पूछना चाहता हूॅ कि 53 करोड़ रुपये की परियोजना थी और उस पे 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया... 153 करोड़ की परियोजना थी और 200 करोड़ खर्च किया गया। उसके बाद भी वो परियोजना फैल हुइ, सफल नहीं हुई। देश की या दिल्ली की जनता का पैसा था बिना जानकारी के ही उसका कितना सफल होगा या असफल होगा और वो बना दिया गया और उसके बाद वो सफल नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा था। उस पैसे का बेमतलब की दुरूपयोग किया गया है। तो मैं तो ये चाहता हूॅ कि जिन अधिकारियों की वजह से ये चीजें हुई थी, उनकी कोई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना जी। 200 करोड़ खर्च करने के बाद भी और उसके बात नतीजा बिल्कुल टॉय टॉय फिस रहा... लिख लेंगे रिकॉर्ड में। तो मैं अध्यक्ष जी ये चाहता हूॅ कि जो भी अधिकारी हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, उससे सदन कम से कम ये गंभीरता से पूछे कि वो 200 करोड़ रुपये किसके थे।

v/;{k egkn;% चलिए, क्वैश्चन हो गया ना?

Jh ukjk.k nRr “kek% हॉ, क्वैश्चन है जी।

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे कुछ?

ifjogu ea=h% क्वैश्चन क्या है, अध्यक्ष महोदय?

ekuuh; v/;{k }kjk iz'u l[;k&124 ij 0;oLFkk

v/;{k egkn;% मैं इस प्रश्न को जो नारायण दत्त जी का है, एस्टीमेट कमेटी को सौंप रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई ऐसा नहीं चलेगा अजय जी। नहीं, बैठ जाइए प्लीज। महेन्द्र यादव जी, चलिए। प्रश्न संख्या 134 जगदीश प्रधान जी। उसके बाद बस अंतिम है 135।

Jh txnh'k iz/kku% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 134 का मंत्री साहब जवाब देने का कष्ट करें:

क) क्या सरकार ने वर्ष 2016–17 में सराय काले खां और आनंद विहार आईएसबीटी के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया था;

ख) क्या सरकार का द्वारका में भी एक नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा खोलने का कोई प्रस्ताव था;

ग) क्या पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत 1400 नए बस क्यू शैल्टर्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव था; और

घ) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है?

ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 134 का उत्तर इस प्रकार है:

(क, एवं ख) जी हॉ, वर्ष 2016 में कैबिनेट निर्णय संख्या 2416, दिनांक 30/08/2016 के अनुसार सराय काले खां, आनंद विहार और द्वारका बस अड्डों के नवीनीकरण तथा पुनर्निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस विषय पर अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग) 1397 नए आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कम्पनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर, 2013 जून 2014, फरवरी, 2015 व दिसम्बर, 2017 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। उपरोक्त के दृष्टिगत बस क्यू शेल्टर्स बनाने का नया मॉडल बनाया जा रहा है जो कि जल्द ही अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा; और

घ) उपरोक्तानुसार।

v/;{k egksn;% प्रधान जी।

Jh txnh'k iz/kku% अध्यक्ष जी, इसमें ख) भाग का जवाब नहीं दिया गया है।

v/;{k egksn;% हॉ, ओम प्रकाश जी।

Jh vkse izdk'k 'kekZ% मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूॅ कि आनंद विहार बस अड्डा, 2014 में जो राष्ट्रपति शासन के

दौरान जो वो बजट था, उसमें इसके लिए फंड का एलोकेशन किया गया था। लेकिन 2014 में जा फण्ड का एलोकेशन किया गया और 2018 तक अभी वहॉ किसी प्रकार का कोई काम चालू नहीं हो पाया है तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे?

ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जानकारी फरदर जैसे ओम प्रकाश जी ने सवाल पूछा है; सराय काले खॉ और आनंद विहार दोनों ही जो आइएसबीटीज बनने हैं, उसमें डीएमआरसी का कुछ काम चल रहा है और जिसमें डीएमआरसी के काम में देरी है और दोनों ही इन डिपो आइएसबीटीज का काम जो है, उस प्रकार से नहीं बढ़ सका आगे। तो जैसे ही डीएमआरसी का काम पूरा होता है और डीएमआरसी से वापिस जो टैम्परेरी बेसिस पे जो लैंड ली गई है, इसमें परमानेंट बेसिस पे भी कुछ पोर्शन जो है, लैंड के, ले लिए गए हैं। आनंद विहार में डीएमआरसी और जमीन मॉग रहा है। तो उसकी वजह से जो भी प्लॉनिंग की गई थी वो दोबारा वापिस सारी प्लॉनिंग करनी पड़ रही है। ये मैं आश्वासन दे रहा हूॅ कि जैसे ही डीएमआरसी का काम खत्म होता है तो पूरे नये सिरे से ये प्लॉनिंग कर इनको जल्दी बनाया जाएगा।

v/;{k egksn;% अजेश यादव जी प्रश्न सं. 135।

Jh vtss'k ;kno प्रश्न संख्या 135 का मंत्री साहब जवाब देने का कष्ट करें।

क) क्या यह सत्य है कि 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिरसपुर हॉस्पीटल खोलने के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

ख) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं;

ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछले वर्ष के बजट में इस अस्पताल के लिए प्रावधान किया गया था;

घ) यदि हॉ, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

ङ) पिछले 3 वर्षों में इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

च) यह अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा?

LokLF; e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 135 का उत्तर इस प्रकार है:

क) जी हॉ;

ख) विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं:

1. भूमि के अधिग्रहण का मामला कोर्ट के तहत विचाराधीन था जो 27/09/2010 को खारिज हुआ है,
2. प्रारंभिक योजना 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण करना था, जिसके लिए एक परामर्शदाता (मैसर्स हॉस्पिटेक मैंनजमेंट कंसल्टैट प्राइवेट लिमिटिड) 09/04/2012 को लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था,

3. 03/08/2012 में निदेशक स्वास्थ्य सेवा द्वारा परामर्शदाता द्वारा तैयार वैचारिक चित्र और डिजाइन को मंजूरी दे दी गई थी;

4. प्रस्तावित लेआउट जनवरी, 2013 में उत्तर दिल्ली नगर निगम

5. को पेश किये गए थे। हालॉकि मई, 2015 तक भवनों की परियोजनाओं को उत्तर दिल्ली नगर निगम कॉरपोरेशन द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी,

6. इस बीच स्वीकृत एफआर को 375 को बढ़ा दिया गया है।

परियोजना की समीक्षा के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा बेड ओर अन्य सुविधाओं की बढी हुई संख्या के साथ नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 1500 बिस्तरों वाले अस्पताल निर्माण को मंजूर किया गया था ओर इसकी चिकित्सा कार्यात्मक कार्यक्रम (एम.एफ.पी.) तैयार करके लोक निर्माण विभाग में भेजा जा चुका है;

ग) बजट उपलब्ध नहीं था;

घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं है;

ङ) 1500 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए एक अनुमोदित चिकिस्ता कार्यक्रम ड्रांइग/योजना तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए 27/01/2016 को लोक निर्माण विभाग को इस सदंर्भ में कई अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त रानी बाग पॉलीक्लीनिक की तर्ज पर एक अस्थाई ओ.पी.डी. स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है;

च) लोक निर्माण विभाग द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के बाद अस्पताल निर्माण शुरू करने की तारीख का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस अस्पताल परियोजना की शुरूआत के लिए संभावित समय–सीमा निम्नानुसार हो सकती है:

सलाहाकार की नियुक्ति	–	3 महीने
योजना और डिजाइन की मंजूरी	–	6 महीने
इएफसी अनुमोदन	–	3 महीने
कैबिनेट की मंजूरी	–	1 माह
माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी	–	1 माह
निर्माण कार्य पूरा करना	–	24 से 36 महीने

v/;{k egkn;% ऐनी सप्लीमेंट्री?

Jh vt;'k ;kno% सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरा क्योंकि इसमें पहला सवाल था कि 35 वर्षों से हॉस्पिटल जो है, इसका पूर्व प्रधानमंत्री ने भी उद्घाटन किया था, तीन बार पूर्व सीएम ने भी किया उद्घाटन। हमने उद्घाटन तो नहीं किया, लेकिन हमने घोषणा की थी कि हमारे सामने बनेगा और पिछले बजट में भी आया, उससे पहले बजट में आया था। अबकी बार के बजट में मैंने नाम नहीं पढ़ा था और मैं थोड़ा घबरा गया था मगर ये क्या कहानी हुई?

v/;{k egkn;% आप घबरा क्यों गये?

Jh vt;'k ;kno% नहीं, लेकिन मैं बस एक ही सवाल करूँगा क्योंकि मैं दो साल से, तीन साल से इलाके में कह रहा था कि कंफर्म बना के दूँगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लडूँगा, तो अब मैं जाके दोबारा कह दूं जैन साहब कि पक्का बन रहा है, भाई ये बता दो।

LokLF; ea=h% अध्यक्ष महोदय, अजेश जी को हम इस सदन के अंदर जरूर देखना चाहेंगे और ये चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं, जरूर पक्का चुनाव लड़ेंगे और हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों...

...(व्यवधान)

rkjkafdr iz'uksa ds fyf[kr mÙkj

123- Jh iou dqekj 'kekZ % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा के गांधी विहार एवं भड़ोला गांव में 2 नए पॉलिक्लिनिक्स खोलने का प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है;

(ख) क्या इन पॉलिक्लिनिक्स हेतु जमीन एवं भवन आवंटित किए जा चुके हैं; और

(ग) इन पॉलिक्लिनिक्स का उनके खोले जाने की तिथि एवं क्षमाता सहित पूर्ण विवरण क्या है?

LokLF; ea=h % (क) जी हां, दिल्ली सरकार के द्वारा गांधी विहार और सराय पीपलथला में 2 नए पॉलिक्लिनिकों को बनाने की सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) भडोला गांव की इमारत लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार को सोंप दी गई है। इस इमारत में बिजली पानी का कनेक्शन का प्रकरण चल रहा है। इस पॉलिक्लिनिक के उपकरण एवं फर्नीचर खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करके पॉलिक्लिनिक चालू कर दिया जायेगा। रोजाना 300–400 मरीजों को ओ.पी.डी. के स्तर का इलाज मुहैया करया जायेगा।

126- Jh euftnj flg fljlk % क्या ykd fuek.k foHkkx e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉल अपार्टमेंट्स (खालसा कॉलेज के सामने) के गेट नम्बर–2 के नजदीक की सड़क जिस अधिशासी अभियंता के क्षेत्राधिकार में आती है, उसका विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि लोक विभाग द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करते हुए इस सड़क पर कुछ कमरे बनाए गए हैं;

(ग) किस प्राधिकारी की अनुमति से ये कमरे बनाए गए;

(घ) क्या यह सत्य है कि ये कमरे और परिसर अब ठेकेदारों द्वारा और रिहायश के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह किसी कानूनी के अनुसार अनुज्ञेय है;

(च) इन व्यक्तियों को क्या–क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(छ) आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे इन अतिक्रमणों को हटाने का क्या कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इस गैर कानूनी गतिविधि के जारी रहने के क्या कारण हैं?

ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) मॉल अपार्टमेंट्स (खालसा कॉलेज के सामने) के गेट नम्बर–2 के नजदीक के कार्यपालक अभियंता, सड़क अनुरक्षण मंडल (केन्द्रीय एवं नई दिल्ली)/एम–413, लो.नि.वि., दि.स. के क्षेत्राधिकार में आती है। इस सड़क का नाम महात्मा गांधी रोड़ है।

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का रखरखाव किया जाता है अतः आवश्यकतानुसार सड़क के रख–रखाव के लिये कमरों का निर्माण जो कि अस्थाई प्रकृति के होते हैं, कराया जाता है।

(ग) लो निर्माण विभाग में अस्थाई कमरों का निर्माण कार्यपालक अभियंता की अनुमति से कराया जाता है।

(घ) खालसा कॉलेज के सामने माल अपार्टमेंट के गेट नं. 2 के पास रोड़ का मंडल कार्यालय है तथा दो अस्थाई कमरें हैं। मंडल कार्यालय रोड़ के रखरखाव का कार्य देखता है। अस्थाई झोपडीनुमा ढांचे सड़क पर उपयोग में सामग्री रखने व नजदीक चल रहें कार्यों के लेबर को रहने के लिये किया जाता है।

(ङ) सड़कों के रखरखाव की सामग्री रखने हेतु इस तरह की अस्थाई ढांचा अनुज्ञेय है अन्यथा रख–रखाव करने में विलम्ब व असुविधा होगी।

(च) इसमें चौकीदार को रहने विश्राम करने की कभी–कभी अनुमति है। अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है।

(छ) यह सड़क के रख–रखाव के लिये है ताकि सड़क के रखरखाव सामग्री शीघ्र भिजवाई जा सकें। इसे हटानेक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) लोक विभाग द्वारा निर्मित ढांचा अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। वैकल्पिक व्यवस्था होने पर या अनुपयोगी होने पर इन ढांचों को हटा दिया जायेगा।

(झ) लागू नहीं।

128- l|Jh Hkkouk xkM % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में मैट्रो स्टेशनों पर निःशुल्क शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या मैट्रो प्राधिकारी द्वारा ये सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ifjogu e=h % (क) जी हां।

(ख) ये सुविधाएं निःशुल्क देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) मैट्रो स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा के लिए 'सुलभ' तथा पीने के पानी की सुविधा के लिए 'पी लो' को अनुबंध प्रदान किया गया है। ये सुविधाएं सफाई खर्चा हेतु शुल्क पर प्रदान की जा रही हैं।

130- Jh egUnz ;kno % क्या ifjogu ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं की गम्भीरता के आधार पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ब्लैक स्पॉट्स का वार्षिक विश्लेषण निकालती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में इन रिपोर्टस का विवरण क्या है;

(ग) क्या परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन स्पॉट्स का फिजिकल इंसपेक्शन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या परिवहन विभाग ने इन स्पॉट्स पर कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(च) क्या सुधारात्मक उपाय करने हेतु परिवहन विभाग ने किसी अन्य विभाग/जमीन की मालिक एजेंसी के साथ कोई समन्वय स्थापित किया है; और

(छ) पिछले 10 वर्षों में विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों पर किए गए खर्च का परियोजनाओं/गतिविधियों की सूची सहित वर्षवार विवरण क्या है?

ifjogu ea=h % (क) उपलब्ध रिकार्डस/सूचनाओं के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता के आधार पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ब्लैक स्पॉट का वर्गीकरण सामान्य, नॉन–इंजरी, इंजरी, घातक दुर्घटना आदि वर्गों में करती है।

(ख) वांछित विवरण संलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(ग) जी नहीं, दिल्ली पुलिस की 'दुर्घटना अनुसंधान सेल' (एक्सीडेंट रिसर्च सेल) द्वारा इन स्पॉट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता है;

(घ) उपर्युक्त जबाब के आलोक में लागू नहीं है।

(ङ) इन स्पॉट्स पर सुधारात्मक कदम संबंधित सड़क की मालिक (निर्माण/मरम्मतकर्ता) एजेंसी द्वारा उठाये जाते है।

(च) सुधारात्मक उपाय हेतु विभाग द्वारा समन्वय का कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा दिल्ली सड़क सुरक्षा परिषद के आदेशों/निर्देशों के सन्दर्भ में किया जाता है।

(छ) सड़क सुरक्षा के उपायों/मुद्दों पर खर्च का विगत 05 वर्षों का उपलब्ध है जिसका ब्यौरा निम्न है:—

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि
1.	2012—13	शून्य
2.	2013—14	18,868/—
3.	2014—15	19,840/—
4.	2015—16	3,62,659/—
5.	2016—17	3,91,979/—
	कुल योग	7,93,346/—

Black Spots of the Year 2013

Sl. No.	Black Spot	Non-Injury Accidents	Simple Accide-nts	Fatal Accide-nts	Total Accide-nts	Persons Injured	Persons Killed
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ISBT Kashmiri Gate	0	20	13	Is	38	14
2.	Mukharba Chowk	0	8	13	21	16	14
3.	Mukhand Pur Chowk	0	10	12	22	14	12
4.	Nangloidtc Depot	0	7	12	19	11	12
5.	Jahangir Puri Bus Stand	0	7	12	19	11	12
6.	CNG Pump (SGT Nagar)	0	5	12	17	6	12
7.	Azadpur Sabzi Mandi	0	11	11	22	13	11
8.	Punjabi Bagh Chowk	0	10	11	21	14	12
9.	Nigam Bodh Ghat	1	20	10	31	21	10
10.	Shyam Lal College	0	12	9	21	16	9
	Black Spots of the Year 2014						
11.	Sarai Kale Khan	3	33	9	45	38	9
12.	Kashmiri Gate Chowk (Mori Gate)	0	16	9	25	19	9
13.	Nigam Bodh Ghat	0	12	9	21	13	9
14.	Mukhandpur Chowk	0	9	9	18	12	11
15.	Dr Bhabha Marg Crossing	1	16	8	25	22	9
16.	Punabi Bagh Chowk	0	6	8	14	7	8
17.	Isbt Kashmiri Gate	0	22	7	29	24	7

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Mahipalpur Flyover	0	20	7	27	26	7
19.	Shani Mandir	0	16	7	23	30	8
20.	Shahdara Flyover	0	11	7	18	12	7
	Black Spots of the Year 2015						
1.	Shastri Park/IT Park	0	21	10	31	32	10
2.	Near Nitesh Kunj Hotel (NH-8)	0	7	9	16	17	9
3.	Peeragarhi Chowk	0	12	8	20	17	9
4.	ISBT Kashmiri Gate	0	12	8	20	29	8
5.	Madhuban Chowk	0	11	7	18	15	7
6.	Punabi Bagh Chowk	0	11	7	18	14	7
7.	Majnu Ka Tila	0	8	7	15	9	7
8.	Budhpur Ganda Nalah/ Hanuman Mandir	0	7	7	14	15	9
9.	Shanti Van	2	15	6	23	27	6
10.	Sanjay T Point	0w	15	6	21	26	6
	Black Spots of the Year 2016						
1.	Shastri Nagar Metro Station	0	18	10	28	26	10
2.	Jahangirpuri Bus Stand	0	13	10	23	18	10
3.	Libas Pur Bus Stand	0	6	10	16	8	10
4.	Rajoukari Flyover	1	9	8	18	13	8
5.	Shani Mandir	0	9	8	17	19	10

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Majnu Ka Tila	0	6	8	14	7	8
7.	ISBT Kashmiri Gate	0	11	7	18	28	7
8.	Sanjay Gandhi Transport Nagar	0	6	7	13	8	7
9.	Burari Chowk	0	22	5	28	J3	6
10.	Bhalswa Chowk	0	16	6	22	24	7
	Black Spots of the Year 2017						
1.	Mukundpur Chowk	1	15	10	26	25	11
2.	Jahangirpuri Bus Stand	0	9	10 .	19	20	10
3.	Azad Pur Chowk	1	9	9	19	12	9
4.	Bhalswa Chowk	0	6	9	15	15	9
5.	Burari Chowk	0	15	8	23	20	8
6.	Britannia Chowk	0	5	8	13	8	8
7.	Siraspur	0	5	8	13	7	8i
8.	Shani Mandir NH-1	0	1	8	9	4	8
9.	Delhi Gate	1	11	7	19	14	8
10.	Shahdara Flyover	0	6	7	13	6	7

lcf/kr foHkkx l 131 dk mÙkj ikl r ugh gqvkA

132- Jh fo'k"k jfo % क्या xg e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में थाना लेवल कमेटियों की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) कितनी बैठकों में सभापति उपस्थित थे;

(ग) थाना लेवल कमेटियों को बंद करने एवं उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या थाना लेवल कमेटियों को दुबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

x`g e=h % संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

136- Jh ,l- d- cXxk % क्या LokLF; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में खोलने हेतु प्रस्तावित मौहल्ला क्लिनिक्स का विवरण क्या है;

(ख) ये मौहल्ला क्लिनिक्स कब तक खोल दिए जाएंगे;

(ग) चाचा नेहरू हॉस्पीटल के लिए नए भवन हेतु क्या डीडीए से जमीन उपलब्ध करा दी गई है;

(घ) यह भवन कब तक बन जाएगा;

(ङ) क्या निजी अस्पतालों में इलाज एवं कमरों की दरें तय करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(छ) दिल्ली में बनने के लिए प्रस्तावित नए अस्पतालों का विवरण क्या है?

LokLF; e=h % (क) कृष्णानगर विधानसभा में खोलने हेतु कुल 02 मौहल्ला क्लीनिक हैंः—

1. दिल्ली जल बोर्ड साईट, ब्लॉक—एस, शर्मा वार्ड के निकट।

2. दिल्ली जल बोर्ड साईट, ब्लॉक 2 ए झील, 310—बी के निकट।

(ख) 08 से 10 महीने।

(ग) डी.डी.ए. द्वारा निम्नलिखित दो भूखंड उपलब्ध कराई गयी हैंः—'

1. एक भूखंड 1250 वर्ग मीटर का 2011 में दिया गया था जो कि मरिजों के रिश्तेदारों के विश्राम कक्ष के लिए है, उसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण योजना एवं अग्नि विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है तथा निर्माण की योजना अस्पताल प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में मंजूर कर दी गयी थी। तब से लेकर विश्राम कक्ष निर्माण का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. के प्रोजेक्ट प्रभाग के पास लंबित है, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पी. डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से पत्राचार एवं संवाद किया है, लेकिन विश्राम कक्ष निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है।

2. एक अन्य भूखंड 9480 वर्ग मीटर का है जो कि अस्पताल के विस्तार के लिए है तथा अस्पताल ने डी.डी.ए. को मार्च, 2017 में जमीन के मूल्य का पूर्ण भुगतान कर दिया था लेकिन डी.डी.

ए. ने अभी तक जमीन का अधिकृत कब्जा नहीं दिया है। जिसके लिए अस्पताल की तरफ से प्रयास लगातार जारी है। भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही डी.डी.ए. द्वारा अधिकृत कब्जा मिलने के पश्चात् ही आरम्भ हो पायेगी।

(घ) डी.डी.ए. द्वारा अधिकृत कब्जा मिलने के पश्चात्, भवन निर्माण से संबंधित कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(ङ) जी हां।

(च) इस कार्य हेतु उच्च स्तरीय नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है जो शीघ्र अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेगे।

(छ) इसकी जानकारी अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

Detail of Proposed New Hospitals (deals in Hospital Cell, DGHS)

Under construction Hospital Projects

Sl. No.	Hospital Project Name	Initial Plan	upgraded plan
1	Ambedkar Nagar Hospital Project	200 beds	600 beds
2	Burari Hospital Project	200 beds	768 beds
3	Indira Gandhi Hospital Project at Sec-9 Dwarka	700 beds	1500 beds
Under Planning stage Hospital Projects			
4	Hospital Project at Sarita Vihar	100 beds	300 beds
5	Hospital Project at Vikas puri (Hastsal)	200 bed	500 bed

Sl. No.	Hospital Project Name	Initial Plan	upgraded plan
6	Hospital Project at Jwalapuri (Nangloi)	262 beds	600 beds
7	Hospital Project at Madipur	200 Beds	600 beds
8	Hospital Project at Siraspur	200 beds	1500 beds + Trauma centre & Medical College
9	Hospital Project at Chhatarpur Village, Mehrauli	225 bedded hospital	
10	Hospital Project at Deendar pur	100 Bed	
11	Hospital Project at Keshav Puram, Near Lawrence Road, Delhi	200 beds	

137- lJh jk[kh fcMyk % क्या mie[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलपुरी विधानसभा में मदर डेयरी के बूथों से दूध के सैम्पलों का निरीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो उन निरीक्षणों का विवरण क्या है; और

(ग) मंगोलपुरी विधान सभा में कितने मदर डेयरी के बूथ हैं?

mie[;e=h % (क) जी हां।

(ख) दिनांक 17.05.2016 को मदर डेयरी बूथ नं. 565, सेक्टर–1, अवन्तिका, रोहिणी, दिल्ली से टोन्ड दूध (खुला) का एक नमूना जांच के लिया गया था, जो जांच में सही पाया गया।

(ग) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 26 मदर डेयरी बूथों/दुकानों को लाइसेंस जारी हुआ है।

138- Jh fxjh'k lkuh % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अंतर्राज्जीय बस अड्डों पर कितने कुली लगे हुए है;

(ख) इन कुलियों के लाभ के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) परिवहन मंत्री द्वारा घोषित किए गए कल्याणकारी कदमों का विवरण क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन का विवरण क्या है?

ifjogu e=h % (क) उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार अन्तर्राज्जीय बस बड्डों पर निम्नलिखित कुली लाइसेंन्स जारी किये गये हैः–

1. कश्मीरी गेट – 168
2. आनन्द विहार – 72
3. सराय काले खां – 09

कुल कुलियों की संख्या – 249

(ख)

(अ) वर्ष 2017 में कुलियों के लाइसेंस (मुत्यु, वृद्ध व अशक्त होने की स्थिति में) स्थानान्तरण करने हेतु पॉलिसी OM. No. DTIDC/2011-

12/0009/88 दिनांक 18.05.2017 बनाई गई है तथा 10 कुलियों के लाइसेंस स्थानान्तरण का अनुमोदन जांच समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, संबंधित आवेदको को लाइसेंस स्थानान्तरण पत्र जारी किया जा रहा है।

(ब) तीनों बस अड्डों आनन्द विहार, सराय काले खां और कश्मीरी गेट पर कुल कुली विश्राम गृह का निर्माण किया गया है।

(स) 2016 में कश्मीरी गेट बस अड्डे पर कुली विश्राम गृह का उन्नयन कार्य किया गया।

(ड़) माननीय परिवहन मंत्री के निर्देश पर कश्मीरी गेट बस अड्डें पर बने कुली रूम के बिजली बिल को परिवहन विभाग/डीटीआईडीसी द्वारा वहन करने के निर्देश को लागू कर दिया गया है।

(ग)

(अ) माननीय परिवहन मंत्री के निर्देश पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बने कुलीरूम के बिजली बिल को परिवहन विभाग/डीटीआईडीसी द्वारा वहन करने के लिए निर्देशित किया गया।

(ब) कुलियों के कल्याण/पेंशन भुगतान का अवलोकन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(घ)

(अ) डीटीआईसीडी के आदेश दिनांक 23.02.2018 द्वारा कश्मीरी गेट पर स्थित कुली आराम कक्ष का बिजली का बिल डीटीआईडीसी द्वारा वहन किया जा रहा है।

(ब) वर्ष 2017 में कुलियों के लाइसेंस (मृत्यु, वृद्ध व अशक्त होने की स्थिति में) स्थानान्तरण करने हेतु पॉलिसी OM. No. DTIDC/2011-12/0009/88 दिनांक 18.05.2017 बनाई गई है तथा 10 कुलियों के लाइसेंस स्थानान्तरण का अनुमोदन जांच समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, संबंधित आवेदकों को लाइसेंस स्थानान्तरण पत्र जारी किया जा रहा है।

139- Jherh ifeyk Vkdl ¼ क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के डीजल से होने वाले प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण रखने हेतु क्या विभाग द्वारा कोई उपाए किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में इनका वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) अनुमति दी गई सीमा का उल्लंघन करते हुए पाई गई बसों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है; और

(घ) कितनी बसों के चालान किए गए, कितनी बसें जब्त की गई और कितनी बसों के परमिट रद्द किए गए, वर्ष वार विवरण दे?

ifjogu e=h ¼ (क) जी हां, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा अन्य राज्यों की बसों के वैध नियंत्रण प्रमाण पत्र की नियमित रूप से जांच की जाती हैं तथा वैध प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में बसों का चालान किया जाता है;

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ें राज्यों के भागों से दिल्ली में आने वाले बसों का पारस्परिक संयुक्त परिवहन समझौते के अनुसार सीएनजी ईधन पर ही चलना अनिवार्य हैं।

(ख) और (ग) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा अन्य राज्यों की बसों के वैध नियंत्रण प्रमाण पत्र की नियमित रूप से जांच की जाती हैं तथा वैध प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में बसों का चालान किया जाता हैं, इस कार्यवाही के अन्तर्गत किये गये चालानों विवरण अलग से नहीं रखा जाता है परन्तु प्रवर्तन शाखा द्वारा बसों के प्रदूषण चलान का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

(घ)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	दिल्ली	अन्य	कुल
2012–13	70	67	72	35	244
2013–14	54	36	71	55	216
2014–15	156	91	85	174	506
2015–16	67	55	39	28	189
2016–17	449	254	117	158	978
2017–फरवरी, 2018 तक	2532	1561	259	734	5086
कुल	3328	2064	643	1184	7219

अन्य राज्यों में पंजीकृत बसों पर की गयी कुल कार्यवाही (सभी उल्लंघनों पर) का वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	वाहन	चालान	जब्त
2013—14	1033	1258	39
2014—15	4191	4584	87
2015—16	1388	1575	121
2016—17	2084	3010	748
2017—18	7961	13962	5359

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा अन्य राज्यों की बसों का परमिट रद्द करने का प्रावधान नहीं है।

140- Jh fotUn xlrk % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली मैट्रो के चौथे चरण के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में सैद्धांतिक रूप से अनुमति दे दी थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस आधार पर तुरंत लौटा दिया गया था कि इस पर वित्तीय पहलूओं से स्वीकृति की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि तब से यह प्रस्ताव भारत सरकार के बार—बार याद दिलाने के बावजूद दिल्ली सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण इस परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(च) मैट्रो के चौथे चरण की परियोजना के संबंध में वास्तविक स्थिति का विवरण क्या है; और

(छ) दिल्ली सरकार इस पर कब तक स्वीकृति दे देगी?

ifjogu e=h ¼ (क) दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट द्वारा दिनांक 06.01.2017 को लिए गए निर्णय के तहत कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था।

(ख) तदनंतर, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और अब आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने 08.06.2017 को माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि वे दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण परियोजना की वित्तीय समीक्षा करने की सहमती एवं केन्द्रीय करों की 50:50 हिस्सेदारी के अनुसार प्रस्ताव भेजें।

(ग) माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार और जी एस टी कर–व्यवस्था के आधार पर की गई दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना की लागत तथावित फन्डिग पैटर्न के परिवर्तित ढांचे के अनुसार संशोधित कैबिनेट नोट तैयार किया। तदनुसार, 06.01.2017 के पहले के कैबिनेट फैसले को संशोधित करने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए संशोधित कैबिनेट नोट तैयार किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल है:

1. परियोजना लागत में संशोधन (रुपये 55,208 करोड़ से रुपये 52,625 करोड़)

2. भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जीएसटी कर में क्रमशः 1:2 के अनुपात में हिस्सेदारी।

इस संशोधित कैबिनेट नोट को विधि, वित्त और योजना विभाग के अवलोकन व विवेचना हेतु भेजा गया व इन विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर डीएमआरसी से जवाब मांगा गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार डीएमआरसी ने रेलनीति, 2017 के प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना 24.01.2018 को प्रस्तुत की।

(घ) इस तरह का कोई आंकलन नहीं किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के द्वारा दिल्ली गाजियाबाद–मेरठ कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 9.12.2016 को जमा कराया गया। इस प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट नोट तैयार किया गया तथा इसे संबंधित विभागों को अवलोकन के लिए भेजा गया।

इस संदर्भ में योजना और वित्त विभाग से प्राप्त हुए अवलोकनों को 16.06.2017 को टिप्पणी और स्पष्टीकरण के लिए NCRTC को भेजा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरिडोर में फंडिंग पैटर्नपरजी एसटी निहितार्थ के लिए व्यापक नोट भेजने के लिए पत्र लिखा। NCRTC को वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गए मुद्दों के स्पष्टीकरण हेतु मार्च, 2018 को

पत्र भेजा गया तथा जिसका जवाब प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को दोबारा वित विभाग भेजा गया है।

(च) मैट्रो चरण–4 परियोजना में डीएमआरसी द्वारा निम्नलिखित छह कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया हैः–

संख्या	कॉरिडोर	लम्बाई (किमी.)
1.	रिठाला–बवाना नरेला	21.73
2.	जनकपुरी पश्चिम से रामा कृष्णा आश्रम	28.92
3.	मुकुंदपुर से मौजपुर	12.54
4.	इंदरलोक से इंदरप्रस्थ	12.58
5.	ऐरोसिटी से तुगलकाबाद	20.20
6.	लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक	07.96
	कुल	103.93

डीएमआरसी ने दिनांक 15.01.2018 को अपने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि यदि चौथे चरण के सभी 6 कॉरिडोर का एक साथ अनुमोदन संभव न हो तो उनमें से तीनों कॉरिडोर को प्राथमिकता दी जाए जोकि निम्नलिखित हैंः–

कॉरिडोर

ऐरोसिटी से तुगलकाबाद

जनकपुरी पश्चिम से रामा कृष्णा आश्रम

मुकुंदपुर से मौजपुर

यह प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।

(छ) यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

vrkjkafdr iz'uksa ds fyf[kr mÙkj

323- Jh vts'k ;kno % क्या yksd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली विधानसभा क्षेत्र का शेरशाह सूरी मार्ग (66 फुटा रोड) कितने समय से टूटा हुआ हैं;

(ख) अब तक इस ऐतिहासिक सड़क को न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस सड़क को बनाने के लिए एस्टीमेट कब बनाया गया था;

(घ) इस सड़क को बनाने का एस्टीमेट कितनी राशि का है; और

(ङ) उक्त एस्टीमेट अब किस स्तर पर है और इस मार्ग का कब तक कर दिया जायेगा?

yksd fuekZ.k ea=h % (क) लगभग दो वर्षों से यह रोड़ टूटा हुआ है। इस रोड पर उपयोगिता सेवा एजेंसियां TPDDL, DJB, MTNL द्वारा सड़क को सेवाएं डालने के लिए लगातार काटा जाता रहा है तथा अभी तक सेवाएं डालने के कार्य का समापन प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है

जिसके कारण यह कार्य करने में देरी हो रही है। हालांकि इस कार्य की A/A & E/S सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के लिए प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है।

(ख) जैसा (क) में दर्शाया गया है।

(ग) संशोधित प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है।

(घ) लगभग 7.00 करोड़।

(ङ) यह प्राक्कलन परिमंडल स्तर पर लंबित है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् यह कार्य छः महीने में पूरा कर दिया जायेगा।

324- Jh v t;'k ;kno % क्या ykd fuek.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली विधानसभा क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी की किन–किन सड़कों पर एलईडी लाइट लगायी गई हैं;

(ख) बादली विधानसभा क्षेत्र में किन–किन स्थानों पर विभाग द्वारा एलईटी हाई मास्ट लाइट लगाई गई हैं;

(ग) विगत 3 वर्षों में बादली विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ने कितने डार्क स्पॉट चिन्हित किये हैं; और

(घ) विगत 3 वर्षों में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाकर कौन–कौन से डॉर्कस्पाट खत्म किये हैं?

ykd fuek.k e=h ¼ (क) अभी तक एल.ई.डी. लाइटें नहीं लगाई गई है। जहांगीर पुरी मुख्य सड़क पर आई.टी.आई. तक एल.ई.डी. लाइटें लगाने का कार्य प्रगति पर है, जो दिनांक 15.04.18 तक पूरा हो जायेगा।

(ख) मुकरबा चौक पर 4 हाई मास्ट में 24 एल.ई.डी. लाइटें लगाई गई है।

(ग) कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है।

(घ) कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है।

325- Jh txnh'k i/kku ¼ क्या ykd fuek.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शास्त्री पार्क चौक पर अन्डरपास बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

ykd fuek.k e=h ¼ (क) लोक निर्माण विभाग में शास्त्री पार्क चौक पर अन्डरपास बनाने की कोई योजना नहीं है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

326- Jh jkepUn ½ क्या ykd fuek.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधान सभा क्षेत्र के शाहाबाद डेयरी, प्रहलादपुर तथा महादेव चौक प्रहलादपुर की तीन सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, के डिवाइडर टूटे हुए हैं और गड्ढे बने हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि चार महीने से प्रहलादपुर गांव के अंदर पीडब्ल्यूडी रोड़ की लाईट कटी हुई है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बवाना चौक, पूठ खूर्द गांव तथा महादेव चौक प्रहलादपुर पर भंयकर जाम लगता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पूछ कलां गांव में भी अवैध कब्जे के कारण रोड पर भयंकर जाम लगता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस क्षेत्र की उक्त सभी समस्याओं के समाधान की क्या कार्य योजना है; और

(च) इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

ykd fuek.k e=h ½ (क) टूटे हुए डिवाइडर मरम्मत कर दिए गए है। लो.नि.वि. के अधीन सड़कों पर गड्ढ़े जब भी निरीक्षण किये जाते है वह नियमित रूप से कार्य स्थल अधिकारी द्वारा यथा सम्भव कम से कम समय में भर दिए जाते है।

शाहाबाद डेरी में डी.डी.ए. द्वारा पानी की सप्लाई लाइन डाली गयी थी इस सड़क पर मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा एक सप्ताह में पूरा कर दिया जायेगा।

(ख) जी हां, सभी लाइटें चालू हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एम.सी.डी. विभाग द्वारा लो.नि.वि. में प्राप्त की गई सड़क पर लो.नि.वि. की मौजूदा नाली से पार पथ (Carriage Way) की तरफ कोई अवैध कब्जा नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के सम्बन्ध में लागू नहीं है।

(च) उपरोक्त (घ) के सम्बन्ध में लागू नहीं है।

327- Jh fotsUnz xqIrk % क्या ykd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी मानसून के दौरान नालों की डीसिल्टिंग के लिए पीडब्ल्यूडी क्या तैयारियां करने जा रही है;

(ख) क्या सरकार इस कार्य के लिए टास्क फोर्स गठित करने जा रही है;

(ग) क्या सम्बन्धित विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान पाई गई कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने के उपाए किए हैं;

(घ) क्या सरकार जल भराव की समस्या से निपटने के लिए इस वर्ष नई मशीनें खरीदने जा रही है, इसका विस्तृत विवरण दें; और

(ङ) निचले हिस्सों में जल भराव की स्थिति से बचने के लिए नालों की सफाई का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

ykd fuek.k e=h ½ (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा नालों की डिसिल्टिंग हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं एवं कार्य 15.04.2018 से शुरू होने का लक्ष्य है।

(ख) लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई टास्क फोर्स गठित करने की योजना नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ) इस वर्ष मानसून से पहले ही 15.06.2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

328- Jh ,l- d- cXxk ½ क्या ykd fuek.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधानसभा में ताज इन्कलेव पुश्ते पर एक एफओबी बनना है;

(ख) यदि हां, तो यह एफओबी कब तक बनकर तैयार हो जायेगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र. के एसडीएम आफिस के सामने पीडब्ल्यूडी की जगह पर अतिक्रमण है;

(घ) यदि हां, तो इस जगह को खाली कराने की पीडब्ल्यूडी की क्या कार्य योजना है;

(ङ) यह जमीन कब तक खाली करा ली जायेगी;

(च) कृष्णा नगर विधानसभा में फ्लाई ओवर के नीचे ब्यूटीफिकेशन कब तक होगा;

(छ) कृष्णा नगर विधानसभा में शिवपुरी रोड के साथ वाले बड़े नाले की सफाई कब–कब हुई तथा इस कार्य पर कितनी रकम खर्च हुई है व ठेकेदार का विवरण क्या है?

ykd fuekZ.k ea=h % (क) लोक निर्माण विभाग में इस स्थान पर एफ.ओ.बी. बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) अतिक्रमण से सम्बन्धित मामला एम.सी.डी. से है परन्तु एस.टी.एफ. की मद्द से अतिक्रमण हटाने हेतु कोशिश की जा रही है।

(ङ) एस.टी.एफ. से सम्बन्धित होने की वजह से कोई नियत तिथि नहीं दी जा सकती।

(च) फ्लाई ओवर के ब्यूटीफिकेशन का प्राक्कलन प्रक्रिया में है।

(छ) जून एवं जुलाई–2017 में डिसिल्टिंग किया गया और कार्य अभी भी चल रहा है। सफाई का कार्य ठेकेदार मैसर्स साई टयूब वेल के पास है व रु. 2.00 लाख के लगभग भुगतान की गई राशि है।

329- Jh fo'k"k jfo % क्या ykd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोलबाद विधानसभा क्षेत्र में सड़को, सरकारी बिल्डिंग व सरकारी स्कूलों की देखभाल के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा कितने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिसटेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरों नियुक्ति हैं;

(ख) क्या इन तीनों श्रेणियों के अधिकारियों के पास कोई डबल चार्ज भी है;

(ग) करोल बाग विधानसभा के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी के पास कुल कितने किलोमीटर सड़के हैं;

(घ) विभाग के नार्म्स के हिसाब से कितनी किलोमीटर पर एक जेई, एई और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए;

(ङ) क्या नार्मस के हिसाब से करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति कम है;

(च) वर्तमान समय में करोलबाग विधानसभा में कार्य कर रहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कब सेवानिवृत्त हो रहे हैं;

(छ) क्या विभाग की करोलबाग जैसे बड़े क्षेत्र के लिए सिंगल चार्ज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नियुक्त करने की योजना है;

(ज) करोलबाग विधानसभा में विभाग द्वारा कितनी सड़कों का पुननिर्माण करने की योजना है; पूर्ण विवरण दें; और

(झ) इन सभी सड़कों का कार्य किस तिथि तक पूरा हो जाएगा, पूर्ण विवरण क्या है?

ykd fuek.k e=h % (क) कार्यपालक अभियंता–1

सहायक अभियंता–2

कनिष्ठ अभियंता–2

(ख) हां, कार्यपालक अभियंता के पास एक अन्य मंडल का कार्यभार भी है।

(ग) लगभग 33.83 कि.मी.।

(घ) विभाग में फिलहाल इस तरह का कोई नियम नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार कोई टिप्पणी नहीं है।

(च) 30.04.2018।

(छ) ऐसी कोई भी जानकारी इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं है।

(ज) रानी झांसी रोड।

देशबन्धु गुप्ता रोड।

पंचकुईंया रोड।

(झ) 30.06.2018।

330- Jh j?kfoUnz 'kkdhu % क्या ykd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की नांगलोई विधान सभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 पर नांगलोई बस डिपो के नजदीक स्थित पुल के चौड़ीकरण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कब कार्य प्रारम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ykd fuekZ.k ea=h % (क) नांगलोई बस डिपोक के नजदीक, नजफगढ़ नाले के ऊपर चौडा पुल बनाने हेतु अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हेतु Ministry of Road Transport and Highways (Govt. of India) विभाग को लोक निर्माण विभाग द्वारा 08.02.2018 को भेजा गया है।

(ख) इस कार्य के लिये Ministry of Road Transport and Highways से प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्राप्ति के तीन महीने बाद कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

331- lqJh Hkkouk xkM+ % क्या ykd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दक्षिणी दिल्ली में शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के सेकेंडरी/सीनियर सैंकेंडरी स्कूल बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जोन–23, 24, 25 और 29 ऑफ डीडी साउथ, नई दिल्ली में अतिरिक्त एसपीएस कक्षा कक्षों का निर्माण, कालकाजी और मदनपुर खादर में पक्के स्कूल भवन का निर्माण की स्वीकृति व्यय–स्वीकृति (AA & ES) कितने कमरों की थी;

(ग) इनमें से कितने भवन बन चुके हैं;

(घ) यदि भवन निर्धारित संख्या में ही बने हैं तो अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति व्यय स्वीकृति (AA & ES) की आवश्यकता क्यों पड़ी;

(ङ) यदि भवनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तो प्रशासनिक स्वीकृति व्यय–स्वीकृति (AA & ES) बढ़ने का क्या कारण है;

(च) यदि इन निर्माणाधीन विद्यालयों–भवनों में कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है तो क्या शिक्षा विभाग ने कोई इसके लिए अनुमति जारी की थी; और

(छ) यदि यह अनुमति जारी की गयी थी तो उसका पूरा विवरण क्या है?

ykd fuekZ.k ea=h % (क) जी हां।

(ख) 2258 नं. अतिरिक्त एस.पी.एस. कक्ष

01 नं. पक्का स्कूल कालकाजी

01 नं. पक्का स्कूल मदनपुर खादर, फेज–2

01 नं. पक्का स्कूल मदनपुर खादर, फेज–3

(ग) 2217 अतिरिक्त एस.पी.एस. कक्ष बन चुके हैं। पक्का स्कूल कालकाजी, मदनपुर खादर फेज–2 एवं मदनपुर खादर फेज–3 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 82 नं. अतिरिक्त एस.पी.एस. कक्ष का निर्माण कार्य संशोधित व्यय स्वीकृति लंबित होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(घ) कुल 2299 अतिरिक्त एस.पी.एस. कक्ष प्रस्तावित हैं परन्तु 82 नं. अतिरिक्त एस.पी.एस. कक्ष का निर्माण कार्य संशोधित व्यय स्वीकृति लंबित

होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका हैं। व्यय बढ़ने के मुख्य कारण निम्नवत हैं।

माननीय लो.नि.वि. मंत्री महोदय के कक्ष में दिनांक 21.06.2017 को हुई मीटिंग में लिए गए निर्णयों के अनुरूप Richer Specification जिनका प्रावधान मूल प्रारम्भिक प्राक्कलन में नहीं था जैसे Brick tile cladding in external finish, granite stone in staircase, Labs etc., full body vitrified tile in dado upto window sill in class room and corridors. False ceiling in Principal/Vice Principal/Staff/labs/MP Hall etc. SS railing in staircase and corridors, extended verandah, Rain water harvesting systems, U/G & O/H water storage tanks, septic tanks/STP, External development of play ground & stages etc. के प्रावधानों के साथ कार्यों का प्रतिपादन एवं कुछ साईट पर भराव की भूमि होने के कारण गहरी नींव व कचरा डिस्पोजल, अच्छी मिट्टी का भराव, Reimbursement of Service Tax to contractor एवं समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी इत्यादि।

(ङ) 'घ' के अनुसार।

(च) 'घ' में दिये गये विवरण के अनुसार जिन कार्यों की वजह से अनुमान से अधिक व्यय हुआ उनके आधार पर संशोधित प्रारम्भिक प्राक्कलन विशेष निदेशक (एल एण्ड ई) को मुख्य परियोजना प्रबन्धक शिक्षा अनुरक्षण द्वारा दिनांक 25.04.2017 को भेजा गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अनुमति अभी जारी होनी बांकी है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(छ) 'च' के अनुसार।

Chief Engineer
Education (Maintenance)
P.W.D. GNCTD, 1st Floor, M.S.O.
Building, New Delhi - 110002
Phone : 011-23317560 Fax : 23319851
E-mail : cepwddelhiedm@gmail.com

No. 23/50/16/CE(Edu)/PWD/General/ 328 Dated 23.6.16

CIRCULAR

Sub.: C/o Additional SPS Class Rooms in Delhi Govt. Schools

In the review meeting held on 21.06.2016 in the chamber of Hon'ble Minister, PWD where deliberation & discussions were held to decide material & specifications. The suggestions made by Architect, Field Engineers, Superintending Engineers & other Sr. Officers were discussed in detail and on 22.06.2016 meeting with Architect Babbar & Babbar Associates the followings were decided.

(1) As provided in the agreement, kota stone is to be used in the flooring of class rooms & verandah.

(2) The colour of puff panel of PPGL profile sheet roofing is to be green.

(3) The extended front corridor upto one floor as proposed by the Architect is to be provided, wherever space is available.

(4) The elevation proposed by the Architect is with brick tile cladding. Same may be adopted in all schools.

(5) Full body vitrified tiles will be used upto sill level in class rooms & verandah.

(6) The door proposed on tine back side on ground floor is not to be provided.

(7) The window in the class room to be provided without recess.

(8) The proposed Zig-Zag wall on-.the corridor side is to be in straight line.

The following clarifications/decision given by Architect M/s Babbar & Babbdr Associates.

1. Terrace

(a) Location of tanks on toilets - All water tanks will be provided on stair case except one drinking water tank to be provided on verandah flat roof

(b) Roofing

(i) Verandah flat, rest sloped roof with PPGL Sheet - Green Colour

(ii) Rain water pipe is to be provided behind columns in verandah

2. Staircase

(a) Flooring Granite - Colour - Autumn rose with double nosing

(b) Sides/dedo Colour-Autumn rose with granite single moulding

(c) Railing - Stainless Steel -90cm high With 50mm dia.

3. Verandah

(a) Kota Flooring - border with Udaipur Green as per drawing pattern

(b) Wall tile-vitrified full body 10 mm upto window sill - as per approved sample

(c) Extended Verandah columns cladding - Quartz tile stone.

4. Class Room

(a) Kota flooring, Border with Udaipur Green.

(b) Wall tile - Vitrified full body 10mm up to sill level - as per approved sample.

(c) Door - Flush door -35mm thick both, side laminated with teak wood beading

5. False ceiling

(a) False ceiling is to be provided in Lab, Principal Room, Staff Room.

यह पत्र मुख्य अभियंता महोदय की सहमति से जारी किया जाता है।

सेवा में,

1. अधीक्षण अभियंता
   शिक्षा, अनुरक्षण, लो.नि.वि., दिल्ली सरकार नई दिल्ली।

2. परियोजना प्रबंधन,
   शिक्षा, अनुरक्षण, लो.नि.वि. दिल्ली सरकार नई दिल्ली।

3. शिक्षा, अनुरक्षण अंचल के अन्तर्गत सभी कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि., दिल्ली सरकार।

Copy To:

1. The Secretary cum Engineer-in-Chief, PWD, GNCTD, New Delhi for information please.

2 The Jr, Chief Engineer (M), PWD, GNCTD, New Delhi for information please.

dk;ky; e[; ifj;ktuk ic/kd
f'k{kk vuj{k.k vpy
yk-fu-fo-] jk"Vh; jkt/kkuh {k= fnYyh
iFke ry] ,e-,l-vk- Hkou]
ubZ fnYyh

O/O THE CHIEF PROJECT MANAGER
EDUCATION ZONE
P.W.D., Govt. of N.C.T. of Delhi
First floor, M.S.O. Bhawan
New Delhi

No.: 23(50)/CPM(Edu)M/PWD/2016-17/1449 Dated 25.04.17

सेवा में,

The Special Director Education (L & E)
Directorate of Education,
Estate Bhawan, Lucknow Road, Delhi

विषयः— Regardin issue of revised A/A & E/S for C/o Additional Class-rooms in various schools of Govt. of Delhi under EO Zones 23,24,25 & 29 under priority-I.

सदर्भः—1. इस कार्यालय का पत्र संख्या 23(49)/17/मु.परि.प्र. (शिक्षा) अनु/लो.नि.वि./Estimate/1244 दिनांक 10.04.2017।

2. 23(49)/17मु.परि.प्र. (शिक्षा) अनु.लो.नि.वि./Estimate/1237 दिनांक 10.04.2017।

3.23(49)/17मु.परि.प्र. (शिक्षा) अनु.लो.नि.वि./Estimate/1350 दिनांक 19.04.2017।

उपरोक्त कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र समाप्त होने की स्थिति में है कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर दिये गये निर्णय एवं माननीय लो.नि.वि. मंत्री महोदय के कक्ष में हुई मीटिंग का संज्ञान लें।

माननीय लो.नि.वि. मंत्री महोदय के कक्ष में दिनांक 21.06.2016 को हुई मीटिंग में लिए गए निर्णयों (सर्कुलर की प्रतिलिपि संलग्न) के अनुरूप Richer specification जिनका प्रावधान मूल प्रारम्भिक प्राक्कलन में नहीं था जैसे Brick tile cladding in external finish, granite stone in staircase, Labs, toilet etc. full body vitrified tile in dado upto window sill in classroom and corridors. False ceiling in principal/vice principal/staff/labs/MP Hall etc. SS railing staircase and corridors, extended varandah, Rain water harvesting systedm, U/G & O/H water Storage tanks, Septic tanks/STP, external developments of play ground & stage etc. के प्रावधानों के साथ कार्यों का प्रतिपादन एवं कुछ sites पर भराव की भूमि के कारण गहरी नीवं व कचरा Disposal एवं अच्छी मिट्टी का भराव एवं Service tax एवं समय–समय पर minimum wages बढ़ोतरी के कारण कार्यों की लागत पूर्व में दिये गये A/A & E/S से 10% से अधिक बढ़ जाने के कारण सक्षम अधिकारी से संशोधित A/A & E/S के लिए RPE, शिक्षा निदेशालय को इस कार्यालय से उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा भेजा जा चुका है जैसा कि कार्यपालक इंजीनियर (शिक्षा) दक्षिण में अपने पत्रांक

संख्या 456 दिनांक 22.04.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा स्पष्ट किया है, संशोधित A/A & E/S के बगैर 10% से ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सक्षम अधिकारी से संशोधित A/A & E/S यथाशीघ्र लेने का कष्ट करें, ताकि कार्यों को यथाशीघ्र complete करवाया जा सके।

e[; ifj;kstuk izca/kd
शिक्षा (अनुरक्षण), लो.नि.वि.

प्रतिलिपीः

1. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजा), लो.नि.वि., (दिल्ली सरकार) बारहवां तल, बहुमंजिला भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक अभियंता (अनुवीक्षण) शिक्षा अनुरक्षण, (दिल्ली सरकार) चतुर्थ तल, लो.नि.वि. बहुमंजिला भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालक अभियंता, शिक्षा अनुरक्षण, मंडल, लो.नि.वि., नई दिल्ली–110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

332- Jh fotsUnz xqIrk % क्या ifjogu ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी ई–रिक्शाएं चल रही हैं;

(ख) सरकार ने ई–रिक्शाएं के कितने लाईसेंस जारी किए हैं;

(ग) इनमें से कितने अधिकृत हैं;

(घ) सरकार ने कब तक कितने ई–रिक्शाओं के लिए कुल कितनी राशि की सब्सिडी दी;

(ङ) क्या सरकार ने इनके खड़े होने के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है;

(च) सरकार ई–रिक्शा चालकों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(छ) सरकार का ट्रैफिक और लोकल पुलिस से ई–रिक्शा के नियंत्रण में किस प्रकार का समन्वय है?

ifjogu e=h ½ (क) विभाग के पास केवल पंजीकृत ई–रिक्शाओं के आंकड़े है इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिनांक 10.03.2018 तक 45,590 ई–रिक्शाओं पंजीकृत है।

(ग) 'ख; में लिखित सभी ई–रिक्शा अधिकृत है।

(घ) परिवहन विभाग ने अब तक 12,159 ई–रिक्शाओं को रु. 34,52,65,000/– की सब्सिडी दी है। DPCC द्वारा 14230 ई–रिक्शाओं को रुपये 34,88,000,00/– की सब्सिडी दी गयी है।

(ङ) इस समय परिवहन विभाग के पास इस तरह की कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

(च) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा समय–समय पर बिना पंजीकृत व पंजीकृत ई–रिक्शा चालकों को अनुशासित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करती रहती है।

जिसमें 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक 365 ई–रिक्शाओं के 417 चालान किए गए व 310 ई–रिक्शाओं को जब्त किया गया।

01 जनवरी, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक 757 गाड़ियों के 946 चालान किए गए व 655 ई–रिक्शाओं को जब्त किया गया।

(छ) ट्रैफिक समस्या तथा कन्जैशन इत्यादि के लिए स्पेशल टास्क फोर्स कमेटियों का गठन किया है, जिसमें परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगमों इत्यादि के प्रतिनिधि है। इन्ही कमेटियों में ई–रिक्शाओं को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तथा लोकल पुलिस से समन्वय किया जाता है।

333- Jh fotsUnz xqIrk % क्या ykd fuekZ.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों के डिजाईन सम्बन्धी त्रुटियों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनाई;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सड़कों को पैदल यात्रियों/साईकिल सवारों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सड़कों का रीडिईन और स्ट्रीट स्कैपिंग की योजना पर कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि विद्यमान साईकिल ट्रैकों पर साईकिलों के स्थान मोटरसाईकिलें दौड़ती हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि साईकिल ट्रैकों के दुरूपयोग के कारण साईकिल चालकों व पैदल यात्रियों की जान को खतरा बना रहता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या उपाए किये हैं?

ifjogu e=h % (क) और (ख) ट्रैफिक जाम की समस्या इस विभाग से संबंधित नहीं है तथापि वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली यातायात पुलिस को अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) सड़कों का रिडिजाईनिंग और स्ट्रीट स्कैपिंग का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तथापि वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों/सड़क स्वामित्व वाली एजेंसीयों को (शहरी विकास विभाग के माध्यम से) अनुरोध किया गया है।

(ङ) से (छ) इस तरह की कोई जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है तथापि जानकारी उपलब्ध करने हेतु दिल्ली यातायात पुलिस को अनुरोध किया गया है।

334- Jh fotsUnz xqIrk % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीटीसी के बेड़े में इस समय कुल कितनी बसें हैं;

(ख) इनमें से कितनी बसें रोज सड़कों पर उतारी जाती हैं; और

(ग) इनमें कितनी लो फ्लोर और कितनी स्टैन्डर्ड बसें हैं;

(घ) सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में कितनी नई स्टैन्डर्ड साईज यूबीएस–2 कम्पलाएंस लो फ्लोर बसें खरीदी हैं;

(ङ) सरकार का कलस्टर योजना के अन्तर्गत कितनी नई बसें जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार ने तीन वर्ष के दौरान बसों की खरीद और बस टर्मिनल के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की और उसमें से कितनी राशि व्यय हुई?

ifjogu e=h ¼ (क) दिनांक 14.03.2018 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 3944 बसें है।

दिनांक 14.03.2018 को 3944 बसों में से, 3635 बसें रोडवर्दी थी तथा 253 बसें विभिन्न डिपुओं में सुरक्षात्मक मरम्मत, दिन–प्रतिदिन होने वाली मरम्मत, पुलिस कस्टडी व अन्य कार्यों हेतु खड़ी थी। इसके अतिरिक्त 56 बसें स्क्रैप/कबाड़ा करने हेतु खड़ी थी।

(ग) कुल 3944 बसों में से 3781 लो फ्लोर बसें हैं तथा 163 स्टेन्डर्ड फ्लोर बसें है।

(घ) कोई भी नई स्टेन्डर्ड साईज यूबीएस–2 कम्पलाईन्स लो फ्लोर बस नहीं खरीदी है।

(ङ) 1000 सीएनजी और 1000 इलैक्ट्रीक बसों की कलस्टर योजना में जोड़ने को प्रस्ताव हैं।

(च) तीन वर्ष के दौरान बसों की खरीद और टर्मिनल के विकास के लिए आवंटित राशि निम्नलिखित हैः—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बस की खरीद के लिए डीटीसी की इक्विटी पूंजी		नई बस टर्मिनल के लिए भूमि की खरीद	
	संशोधित अनुमान (आर ई)	व्यय	संशोधित अनुमान (आर ई)	व्यय
2015—16	0.00	0.00	17500.00	17350.03
2016—17	0.00	0.00	6049.24	5463.50
2017—18	0.00	0.00	7000.00	वित्तीय वर्ष के अन्त तक सारी राशि का व्यय कर दिया जाएगा।

335- Jh euftnj flg fljlk % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ट्रैफिक टास्क फोर्स को लेकर गम्भीर नहीं है;

(ख) इसके सदस्य कौन–कौन हैं और उनकी बैठकें कब–कब हुई;

(ग) अब तक कितने कॉरिडोरों को जाम मुक्त बनाने का निर्णय हुआ है; और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे; और

(घ) टास्क फोर्स की क्या–क्या सिफारिशें हैं और उन पर क्या–क्या काम हो रहा है?

ifjogu e=h % (क) यह सत्य नहीं हैं।

(ख) सूची संलग्न है और बैठकों का विवरण दिल्ली पुलिस द्वारा एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) इसका विवरण भी दिल्ली पुलिस से एकत्रित किया जा रहा है।

(घ) इसका विवरण भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एकत्रित किया जा रहा है।

ANNEXURE

Constitution of Task Force Teams

	Sl. No.	Name	Designation	Department
Task Force	1	Shri Kimi Kerning - Convenor	DCP/Traffic - Eastern Range	Police
Eastern Range	2	Shri Rajesh Kumar	SE (North East)	PWD
	3	Shri Rajesh Taneja	SE (EMS)	EDMC
	4	Shri R.K. Jain	RM (East), IPD 8744073046	DTC
	5	Shri Manish Verma	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA
	6	Shri V. D. Sharma	Enforcement Officer	Transport Deptt.
	7	Shri R. P. Singh	Project Director (Gzb)	NHAI
Task Force-2	1	Shri Rajinder Singh Sagar - Convenor	DCP/Traffic-Western Range	Police
Western Range	2	Shri R. K. Solanki	SE (South West)	PWD
	3	Shri Anil Sharma	SE(E/M) - Najafgarh	SDMC
	4	Shri M.K. Sharma	RM(West) MPD 8744073035	DTC
	5	Shri Sudhir Kain	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA

	6	Shri Ashok Kumar Kaushik	Enforcement Inspector	Transport Deptt.
Task Force-3	1	Shri Vijay Singh - Convenor	DCP/Traffic-North District	Police
Northern Range	2	Shri S. K. Aggarwal	SE (North)	PWD
	3	Shri N.C. Sharma	SE (C) North	MCD (North)
	4	Shri U.S. Tripathi	RM(North), Subhash Place Depot 8744073061	DTC
	5	Shri Ajay Saroj	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA
	6	Shri Vedpal	Enforcement Inspector	Transport Deptt.
	7	Shri Rajiv Yadav	General Manager	NHAI
Task Force-4	1	Shri Dinesh Kumar Gupta -Convenor	DCP/Traffic-Southern Range	Police
Southern Range	2	Shri M. K. Meena	SE (South)	PWD
	3	Shri Vishnu Sharma	SE (E)	SDMC
	4	Shri D.S. Sharma	RM (South) WD 8744073027	DTC

	Sl. No.	Name	Designation	Department
	5	Shri Manish Verma	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA
	6	Shri Sultan Singh	Enforcement Inspector	Transport Deptt.
	7	Shri A. K. Sharma	Project Director (Gurgaon)	NHAI
Task Force-5	1	Shri Vijay Singh - Convenor	DCP/Traffic-Outer Range	Police
Outer Range	2	Shri Manmohan	SE (West)	PWD
	3	Shri Rajesh Khanna	SE (C)	MCD (North)
	4	Shri R.B.L. Shrivastva	DCGM (Tr)/Depot Inspection, IPD 8744073044	DTC
	5	Shri Sudhir Kain	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA
	6	Shri Vijender Kumar	Dy. Commissioner (Planning)	Transport Deptt.
Task Force-6	1	Shri A.K. Singh - Convenor	DCP/Traffic-Central Range	Police
Central Range	2	Shri Mukesh Kumar	SE (Cen. & ND.)	PWD

3	Shri R. G. Garg	SE (C)	MCD (North)
4	Shri Anant Kumar	Chief Engineer (Roads)	NDMC
5	Shri R.S. Minhas	DCGM (Pr), DTC HQ 8744Q73048	DTC
6	Shri Ajay Saroj	Dy. Director (UTTIPEC)	DDA
7	Shri D. R. Arora	Dy. Commissioner (VIU)	Transport Deptt.

The Task Force may co-opt representative of any other department also, if their services are required to redress traffic related problems in some roads.

In race of transfer of any member of Task Force, the successor officer will be..................

336- Jh euftnj flg fljlk % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016 में डीटीसी बसों, मैट्रो रेल और कलस्टर बसों में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कॉमन मोबिलिटी पेमेन्ट कार्ड के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक टिकेटिंग मशीनें लगाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की क्या प्रगति है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016 में प्रत्येक बस स्टॉप पर एक यात्री सूचना प्रणाली लगाने का वायदा किया था; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई0;

ifjogu e=h % (क) जी हां।

(ख) कॉमन मोबिलिटी पेमेंट कार्ड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की शुरूआत एक पायलअ प्रोजेक्ट के रूप में 200 डीटीसी तथा 50 कलस्टर बसों में 08 जनवरी, 2018 से की जा चुकी है।

(ग) सभी डीटीसी तथा कलस्टर बसों में कॉमन मोबलिटी कार्ड 15 अप्रैल, 2018 तक पूर्ण करने का परिवहन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ)1. परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 06.05.2011 को डिम्ट्स (DIMTS) और एक प्राईवेट एजेन्सी के साथ इस कार्य के लिए 5 वर्षों के लिए समझौता किया गया था, इस योजना में 500 बस क्यू शैल्टर्स पर पीआईएस बोर्ड लगाने का प्रावधान था। इनमें से 160 बस क्यू शैल्टर्स पर पीआईएस बोर्ड को लगाया गया है।

2. परिवहन विभाग और डिम्ट्स के अर्न्तगत जीपीएस/एवीएलएस सिस्टम के सुचारू रूप से न चलने के कारण पीआईएस बोर्ड पर आने वाली सूचना की गुणवत्ता प्रभावित हुई जिसके कारण अन्य बीक्यूएस पर नहीं लगाया जा सका।

3. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नए जीपीएस/एवीएलएस सिस्टम का टेन्डर जारी किया गया है। इसके उपरान्त नए पीआईएस बोर्ड लगाने पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

337- Jh fo'k"k jfo % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा विभाग को भेजे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है?

ifjogu e=h % (क) वर्ष 2015 से 2018 के बीच करोलबाग विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा में भेजे गए पत्रों पर की गयी कार्यवाही का रिकॉर्ड अलग से नहीं बनाया गया है, माननीय विधायकों द्वारा भेजे गए पत्रों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

डीटीआईडीसी द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार माननीय विधायक को उनके पत्र दिनांक 22.7.2017 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 503 दिनांक 17.08.2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि 1397 नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और करोलबाग विधान सभा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर नए बस क्यू शैलटर्स बनाए जाएंगे और बाकी स्थान जो कि 1397 की सूचि में सम्मलित नहीं है उन पर अगले चरण में विचार किया जाएगा।

परिचालन शाखा में उपलब्ध रिकार्ड/सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा केवल ई–रिक्शा सब्सिडी के सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुए थे जिनको कि उचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में तुरन्त ही भेज दिया गया था।

338- Jh fnus'k ekgfu;k % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सेवा में चलने वाले वाहनों की पिछले पांच वर्षों की वर्षवार सूची क्या है;

(ख) क्या इन वाहनों में जीपीएस इकाई अभिलेखों के अनुसार कितने ग्रामीण सेवा वाहनों में जीपीएस इकाई चालू हालत में लगी है;

(ग) यदि हां, तो परिवहन विभाग के अभिलेखों के अनुसार कितने ग्रामीण सेवा वाहनों में जीपीएस इकाई चालू हालत में लगी है;

(घ) विगत पांच वर्षों में जीपीएस इकाई के चालू हालत में न होने की समस्या के समाधान के लिए विभाग ने कितने सर्कुलर जारी किए तथा

आयुक्त/सचिव परिवहन अथवा विशेष आयुक्त परिवहन या एसटीए ने ग्रामीण सेवा परिचालकों के साथ कितनी बैठकें कीं;

(ङ) विगत पांच वर्षों में जीपीएस इकाई के चालू हालत में होने को सुनिश्चित करने के लिए कितने सतर्कता अभियान चलाए गए;

(च) इन अभियानों में कितने वाहन बिना जीपीएस के पाए गए, इनमें से कितनों का चालान किया गया और कितनों के परमिट रद्द किए गए; और

(छ) इन पांच वर्षों के दौरान जो भी अधिकारी सचिव/आयुक्त परिवहन व विशेष आयुक्त परिवहन के पद रहे हैं, उनके नाम क्या हैं?

ifjogu e=h ¼ (क) ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत 6153 वाहन 2010 में पंजीकृत हुए थे उसके उपरान्त ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत कोई वाहन पंजीकृत नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) 557 ग्रामीण सेवा वाहनों में जीपीएस इकाई चालू हालत है।

(घ) ग्रामीण सेवा वाहनों में जीपीएस के गैर–सक्रियण की समस्या को हल करने के लिए विभाग ने एक आदेश दिनांक 13.02.2018 को जारी किया था। परिवहन सचिव एवं आयुक्त अथवा विशेष आयुक्त परिवहन या एस.टी.ए. द्वारा ग्रामीण सेवा परिचालकों के साथ की गई बैठकों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया हैं।

(ङ) और (च) विगत पांच वर्षों में जीपीएस इकाई के चालू हालत में

होने को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सेवाओं के लिए अलग से विशेष सतर्कता अभियान नहीं चलाया गया।

किसी ग्रामीण सेवा वाहन का परमिट रद्द नहीं किया गया है।

(छ) इस अवधि में परिवहन विभाग में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रास्पोर्ट के पद पर तैनात रहेः—

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक

स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री गामली पादू	26.12.2012	19.09.2013
श्री सतीश माथूर	13.09.2013	31.12.2014
श्री एस. के. सक्सैना	02.01.2015	15.01.2016
श्री के. के. दहिया	26.11.2015	अभी तक
श्री एस.बी. शशांक	30.11.2015	24.08.2016
श्री अंकुर गर्ग	29.12.2015	12.03.2016
श्री इन्दु शेखर मिश्रा	07.01.2016	03.08.2016
श्री संजय कुमार	15.03.2016	2016
श्री अनिल बांका	09.08.2016	अभी तक

339- Jh idt i"dj ½ क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के पास दिल्ली या किसी अन्य राज्य में कौन–कौन सी परिसंपत्तियां हैं और इनका क्या–क्या उपयोग हो रहा है, पूरी सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) परिवहन विभाग की ऐसी कौन–कौन सी परिसंपत्तियां हैं जो किसी अन्य विभाग या व्यक्ति द्वारा उपयोग की जा रही हैं;

(ग) ऐसी सभी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुबंध की प्रति एवं उससे प्राप्त हो रहे राजस्व का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं;

(घ) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में बंदा बहादुर सिंह मार्ग पर परिवहन विभाग के बस डिपो, क्लस्टर बस डिपो एवं हरियाणा रोडवेज का बस डिपो एवं हरियाणा रोडवेज का बस डिपो स्थित है, इन तीनों संपत्तियों का मालिकाना हक किसका है, विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि ये तीनों डिपो घनी आबादी के बीच में हैं, दिन भर खाली बसों के आने–जाने के कारण इस रोड पर लगभग स्थाई जाम और अनेक दुर्घटनाएं होती रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन दुर्घटनाओं और स्थाई जाम से निजात दिलाने के लिए सभी बस डिपो को कहीं ओर स्थानांतरित करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इन डिपोज को अन्यत्र स्थानांतरित कब तक किया जा सकता है?

ifjogu e=h ¼ (क) दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के पास दिल्ली या किसी अन्य राज्य में निम्नलिखित परिसंपत्तियां हैः–

क्र.सं.	जमीन का स्थान	उद्देश्य
1.	5/9, अंडर हिल रोड़	मुख्यालय, एम.एल.ओ. (मु.), एस.टी.ए.
2.	खैबर पास, मॉल रोड	क्षेत्रीय कार्यालय एन. जेड–1
3.	डीडीए मार्किट शेख सराय	क्षेत्रीय कार्यालय एसजेड
4.	जनक पुरी, मध्य जिला	क्षेत्रीय कार्यालय डब्ल्यू जेड–1

क्र.सं.	जमीन का स्थान	उद्देश्य
5.	लोनी रोड, शाहदरा	क्षेत्रीय कार्यालय एन.ई.जे.
6.	सराय काले खां	क्षेत्रीय कार्यालय सी.जेड
7.	निरीक्षण इकाई, बुराड़ी	वीआईयू, एआरयू, प्रवर्तन (परिबंधन पिट)
8.	झुल झुली	वीआईयू
9.	छत्तरपुर	रिक्त
10.	खड़खड़ी नाहर	बस डिपो के लिए भूमि का आबंटन हुआ है।
11.	रेवला खानपुर	
12.	द्वारका सैक्टर–22	
13.	बवाना सैक्टर–1	
14.	बवाना सैक्टर–5	
15.	रोहिणी फेस–5 (रानी खेड़ा)	
16.	नरेला ए1, ए4	
17.	रोहिणी सैक्टर–37	
18.	ईस्ट विनोद नगर	

क्र.सं.	जमीन का स्थान	उद्देश्य
19.	मुडेंला कला	
20.	वंसत कुंज	
21.	गदईपुर	
22.	मलिकपुर	
23.	दौराला	
24.	बिंदापुर	बस टर्मिनल
25.	द्वारका सैक्टर–12	बस टर्मिनल के लिए भूमि का आबंटन हुआ है।
26.	द्वारका सैक्टर–10	
27.	द्वारका सैक्टर–4	
28.	नरेला सैक्टर–ए 7 पॉकेट 11	
29.	नरेला सैक्टर–ए 9 पॉकेट 4 फेस 1	
30.	विकासपुरी एच 3 ब्लॉक	
31.	रोहिणी सैक्टर 28	

(ख) परिवहन विभाग की निम्नलिखित परिसंपत्तियों अन्य विभाग या व्यक्ति द्वारा उपयोग की जा रही है:—

क्र.सं.	जमीन का स्थान	उद्देश्य
1.	सराय काले खॉ	आईडीटीआर, मारूती
2.	लोनी रोड़ शाहदरा	आईडीटीआर, मारूती
3.	बुराड़ी	डीटीआई, अशोका लीलैंड

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है। तदोउपरान्त सम्बन्धित विधायक को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

(घ) बन्दाबहादुर मार्ग पर परिवहन विभाग के कलस्टर बस डिपो का मालिकाना हक दिल्ली परिवहन निगम के पास है। हरियाणा रोड़वेज के बस डिपो का मालिकाना हक परिवहन विभाग के पास नहीं है।

(ङ) यह सत्य है कि तीन डिपो घनी आबादी के बीच में है, परन्तु बसो के आने जाने कारण इस रोड़ पर स्थायी जाम नहीं लगता है। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में परिवहन विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

340- Jh egn xk;y % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितनी बसें ली गई हैं;

(ख) यह पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था;

(ग) इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीसीटीवी लगी हुई बसों में महिला–सुरक्षा से संबंधित कितने मामले रिकॉर्ड किए गए हैं;

(घ) दर्ज किए गए मामलों में से कितने गंभीर प्रकृति के थे;

(ङ) रिकॉर्ड किए गए सभी मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण क्या है, वर्षवार ब्यौरा दें;

(च) जिस वर्ष यह पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था, तब से सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त परिवहन तथा मुख्य प्रबंध निदेशक डीटीसी ने सीसीटीवी कमांड सेंटर के कितने दौरे किए, वर्षवार जानकारी दें;

(छ) प्रत्येक दौरे के समय उपर्युक्त में से जो भी अधिकारी थे, उनका नाम क्या है; और

(ज) प्रत्येक दौरे से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं?

ifjogu e=h % (क) डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने के पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 200 बसें ली गई है (जिसमें 100 बसे राजघाट डिपो–1 व 100 बसें सरोजनी नगर डिपो की हैं)

(ख) यह पायलट प्रोजेक्ट जनवरी, 2015 से कार्यरत है।

(ग) इस पाइलट प्रोजेक्ट के अर्न्तगत महिला सुरक्षा से सम्बन्धित 01 मामला रिकार्ड किया गया है।

(घ) यह 01 मामला गम्भीर प्रकृति का था।

(ङ) वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(च) डीटीसी के 02 डिपो (राजघाट डिपो एवं सरोजनी नगर डिपो) की बसों में सीसीटीवी लगे हुए हैं एवं उपरोक्त डिपो में सर्वर भी लगे हैं। अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक ने दिनांक 06.07.2017 राजघाट डिपो एवं 18.10.2017 को सरोजनी नगर डिपो का दौरा किया था एवं दौरे के दौरान सर्वर रूम का अवलोकन किया था।

(छ) श्री संदीप कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, डीटीसी।

(ज) सर्वर रूम के अवलोकन के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी रिपोर्ट की कापी परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

ifjf'k"V d

lj‚tuh uxj fMik e/;&

वर्ष	मामलों की संख्या	कार्यवाही
2015	05	सभी मामलों में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।
2016	04	सभी मामलों में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।
2017	05	सभी मामलों में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।

jkt?kkV fMik&1

वर्ष	मामलों की संख्या	कार्यवाही
2015	14	01 मामलें में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।
2016	15	05 मामलें में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।
2017	09	06 मामलें में पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाने पर उपलब्ध करा दी गई।
2018	01	परिवार द्वारा फुटेज मांगी गई जिसे उपलब्ध करा दिया गया।

ifjf'k"V&[k

DELHI TRANSPORT CORPORATION
I.P. Estate : New Delhi

Report of Field Visit for the week 16th October, 2017-20th October, 2017

Date of visit	-	18.10.2017
Place of visit	-	Sarojini Nagar Depot
Time	-	04.00 PM onwards

Observations:-

(1) Shri Prashant Kumar, Depot Manager was present in the Depot.

(2) The Depot has a fleet of 100 Low Floor buses out of which 65 buses are AC buses. The morning outshedding was short by 3 buses on 18.10.2017 against the scheduled outshedding of 95 buses which was due to repair and maintenance work of the buses. The evening outshedding upto 5 PM was 74 buses and was short by 12 buses due to shortage of operational crew. The Depot is having shortage of drivers as well as conductors. The officer concerned attributed the non-reporting of staff to festive season of Diwali. The Depot Manager was asked to take up the matter with the concerned department for providing required number of drivers and conductors.

(3) The ETP is not functioning. The officer concerned was asked to take up the matter with concerned department for repair of the same.

(4) The Depot has two Pass Sections i.e. at Central Secretariat and at the Depot itself. The Pass Sections function from 7 AM to 7 PM. At Sarojini Nagar Depot Pass Section, 162 Bus Passes were issued upto 5.25 PM with total revenue collection of Rs. 1,53,880/- on 18.10.2017.

(5) All the 100 buses of the Depot have been fitted with CCTV by M/s Matrix with 3 cameras in each bus. The CCTV Monitoring Section functions in two shifts i.e. from 9 AM to 5.30 PM and 9 PM to 5 AM After every 5 days, the data from the hard disk are copied to the server and it remains in the server for 15 days after which it automatically gets erased. The data from the server are" copied to CD in the event of request from Depot Authority or Delhi Police to investigate public complaints, accidents, pic-pocketing etc. if any.

(6) The Depot has a total number of 172 Electronic Ticketing Machines (ETMs) out of which 112 are in working qrder and rest are lying with service centre for repair. The officer concerned was asked to take up the matter with the IT Department immediately.

(7) The Depot canteen, restroom and toilets were found clean. The Depot has water supply provision by NDMC. There are number of potholes in the Depot yard and also near the Depot gate which needs to be repaired.

(8) It was observed that the posters containing preventive measures for Dengue, Cbikungunya, Malaria & other vector borne diseases were affixed at different places.

(SANDEEP KUMAR)

Chairman-cum-Managing Director

Copy to:

1. CGM (Operation)

2. CGM (CED).

3. CGM (PLD)

DELHI TRANSPORT CORPORATION
CMD SECERETARIAT

Report of field visit for the week 3rd July - 7th July, 2017 I

Date of visit	-	06.07.2017
Place of visit	-	Raj Ghat Depot-I
Time	-	11.30 AM

Observations:-

(1) It was observed that a plot of around one acre land adjacent to the depot is lying unused. The possibility of developing the same needs to be examined.

(2) It came to notice that the incidents of fire are occurring repeatedly in the barren area located adjacent to the right side of the depot and the same is a risk to our buses and other property of the depot. The Depot Manager shall, therefore, immediately write to the concerned Department to take necessary action to prevent the incidents of fire in the future, especially in the summer season.

(3) The presentability of the buses was also checked. It was observed that the washing and cleaning of the buses was not up to satisfactory level and needs to be improved. The concerned officers of DTC and Ashok Leyland who were present at the time of visit were directed to take necessary action in this regard.

(4) The depot yard had several potholes, which causes damage to the buses and also affects the tyre life. These potholes needs to be repaired immediately.

(5) The outshedding of the buses was checked and the same was found satisfactory as all scheduled buses were outshedded mostly in time.

(SANDEEP KUMAR)
Chairman-cum-Managing Director

Copy to :

1. CGM(O) } For necessary action
2. CGM (Civil) }

341- Jh _rjkt xkfon % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हे कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) से संबंधित 7667 दर्ज की गई जिसमें से 71 शिकायतें अभी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 21 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 2824 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये;

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई इसका विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए इसका विवरण प्रदान करें; और

(ञ) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जायेगा?

ifjogu e=h ¼ (क) जन शिकायत निगरानी प्रणाली से निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक 7676 शिकायतें पीजीएमएस के द्वारा प्राप्त हुई, जिनमें से 7634 शिकायतें पीजीएमएस के द्वारा प्राप्त हुई, जिनमें से 7634 शिकायतों का निवारण किया गया तथा केवल 42 शिकायतें दिल्ली परिवहन निगम के विभिन्न विभागों में लम्बित रहीं।

(ख) जन शिकायत निगरानी प्रणाली से निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक 20 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लम्बित थी।

(ग) प्रशासनिक कार्यवाही में कुछ समय लग जाता है परन्तु मुख्य उद्देश्य निगम का शिकायतों का सही निपटान करना होता है। जो वर्तमान में अनुमोदित नीति/नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(घ) जन शिकायत निगरानी प्रणाली से निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक दिल्ली परिवहन निगम की ऐसी 2830 शिकायतें है।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा शिकायतों का अध्ययन करने के उपरांत पाया गया कि ज्यादातर शिकायतें बस सर्विस से सम्बंधित हैं तथा कुछ शिकायतें स्टाफ का स्थानान्तरण व उनको पुनः नौकरी पर रखने के संदर्भ में हैं। बस सर्विस से सम्बंधित शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया गया हैं कि विभाग में नई बस आने के उपरान्त सहानुभूति से विचार किया जायेगा जबकि स्टाफ के स्थानान्तरण व उनके

पुनः सर्विस पर लेने के संदर्भ में विभाग अपनी पालिसी के अनुसार उचित कार्यवाही कर रहा है।

(च) जी हां।

(छ) समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालय से शिकायतों के निवारण के लिए जो निर्देश आते है उन निर्देशों को निगम के सभी विभागों में वितरित किया जाता है तथा फोन द्वारा भी विभिन्न विभागों के मुखियाओं से संपर्क किया जाता है जिसका परिणाम निगम के द्वारा शिकायतों के निपटान से प्रदर्शित होता है जो कि रिपोर्ट के अनुसार 99 प्रतिशत दर्शाया गया है।

(ज) लम्बित 42 शिकायतों में से 20 शिकायतें उप मुख्य महाप्रबन्धम (कार्मिक), 5 आर.एम. (साउथ), 3 उपमुख्य महाप्रबन्धक (या.), 3 उप मुख्य महाप्रबन्धक (परि.), 1 आर.एम. (ईस्ट), 1 आर.एस. (वैस्ट), 1 आर.एस. (नार्थ), 6 शिकायतें सर्तकता विभाग, 02 सीजीएम सिविल के पास लम्बित हैं।

(झ) जन शिकायत निगरानी प्रणाली से निकाली गयी रिपोर्ट के अनुसार लम्बित 42 शिकायतों में से आज तक विभिन्न विभागों द्वारा 7 शिकायतों का पूर्ण निपटान कर दिया गया है तथा 26 शिकायतों में विभाग ने शिकायतकर्ताओं को अंतरिम जवाब भेजा गया है जिनमें अभी प्रशासनिक कार्यवाही में कुछ समय लग सकता है। जबकि 9 शिकायतों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही इनका निपटान नियमानुसार कर दिया जायेगा।

(ञ) बकाया पीजीएमएस शिकायतों को निपटान भी यथा सम्भव नियमानुसार जल्दी ही कर दिया जायेगा।

342- Jh ,l- d- cXxk % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 15 साल पुराने कितने कमर्शियल वाहन हैं;

(ख) ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने की क्या प्रक्रिया हैं;

(ग) ड्राईविंग लाईसेंस कितने समय में बनता है;

(घ) ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में परिवहन विभाग ने कितनी गाड़ियों के चालान काटे है तथा इससे वर्षवार कितना रेवन्यू आया है; और

(च) वर्ष 2017 में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आनन्द विहार बस अड्डे पर किए गए कार्यों का विवरण, इनके ठेकेदार का नाम तथा प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि का ब्यौरा क्या है?

ifjogu e=h % (क) दिल्ली में 1,88,126 (एक लाख अट्ठासी हजार एक सौ छब्बीस) 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन हैं।

(ख) ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने के लिए पहले लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस का आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराया जाता है। उसके पश्चात् लर्निग ड्राईविंग लाईसेंस कम्प्युटर टेस्ट पास करने पर तुरन्त मिल जाता है। फिर कम से कम 30 दिन बाद तथा अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थाई लाईसेंस के लिए ऑन लाईन आवेदन उचित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। इसके पश्चात् अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में

अपने वाहन के साथ ड्राईविंग टेस्ट के लिए उपस्थित हो। उसमें पास होने के बाद एक सप्ताह के भीतर लाईसेंस आवेदक के घर डाक द्वारा पहुंच जाता है।

(ग) एक ही दिवस में बन जाता है।

(घ) लर्निंग लाईसेंस–

एक श्रेणी के लिए 500 रुपये।

दो श्रेणी के लिए 950 रुपये।

तीन श्रेणी के लिए 1400 रुपये एवं

स्थाई लाईसेंस के लिए– 400 रुपये।

(ङ) वर्ष 2016 में 208061 गाड़ियों के 230274 चालान बनाये गए व 16041 गाड़ियां जब्त की गयी।

वर्ष 2017 में 167646 गाड़ियों के 198204 चालान बनाये गए एवं 24765 गाड़िया जब्त की गयी।

लेखा शाखा द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वर्षवार में निम्नलिखित रेवन्यू प्राप्त हुईः–

वर्ष	राशि (रुपये)
2016	4,80,03,775/–
2017	3,49,22,060/–

(छ) वर्ष 2017 में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आनन्द विहार बस अड्डे पर किए गए कार्यों का विवरण निम्न हैः—

	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कुल लागत रुपये
1	2	3	4
1.	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा आनन्द विहार में कच्चे हिस्से पर पानी के छिड़काव हेतू पानी के टैंकर की आपूर्ति।	संजीव एंटरप्राईसेस	186240/—
2.	अनुपयुक्त जल कुलर के प्रतिस्थापन सहित जल कूलरों की मरम्मत और सर्विसिंग।	सोनी इंजीनियरिंग वकर्स	237346/—
3.	हवा परिसंचारी, डेजर्ट कूलर, सीलिंग पंखों और निकास पंखों की रिवाइंडिंग मरम्मत।	के एण्ड एस इंजीनियरिंग वकर्स	142151/—
4.	उच्च मस्तूल खंभों की फिटिंग और बाहरी रोशनी की मरम्मत।	के एंड एस इंजीनियरिंग वकर्स	466464/—

1	2	3	4
5.	125 केवीए डीजल जेनेरेटर सेट नं. 2 की मरम्मत और ओवरहॉलिंग।	के एण्ड एस इंजीनियरिंग वकर्स	146266/–
6.	उप–स्टेशन उपकरणों की वार्षिक सर्विसिंग।	के एण्ड एस इंजीनियरिंग वकर्स	220123/–
7.	अन्तर्राज्जीय बस अड्डा आनन्द विहार में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए रोड़, पार्किंग क्षेत्र और फुटपाथ का पुर्नविकास और सवारी गुणवत्ता की सुधार, प्लेटफॉर्म का सुधार, मूत्रालयों और पेशाबघरों में वृद्धि एवं संकेत पटल को उपलब्ध कराना।	कल्याण चंद्र गोयल और कंपनी	38819847/–

343- l|Jh Hkkouk xkM+ ¼ क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की सड़कों पर हर रोज बड़ी तादाद में दुर्घटनाएं घटती रहती हैं;

(ख) क्या दिल्ली की सड़क पर सुरक्षा के लिए कोई सड़क सुरक्षा नीति तय है;

(ग) यदि हां, तो वो क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर कितनी दुर्घटनाएं घटी, इसमें कितने लोग घायल हुए और कितनी मृत्यु हुई, पूर्ण ब्यौरा क्या है?

ifjogu e=h % (क) जी हां, (दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गए रिकार्ड्/सूचना के आलोक में)।

(ख) से (घ) दिल्ली सड़क सुरक्षा का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा सम्बन्धित विभागों से इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) वांछित विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	घटनाओं की संख्या			व्यक्ति		
	गैर चोट	साधारण	घातक	कुल	घायल	मरे गये
2016 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	129	5698	1548	7375	7154	1591
2017 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	91	5017	1565	6673	6604	1584

344- Jh txnhi flg % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने अधिकृत पीयूसीसी (पॉल्यूश्न अंडर कंट्रोल सेंटर) काम कर रहे हैं;

(ख) ये प्रदूषण केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर करें, इसकी निगरानी के लिए सरकार ने क्या जांच–उपाय किए हैं;

(ग) विगत पंद्रह वर्षों में कितने केन्द्र परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकोल का उल्लंघन करते पाए गए;

(घ) इनमें से प्रत्येक क विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) निर्धारित प्रोटोकोल का पालन न करने के लिए जिन केन्द्रों को बंद किया गया, उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) दिल्ली में इन प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों पर नियमित निगरानी रखने के लिए कितने निरीक्षकों की आवश्यकता है, और वर्तमान में कितने निरीक्षक इस कार्य में लगे हैं;

(छ) इन केन्द्रों के कार्य पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षकों की कम संख्या को देखते हुए विगत दस वर्षों में परिवहन विभाग ने निरीक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ज) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव में स्टॉफ के कितने पदों पर रिक्तियों को भरा जाना था;

(झ) इनमें से कितने रिक्तियां वास्तव में भरी गईं, वर्षवार ब्यौरा बताएं;

(ञ) इन वर्षों में कौन–कौन से अधिकारी सचिव/आयुक्त परिवहन के पद पर रहे, वर्षवार नाम बताएं; और

(ट) परिवहन विभाग में निरीक्षकों की रिक्तियों को भरने में तेजी लाने के लिए इन अधिकारियों ने कितने पत्र लिखे या डीएसएसबी के साथ कितनी बैठकें कीं?

ifjogu e=h ¼ (क) दिल्ली में 19.03.2017 को 972 प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत है।

(ख) इन प्रदूषण जांच केन्द्रों को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु और उनकी बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के द्वारा इन प्रदूषण जांच केन्द्रों को जोड़ा गया है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप को घटाया जा सके।

(ग) सम्बन्धित निर्धारित नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए परिवहन विभाग द्वारा पाए गए प्रदूषण जांच केन्द्रों का सूचीबद्ध ब्यौरा वर्ष 2017 से ही उपलब्ध है, जो कि निम्नलिखित है:–

– वर्ष 2017 में 103 प्रदूषण जांच केन्द्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

– वर्ष 2018 (28.02.2018 तक) 29 जांच केन्द्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

(घ) कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है।

लिखित चेतावनी	निलंबन	मान्यता रद्द की गई
60	48	24

(ङ) मान्यता रद्द करने का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है।

वर्ष	मान्यता रद्द की गई
2017	21
2018 (28 फरवरी तक)	3

(च) वर्तमान में 18 प्रदूषण स्तर जांच निरीक्षक, परिवहन विभाग में कार्यरत है, और इनमें से एक निरीक्षक इस काम के लिए तैनात है इसके अतिरिक्त 09 प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अन्य कार्यों के साथ इस कार्य में भी लगाए गये है।

(छ) परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव दिनांक 19.01.2018 को भेजा है।

(ज) 17 पदों को भरा जाना है।

(झ) कोई नहीं।

(ञ) इस अवधि में परिवहन विभाग में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रास्पोर्ट के पद पर तैनात रहेः—

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री आर. के. वर्मा	18.02.2008	01.07.2011
श्री एम. एम. कुट्टी	02.07.2011	11.08.2011

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री चंद्र मोहन	12.08.2011	31.10.2012
श्री राजेन्द्र कुमार	01.11.2012	31.01.2013
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक

(ट) एक प्रस्ताव दिनांक 19.01.2018 को भेजा है।

345- Jh iou 'kekZ % क्या ifjogu ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने जिलों में 'डिस्ट्रक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों' का गठन किया गया है और इनका गठन कब किया गया था;

(ख) इन कमेटियों की बैठकें आमतौर पर कितने अंतराल पर होती हैं;

(ग) जिस वर्ष से इन कमेटियों का गठन हुआ है तब से अब तक इनमें से प्रत्येक कमेटी की वर्षवार और जिलेवार हुई बैठकों का विवरण क्या है;

(घ) इन वर्षों के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अधिकारियों का नाम बनाएं;

(ङ) इनमें से प्रत्येक बैठक के मिनट्स उपलब्ध कराए जाएं और प्रत्येक बैठक में हुए निर्णय के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण बताएं; और

(च) अब तक जो निर्णय पूरी तरह लागू किए जा चुके हैं सारांश रूप में उनका संपूर्ण विवरण क्या है?

ifjogu e=h ¼ (क) अधिसूचना सं. 17(102)/Plg./Tpt./2007/525 दिनांक 17.06.2014 के द्वारा दिल्ली के सभी ग्यारह राजस्व जिलों में ''डिस्ट्रिक्ट रोड सेटी कमेटियों'' का गठन किया गया।

(ख) अधिसूचना सं. 17(102)Plg-/Tpt-/2007/525 दिनांक 17.06.2014 के अनुसार ''डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों'' को कम से कम तीन महीने में एक बार या जरूरत के मुताबिक बैठकें करनी है, परन्तु राजस्व विभाग के जिलों में बैठकें अलग–अलग अन्तराल पर की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, अतः वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है, तथापि इस शाखा में उपलब्ध रिकार्ड्स/सूचना के अनुसार, विवरण संलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है।

(ङ) प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है।

(च) प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः वांछित जानकारी उपलब्ध करने हेतु राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है।

lyXud ^d*

As per record available/maintained in Lead Agency for Road Safety, Transport Department, the details of meeting of District Road Safety Committees is as under:

Name of District	Date of meeting	Total No. of meetings
North	19.02.2018	
South	23.10.2017	01
East	-	-
West	-	-
Central	28.12.2017	01
New Delhi	24.08.2017, 17.01.2018	02
North West	18.08.2017, 08.11.2017, 05.02.2018	03
North East	-	-

Name of District	Date of meeting	Total No. of meetings
South East	-	-
South West	-	-
Shahadara	-	-

346- Jh vke iidk'k 'kek ¼ क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बस सेवा प्रारम्भ की थी;

(ख) इसके क्या परिणाम रहे, विस्तार में बताएं;

(ग) क्या सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इनके पंजीकरण पर रोड टैक्स के भुगतान में छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

ifjogu e=h ¼ (क) दिल्ली परिवहन निगम को एक इलैक्ट्रिक ऐसी लो फ्लोर बस चलाने के लिए मार्च 2016 में 04 माह के लिए अस्थायी परमिट एसटीए द्वारा जारी किया गया था। यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा एक इलैक्ट्रिक बस संख्या GJ1DZ139 का परिचालन परीक्षण के आधार पर माह मार्च–2016 से जून–2016 तक मिलेनियम डिपों से किया गया था।

(ख) विवरण संलग्न है:–

पैरामीटर	23 मार्च, 2016 से	अप्रैल–2016	मई–2016	20 जून, 2016 तक	कुल
टोटल कि.मी. कवर	1192	4279	3835	3616	12922
टोटल यूनिट कन्जयूम	1601	6290	6824	6020	20735
एवरेज रेट पर यूनिट एज पर बीएसईएस (रु.)	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66
टोटल एक्सपंडीचर (रुपये)	17067	67051	72744	64173	221035
एक्सपंडीचर पर कि.मी. (रु.)	14.32	15.67	18.97	17.75	17.10
अर्निंग इन रूपीज	46810	109370	79990	84485	320655
ईपीके		44.53	31.19	37.38	

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्ताव माननीय परिवहन मंत्री को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

347- Jh i|dt i|"dj % क्या xg e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनसंख्या के अनुपात में कुल कितने पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है;

(ख) दिल्ली में कुल कितने पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, अलग–अलग थाने एवं जिलावार विवरण उपलब्ध करें;

(ग) पदानुसार इनके कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आवर्स (कार्य अवधि) की वास्तविक स्थिति क्या है और इन्हें कितनी अवधि की ड्यूटी करनी होती है;

(ङ) थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों को साप्ताहित तथा पूरे वर्ष में मिलने वाले अन्य अवकाशों की वस्तु स्थिति क्या है और पुलिस कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का विवरण क्या है; और

(च) वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 और वर्ष अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक दिल्ली में अलग–अलग श्रेणियों में कुल कितने अपराध दर्ज किए गए और इनमें से कितनी घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिल सकी; श्रेणीवार विवरण दें?

xg e=h % (संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

348- Jh i-d t i"dj % क्या xg e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनसंख्या और वाहन संख्या के अनुपात में कुल कितने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है और वर्तमान में कुल कितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। अलग–अलग जोन, सर्कल एवं जिलावार विवरण उपलब्ध करें;

(ख) अलग–अलग जोन, सर्कल एवं जिला वार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, और कुल कितने पद रिक्त है, पदनाम के साथ विवरण दें;

(ग) अलग–अलग जोन, सर्कल में कार्यरत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी करनी होती है;

(घ) जोन, सर्कल में कार्यरत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक तथा पूरे वर्ष में मिलने वाले अन्य अवकाशों की वस्तुस्थिति क्या है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का विवरण क्या है; और

(ङ) वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 और वर्ष अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक दिल्ली में अलग–अलग श्रेणियों में कुल कितने रोड एक्सीडेंट तथा ट्रैफिक से जड़े अन्य अपराध दर्ज किए गए;

(च) इनमें से कितनी घटनाओं में दंड, चालान या अन्य कार्रवाई की गई, श्रेणीवार विवरण दें?

xg e=h % (संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

349- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या xg e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्नकर्ता से संबंधित ग्रांटेड/पेंडिंग/रीविजेटिड प्रोसीक्यूशन स्वीकृति की सम्पूर्ण फाईल उपलब्ध करायें;

(ख) जो भी व्यक्ति विधायक, सांसद, पार्षद, केन्द्र व दिल्ली सरकार में मंत्री हैं या रहे हैं, उनके विरूद्ध ग्रांटेड/पेंडिंग फॉर कंसीडरेशन/रीकंसीडरेशन

प्रोसीक्यूशन स्वीकृति के सभी मामलों का पूरा विवरण उपलब्ध करायें जिसमें नाम, पदनाम, पता, संबंधित राजनीतिक दल, आरोपित अपराध की तिथि, प्रोसीक्यूशन के अनुरोध की तिथि, प्रोसीक्यूशन स्वीकृत ग्रांटेंड की तिथि (यदि ग्रांटेड हो), अपराध का विवरण, एफआईआर का विवरण (यदि कोई हो) और उस मामले की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रारम्भ होने से जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में स्टेट प्रोसीक्यूशन विभाग में अधिक कुशलता लाने के लिये गृह विभाग ने अब तक क्या उपाय किये हैं व क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(घ) जिला न्यायालयों व उच्च न्यायालय में इस समय लंबित मुकदमों का विवरण अदालतवार उपलब्ध करायें;

(ङ) अदालतों को किसी अदालती मामले में औसत निर्णय समय 6 महीने तक का कराने के लिये किन संसाधनों की आवश्यकता होगी;

(च) जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में वर्तमान औसत निर्णय समय क्या है, इसका विवरण अदालतवार व श्रेणीवार जैसे दीवानी, आपराधिक, पारिवारिक, चैकबाउंस, जघन्य अपराध आदि उपलब्ध कराएं;

(छ) दिल्ली सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के रूप में अनुबंधित वकीलों का विवरण प्रदान करें जिसमें केस का नाम, स्वीकृती प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम, वकील का नाम, सरकार से अब तक वसूली गई राशि, फोन नंबर, वकालत का अनुभव, कोर प्रक्टिस एरिया व केस का परिणाम सम्मिलित हो;

(ज) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न अदालतों में अनुबंधित आर्गुइंग काउंसिलों का विवरण उपलब्ध कराएं तथा यदि प्रफोमेंस आडिट किया गया हो तो उसकी रिपोर्ट भी बताएं;

(झ) जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायलय एवं विभिन्न ट्रायबुनलों में दिल्ली सरकार के पैनल में मौजूद वकीलों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ञ) पिछले चार साल में सॉलीसिटर जरनल व एडिशनल सॉलीसिटर जनरल व एटार्नी जनरल अर्थात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त कानूनी अधिकारियों अथवा अन्य किसी कानूनी दिग्गज से दिल्ली सरकार अथवा उपराज्यपाल ने कितनी बार कानूनी सलाह ली है;

(ट) उक्त सभी कानूनी सलाहों की प्रतिलिपि तथा इसकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी तथा इस पर आय खर्च का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ठ) क्या उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से सीधे अथवा दिल्ली सरकार के माध्यम से इस समय दिल्ली में चल रहे सीलिंग के बारे में कोई कानूनी सलाह ली गई है; और

(ड) दिल्ली सरकार के इतिहास में माननीय उपराज्यपाल द्वारा कब–कब प्रेस कान्फ्रेंस की गई, इसमें संबंधित मुद्दा, प्रेस कान्फ्रेंस किये जाने की तिथि अथवा उपराज्यपाल महोदय का नाम का विवरण क्या है?

xg e=h % (क) से (च) यह सूचना विभिन्न विभागों से संबंधित है और इसकी सूचना विभिन्न विभागों से उपलब्ध होने के बाद प्रदान की जायेगी।

(छ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ज) और (झ) यह सूचना विधि विभाग से मांगी गई है और सूचना उपलब्ध होने पर प्रदान की जायेगी।

(ञ) से (ठ) दिल्ली विधान सभा के नियम संख्या 31 (xvi) के अनुसार विधि अधिकारियों द्वारा माननीय उपराज्यपाल को दी गई सलाह के विषय में विधान सभा में प्रश्न पूछना स्वीकार्य नहीं है।

(ड) दिल्ली विधान सभा के नियम संख्या 29 के अनुसार विधान सभा के प्रश्न, प्रशासन जिसके लिये सरकार जिम्मेदार है, से संबंधित होना चाहिये।

350- Jh lkjHk Hkkj}kt % क्या xg e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चिराग दिल्ली व शेख सराय फेज–2 में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को पार करने में पदयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या प्रश्नकर्ता स्थानीय विधायक ने इस सस्या के बारे में यातायात पुलिस को सूचित किया है;

(ग) क्या यातायात पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो एतद्संबंधी फाइल नोटिंग्स उपलब्ध कराएं;

(ङ) क्या यातायात पुलिस ने चिराग दिल्ली और शेख सराय फेज–2 में पदायात्रियों की सुविधा के लिए 'क्रॉसिंग ट्रेफिक लाइट्स' लगाने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(च) यदि हां, तो एतद्संबंधी पत्रों, फाइल नोटिंग्स, आदि की प्रतियां उपलब्ध कराएं?

x`g e=h % (संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

351- Jh egUn xks;y % क्या x`g e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास दिल्ली के कौन–कौन से कारागारों के संचालन की जिम्मेदारी है;

(ख) पिछले 15 वर्षों के दौरान कितने नये कारागार बनाए गये, उनकी स्थिति, क्षमता और कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताएं;

(ग) क्या जेलों में रसद, कैदियों को दिये जाने वाले खाने, चाय, नाश्ता, साबुन बिस्तर और अन्य जरूरत की चीजों को खुले बाजार से खरीदा जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसकी खरीद की प्रक्रिया और उनका मापदंड क्या है; और

(ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान इन कारागारों में सामान सप्लाई करने वाली कम्पनियों या फर्मों के नाम बताएं, उनसे लिए गये समान की सूची और बदले में किये गये भुगतान का विवरण क्या है?

x`g e=h % (क) दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास तिहाड़ जेल परिसर के 09, मंडोली जेल परिसर के 06 तथा रोहिणी जेल परिसर का एक केंद्रीय कारगर संचालन में है। इसके अलावा तिहाड़ एवं मंडोली जेल

परिसर में 2 सेमी ओपन जेल तथा एक ओपन जेल भी संचालन में है।

(ख) पिछले 15 वर्षों के दौरान 11 जेलों को निर्माण करवाया गया है। जेल नं.–8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेमी ओपन जेल, तिहाड़ एवं सेमी ओपन जेल, मंडोली। इन जेलों की क्षमता 'अनुलग्नक–1' में संलग्न है।

(ग) कैदियों को दिये जाने वाले रसद एवम अन्य सामग्री खुले बाजार से भी खरीदी जाती है और कुछ वस्तुएं जेल में भी निर्मित होती हैं।

(घ) खरीद की प्रक्रिया G.F.R नियमों के अनुरूप की जाती है।

(ङ) विवरण अनुलग्न–2 में संलग्न है।

Daily Population Report As On : 19.03.2010 (At morning lock-out)

Jail No.	Capacity	Actual Population Lodged					Status as on 22.01.2018
		UT	CT	DT	CP	Total	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	565	1721	203	0	0	1924	2171
2	455	1	655	0	0	656	593
3	740	1708	243	0	0	1951	2152
4	740	2227	173	0	0	2400	2648
5	750	846	19	0	0	865	885
6 (Female)	400	319	97	0	0	416	504

1	2	3	4	5	6	7	8
7	350	543	46	2	25	616	674
8	600	762	69	0	0	831	929
9	600	714	91	0	0	805	882
10	1050	1376	187	0	0	1563	1737
11	700	610	67	0	0	677	60
12	980	895	104	0	6	1005	691
13	980	217	249	0	0	466	534
14	588	0	563	0	0	563	411
15	280	96	76	0	0	172	109
16 (Female)	248	135	23	0	0	158	62
Grand Total	10026	12170	2865	2	31	15068	16050

Semi Open Jail* (Tihar)	Total Convict=63	Parole/ Furlough-14	Present Convict=49
Open Jail*(Tihar)	Total Convict=5	Parole/ Furlough=1	Present Convict=4
Semi Open Jail** (Mandoli)	Total Convict=4	Parole/ Furlough=1	Present Convict=3
Open Jail* (Mandoli)	Total Convict=0	Parole/ Furlough=0	Present Convict=0

Note '*':- Population of Open Jail and S.O.J already included in population of CJ-2 & CJ-14)

ACHIEVEMENTS/BEST PRACTICES DURING LAST THREE YEARS OF DELHI PRISONS

There are 16 Central Jails at Delhi Prisons out of which 09 are at Tihar, 01 at Rohini and 06 are at Mandoli, East Delhi with a combined sanctioned capacity to lodge 10026 prisoners. As on 31.12.2017, all jails are functional, having inhouse population of 12264 prisoners lodged in Delhi Jails. A number of corrective measures have been taken for reformation and rehabilitation of prisoners, some of which are as under:-

1. **Swachh Bharat Abhiyan- Clean & Green Tihar :** Swachh Bharat Abhiyan or the Clean India Mission is a national level initiative launched by the Government of India to clean the streets and other public areas of the country. The Abhiyan was kickstarted at the Prisons Headquarter by the Drector General Prisons Sh. Alok Kumar Verma, IPS. The inmates and the jail officials have also been participated in this initiative. He took an oath to maintain cleanliness and also cleaned the wards to promote the initiative. They also took a solemn pledge that cleaning the premises is not only the responsibility of the karamcharis or workers, but the duty of all the prisoners and jail officials. Since then, cleanliness drives are being conducted on a daily basis in the prison. Some important steps which have been taken towards a "Swachh Tihar" are as follows:

    - Removal of malba and building material,
    - Cleaning and chlorination of water storage tanks/ syntax tanks in the premises,
    - Clearing of all roofs of various wards/ offices of the complex
    - Immediate removal of garbage from the premises,
    - Regular cutting of grass in parks,
    - Pruning of trees and removal of brushes,

- Plantation of trees in the complex,
- Regular cleaning and repairing of barrack/cell/common toilets in the complex,
- Regular washing of clothes and bedding material,
- Providing sufficient supplies for shaving, cutting of hair and nails by the deputed barbers so as to maintain physical hygiene of the prisoners,
- White-washing/ painting buildings after repair work,
- Removal of damaged furniture, and having the same repaired/ condemned as per existing rules, and weeding out the old records,
- Stock taking of all stores
- Providing soap, toiletries, toothpaste, toothbrush etc to all the prisoners.

2. **Jan Dhan Yojna for Prison Inmates :** Urder the Jan Dhan Yojna, the bank accounts of all the convicts are being opened wi:h the Tihar branch of Indian Bank. This move will make it easier for the prisoner and his family to manage money and will bring more transparency in transactions. A total of 3500 accounts have already been opened with the Indian Bank in the year 2014.

3. **Semi Open/Open Jail at Tihar :** Semi Open Prison is functional at Tihar in which 67 convicts are presently lodged. The aim and objective behind starting SOP in Delhi Prisons is to mould the thinking of a prisoner towards positive activity by reposing trust in him so that he may re-socialise in the society after his release from the prison. The treatment of SOP is extended only to convict prisoners with good Prison conduct and who are physically and mentally fit and are willing to do hard work as prescribed for them. Convict should have been sentenced to term of imprisonment for more than five years but less than twelve years and their remaining sentence is less than two years and also the life convicts who have under gone twelve

years of actual imprisonment without remission. The Govt, has also approved the guidelines for starting Open Jail at Tihar Complex under which a prisoner can go outside the jail complex for earning the livelihood and will have to come back in the evening to the Open Prison complex.

4. **Tihar Inmate Phone Call System :** The 'Tihar inmates Phone Call System, introduced in all the jails to facilitate prisoners communication with their family/friends was earlier available to prisoners once in a week which has been extended to all the week days (7 times a week).

5. **Smart Cards for jail inmates :** A Smart Cash Card System has been introduced to assist prisoners in their various monetary transactions with jail canteen, thus replacing the old coupon system. Every inmate is being given a smart card in which his transactions are credited. This has brought transparency in the accounts of prisoners. Money of inmates is now credited in their accounts by name for use via smart card. The Prison administration is in the process of using Smart Card for Prisoner Property Account also. A prisoner is allowed to accept cash worth Rs. 15,00/- per week during the interview.

6. **Launch of "Padho aur Padhao" at Tihar :** Educational activities are an integral part of the daily routine of the prisons in Delhi. They are organized at different levels for different categories of prisoners like illiterates, neo-literates, semi-literates, literates and for those desirous of getting higher education. A comprehensive educational program in association with National Literacy Mission, Ministry of HRD, Govt, of India called "Padho Aur Padhao" has been launched. This programme is the first ICT (Information and Communication Technology) enabled literacy programme conducted in any Indian prison. This programme is being vigorously followed in all the jails as a result of which illiteracy rate had declined from earlier 40% to around 5%. Having acquired functional literacy after undergoing this programme, an inmate can pursue his further studies as we have tie-ups

with National Institute of Open Schooling and Indra Gandhi National Open University who have opened their sub centre in the jails.

7. **Opening of Art & Craft Gallery :** An Art & Craft Geillery has been opened in Central Jail No.2 & 3, in which paintings by the prisoners; and craft work have been exhibited. The purpose behind establishing the Art & Craft Gallery is to encourage such activity amongst the prisoners.

8. **Computer Centers in Jail :** Computer centers have been established in jails to give computer training to the prisoners. Further, computers are being used in adult education for imparting computer literacy to the prisoners. These are also being used in the Legal Aid Cells of the jails for preparing the petitions of prisoners.

9. **E-visitor management software** is being launched on 5.11.2015 vide which the relatives of prisoners could meet prisoners on any two days of working days. The detail is enclosed.

10. **Commissioning of Model Wards in the Jails. :** The wards in old prisons is being renovated and model wards are being created in all the Jails which are provided with various facilities for carrying out reformation/ cult ural activities and comprises both cells and barracks for lodging newly admitted casual prisoners. They are well ventilated with provision of exhaust fans. There is provision of recreation room equipped with facilities of Indoor gamer., library nnd a TV for entertainment of inmates. In addition, there is sufficient space for holdi ng classes for adult education, different reformation activities like yoga and medication etc. Washing and bathing facilities have been provided in the wards. Toilets are fitted with efficient flush system. Sufficient water has been provided for drinking and bathing purposes.

11. **Launch of Music Album :** Inter jail music: contests under the banner of 'Tihar Idol' were organized amongst five cate. gories Singing, Dancing, Playing in instrument, Acting and writing lyrics. These contests organised

with the help of NGO Music One Record were organized in all the jail is to search hidden talent of jail inmates. The performance of inmates was judged by the expert panel comprising of well known personalities from the field of singing, music, dancing, writing and acting. An album JAANE ANJAANE containing the rveriormance of the finalist has been released. An audio album comprising song written, sung and composed by inmates Jee le jara has also been launched. The second addition of Tihar Idol is under the way.

12. **Visit of Foreign Delegates :** Delhi Jails have been successful in breaking the myth in the western world that the Prisons in third world countries are medieval hellholes. Today Delhi Jails are perceived as harbinger of human rights of prisoners and are being considered as role model by the National as well as International Prison Community. A number of delegation from foreign countries are visiting Tihar so that its way of functioning may be replicated in their countries. The drug de-addiction facility in Tihar are a unique example of Model de-addiction centre for the jails of the world.

13. **Visit of Parliamentary Committee :** A Parliamentary Standing Committee on Empowerment of Women visited the women's jail on 31st October 2014, in connection with the examination of the subject 'Women in Detention and Access to Justice'. The Director General Prisons, Sh. Alok Kumar Verma, received them at the Prisons Headquarter, after which a presentation on the functioning of the women's jail was given to the Hon'ble members. The Committee is headed by Smt. Bijoya Chakravarty, hon'ble members saw the creche, the library, the vocational training centre, the jail kitchens, the job work centre etc, and also interacted with the prisoners. The inmates also presented an entertaining cultural show before the Committee. The members of the committee were highly impressed with the functioning of the female jail.

"Last four hours along with members MPs move around women jail of Tihar. I am very happy that women are seems to be happy. They get good

food, health care also (women) getting by children here. Only problem is Judicial cell be more active. I must thank all the staff and officials."

14. **Hospital and Medical Facilities :** Inmates are provided round the clock medical attention in Delhi Jails for which there is a 150 bedded primary care hospital in Central Jail No.3 and dispensaries equipped with MI Rooms in other jails. For women prisoners there is a separate and exclusive dispensary in women prison i.e. Central Jail No.6, Tihar and a MI Room. Ayurvedic, Unani and Homoeopathic treatments are also available to prisoners in addition to allopathic system. The main features of health facilities in Dehhi Prisons are as follows: 150 bedded primary care Hospital with medical, surgical, tuberculosis and psychiatric wards.

- A 120 bedded de-addiction centre functioning in Central Jail Hospital.
- De-addiction Centre (CJH) is ISO 9001-2008 certified.
- One integrated Counselling and Testing Centre for HIV, functioning in Central Jail Hospital.
- Special diet for HIV/AIDS, Tubercular and other deserving inmates.
- Cases of seriously sick inmates are taken up with the concerned court for their bail /early disposal of case.
- DOTS centre for T.B.
- Complete Dental Unit in Central Jail Hospital, CJ-4, CJ-6 and Distt. Jail, Rohini.
- Dental Camp held for inmate prisoner patients requiring partial/ complete denture with the help of NGOs.
- Pulse Polio immunization programmes are carried out regularly as per Pulse Polio schedule of Delhi Government, in CJ-6.
- The prisoners suffering from various contagious diseases are kept separately.

- Prisoners are referred to various specialty and super specialty hospitals for providing medical care.
- Various NGO's also working with Tihar Prisons and contributing towards medical services.
- 110 sanctioned posts of Doctors and 189 of paramedical staff.
- 64 Doctors and 138 paramedical staff presently posted for prison health care.
- Round the clock casualty services in Central Jail Hospital.
- A minor O.T. in Central Jail Hospital.
- Investigation facility for Biochemistry, Pathology, X-Ray, ECG available.
- Round the clock dispensaries in all the Jails including Distt. Jail Rohini.
- Biomedical waste management is done as per rules of DPCC.
- Various specialists/Senior Residents in the fields of Medicine, Ophthalmology, Orthopedics, Chest and TB, Skin, Psychiatry and Pathology ate available.

15. **Vocational Activities :** Vocational activities form the integral part of the Prison management so that a prisoner is taught the vocation to create self confidence in his abilities to shun the path of crime. There are various vocations taught in Delhi Jails to engage the prisoners in positive activities. Some of the vocations like blanket unit, soap unit, artificial flower unit, dhoopagarbatti making, fashion designing etc. have been started so that prisoner may engaged inside the prison in purposeful manner and also earning wages. It is respectfully submitted that Tihar has consistently been pioneer in putting forth the novel ideas for rehabilitation of prisoners. There

are other vocational courses which are taught in Delhi Prisons and the details thereof are as under:

Computer, Art & Craft, personality development and life skills, painting, shoes making, English, Weaving Section, cutting and tailoring, creche and Balwari training, Beauty Parlour, Plumber, Electrical, Adult Education, Music, Jute, Puppet Making, Papad and Pickle, Bag manufacturing, Namkeen Unit, Dance, Jeans stitching etc.

16. **Yoga, Meditation & Spiritual Courses :** Yoga, meditation and spiritual activities an important component of reformation and rehabilitation policy of Delhi Prisons which bring qualitative change in the life of prisoners. A number of Non-Governmental organizations are helping the Jail administration in carrying out various activities and augment religious preaching to inmates. Some of these are Vipassana, Art of Living, Raj Yog, Sahaj Yoga and satsang, Thousands of prisoners have participated in the meditational programmes conducted and a marked change has been observed in the behaviour of such prisoners. Further, during morning hours the prisoners do yoga and physical exercises.

    Daily Yoga classes are being conducted in Delhi Prisons under Panchwati Yoga Ashram Care Centre (NGO).

17. **Video Conferencing :** Video Conferencing facilities have been provided in the jails for the extension of Judicial Remand of prisoners, thus saving the prisoner from the hardship of visiting the courts for the purpose of remand extension. Further, legal aid facilities through Delhi High Court Legal Services Committee are also being provided to the prisoners through the medium of video conferencing.

18. **Senior Citizen Ward :** This ward has been created in Central Jail No.3, hospital where senior citizens above the age of 60+ are kept. They have been given bed and their dietary requirement are given due consideration.

19. **Revision in Wages of Prisoners :** The Govt. of NCT of Delhi has revised the wages paid to the prisoners as follow :-

	Skilled	Semi-Skilled	Unskilled
New Wages structure	171/-	138/-	107/-
75% of wages payable to prisoners	128/-	103/-	80/-
Deduction of 25% for Victim Welfare Fund	43/-	35/-	27/-
Earlier wages structure	99/-	81/-	70/-

All the new entrant are classified as unskilled worker and their cases for transfer to semi skilled category are taken up after getting three months experience and recommendation from the Supervisor that he has attained some skill.

Similarly, a semi-skilled worker could be classified as skilled worker after three months. It means that new entrant should be required to have more than 6 months experience to be eligible for classification as skilled worker after following above procedure.

This criterion will however not apply in cases where prisoners have attained skilled or semi-skilled status because of his outside working experience. The above wages structure further stipulates that working hours of prisoners should not exceed 8 hours per day and there should be routine medical check-up of labouring convicts.

20. **Construction of New Jail : New Central Jail at Mandoli :** The foundation of a new prison complex was laid down at Mandoli in 2008, in order to decongest the overcrowding Central Jail at Tihar and having a capacity of 3776 inmates including 6 central jails, one each for women (280 inmates), adolescent (700 inmates) and high security prisoners (248 inmates) and rest for the other convicted and undertrial prisoners.

21. **Board of Visitors :** Home Department, Govt. of NCT of Delhi has appointed 9 Official Visitors and 21 Ncn-officials visitors of jail in NCT of Delhi to act as such and discharged the functions of the visitors as assigned to them. Meetings are also convened time and again with the visitors on the multiple issues related to the prison reforms.

22. **Welfare Activities:** The Prison Welfare Services from Department of Social Welfare is providing Financial and Social support to the eligible convicts and their family members. They further help the convict in the following matters:

    (i) Counselling and Guidance (ii) Financial Assistance: (iii) Rehabilitation Grant to released convicts (iv) Submission of Social Investigation Report in Sentence Reviewing Board, Niercy petition & Parole case (vi) Follow up of released prisoners, (vii) Rehabilitation grant to the children of incarcerated parents.

    The way inmates spend and receive their money has also been revamped. An inmate's friend/relativte can swipe a debit or credit card at POS machines and the money will be automatically transferred to the Prisoner Property Account. The families of prisoners who are not in Delhi can directly wire the money to the inmates account of the Delhi Jails. The wages earned by inmates are automatically credited to their prisoners property account opened at Indian bank. The inmates have smart cards which they can recharge for up to Rs.6000 in a month and spend the money on buying eatables and daily use stuff from the prison canteen.

23. **Drama Club and Plays -** Tihar Drama Club recently established in Tihar which was set up by an inmate has been the cynosure of the Jail its production which include previously scripted plays as well as improvisation mounted by actors of the club have earned it a lot of acclaimed within the prison as well as the media outside, its production include successful run of classical Hindi short story called 'Kafan' by Munshi Prem Chand, 'Court

Martial' and the eternal Chhatisgarhi classic of hindi stage, 'Charan Das Chor' which won the best play award at Edinburgh, the greatest theatre competition in the world.

24. **Special Courts —** Tihar Court Complex has been established in the Tihar premises to dispose of the cases of undertrial prisoners who are lodged in the jails in minor offences and ready to confess their guilt. Till dated 196 Courts have been held and 6046 cases have been disposed off.

25. **Art Gallery at Central Jail No.4 -** The art Gallery inside Central Jail No.4 have been inaugurated for imparting training to the inmates in paintings and sculptures. The idea behind the art school is to help inmates use their time constructively. The paintings done at Art Gallery in different mediums— oil, acrylic, water paint-deal with myriad themes: streetscapes, metro trains, portraits of women, the ghats of Banaras, landscapes. The inmates have been trained first by a group of oostgraduate students of the College of Art, Delhi, and then by well-known artists associated with the Lalit Kala Akademi at a five-day workshop.

26. **Tihar Fest-2017 :** With the progressive and rehabilitative approach to reform, rehabilitate and to reintegrate the inmates with the society Delhi Prisons is celebrating 'Tihar Fest-2017' under the aegis of Govt. of NCT of Delhi from 19th to 1st September, 2017. Tihar Fest having main components as an interactive painting and sculpture workshop-cum-camp participated by prison inmates followed by an exhibition of their art work at Lalit Kala Academy in New Delhi. Apart from this talent of convicts in singing, dance, music, theatre have also presented at Delhi Hat, Pitam Pura, I.N.A. and Janak Puri. Abour 100 convicts from other 8 States and 50 popular artists have also participated in this Art Festival.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF PRISONS

PRISONS HEAD QUARTER : NEAR LAJWANTI GARDEN CHOWK JANAK PURI, NEW DELHI

F.21(13)/ND(465)/Vidhan Sabha Question/Prov/2012-13/CD No. Dated :

The AIG (Prisons)
Prisons Headquarter,
Central Jail, Tihar,
New Delhi

Subject: Reg. reply to Vidhan Sabha Un-starred Question Mo. 76 for 22.03.2018 raised by Sh. Somnath Bharti and Question No. 351 for 27.03.2018 raised by Sh. Mahender Goel.

Sir,

With reference to the Vidhan Sabha question No. 76 & 351, as mentioned above, the reply of the Provision Branch is as under:

Question No. 76 :

The Provision Branch of Prisons Deptt, GNCTD only publishes tender notices in the newspapers and no advertisements are placed by this branch.

Question No. 351: Only Subpoint No. C, D & E pertains to the Provision Branch, PHCi. The Pointwise reply is as under:

Question No. C : The raw materials for food, tea, eatables are procured from M/s. Kendriya Bhandar while Milk and Vegetables are procured from M/s. Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt. Ltd. Soap, Bread, Biscuits and bedding are manufactured in Jail Factories for in-house consumption by the jail inmates.'

Question No. D : Earlier, the procurement of various dietary items were made through Tendering / E-tendering uptill 2013-14. However, after approval of Hon'ble L.G. of Delhi, the Prisons Deptt. has signed MoU with M/s. Kendriya Bhandar for procurement of dietary items and to procure for procurement of Milk and Vegetables MoU has been signed with M/s. Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt. Ltd. After signing the MoU, good.s are procured from M/s. Kendriya Bhandar and M/s. Mother Dairy Fruit and Vegetables Pvt. Ltd.

Question No. E : It is to inform that records before 2009-10 had been weeded out, thus, the information is available w.e.f. 2009-10 only. The list of firms, who had supplied the dietary items w.e.f. 2009-10 and detail of payments made to them is as under:

Sl. No.	Financial Year	Name of Firms supplied items	item Description supplied by firms	Approx. Payment made to the firms	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6
1.	2009-10	Singla Traders	Datun,	3,03,245/-	Imli Seedless & Eggs for 2008-09) for which payment was made in 2009-10. Rs.57314/- were paid in f.y. 2010-11.
2.		P.A. Sales Corporation	Atta, Tea leaf, Lobhia White, Salt, Imli (Seedless)	1,08,27,709/-	Atta, Tea leaf, Lobhia White, Salt, were extended till 31.05.2010, for which payment was made in 2010-11. 596446/- were paid in f.y. 2010-11.
3.		Vijay Chadha	Eggs	43,671/-	
4.		Gupta Agencies	Wheat (Darra), Urad Whole, Urad Chilka (2009-10), Moong Whole,	68,35,205/-	Moong Dhuli, Moong Chilka, Arhar, Salt, Tea Leaf (for 2008-09) for

1	2	3	4	5	6
					which payment was made in 20O9-10,Wheat Darra was extended till 31.05.2010, for which payment was made in 2010-11.1888223/- were paid in f.y. 2010-11.
5.		Jagdamba Sales Corporation	Rice Parmal, Dal Chana (Agmark), Rajma Chitra, Lobhia Red, Kabli Chana (Medium), Corriander (Raw Material for spices). Gram Black, Sugar	1,39,38,780/-	Extended till 31.05.2010, for which payment was made in 2010-11.917396/- were paid in f.y. 2010-11.
6.		Surender Kumar & Co.	Atta (for 2008-09)	8,58,369/-	
7.		Shakti Sales Corporation	Dal Urad (Whole), Dal Urad (Chilka), Dal Urad (Dhuli), Soyabin (Nutrela/ Nutn Nugget), Dal Moong (Chilka)	24,15,710/-	

8.		NAMC India Ltd.	Risk Purchase for Eggs	7,770/-
9.		Coffret Enterprises	Tea at Judicial Lock-ups	4,91,329/-
10.		Vijay Chadha	Vegetables	65,80,023/-
11.		Mahender Pal Fruits & Vegetable	Lemons	4,26,859/-
12.		Parag Dairy	Milk	1,27,20,823/-
13.	2010-11	P.A. Sales Corporation	Lobia Red, Dal Moong Whole	61,71,892/-
14.		Gupta Agencies	Tea Leaf, Wheat Darra,	1,04,52,845/-
15.		Jagdamba Sales Corporation	Atta, Sugar, Arhar, Rice Parmal,	1,59,32,271/-
16.		Shakti Sales Corporation	Dal Malka, Urad Chilka, Urad Whole, Urad Dhuli, Rajma Chitra, Lobia White, Kabli Chana, Dal Chana, Sugar, Dal Moong Chilka, Dal Moong Dhuli, Dal Arhar,	1,17,66,167/

1	2	3	4	5	6
17,		Singla Traders	Eggs	7,20,511/-	
18.		Ram Karan Surender Kumar	Rice Parmal, Salt, Datun, Soyabin (Nutrela), Gur Pedi, Imli Seedless, Turmeric, Corriander	47,51,152/-	
19.		Coffret Enterprises	Tea at Judicial Lock ups	63,861	
20.		Mother Dairy Fruits and Vegetables	Milk	1,63,12,919/-	
21.		Vijay Chadha	Vegetables	57,36,761/-	
22.	2011-12	P.A. Sales Corporation	Kabli Chana, Red Chilly with stick, Sugar	53,48,715/-	
23.		Gupta Agencies	Rice Parmal, dal Moong Chilka, dal Moong Dhuli, Dal Urad Whole, Dal Urad Chilka, Dal Urad Dhuli, Black Gram, Tea Leaf	1,34,05,374/-	1469821/- were paid in f.y. 2012-13.

24.	Jagdamba Sales Corporation	No item was awarded	-	Payment, of 2010-11 was extended for which payment of Rs.24,81,048/- was made in 2011-12.
25.	Shakti Sales Corporation	Dal Arhar, Dal Moong Whole, dal Chana, Dal Malka, rajma Chitra, Lobhia White, Lobhia Red	1,01,12,188/-	
26.	Singla Traders	Soyabin (Nutrela / Nutri Nugget), Salt, Gur Pedi, Imli Seedless, Turmeric, Coriander, Eggs, Datun	23,54,645/-	143707/- were paid in f.y2012-13
27.	Ram Karan Surender Kumar	Atta	73,34,780/-	
28.	Katyayani Enterprises	Wheat Darra	1,63,85,650/-	
29.	Vending Solutions	Tea at Judicial Lock ups	5,46,776/-	400807/- were paid in f.y. 2012-13
30.	Vijay Chadha	Vegetables	82,57,860/-	1335045/- were paid in f.y 2012-13

1	2	3	4	5	6
31.		Parag Dairy	Milk	1,18,92,409/-	459849/- were paid in f.y, 2012-13
32.	2012-13	Ram Karan Surender Kumar	Atta,	27,65,569/-	
33.		Om Prakash Kanwar Lai	Wheat	1,05,09,160/-	
34.		Vijay Chadha	Eggs	5,51,919/-	
35.		Delhi Consumer Co-o Wholesale Store	Risk Purchase for Sugar, White Lobhia,, Kala Chana, Dal Chana	33,67,200/-	
36.		Jagdamba Sales Corporation	Lobhia White, Dal Moong Chilka, Dal Malka, Rajma Chitra, Dal Urad Whole, Dal Urad Chilka, Dai Urad Dhuli,Kabli Chana,	1,25,53,233/-	
37.		Singla Traders	Datun, Salt, imli Seedless, Gur Pedi	18,01,839/-	
38.		Gupta Agencies	Tea Leaf, Rice Permal, Moong Dhuli, Lobhia Red, Moong Whole, Dal Arhar,	1,32,28,207/-	

39.		Rajat Agro Industries	Risk Purchase for Soyabin Ruchi Brand,	51,000/-	
40.		Shakti Sales Corp.	Sugar, Soyabin, Gram Black, Dal Chana	26,09,644/-	
41.		Future Agrovet Ltd.	Risk Purchase for Soyabin, Gram Black	19,38,845/-	
42.		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	20,08,732/-	
43.		Vijay Chadha	Vegetables	1,01,63,754/-	
44.		Quality Dairy	Milk	1,65,88,300/-	
45.	2013-14	Syndicate Fruit Dealers & Vijay Chadha	Vegetables	1,35,03,331/-	
46.		Sterling Agro	Milk	1,80,00,131/-	
47.		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	29,04,045/-	
48.		Syndicate Fruit Dealers	Lemons	4,97,880/-	
49.		Singla Traders	Salt, Datun, Eggs,	11,31,635/-	Rs.4,89,431/- were paid in 2014-15
50.		P.A. Sales Corp	Rice Parmal, Soyabean, Imli Seedless, Lobhia Red, Tea Leaf,	42,64,298/-	32,73,450/- were paid in 2014-15

1	2	3	4	5	6
51.		Jagdamba Sales Corp	Atta, Wheat Darra, Dal Malka, Lobhia White, Sugar, Dal Chana, Kabuli Chana, Black Gram	2,22,98,025/-	92,64,862/- were paid in 2014-15
52.		Gupta Agencies	Dal Urad Whole, Urad Chilka, Rajma Chitra, Gud Pedi, Moong Dhuli, Urad Dhuli, Arhar.	82,36,336/-	43,46,902/- were paid in 2014-15
53	2014-15	Kendriya Bhandar	Dietary Items (Pulses, Wheat Darra, Rice, Sugar, Soyabean, Salt, Imli, Gur Pedi, Tea Leaf, Raw Spices, Eggs, Atta etc.)	11,00,11,382/-	
54		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Milk	2,34,77,402/-	
55		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Vegetables & Lemons	2,54,42,037/-	
56		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	27,21,978/-	
57	2015-16	Kendriya	Dietary Items (Pulses,	13,16,21,997/-	

		Bhandar	Wheat Darra, Rice, Sugar, Soyabean, Salt, Imli, Gur Pedi, Tea Leaf, Raw Spices, Eggs, Atta, Tooth Brush, Tooth Paste etc.)	
58.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Milk	2,14,62,332/-
59.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Vegetables & Lemon	2,48,76,409/-
60.		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	17,18,886/-
61.	2016-17	Kendriya Bhandar	Dietary Items (Pulses, Wheat Darra, Rice, Sugar, Soyabean, Salt, Imli, Gur Pedi, Tea Leaf, Raw Spices, Eggs, Atta etc.)	13,93,47,596/-
62.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Milk	1,54,45,615/-
63.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Vegetables	3)16,36,559/-

1	2	3	4	5	6
64.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Lemon	61,34,745/-	
65.		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	16,79,843/-	
66.	2017-18	Kendriya Bhandar	Dietary Items (Pulses, Wheat Darra, Rice, Sugar, Soyabean, Salt, Imli, Gur Pedi, Tea Leaf, Raw Spices, Eggs, Atta etc.)	14,09,21,438/-	
67.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Milk	1,84,72,571/-	
68.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Vegetables	3,13,63,296/-	
69.		Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.	Lemon	17,66,026/-	
70.		Vending Solutions	Tea at Judicial Lock-ups	24,39,040/-	

Yours faithfully,

Dy. Supdt. (Prov.): PHQ

352- Jh jkepUnz % क्या m|kx e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना फैक्ट्री एरिया में डीएसआईआईडीसी में 16000 फैक्ट्री हैं और ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यहां कार्यरत उद्यमियों को सर्विस टैक्स जमा करने 40–45 कि.मी. दूर पटपडगंज बैंक जाना पडता है;

(ग) क्या सरकार इन फैक्ट्री मालिकों को अपना अपना टैक्स बवाना या आसपास जमा कराने की सुविधा देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक यह सुविधा शुरू कर दी जायेगी;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि बवाना में डीएसआईआईडीसी के खाली पडे ऑफिस भवन में डीएसआईआईडीसी का ऑफिस शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा?

m|kx e=h % (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, डीएसआईआईडीसी में पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता।

(ग) पट्टा किराया (Lease Rent) तथा अन्य देय राशी का online भुगतान डीएसआईआईडीसी की वेबसाईट www.dsiidc.org पर उपलब्ध Allottees Friendly Portal" के माध्यम से किया जाता है।

(च) और (छ) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

353- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या jkt xkj e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम विभाग के कारणों एवं उद्देश्यों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) क्या कभी इस विभाग का उपयोगिता की दृष्टि से सामाजिक ऑडिट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं;

(घ) क्या श्रम विभाग द्वारा आम आदमी पाटी की पिछली दो सरकारों के दौरान कोई सुधारात्मक कार्य किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी सूची उपलब्ध कराएं और बताएं कि क्या वे सुधार अभी भी लागू हैं;

(च) लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों द्वारा पालन की जाने वाली श्रमिनीति क्या है;

(छ) क्या कभी इसके उल्लंघन की जांच हेतु निरीक्षण किए गए हैं;

(ज) यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं;

(झ) 3 मार्च, 2017 से लागू संशोधित न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन के कितने मामले श्रम विभाग में दर्ज किए हैं, इनकी सूची व वर्तमान स्थिति का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ट) श्रम अदालतों व उनके पीठासीन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं जिसमें उनके नाम, फोन नंबर, लंबित मामलों का विरण तथा एक लेबर केस के निपटाने में लगने वाला औसतसमय सम्मिलित हों;

(ठ) बाल श्रमिक कौन होता है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या सजा है;

(ड) पिछले तीन वर्ष में विभाग में बाल–श्रम से संबंधित कितनी शिकायतें आई हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ढ) इस विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं; और

(ण) उनकी संपूर्ण सूची, उनका लाभ उठाने के लिए पात्रता व प्रक्रिया में लगने वाला समय क्या है?

jktxkj e=h % (क) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार का मुख्य रूप से संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत उनके वैधानिक हितों की रक्षा करने का जिम्मा है, जिससे कि औद्योगिक शांति बरकरार रह सके एवं कर्मचारियों का शोषण न हो। विभाग द्वारा श्रम प्रावधानों का प्रबंधकों द्वारा उल्लंघन करने की परिस्थितियों में प्रोसिक्यूशन/चालान इत्यादि करने की कार्यवाही भी की जाती है। श्रम विभाग की तकनीकि शाखा द्वारा बिजली के उपक्रम व कारखाना संबंधित, लिफ्ट संबंधित एवं बॉयलर संबंधित लाइसैंस/अनुमति दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) श्रम विभाग द्वारा 55 सेवायें ऑन लाईन उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित की गयी हैं, जिसमें से प्रथम चरण में 07 सेवाओं को ऑन लाईन लागू किया गया है। (इसके अतिरिक्त श्रम विभाग में श्रमिक हेल्प लाईन 155214 भी उपलब्ध करायी गयी है, इस हेल्प लाईन के द्वारा श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों व प्रबंधकों इत्यादि को श्रम विषयों व शिकायतों के बारे में सूचना/सलाह दी जाती है।) 07 सेवाओं को जिन्हें ऑन लाईन किया गया है, वे हैं:–

1. ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता का पंजीकरण।
2. ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदार का लाइसैंस देना।
3. पैसेन्जर लिफ्ट लगाने की अनुमति।
4. पैसेन्जर लिफ्ट लगाने के लिए लाइसैंस।
5. दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के अंतर्गत दुकानों का पंजीकरण
6. कारखाना/फैक्ट्री संबंधित नक्शे की स्वीकृति (एमसीडी पोर्टल के माध्यम से)
7. भवन एवं अन्य संनिर्माण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

श्रमिक हेल्प लाईन पर पिछले लगभग एक साल (मार्च, 2017 से फरवरी, 2018) में 26719 संपर्ककर्ताओं को सूचना/जानकारी सलाह दी गयी है। यह हेल्प लाईन सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

(च) लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों पर सामान्य रूप से सभी श्रम कानून लागू होते हैं, जिसमें मुख्य हैः– औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, उपादान अधिनियम 1972, ईएसआई अधिनियम 1948, भविष्य निधि अधिनियम 1952 इत्यादि–इत्यादि।

(छ) श्रम विभाग द्वारा 09 जिला कार्यालय स्थापित किये गये हैं, शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् व समाधान हेतु श्रम निरीक्षक/कारखाना निरीक्षक द्वारा संस्थान/ईकाई का निरीक्षण करवाया जाता है, उल्लंघन पाये जाने की परिस्थितियों में प्रबंधक को उल्लंघन दूर करने की सलाह दी जाती है एवं प्रबंधक द्वारा उल्लंघन दूर न करने की परिस्थिति में उसके विरूद्ध प्रोसिक्यूशन/चालान मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किये जाते हैं।

(ज) गत 01 वर्ष (जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017) में श्रम विभाग द्वारा भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्रबंधनकों के विरूद्ध 830 प्रोसिक्यूशन/चालान मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं।

(झ) श्रम विभाग द्वारा दिनांक 3.3.2017 को अधिसूचना जारी करके न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई गयी, परन्तु इस अधिसूचना के विरूद्ध माननीय

दिल्ली उच्च न्यायालय में 82 याचिकायें दाखिल की गयी, विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में अपना उत्तर/पक्ष सरकारी वकील के माध्यम से रखा गया, एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2017 यह आदेश जारी किये गये कि श्रम विभाग द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(ट) श्रम विवादों को निपटाने हेतु दिल्ली में 08 श्रम न्यायालय व 01 इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल उपलब्ध थे, परन्तु विवादों के और शीघ्र निपटान हेतु श्रम विभाग के अनुरोध के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 06 नवम्बर, 2017 से 02 अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं 01 अतिरिक्त इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की स्वीकृति दी, इस तरह से दिल्ली में 10 श्रम न्यायालय एवं 02 इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कार्य कर रहे हैं।

औसतन श्रम विवाद को निपटाने हेतु लगभग 2 साल से 2.5 साल का समय लगता है, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में लगभग 1000 से 1100 मामले लंबित हैं। पीठासीन अधिकारियों के नाम व दूरभाष संख्या सहित सूची में दर्शाये गये हैं।

(ठ) बाल श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 2(II) के अंतर्गत बाल श्रम को परिभाषित किया गया है, परिभाषा के आधार पर 14 साल या उससे कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक माना जाता है एवं उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधकों के विरूद्ध माननीय मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान लगाये जाते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा उल्लंघनकर्ता को कम से

कम 03 महीने से लेकर 01 साल तक या 10 हजार रुपये लेकर 20 हजार तक की राशि का जुर्माना किया जा सकता है। जिसका निर्णय माननीय मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त उल्लंघनकर्ता प्रबंधकों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20,000/– की राशि बाल श्रमिक के पुनर्वास हेतु वसूली जाती है व न्यूनतम वेतन भी वसूला जाता है।

(ड) o"k 2015 में 100 बाल श्रम से संबंधित छापे मारे गये, जिसमें 660 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये, 69 प्रबंधकों के विरूद्ध सीलिंग एंव गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी, 10,40,000/– रुपये पुनर्वास राशि के रूप में वसूले गये, इसके अतिरिक्त 57,58,004/– रुपये की राशि न्यूनतम वेतन के रूप में वसूले गये, जिसे बाल श्रमिकों को दी गयी।

o"k 2016 में 53 बाल श्रम से संबंधित छापे मारे गये, जिसमें 479 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये, 54 प्रबंधकों के विरूद्ध सीलिंग एवं गिफ्तारी की कार्यवाही की गयी, 2,60,000/– रुपये पुनर्वास राशि के रूप में वसूले गये, इसके अतिरिक्त 21,73,537/– रुपये की राशि न्यूनतम वेतन के रूप में वसूले गये, जिसे बाल श्रमिकों को दी गयी।

o"k 2017 में 45 बाल श्रम और संबंधित छापे मारे गये, जिसमें 643 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये, 33 प्रबंधकों के विरूद्ध सीलिंग एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी, 1,40,000/– रुपये पुनर्वास राशि के रूप में वसूले गये, इसके अतिरिक्त 7,63,987/– रुपये की राशि न्यूनतम वेतन के रूप में वसूले गये, जिसे बाल श्रमिकों को दी गयी।

(ढ) श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के वैधानिक हितों की रक्षा श्रम प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा निम्नलिखित सेवायें भी प्रदान की जाती हैं:—

ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत, ठेकेदारों को लाइसैंस एवं मुख्य नियोक्ताओं को रजिष्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लिफ्ट लाइसैंस इत्यादि।

(ण) उक्त सेवाओं का लाभ उठाने हेतु, अनुमोदनकर्ता की पात्रता प्रावधानों के अंतर्गत श्रम विभाग की वेबसाईट (www.labour.delhigovt.nic.in) में पूर्ण रूप से प्रतिक्रिया सहित दर्शायी गयी है।

ihBklhu vf/kdkfj;ksa dk uke ¼bMfLVª;y fVªC;quy½

1. श्री चन्द्र गुप्ता, न्यायालय सं. 501, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.—011—28043014

2. श्रीमती शैल जैन, न्यायालय सं. 510, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली। दूरभाष सं.—011—28042005

ihBklhu vf/kdkfj;ksa dk uke ¼Je U;k;ky;½

1. श्री अतुल कुमार गर्ग, न्यायालय सं. 504 द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.—011—28043262

2. श्री राकेश कुमार—1, न्यायालय सं. 509, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं. —011—28042045

3. श्री उमेद सिंह, न्यायालय सं. 514, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.—011—28041432

4. श्रीमती बरखा गुप्ता, न्यायालय सं. 502, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28042846

5. श्रीमती प्रीति अग्रवाल गुप्ता, न्यायालय सं. 515, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28042876

6. श्री लोकेश कुमार शर्मा, न्यायालय सं. 513, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28044131

7. श्री जितेन्द्र मिश्रा (निलंबित) न्यायालय सं. 203, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28042865

8. श्री मोहिन्द विराट, न्यायालय सं. 204, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28043402

9. श्री विनय सिंघल, न्यायालय सं. 516, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28042457

10. श्रीमती वीणा रानी, न्यायालय सं. 503, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली दूरभाष सं.–011–28042873

354- Jh egn xk;y % क्या jktxkj e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षवार दिल्ली सरकार द्वारा कितने रोजगार मुहैया कराये गये;

(ख) पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा ये रोजगार प्रदान करने के लिए वर्षवार कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, इनमें कितने युवाओं ने पंजीकरण करवाया और कितनों को रोजगार मिला, पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन पांच सालों में युवाओं को रोजगार मेले की जानकारी देने के लिए विज्ञापन के किन तरीको का उपयोग किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है;

(ङ) इन पांच वर्षों में रोजगार मेलों के आयोजन पर व्यय राशि का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(च) इन पांच वर्षों में जिन अधिकारियों ने रोजगार मेले के आयोजन हेतु फण्ड जारी किया, उनके नाम और पद सहित विवरण क्या है;

(छ) पिछले पांच वर्षों में इन रोजगार मेलों के प्रति विज्ञापन पर व्यय राशि का वर्षवार विवरण क्या है;

(ज) इन पांच वर्षों में जिन अधिकारियों ने रोजगार मेले के आयोजन के विज्ञापन का फण्ड जारी किया, उनके नाम पर पद सहित विवरण क्या है;

(झ) इन पांच वर्षों में रोजगार मेले के आयोजन की फाइल की तारीख अनुसार मूवमैंट की जानकारी क्या है;

(ञ) पिछले पांच वर्षों में इन रोजगार मेलों के उपरांत प्रत्येक वर्ष कितने आवेदकों को सरकारी नौकरी मिली; और

(ट) रोजगार मेले में पंजीकृत उम्मीदवारों और रोजगार मेले के माध्यम से रोजागर पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है।

jkt xkj e=h ¼ (क) यह विभाग रिक्तियों का सृजन नहीं करता अपितु नियोक्ता की मांग के अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची नियोक्ता को

उनके द्वारा वांछित आवश्यक शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव तथा कौशल आदि के आधार पर प्रेषित कर रोजगार दिलाने में सहायता करता है इसके साथ ही बुलावा पत्र/नियुक्ति पत्र देना आदि समस्त प्रक्रिया नियोक्ता द्वारा ही सम्पन्न की जाती है। विगत पांच वर्षों में नियोक्ताओं द्वारा सूचित, चयन किये गए अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	चयन
2013	73
2014	417
2015	176
2016	102
2017	66
2018 (मार्च तक)	46

(ख) रोजगार निदेशालय द्वारा वर्ष 2015 से 7 रोजगार मेलों का आयोजन किया है जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	नंबर ऑफ जॉब फेयर	अभ्यर्थियों का पंजीकरण	साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	नौकरी प्रदान करने हेतु शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
2015	02	—	3000	14000
2016	—	—	—	—

1	2	3	4	5
2017	04	21271	31387	10385
2018	01	18094	16614	5995
	कुल		78001	30380

(ग) इन पांच मेलों में रोजगार मेले की जानकारी के लिए प्रिंट मीडिया और एफएम के द्वारा विज्ञापन किया है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के उत्तर अनुसार लागू नहीं होता है।

(ङ) वर्ष 2013—14 एवं वर्ष 2014—15 में को कई खर्च नहीं हुआ वर्ष 2015—16 से वर्ष 2017—18 तक आयोजित किये गए 7 रोजगार मेलों पर अभी तक रुपये 33.11 लाख भुगतान किया गया है।

(च) इन पांच वर्षों में रोजगार मेलों के आयोजन हेतु फण्ड वित विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है विभागीय स्तर पर कार्यालय प्रमुख इत्यादि की संस्तुति पर विभाग्याध्यक्षों (श्री के आर मीणा), (1 सितम्बर, 2015 से जून, 2016), श्री ऐ के सिंह (जून 2016 से अप्रैल 13, 2017) श्री एस के सक्सेना (13 अप्रैल 2017 से अब तक) द्वारा व्यय स्वीकृत किया गया था।

(छ) विज्ञापन के लिए विभाग द्वारा होर्डिंग पर रुपए 1556292/— खर्च किया गया, जिसके भुगतान की प्रक्रिया जारी है अखबार में विज्ञापन से सम्बंधित खर्च का वहन दिल्ली सरकार के सूचना विभाग द्वारा किया गया है। इस मद में रेडियो जिंगल पर वर्ष 2017 में रुपए 781260/— खर्च किया गया जिसके भुगतान की प्रक्रिया जारी है;

(ज) उपरोक्त 'छ' के उत्तर अनुसार।

(झ)

क्र. सं.	तारीख	फाइल मूवमेंट की तारीखें
1.	1 से 8 अगस्त, 2015	मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय स्तर पर हुआ।
2.*	16 नवंबर से 5 दिसम्बर, 2015	दिनांक 10.09.2015 को माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के अधीन हुई मीटिंग के निर्णयनुसार।
3.	17 मार्च से 18 मार्च, 2017	मेले का आयोजन रोजगार कार्यालय स्तर पर हुआ।
4.	12 मई, 2017	मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय स्तर पर हुआ।
5.	11 से 15 जुलाई, 2017	मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय स्तर पर हुआ।
6.*	7—8 नंबर, 2017	दिनांक 31.08.2017 को माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के अधीन हुई मीटिंग के निर्णयनुसार।
7.*	15—16 फरवरी, 2018	दिनांक 24.01.2018 को माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के अधीन हुई मीटिंग के निर्णयनुसार।

*मेगा मेले

(ञ) रोजगार विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों में निजी क्षेत्र के संस्थानों/नियोक्ताओं द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है इन मेलों के माध्यम से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है।

(ट) रोजगार मेलों में भाग लेने हेतु जून, 2017 से प्रारम्भ 'ऑनलाइन जॉब फेयर पोर्टल' पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या 39365 है तथा 2015 से अब तक आयोजित किये गए रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी पाने हेतु शॉर्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 30380 है।

355- Jh _rjkt xkfoUn % क्या jktxkj ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2017–18 में कुल कितने रोजगार दिए जाने का वायदा किया गया है;

(ख) इस वायदे को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 में कितने 'स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम' आयोजित किए गए;

(ग) वर्ष 2017–18 में इन स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कितना बजट आबंटित किया गया था;

(घ) इसमें कितने प्रतिशत राशि इस वित्त वर्ष में अब तक खर्च की जा चुकी है;

(ङ) ये स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाने के लिए किस अधिकारी ने कितना समय लिया, नाम व पदनाम सूचित करें;

(च) स्किल ट्रेनिंग की फाइल किस–किस अधिकारी के पास कितने–कितने

समय (घंटो में) तक लंबित रही, नाम पदनाम सहित पूरा विवरण क्या है; और

(छ) यदि आबंटित बजट शत प्रतिशत खर्च नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है?

jkt xkj e=h ¼ (क) वर्ष 2017–18 में रोजगार दिए जाने की संख्या का कोई वादा सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

(ख) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत सूचना अनुसार वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गयाः–

क्र.सं.	स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1.	कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्नीक (सीडीटीपी)	1301
2.	टेक्निकल एजुकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम (टीईसीओएस)	4938
3.	क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीएसटीएस)	10323
	कुल संख्या	16562

(ग) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार वर्ष 2017–18 में इन तीनों स्कीमों का कुल आबंटित बजट 109.73 करोड़ है; और

(घ) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत सूचना अनुसार फरवरी, 2018 तक बजट (संशोधित एस्टीमेट) का कुल 94.17 प्रतिशत खर्च हो चुका है।

(ङ) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत सूचना अनुसार स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार किया जा रहा है यह कोई नया स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं है।

(च) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत सूचना अनुसार चूंकि, स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों को आयोजन पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार किया जा रहा है अतः इससे सम्बन्धी कोई फाइल किसी अधिकारी के पास लंबित नहीं है।

(छ) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार चूंकि अभी मार्च का महीना बाकि है और बजट में अतिरिक्त खर्चा होने की संभावना है, इसलिए लागू नहीं।

356- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सकीय व जन स्वास्थ्य नीतियों के लिए निर्देशक दस्तावेज क्या हैं व रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए तत्संबंधी मूलभूत ढांचा संबंधी विकास की स्थिति क्या है, इनकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं जिसमें दस्तावेजों की अनुक्रमणिका व उनके जारी किए जाने और लागू किए जाने की तिथियां सम्मिलित हों;

(ख) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों की सूची प्रदान करें जिसमें प्रत्येक अस्पताल के एम.एस., डिप्टी एम.एस. के नाम, टेलीफोन नंबर तथा

पता, उनमें मौजूद विभागों का ब्यौरा, बिस्तरों की संख्या, यदि बिस्तरों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित है तो उसकी जानकारी सम्मिलित हो;

(ग) यह भी बताएं कि क्या उक्त सभी अस्पतालों में पर्याप्त मेडीकल और नॉन मेडीकल स्टॉफ है;

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक में कितनी रिक्तियां हैं और उन्हें भरे जाने की अंतिम तिथि क्या है; और

(ङ) उक्त अस्पतालों में से प्रत्येक में औसतन कितने व्यक्ति रोज़ आते हैं और पिछले तीन वर्षों में इनकी संख्या में कमी आई है या वृद्धि हुई है;

(च) अस्पतालों, पोली क्लीनिकों व मोहल्ला क्लीनिकों की विधानसभा क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध कराएं;

(छ) मोहल्ला क्लीनिक और पोलीक्लीनिक स्थापित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ज) उक्त नीति के अनुसार जिन विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक या पोलीक्लीनिक अपेक्षित संख्या से कम हैं, वहां उन्हें पूरा करने के लिए क्या नीति है;

(झ) नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में निर्धारित/प्रार्थित स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के निर्माण से संबंधित विवरण व उन्हें पूरा कर लिए जाने और उद्घाटन की अनुमानित तिथि क्या है;

(ञ) केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा हौजरानी में जन कल्याण सुविधा स्थानित करने के लिए दी गई संपत्ति, जहां पर

प्रश्नकर्ता विधायक, ने मोहल्ला क्लीनिक बनाने का अनुरोध किया था; की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ट) मालवीय नगर स्थित मदनमोहन मालवीय अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण क्या है;

(ठ) क्या पिछले छह महीने में इस अस्पताल में कोई सर्जरी की गई है;

(ड) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और इस अस्पताल में कंसल्टेंट सर्जन कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा;

(ढ) क्या वरिष्ठ रेजीडेंट डॉक्टर को कंसल्टेंट सर्जन के रूप में काम करने के लिए कहा जा सकता है;

(ण) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में;

(त) रोगीकल्याण समिति की स्थिति क्या है, क्या इसके सभापति का पद 'लाभ का पद' है, जिससे विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है;

(थ) रोगी कल्याण समिति को अस्पतालों के सुधार के लिए दंडात्मक निर्णय सहित सभी निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए किए जाने वाले संशोधनों की स्थिति क्या है;

(द) सभी रोगी कल्याण समितियों और विशेषकर मदनमोहन मालवीय अस्पताल में स्थित रोगी कल्याण समिति में सदस्यों को बदले जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ध) मदनमोहन मालवीय अस्पताल में कार्यरत सभी अनुबंधित तथा कर्मचारियों की सूची, उनका कार्यक्षेत्र, नियुक्ति की तिथि व उनके कार्यनिष्पादन की यदि कोई जांच की गई हो तो उसके ब्यौरे सहित सूची उपलब्ध कराएं?

LokLF; e=h ¼ (क) समय–समय पर सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सकीय एवं जन स्वास्थ्य नीतियां बनाई जाती हैं तथा मंत्रीपरिषद एवं माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति पश्चात् नीतियां लागू की जाती हैं।

मूलभूत ढांचा संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वर्तमान स्थिति 'ख' अनुसार संलग्न है।

(ख) सूची संलग्न है। (संलग्नक–5)*

(ग) पर्याप्त है, लेकिन जब कभी सेवानिवृत्त और पदोन्नित के कारण रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भरी जाती है। अतिरिक्त मांग के लिए नये पद अस्पताल की आवश्यकतानुसार सृजित किये जाते हैं। यह 'सर्विसेस' का मामला है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

(ङ) उपरोक्त 'ख' की सूची में स्तम्भ 'के' एवं 'एल' में वर्णित है।

(च) अस्पतालों की विधान सभा वार सूचि उपलब्ध नहीं है। पॉलीक्लीनिकों की सूचना संलग्न '1' में संलग्न है। मौहल्ला क्लीनिकों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्नक '1ए' में संलग्न है।

(छ) इस विषय में दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति संलग्नक '2' व '3' में संलग्न है।

---

* सभी संलग्नक www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

सरकारी विभागों से जमीन की एन.ओ.सी. लेने के उपरान्त मुख्य जिला अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ भूमि निरीक्षण करते हैं। हर मौहल्ला क्लीनिक 10000–15000 आबादी के साथ जुड़ा होता है। सही पाये जाने पर यह भूमि पीडब्ल्युडी को निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है। निर्माण के बाद ये मौहल्ला क्लीनिक मुख्य जिला अधिकारी को चलाने के लिए दे दिया जाता है। (संलग्न–4)

(ज) विधान सभा क्षेत्रानुसार पोलिक्लीनिक खोलने की दिल्ली सरकार की कोई नीति नहीं है।

जिन विधान सभा क्षेत्रों में मौहल्ला क्लीनिक कम होते है, कोशिश होती है कि चुनिन्दा मौहल्ला क्लीनिक में निर्माण कार्य वहां पहले आरम्भ हो और जल्द पूरा हो।

(झ) नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में नई स्वास्थ्य सेवाएं/अपग्रेड होने वाली स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित है–

1. दिल्ली सरकार औषधालय, चिराग दिल्ली (अपग्रेड करके पोलीक्लीनिक बनाने हेतु), आज की स्थिति में अपग्रेड करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

2. नारायणा विहार (नई पोलीक्लीनिक)– खाली भूमि पर नई पोलीक्लीनिक खोलने की नीति विचाराधीन है।

(ञ) मौहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए जगह निरीक्षण करने के पश्चात् मौहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए एनओसी दो बार भूमि स्वामित्व विभाग को भेजा गया है और प्रक्रिया जारी है।

(ट) विभिन्न विशेषता वाले विभागों को ओ.पी.डी. सेवाएं उपलब्ध हैं। इन्डोर सेवाओं के लिए विभिन्न विशेषताओं की आवश्यकतानुसार 103 बिस्तर क्रियान्वित हैं।

इसके अलावा आकस्मिक सेवाएं, लेबर रूम एवं नर्सरी सेवाएं उपलब्ध हैं। दो मेजर ओ.टी. एवं तीन माइनर ओ.टी. भी उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार के पैथोलॉजिकल जांच के लिए लैब सेवाएं भी उपलब्ध है।

(ठ) इस अस्पताल में पिछले 6 महीने में माइनर सर्जरी 875 और मेजर सर्जरी 737 की गयी है।

(ड) उपरोक्त 'ठ' के अनुसार लागू नहीं है।

(ढ) यह 'सर्विसेस' से संबंधित मामला है।

(ण) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(त) रोगी कल्याण समिति आदेश दिनांक 23.03.2016 के अनुसार गठित की गई जो इसके वाइलॉज के तहत काम करती है। लाभ के पद की परिभाषा एवं सूची स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(थ) पं. मदनमोहन मालवीय अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के कुछ सदस्यों को बदलने का प्रस्ताव दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन में भेजा गया था। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्रश्न उठाया है कि क्या बदले जाने वाले सदस्यों में अपना त्यागपत्र दिया है, और यह मामला दिनांक 15.03.2018 को आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक में रखा गया था।

(द) यह 'सर्विसेस' से संबंधित मामला है।

357- Jh iadt iq"dj % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स, तिमारपुर में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कौन–कौन सी क्लीनिक चल रहे है;

(ख) प्रत्येक क्लीनिक में से कुल कितना स्टाफ स्वीकृत है और कितना कार्यरत है? नाम, पदनाम और फोन नम्बर सहित विवरण दें;

(ग) प्रत्येक क्लीनिक में रोस्टर पर उपलब्ध होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों का 1 अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक का विवरण क्या है;

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक सप्ताह उपस्थित रहे विशेषज्ञ डॉक्टर का उनके नाम, पदनाम और उनकी उपलब्धता के दिनों के साथ विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान पर चलने वाली पॉलीक्लिीनिक में पहले शाम को भी बाहरी रोगियों को देखने की सुविधा थी;

(च) क्या शाम को बाहरी रोगियों को देखने की सुविधा को कुछ समय पहले बन्द कर दिया गया;

(छ) यदि हां, तो क्लीनिक में शाम में ओपीडी कब पुनः चालू की जा सकेगी;

(ज) प्रत्येक क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाएं, होने वाली जांच एवं उपलब्ध दवाईयों की सूची क्या है; पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं; और

(झ) 01 अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक पाली क्लीनिक में मरीजों की जो जांच परीक्षण निःशुल्क करवाए गए, उनका विवरण क्या है? (अलग–अलग प्रति माह का आंकड़ा प्रस्तुत करें।)

LokLF; e=h % (क) तिमारपुर डिस्पेंसरी में अरूणा असिफ अली अस्पताल की मदद से विभिन्न क्लीनिक चल रहे हैं:– मेडिसिन, सर्जरी, ओर्थो, स्त्री रोग, शिशु रोग। इसके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और मनोचिकित्सा विभागों की सुविधा भी उपलब्ध हैं।

(ख) तिमारपुर डिस्पेंसरी के स्वीकृत कर्मचारियों की सूचना संलग्न है। अरूणा असिफ अली अस्पताल में क्लीनिक चलाने के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी स्वीकृत नहीं हैं अस्पताल अपने स्वीकृत कर्मचारियों में से ही कुछ चिकित्सकों को रोस्टर द्वारा तिमारपुर पोली क्लीनिक भेजता है।

(ग) और (घ) 01.04.2017 से 31.01.2018 तक विभिन्न स्पेशलिस्टों की उपस्थिति निम्नलिखित है:–

मेडिसिन–99(मंगलवार/बृहस्पतिवार/शनिवार)

सर्जरी – 41 (शुक्रवार)

ओर्थो – 40 (बुधवार)

स्त्री रोग – 78 (सोमवार/शनिवार)

शिशु रोग – 105 (सोमवार/बुधवार/शनिवार)

(ङ) हां।

(च) हां, सितंबर, 2017 से ये सुविधा चिकित्सा अधिकारी की कमी के कारण स्थगित कर दी गई थी।

(छ) शाम को ओ.पी.डी. चिकित्सा अधिकारी की उपलब्धता एवं पोली क्लीनिक के नवीनीकरण के उपरांत शुरू कर दी जाएगी।

(ज) सूची संलग्न है।

(झ) सूची संलग्न है।*

358- Jh _rjkt xkfon % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य मंत्री विभाग द्वारा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का विवरण क्या है; और

(घ) उन स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक कब तक खोल दिया जायेगा?

LokLF; ea=h % (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 10 स्थानों की सूची संलग्न है।

(घ) सभी उचित मौहल्ला क्लीनिक 8 महीने में तैयार हो जाएंगे।

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

As per list received from State Nodal Officer, AAMC Project of Mohalla Clinics in Kirari Vidhan Sabha

Sl. No.	List of Mohalla Clinics in Kirari
1.	Kirari 40 - Nithari DDA Land Inder Enclave Baljeet Vihar Bus Stand
2.	DDA Land E-Block, Agar Nagar Pond Gram Sabha, Kirari
3.	Kirari 41 - Aman Vihar DDA Land Pratap vihar Part-III
4.	DDA Land Kirari Bear Kailash Vihar Kirari
5.	Kirari 43 - Prem Nagar Tripathi Enclave DDA Land
6.	RST Block near main drain Durga Chowk, Kirari
7.	Kirari 44-Mubarakpur Dabas Vacant land near Bus Stand
8.	Kirari, Laxmi Vihar
9.	DJB office, Mubarakpur, Dabas Village, Kirari
10.	DJB Pumping Station, Niti Vihar, Kirari

359- Jh vt;'k ;kno % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने मोहल्ला क्लीनिक बनाये गये हैं;

(ख) बादली विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने पॉली क्लीनिक बनाये गये हैं;

(ग) बादली विधानसभा क्षेत्र में कितने और मोहल्ला क्लीनिक व पॉली क्लीनिक बनाने की योजना है;

(घ) बादली विधानसभा क्षेत्र में किन स्थानों पर, कब तक ये क्लीनिक बनाये जायेंगे; और

(ङ) अब तक बादली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी मोहल्ला क्लीनिक या पॉली क्लीनिक न बनाये जाने के क्या कारण है;

LokLF; ea=h % (क) बादली विधानसभा क्षेत्र में एक मौहल्ला क्लीनिक किराये पर चल रहा है।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) बादली विधानसभा क्षेत्र में 06 मौहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है और एक पॉली क्लीनिक बनाने की योजना है।

(घ) 06 स्थानों की सूची संलग्न है।

(ङ) एक मौहल्ला क्लीनिक चल रहा है। उपर्युक्त भूमि और भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण बादली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पॉली क्लीनिक नहीं बनाया जा सका।

Sl. No.	Badli List
1.	DJB Je (Water) Office, Mandir, Mohalla, Badli
2.	DJB Booster Pumping Station, Sanjay Gandhi Transport Nagar, Delhi-42
3.	DJB UGR & Booster Pumping Station, Bhatta Road, Gali No. 15, Swaroop Nagar, Delhi-42

Sl. No.	Badli List
4.	DJB UGR & Booster Pumping Station, CD Park Jahangirpuri, Delhi
5.	Samaypur Badli Metro, Ground Floor area in front of Pump Room By the side of under pass of samaipur Badli
6.	Haiderpur Metro, Ground floor in front of pillar No. 195

360- Jh fo'k"k jfo % क्या LokLF; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एन.सी. जोशी अस्पताल में कोई जच्चा बच्चा वार्ड तैयार होने के बावजूद बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त वार्ड कब से कार्य करना शुरू कर देगा?

LokLF; e=h % (क) जी हां, यह सत्य है कि जच्चा बच्चा वार्ड की बिल्डिंग तैयार है।

(ख) यह वार्ड पिछले साल 2017 में तैयार हो गया था परन्तु स्टाफ की कमी के कारण यह वार्ड कार्य नहीं कर पा रहा है।

(ग) स्टाफ की भर्ती हेतु दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ प्रक्रिया चल रही है। स्टाफ की भर्ती होते ही उक्त वार्ड कार्य करना शुरू कर देगा।

361- Jh j?kfoUnz 'kkdhu % क्या LokLF; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगलोई विधानसभा के अंतर्गत ज्वालापुरी में बनने वाले अस्पताल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अस्पताल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) अस्पताल का निर्माण कार्य कब पूरा होगा?

LokLF; ea=h % (क) ज्वालापुरी अस्पताल परियोजना (नांगलोई विधान सभा) के संबंध में 600 बेड का अस्पताल बनाने के लिए सलाहकार परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी है और अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा अस्पताल निर्माण के संबंध में सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा (tender) किया जाना है।

(ख) पीडब्ल्यूडी द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के बाद अस्पताल निर्माण शुरू करने की तारीख का निर्णय लिया जाएगा।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

362- Jh iou dqekj 'kekZ % क्या LokLF; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य सचिव के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे हैं;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दौरा किया है;

(ग) वर्षवार प्रत्येक दौरे के तिथि, इन्सपेक्शन रिपोर्ट और एक्शन–टेकन रिपोर्ट भी प्रदान करें?

LokLF; ea=h % (क) विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य सचिव के पद पर रहे अधिकारी निम्नवत है:

क्रम सं.	वर्ष	अधिकारी का नाम
1.	2013–2014	श्री एस.सी.एल. दास (अक्तूबर, 2012 से मई, 2015 तक)
2.	2013–2015	श्री एस.सी.एल. दास (अक्टूबर, 2012 से मई, 2015 तक)
3.	2015–2016	श्री अरून बरूका (मई, 2015 से जून, 2015 तक)
		श्री अमरनाथ (01.05.2015 से 03.06. 2016 तक)
4.	2016–2017	श्री तरूण सीमा (फरवरी, 2016 से अगस्त, 2016 तक)
		श्री चन्द्राकर भारती (अगस्त, 2016 से जनवरी, 2017 तक)
5.	2017–2018	श्री मधूप व्यास (जनवरी, 2017 से सितम्बर, 2017)
		श्री राजीव यदुवंशी (सितम्बर, 2017 से अब तक)

(ख) इन अधिकारियों ने कार्यकाल के दौरान किये गये दौरे निम्नवत् हैं।

वर्ष 2013 से जून, 2015 के दौरान सचिव (स्वास्थ्य) ने किसी भी स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रों का दौरा नहीं किया है।

वर्ष जुलाई, 2015 में श्री अमर नाथ सचिव (स्वास्थ्य) ने केवल 01 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक जो पीरागढ़ी में स्थित है का 07.07.2015 को दौरा किया। इससे संबंधित ब्यौरा दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।

वर्ष अगस्त, 2015 से सितम्बर, 2017 के दौरान कार्यरत किसी भी स्वास्थ्य सचिव ने किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र दौरा नहीं किया।

वर्ष सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान पदासीन अधोहस्ताक्षरी ने 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आम आदमी मौहल्ला क्लिनिकों का निम्नलिखित दिनांक में दौरा किया:–

23.09.2017	–	दिलशाद गार्डन डिस्पेंसरी
23.09.2017	–	सीमापुरी डिस्पेंसरी।
23.09.2017	–	विवेक विहार मौहल्ला क्लीनिक।
17.02.2018	–	1. रोहिणी सेक्टर–16 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		2. रोहिणी सेक्टर–17 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		3. घेवर विलेज आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		4. निजामपुर आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
28.02.2018	–	हाई कोर्ट, डी.जी.डी.

(ग) दौरे की तिथि कालम ख अनुसार है इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न है। इन दौरों के दोरान कार्यप्रणाली में कोई खामी पाई जाती है तो तुरन्त संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश दिये जाते हैं। संबंधित अधिकारी संबंधित फाइल में उन सभी खामियों एवं मुद्दों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण होता है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE PR, SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)
9TH LEVEL, A WING, DELHI SACHIVALAYA, IP ESTATE,
NEW DELHI-2

Ph: 011-23392017; Fax: 011-23392464; email: pshealth@nic.in

INSPECTION REPORT

This is with reference to Circular No. 19/16/AR/2016/Misc/PF-3/4354-4443, dated 02/06/2017, the undersigned went on inspection to below mentioned Aam Admi Mohall Clinics (AAMC):

1. Inspected AAMC at Sector 16, Rohini, Near Sukhdev Management College, Delhi-85, on 17/02/2018 from 12.00 noon to 12.30 pm.
2. Inspected AAMC at Sector 17, Rohini, Near TPDDL Office, Delhi-85 on 17/02/2018 from 12.30 pm to 1.00 PM
3. Inspected AAMC at Village Ghevra on 17/02/2018 from 0135 PM to 02.00 pm
4. Inspected AAMC at Village Nizampur on 17/02/2018 from 02.15 PM to 3.00 PM

(RAAJIV YADUVANSHI)
Pr. Secretary (Health & FW)

Secretary (AR)

Nc.. PS/HFW/2017/prsecyhfw/235 Date: 19/02/2018

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG
2. Spl. Secretary to Hon'ble CM
3. OSD to Chief Secretary

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE PR, SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)
9TH LEVEL, A WING, DELHI SACHIVALAYA, IP ESTATE,
NEW DELHI-2

Ph: 011-23392017; Fax: 011-23392464; email: pshealth@nic.in

INSPECTION REPORT

This is with reference to Circular No. 19/16/AR/2016/Misc/PF-3/4354-4443, dated.02/06/2017/the undersigned went on inspection to below mentioned Hospital:

1. Inspected Delhi High Court Medical Centre/DGD (Delhi High Court) on 28/02/2018 from 04.00 pm to 04.45 pm.

(RAAJIV YADUVANSHI)

Pr. Secretary (Health & FW)

Sectary (AR)

No. PS/ HFW/ 2017/ prsecyhfw/248 Date: 05/03/2018

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG
2. Spl. Secretary to Hon'ble CM
3. OSD to Chief Secretary

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE PR, SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)
9TH LEVEL, A WING, DELHI SACHIVALAYA, IP ESTATE,
NEW DELHI-2

Ph: 011-23392017; Fax: 011-23392464; email: pshealth@nic.in

INSPECTION REPORT

1. Inspection of the dilapidated building of Dilshad Garden, B-block Dispensary at 9 A.M. on 23/09/2017
2. Inspection of old dispensary to ease congestion and up gradation for polyclinic at 9.30 AM on 23/09/2017
3. Inspection of Vivek Vihar Poly Clinic for congestion issues at 10.00 AM on 23/09/2017

(RAAJIV YADUVANSHI)

Pr. Secretary (Health & FW)

Sectary (AR)

No. PS/ HFW/ 2017/ prsecyhfw/160-63 Date: 23/09/2017

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG
2. Spl. Secretary to Hon'ble CM
3. OSD to Chief Secretary

363- Jh vf[ky'kifr f=ikBh ¼ क्या LokLF; eU=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने 08 अप्रैल, 2016 को भारत का राजपत्र (गजट) के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कचरे को अलग–अलग इकट्ठा करने और कम्पोस्ट या बायोगैस से कचरे के निष्पादन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) यदि हां तो उपरोक्त के संदर्भ में सरकार की कार्य योजना है;

(ग) कौन सी एजेंसी इसके लिए निर्धारित की गई है;

(घ) कौन इसकी मॉनियटरिंग करेगा;

(ङ) गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से कचरे का निष्पादन किया जाना कब से सुनिश्चित किया जाएगा, विवरण दें; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त नोटिफिकेशन का अनुपालन करवाना किस निकाय का दायित्व है;

'kgjh fodkl eU=h ¼ (क) जी हां।

(ख) 1. दिल्ली के लिए ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी राज्य सरकार की नीति/कार्यनीति की अधिसूचना 3 नवंबर, 2017 को जारी की गई है।

2. ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत अधिसूचना 15 जनवरी 2018 स्थानीय निकायों हेतु जारी की गई है।

(ग) यह कार्य स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) स्थानीय निकायों द्वारा कचरे का निष्पादन जारी है।

(च) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

364- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या m|kx e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए वांछित प्रक्रिया का विवरण प्रदान करें जिसमें अधिकारी का नाम, फोन नंबर अपेक्षित दस्तावेज, देय शुल्क (यदि कोई हो) तथा संपूर्ण प्रक्रिया में लगने वाला समय सम्मिलित हो;

(ख) घरेलू उद्योग में घरेलू की परिभाषा क्या है;

(ग) आधुनिक तकनीक व विभिन्न प्रकार की प्रगति को देखते हुए इस परिभाषा पर पुनर्विचार किए जाने की प्रक्रिया का विवरण क्या है;

(घ) जब अंतिम बार घरेलू शब्द को परिभाषित किया गया था; तत्संबंधी फाइल उपलब्ध कराएं;

(ङ) विभाग में पंजीकृत उद्योगों का जोन के अनुसार विवरण क्या है तथा उन उद्योगों द्वारा देश के कानूनों, नियमों और विनियमों के संदर्भ में अनुपालन की आज की स्थिति का विवरण क्या है;

(च) क्या दिल्ली सरकार की कोई उद्योग नीति है; और

(छ) यदि हां, तो उसकी एक प्रति समस्त संशोधनों और संबंधित सर्कुलरों सहित उपलब्ध कराएं?

m|kx e=h % (क) दिल्ली में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कोई भी इच्छुक उद्यमी संबंधित नगर निगम में लघु उद्योग व घरेलू उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकता है और अगर वह उद्यमी घरेलू उद्योग की परिभाषा में आता है तो संबंधित नगर निगम इसके आवेदन को निरिक्षण के बाद, हॉई पावर कमेटी में अनुशंसा के लिए लगाता है तथा हॉई पावर कमेटी की अनुशंसा के बाद लाइसेंस संबंधित नगर निगम द्वारा जारी कर दिया जाता है।

mRrjh uxj fuxe %&

lcaf/kr vf/kdkjh %&

श्री पंकज शर्मा, सहायक आयुक्त, फैक्ट्री लाईसेंसिंग विभाग, 11वां तल सिविक सेंटर नई दिल्ली,
दूरभाष नं 011–23226107,
देय शुल्क :– 550 रुपये

iwohZ uxj fuxe %&

lcaf/kr vf/kdkjh %& उपायुक्त, फैक्ट्री लाईसेंसिंग विभाग, 419 उद्योग सदन, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110092

दूरभाष नं 011–66667586,

देय शुल्क :– 5000 रुपये

वर्ष के लिए तथा रुपए 10,000 तीन वर्ष के लिए।

दक्षिणी नगर निगम में ऑनलाइन घरेलू उद्योग लाइसेंस प्रदान करने की नीति अभी स्थायी समिति की पुनर्विचार कमेटी के अंतर्गत विचाराधीन है।

(ख) ऐसे उद्योग जो निम्नलिखित शर्तों के साथ मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के तहत घरों में चलाने हेतु निर्दिष्ट किये गये, उन्हें घरेलू उद्योग माना गया है:—

1. घरेलू उद्योगों की सूची दिल्ली के मास्टर प्लॉन 2021 के अनुच्छेद 1 (अध्याय—7) पर उपलब्ध है।
2. घर के कुल क्षेत्रफल के 50 से ज्यादा औद्योगिक उपयोग नहीं होना चाहिये।
3. 5 लोगों से ज्यादा उद्योगों में कार्यरत नहीं होने चाहिये।
4. 5 किलोवाट से ज्यादा बिजली का उपयोग नहीं होना चाहिये।
5. कोई भी उद्योग जल एवं वायु प्रदूषण मुक्त होना चाहिये।
6. ध्वनि प्रदूषण तक मानक के अनुसार होना चाहिये।*

संबंधित मास्टर प्लान की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) परिभाषा में बदलाव हेतु डीडीए का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् दिल्ली डवलपमेंट एक्ट की धारा 11 (क) के तहत प्रक्रिया पूरी कर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही इस संबंध में मास्टर प्लॉन 2021 से संबंधित अध्याय में संशोधन की अधिसूचना जारी की जाती है।

(घ) अंतिम बार घरेलू शब्द दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में 7.2.2007 को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

---

*पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर—20423 पर उपलब्ध।

(ङ) उद्योग विभाग में उद्योंगों को जोन के अनुसार आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। न ही उद्योग विभाग को उद्योग को उद्योगों को विनियमित करने की कोई जिम्मेदारी दी गई है।

(च) जी हां।

(छ) औद्योगिक नीति की प्रतिलिपि संलग्न है।

Chapter-7 (MPD-20121)

	Use Zone / Use Premises	Groups Permitted (Refer Annexure)	Conditions	
			Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)
b)	Flatted Industries	All industries except those prohibited, and of Non-polluting &non-hazardous nature, excluding industries producing noise / water / vibrations / odour pollution	20	As per need

Notes:

i) Maximum no. of workers shall be as per notification issued by the competent authority from time to time.

ii) The power requirement for operating pollution control devices and non-manufacturing use shall be over and above the aforesaid permissible load.

iii) Existing Industrial Estates in the Growth Centres shall be considered as industrial use.

7.4 Household / Service Industries

i) Household industrial units with maximum 5 workers and 5 kilowatt power may be allowed to continue in residential areas and new industrial units of this type could be pemiitted in residential areas subject to the condition that no polluting industrial unit shall be permitted as household industry.

ii) The industrial units could be permitted only after provisional registration by the Govt. of NCTD.

iii) Household industrial units shall be allowed on any floor to the extent of 50% of permissible floor area of the dwelling unit.

iv) Further additions / alterations to the list of Household Industries could be made, if considered appropriate and in public interest by the Central Government to do so.

v) No inflammable or hazardous substance is permitted to be stored.

vi) Separate industrial electric connection (single phase) and Municipal License, would be necessary to set up a household industry.

7.5 No Industrial Activity Zone

In order to maintain the city's ambience and pollution free environment in important and historic areas of Delhi, following locations are categorized as 'No Industrial Activity Zone' where no industrial activity including household industry, shall be permitted.

a) Lutyens' Bungalow Zone

b) Civil Lines Bungalow Area

c) Employer Housing

d) Group Housing (excluding Janata Flats)

365- I|Jh Hkkouk xkM+ % क्या m|kx ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय लाईसेंस शुदा और बगैर लाईसेंस के चलने वाली फैक्टरियां की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कितनी फैक्टरियां को लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ग) उद्योग विभाग की अनुमति के बिना चल रही फैक्टरियों के, वर्ष 2015 से अब तक कुल कितने चालान किए गये हैं;

(घ) उपरोक्त चालानों से अब तक दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ङ) अवैध रूप से चलने वाली फैक्टरियों में से, वर्ष 2015 से अब तक कितने मामलों में पानी एवं बिजली के कनेक्शन काटे गये हैं; और

(च) इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

m|kx ea=h % (क) प्राप्त सूचना के अनुसार लाइसेंस शुदा फैक्टरियों की संख्या :–

1. दक्षिणी नगर निगम – 3456
2. उत्तरी नगर निगम – दिनांक 01.04.2016 से बिना लाइसेंस के चलती पायी गई फैक्ट्ररियों की संख्या–1214
3. पूर्वी नगर निगम–10977

(ख) उद्योग विभाग में फैक्ट्री लाईसेंस जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता।

(च एवं छ) दक्षिणी नगर निगम ने 826 मामलों में, उत्तरी नगर निगम ने 1214 मामलों में तथा पूर्वी नगर निगम ने 2843 मामलों में औद्योगिक इकाईयों के बिजली पानी काटने के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी किये हैं।

366- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या fof/k ,oa U;k; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में दिल्ली की जेलों में किए सुधारों का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) दिल्ली की जेलों की क्षमता और उनमें मौजूद कैदियों के बारें में विवरण प्रदान करें, इन दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है।

(ग) जो कैदी वकीलों की फीस नहीं दे सकते उनके लिए कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने संबंधी विवरण क्या है; और

(घ) विभिन्न जेलों में जो विचाराधीन कैदी सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में बंद हैं, उनका वर्षवार संपूर्ण विवरण क्या है?

fof/k ,o U;k; e=h % (क) दिल्ली की जेलों में पिछले तीन वर्षों में किए सुधारों का विवरण संलग्न (क) है।

(ख) दिल्ली में उपस्थित 16 जेलों की कुल क्षमता – 10026 है। दिनांक 20.03.2018 को कुल बन्दियों की संख्या–15041 है। इन दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए:–

1. दिल्ली कारागार विभाग द्वारा मण्डोली (उत्तर–पूर्व दिल्ली) में छः नई जेलों को आरंभ किया गया है।

2. वे बन्दी जिनको न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान कर दी गई है परंतु किसी कारणवश वे अपनी जमानत प्रदान कर दी गई है परंतु किसी कारणवश वे अपनी जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं उसके समाधान के लिए लगातार न्यायालय को सूचित किया जाता है।

3. लोक अदालत लगाई जाती है जिसमें जो बन्दी छोटे अपराध में बन्द होते हैं उन्हें कम से कम सजा देकर दोबारा अपराध करने की जमानत पर रिहा किया जाता है।

4. 436 सी.आर.पी.सी. के आधार पर उन बंदियों की सूचना अदालत को भेजी जाती है जो अपने संभावित सजा का आधे से ज्यादा समय जेलों में बिता चुके होते हैं।

5. सेमी ओपन जेलों का निर्माण किया गया है।

6. कैदियों को समय–समय पर पैरोल एवम फरलों पर रिहा किया जाता है।

(ग) जो कैदी वकीलों को फीस देने में असमर्थ होते हैं उनको दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्राधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान कार्रवाई जाती है।

(घ) दिल्ली कारागार विभाग में सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में बंद विचाराधीन बन्दी का वर्षवार विवरण अनुरक्षित नहीं किया जाता है। दिनांक 20.03.2018 तक सात वर्ष से कम सजा वाले कुल 1165 विचाराधीन बन्दी बंद हैं।

fnYyh dkjkxkj dh J"B xfrfof/k;k

दिल्ली कारागार के अंतर्गत 16 केन्द्रीय कारागार हैं जिनमें से 09 कारागार तिहाड़ में है, 01 रोहिणी में और 06 मंडोली में हैं जिनकी कुल आवास क्षमता 10028 हैं। आज दिनांक 20.03.2018 को सभी कारागार संचालित हैं जिनमें वर्तमान में कुल 15041 बंदी आवासित हैं। बंदियों के सुधार एवं पुर्नवास के लिए अनेक सुधारात्मक कार्यक्रम किये जा रहे हैं जिनमें से प्रमुख निम्न है:

1- f'k{kk &

^i<k vkj i<kvk* % दिल्ली कारागार में शैक्षणिक गतिविधियों दैनिक कार्यक्रमों की अभिन्न भाग हैं। ये विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों जैसे निरक्षर, पूर्णतया निरक्षर, अर्द्ध साक्षर, साक्षर और ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के इच्छुक हैं के लिए संचालित किये जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, के सहयोग से दिल्ली

कारागार में विस्तृत शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरुप साक्षरता दर 40 प्रतिशत से करीब पांच प्रतिशत रह गई है। बंदियों को कंप्यूटर संचालन में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल नं. 5 में किशोर बंदियों के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट अथार्टी ऑफ इंडिया व गैर सरकारी संस्थानों जैसे टाईसिया, प्रोत्साहन आदि के सहयोग से एक उच्च स्तरीय स्कूल स्थापित किया जा रहा है।

2- vkfFkd fuokg ;kstuk % एक नई योजना शीर्षक 'बंदी अभिभावकों के बच्चों के कल्याण, शिक्षा और आर्थिक निर्वाह के लिए योजना 2014' क्रियान्वित हो रही है। इस योजना का प्रारुप दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है बंदी अभिभावकों के बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए।

3- 0;kolkf;d izf'k{k.k % दिल्ली कारागार में बंदियों के सुधार व पुर्नवास के उद्देश्य से, उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न हस्त कौशल में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे कारपेंटरी, कागज निर्माण, बुनाई, साबुन निर्माण, बेकरी उत्पाद, कृत्रिम पुष्प निर्माण, बैग निर्माण आदि। इसके अतिरिकत रेडिया जॉकी की कला में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। पेंटिंग/चित्रकला को बंदियों के लिए व्यवसाय के रुप में विकसित करने के लिए आर्ट गैलरी स्थापित की गई।

4. बंदियों के मनोरंजन व अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। तिहाड़ ओलंपिक शीर्षक से दिल्ली कारागार में अंतर जेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता

है। दिल्ली कारगार में क्रिकेट अकादमी स्थापित की गई है जिसमें नामी प्रशिक्षक के दिशानिर्देशन में प्रतिभाशाली खिलाड़ी बंदियों के कौशल को और अधिक निखारा जाता है।

5. बंदियों की आवास सुविधा में वृद्धि करते हुए मंडोली में 06 कारागार आरंभ की गई जिससे बंदियों के जीन के रहन सहर के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

6. सेमी ओपन जेल योजना को विस्तार देते हुए ओपन जेल की व्यवस्था स्थापित की गई है। सेमी ओपन जेल का विस्तार करते हुए तिहाड़ जेल के अतिरिक्त मंडोली जेल में सेमी ओपन जेल स्थापित की गई ताकि अधिक से अधिक बंदियों को वहां आवासित किया जा सके। ओपन जेल के बंदियों को कारागार से बाहर रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

7. बंदियों को फरलो सुविधा के विषय में जागरुक करते हुए उन्हें अधिक से अधिक फरलो व पैरोल सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

8. बंदियों को तनावरहित करने में फोन कॉल सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक इच्छुक बंदी को पूर्वघोषित फोन नंबर पर प्रतिदिन 5 मिनट फोन करने की सुविधा उपलब्ध है।

367- Jh _rjkt xkfon % क्या Hkfe ,o Hkou e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में डी.डी.ए. की जमीन का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक प्रत्येक वित्त वर्ष में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में दिल्ली प्राधिकरण की जमीन पर विभाग की क्या कार्य योजना है?

Hkfe ,o Hkou foHkkx e=h % (क) से (घ) संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

368- Jh fo'k"k jfo % क्या lkekU; i'kklu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सचिवालय में विधायकों की बैठने की क्या व्यवस्था है;

(ख) दिल्ली सविचालय में विधायकों द्वारा मीटिंग लेने की क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या दिल्ली सचिवालय में विधायकों के बैठने के लिए एमएलए लॉज बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो यह लॉज कब तक तैयार हो जाएगी;

(ङ) दिल्ली सचिवालय में विधायकों के लिए गाड़ी पार्क करने की क्या व्यवस्था है;

(च) सचिवालय में जहां माननीय मंत्रीगणों की गाड़ियां पार्क होती हैं, क्या वहां विधायकों को गाड़ी पार्क करने की अनुमति है;

(छ) दिल्ली सचिवाय में जहां मंत्रिगणों की गाड़िया खड़ी होती हैं, उसके अलावा कुल कितनी गाड़ी खड़ी करने का पार्किंग स्पेस है;

(ज) दिल्ली सचिवालय में किस श्रेणी के अधिकारियों को यहां गाड़ी पार्क करने की अनुमति है;

(झ) ऐसी श्रेणी के अंतर्गत दिल्ली सरकार के कितने अधिकारी आते हैं; और

(ञ) क्या दिल्ली सचिवालय में विधायकों के लिए उपयुक्त कर पार्किंग बनाने की कोई योजना है?

lkekU; iz'kklu ea=h % (क) आगंतुक विधायक जन मंत्री से मिलना चाहते हैं उनके कार्यालय के प्रतीक्षा स्थल पर बैठ सकते हैं।

(ख) पूर्ववर्ती सूचना के द्वारा दिल्ली सचिवालय के कांफ्रेंस रूप को बुक किया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 7 के विपरीत विधायक पार्किंग एरिया में विधायकों के लिए गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था है।

(च) जी नहीं। लेकिन वहां पर विधायक गाड़ी ला सकते हैं, यदि पार्किंग की जगह हो तो गाड़ी पार्क कर सकते हैं और अगर वहां जगह नहीं है तो गाड़ी को अधिकारियों की गाड़ी की पार्किंग की जगह खड़ी कर सकते हैं।

(छ) लगभग 10 से 12 अतिरिक्त गाड़ियों का पार्किंग स्पेस है।

(ज) दिल्ली सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों के सरकारी गाड़ियों के अलावा दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के गाड़ियों को भी पार्किंग की अनुमति है जिन्हें पार्किंग लेवल जारी किया गया है।

(झ) उपरोक्त (झ) के संदर्भ में करीब 550 पार्किंग लेवल जारी किए गये हैं।

(ञ) दिल्ली सविचालय गेट नंबर 7 के विपरीत विधायक पार्किंग एरिया में विधायकों के लिए गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिकत अगर जगह हो तो जहां मंत्रीगणों की गाड़ियां पार्क होती हैं, और अधिकारियों की गाड़ी पार्क होती है वहां पर भी गाड़ी खड़ी की जा सकती है।

fo'ks"k mYys[k ¼fu;e 280½

v/;{k egksn;% वापस करो, ये 280 रह जायेगा।

Jh vt;'k ;kno% चलो जी, मेरा पक्का हो गया।

v/;{k egksn;% 280, 280 शरद कुमार जी।

Jh "kjn dqekj pkSgku% हॉ जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अब डिप्टी सीएम साहब तो हैं नहीं। हॉ, मेरे यहॉ पे काफी स्कूल हैं और जगह भी काफी है। ऐसा नही है... मुझे लगता है बहुत से विधायकों के यहॉ तो स्कूलों की जगह ही नहीं है या उनके पास स्कूल खोलने के

लिए। अपने पास जगह बहुत है नरेला विधान सभा में और ग्रामीण क्षेत्र है, 40 गॉव के आस पास आते हैं। तो कहीं पे भी स्कूलों में खेलने का स्टेडियम नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए और सारा ग्रामीण क्षेत्र तो स्पोर्ट्स में भी काफी रूचि रखते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आपके तहत मैं यह कहना चाहूॅगा कि दो चार स्कूलों में मैंने लिख के भी भेजा है कि कहीं उनमें छोटे मिनी स्टेडियम टाइप के... क्योंकि बड़े बड़े स्कूल हैं; बीस बीस एकड़ में स्कूल हैं और स्कूलों की बिल्डिंग बनी हुई हैं एक या डेढ़ एकड़ में, खाली पड़े हुए हैं, तो उनमें मिनी स्टेडियम वगैरह हमारे बन सकते हैं तो आपके माध्यम से ही मैं चाहूॅगा कि दो तीन स्कूलों का अगर हो जाये तो मिनी स्टेडियम बन जाये तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, धन्यवाद।

v/;{k egksn;% अनिल बाजपेयी जी।

Jh vfuy ckt i s;h% माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूॅं कि आपने 280 के अंतर्गत मुझे बोलने का मोका दिया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गांधी नगर, एसडीएम आफिस की ओर दिलाना चाहता हूॅं जो कि आज से कई वर्ष पूर्व... छः वर्ष पूर्व एसडीएम आफिस को नन्द नगरी ट्रांसफर कर दिया गया और आज गॉधी नगर के लोग नंद नगरी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने इन सारी समस्याओं को लेकर जाते हैं। गॉधी नगर से डायरेक्टली कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर आदमी वहॉ 12.00 बजे तक लाइन में लगा, जरा सी कोई गलती हो गयी, उसको भेज दिया, वापस आ गया, उसका कम से कम डेढ़ सौ, सौ रुपये किराया सर, खर्च होता

है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि डीडीसी में विधायक फंड का पैसा वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर है और हमारा एसडीएम गॉधी नगर, जो कि टीसी शर्मा जी हैं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और काम मेरा जो है, वो एसडीएम विवेक विहार देखते हैं, तो एक एसडीएम गांधी नगर भी है, इलेक्ट्रिकल रोल जो हमारा है, वो एसडीएम गॉधी नगर के अंदर आता है। अगर वोटर सर्टिफिकेट के लिए काम के लिए जाना है, तो एसडीएम गॉध ी नगर को ही जायेगा और ये कहके ट्रांसफर किया गया था, उस समय के डिविजनल कमिश्नर ने कि ये छः महीने में वापिस आ जायेगा।

माननीय कैलाश गहलौत साहब यहॉ पर उपस्थित हैं। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिला था। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उसको अप्रूव कर दिया था, फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चली गयी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी उसको परमिट कर दिया, परमिशन दे दी। अब माननीय कैलाश गहलोत साहब के ऑफिस में वो फाइल पड़ी हुई है। आप ने भी डिविजनल कमिश्नर साहब को दे दी। डिविजनल कमिश्नर साहब, मनीषा सक्सेना जी से कम से कम दस बार मैं मिला हूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे कहा। वो हर बार ये कहती हैं कि दस दिन में फाइल निकाल दूँगी... मैं अगले दस दिन में निकाल दूँगी... अब फाइल इसलिए लटका रखी है कि हिन्दी का ट्रांस्लेशन उसका होना है, मैं खुद डीडीसी का वहॉ चैयरमैन, डीडीसी ईस्ट में मेरा फण्ड मिले और एसडीएम आफिस... सर, वहॉ नंद नगरी भेज दिया है, तो मेरा अनुरोध है और माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है ये कि आप छः साल से जो वहॉ धक्के खा रहे हैं और मेरे सामने एक ही रास्ता बचा है मंत्री जी, आज मैं खुले मन से घोषणा करके कह रहा हूँ कि अगर एक महीने के अंदर मेरा ये

वापिस नहीं आया तो मैं गॉधी नगर की जनता के साथ मैं आमरण अनशन पे बैठूॅगा या मनीषा सक्सेना के यहॉ बैठूॅगा या सर आपके यहॉ बैठूॅगा, आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूॅ।

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी, अनिल बाजपेयी जी सदन में कम से कम दो बार पहले भी ये उठा चुके हैं मुद्दा। मुझसे भी व्यक्तिगत कई बार मिले। इस बार आप सीरियसली आप देख लें प्लीज। सिरसा जी अनुपस्थित, श्री राजेश गुप्ता जी।

Jh jkts'k xqIrk% अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा कि सभी अखबारों के माध्यम से और आपकी विधान सभा में... शायद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में पानी की भयंकर कमी चल रही है। मेरी विधान सभा के एक हिस्से में पानी की बहुत कमी है। हालॉकि सरकार उसके ऊपर पूरे तरीके से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वाइस चैयरमेन साहब पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक भी वो बात पहुंच चुकी है। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि हाई कोर्ट के आदेशों के वाबजूद भी हरियाणा सरकार के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो दिल्ली का पानी रोक के बैठी हुई है। मेरा इसमें ये कहना था कि जब तक कोर्ट के अंदर ये चीजें चल रही हैं और हमारे चैयरमैन साहब और मुख्यमंत्री जी इसपे काम कर ही रहे हैं। अभी वहॉ पर जो हमारे पास में जो टैंकर हैं, वो सिर्फ 16 हैं, जो पूरे डिविजन के लिए हैं। यानी कि जो चार विधान सभाएं हैं और वहॉ पे भी कुछ ऐसे इलाकें हैं, जहॉ पर टैंकर भेजने पड़ते हैं, तो इफेक्टिवली मेरे यहॉ पर सिर्फ आठ या नौ टैंकर ही ऐसे हैं जो वहॉ पे फेरा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसके ऊपर फिर

झगड़े होते हैं और झगड़े में ही एक आदमी की मृत्यु भी हुई। हालांकि हमने अपना काम करा था, टैंकर भेजा था, लेकिन अगर टैंकरों की व्यवस्था ज्यादा हो जाये, हमने इसका पूरा अनुमान लगाया है पूरी अच्छी तरीके से, उसका रूटमैप बनाया है तो हमको तकरीबन 35 टैंकरों की जरूरत है, तो मैं आपके माध्यम से क्योंकि वाइस चैयरमेन साहब यहॉ बैठे हुए हैं, कहीं से व्यवस्था की जाये या किराये पे लिए जायें या दूसरी डिविजन से मंगाये जायें और जब तक पानी की ये ऐक्यूट प्रॉब्लम है क्योंकि वो झुग्गियों का एरिया है, जहॉ ये ज्यादा दिक्कत है। वो टैंकर वहॉ पर बढ़ा दिये जायें, खड़े होने वाले टैंकर हो जायें या जो जीपीएस वाले टैंकर हैं, जैसे भी हो 35 टैंकर वहॉ अगर चले जायें तो जब तक पानी हरियाणा सरकार से.. . माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनको आदेश देता तो यह व्यवस्था हो जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

Jh vke izdk'k 'kek% धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि वो अपने चौथे बजट में आउटकम से इतना मोहित हो गये कि वे अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की आम पार्टी के दर्शन शास्त्र दर्शाने वाली पुस्तक स्वराज्य, स्वराज्य बजट, मोहल्ला सभा और लोकपाल सबको भूल गये और सबको भूल कर...

...(व्यवधान)

Jh vke izdk'k 'kek% 280 है भाई।

v/;{k egkn;% ठीक है, वो एडमिट हुआ है।

Jh vke i:dk'k 'kek% ये क्या प्रॉब्लम है?

v/;{k egkn;% भई जो एडमिट हुआ है,

Jh vke i:dk'k 'kek% ये क्या करूँ इसका?

v/;{k egkn;% भई...

Jh vke i:dk'k 'kek% अरे! क्या करूँ इसका?

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, ये अननेसेसरी लंबा समय...

Jh vke i:dk'k 'kek% ये तो अध्यक्ष के लिए आवाज किया, उसको मना कर रहे हैं आप। ये अध्यक्ष जी का अपमान कर रहे हैं क्या आप?

v/;{k egkn;% चलिये आप पढ़िये, पढ़िये।

Jh vke i:dk'k 'kek% मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये जितनी बार कहोगे, उतनी बार पढूँगा।

v/;{k egkn;% ये सदन का कीमती समय खराब हो रहा है। अननेसेसरी टोका टिपण्णी से सदन का समय खराब हो रहा है।

Jh vke i:dk'k 'kek% अध्यक्ष जी, मेरा कहना ये है कि इतना मोहित हुए कि वे अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के दर्शन शास्त्र दर्शाने वाली पुस्तक स्वराज, स्वराज बजट, मोहल्ला सभा, लोक पाल सभी को भूलकर राज्यपाल से जा लिपटे। वे जनता की भागीदारी को भी भूल गये। सरकार ने अपने कार्यकाल में मोहल्ला सभाओं के नाम पर 600

करोड़ रुपये से ज्यादा आबंटित किये परन्तु मोहल्ला सभायें बनाने की आज तक कोई पहल नहीं की गयी जिसके ऊपर आप ये चुनाव जीतकर आये हैं। इसी के कारण दिल्लीवासी अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शीला सरकार की भागीदारी योजना जो रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को सुचारू रूप से जोड़ा गया था परन्तु आम आदमी पार्टी सरकार ने भागीदारी को तो समाप्त कर दिया परन्तु मोहल्ला सभाओं को लाने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपने आपको अलग–थलग महसूस कर रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करे। मोहल्ला सभाओं में जान फूके और शहर के हर गली–कूचे में मोहल्ला सभा स्थापित करे ताकि नागरिक अपने आपको सरकार के साथ सहभागिता में वो अपना वो योगदान समझें।

v/;{k egkn;% श्री विशेष रवि जी।

Jh fo'k"k jfo% धन्यवाद अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% अब सरेआम पूछोगे, तो कैसे बताएंगे? विशेष रवि जी, प्लीज।

Jh fo'k"k jfo% अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष डूडा में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा काम न करने और क्षेत्र में विकास कार्यों में आ रही बाधा की जानकारी आपके आगे रख रहा हूँ।

अध्यक्ष जी, 13 दिसम्बर को सरकार के एक फैसले से ये तय हुआ था कि अब जितने भी एमएलए फण्ड के काम हैं, वो सभी काम अब डूडा

से यूडी के माध्यम से किए जाएंगे। जनवरी में डूडा से हमें ये बताया गया कि अब हम कोई भी प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो भी आपको अपना एस्टीमेट या प्रपोजल भेजा जाएगा वो यूडी को भेजा जाएगा। अध्यक्ष जी, यूडी में हम जनवरी से बात कर रहे हैं। तो जनवरी से वो ये कह रहे हैं कि जब तक डूडा अपने एकाउन्ट सबमिट नहीं करेगा। प्रिंसिपल एकाउन्ट अपने सबमिट नहीं करेंगे, तब तक हम आपके नये एस्टीमेट नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एकाउन्ट सबमिट होने के बाद ही पता लगेगा हमारे को कि आपके पास कितना शेष बैलेन्स बचा हुआ है। कौन सा काम हम आपके कर सकते हैं अप्रूव, और कौन से नहीं कर सकते है। ये जब तक डूडा अपने एकाउन्ट सबमिट नहीं करेगा तब तक नहीं पता लगेगा। सर मैं...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% उनको अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे आप? नहीं, वो फालतू खड़े हैं? आपको कुछ बोलना है तो आप बात रखिएगा अभी। उनको अपनी बात तो पूरी करने दो।

Jh ffo'k"k jfo% सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट है। जिसमें डूडा की तरफ से जब दिसम्बर में ये तय हुआ कि अब यूडी करेगा काम। यूडी की तरफ से डूडा में दो पत्र गये हैं। एक 23/2 को गया है एक 9/3 को गया है और दोनों में ये कहा गया है यूडी की तरफ से कि भाई अपने एकाउन्ट्स जो हैं, उनको आप सबमिट कीजिए। एमएलएज के हमारे पास काम आ रहे हैं। उनको हमें सैंक्शन करना है। वो हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज की तारीख तक भी, आज

सुबह भी मेरी बात नहीं हो पायी है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की डीएम का नाम श्रीमती निधि श्रीवास्तव है। वो फोन नहीं उठा रही हैं। मेसेज का जवाब नहीं दे रही हैं। कल मुझे फाइनली एक पत्र उनके ऑफिस में देना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि आपका ऑफिस... आप काम नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए हैं। पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारी ये तैयारी थी कि ट्यबूवेल से जीआई लाइन के माध्यम से हम कुछ कनेक्शन करेंगे। ट्यूबवेल से लोगों के घर तक पानी पहुॅचाएंगे ताकि जो जल बोर्ड की सप्लाई है... उसमें लोगों को समस्या आ रही है, उससे उनको रिलीफ मिले। लेकिन कल तक भी डीएम आफिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। ये समस्या मुझे लगता है कि लगभग दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में आ रही होगी। दिसम्बर के बाद से लेके अब तक... अध्यक्ष जी, अप्रैल शुरू हो गया है। मार्च का महीना खत्म हो गया है। पिछले साल के मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के दो करोड़ रुपये बैलेन्स हैं और वो दो करोड़ रुपये मैं खर्च नहीं कर पाया हूॅ। 25 प्रपोजल मेरे आज भी यूडी में रखे हुए हैं उनके पास, लेकिन उसको वो सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत गम्भीर समस्या है सर। एक तो काम नहीं करना, ऊपर से ऑफिसर्स का फोन नहीं उठाना, पब्लिक के विकास के कार्यो में बाधा डालना। ये एक गम्भीर समस्या है सर। मुझे लगता है कि इसमें आपको इसको संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूॅगा कि इसके बारे में वो जवाब दें, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% श्री जरनैल जी। बस, इस पर चर्चा नहीं होगी। जरनैल जी को मैं एलाऊ कर रहा हूॅ।

Jh tjuSy flag% बहुत ही अध्यक्ष जी, गम्भीर समस्या है। मेरा सिर्फ एक सुझाव है छोटा सा इसमें कि डूडा में जो पेन्डिंग प्रपोजल्स पड़े हैं, उनकी एक लिस्ट मंगा ली जाए एमएलए वाइज। आपको खुद मालूम चल जायेगा कि कितने बड़े लेवल पर लापरवाही हो रही है और यूडी से भी अभी तक नये प्रपोजल एप्रूव नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

Jh fo'ks"k jfo% ये मैटर किसी कमेटी को दें। इसमें सर, जवाबदेही तय करवाएं कि अगर... सर, क्वैश्चन एण्ड रेफरेन्स कमेटी को ये मैटर दिया जाए।

v/;{k egksn;% ये विषय बहुत गम्भीर विषय है और सभी विधायक इससे पीड़ित हैं। ये क्वैश्चन रेफरेन्स कमेटी को मैं रेफर कर रहा हूॅं। सांतवॉं, श्री रामचन्द्र जी। श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nRr% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर में एक गॉव है। बहुत प्राचीन गॉव, खानपुर के विषय में कुछ चीजें रखना चाहता हूॅं। अभी करीबन एक–डेढ़ साल से खानपुर गॉव के लोग कई बार मेरे पास आए और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा गॉव है और उस गॉव में खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है तो मैं उनके साथ मौके पर दौरा करने गया, देखा तो उस गॉव के साथ दिल्ली परिवहन निगम का एक बहुत बड़ा एक बस डिपो है और उस बस डिपो में कुछ बिल्डिंग बनी हुई हैं पुरानी, जो खण्डहर हालत में हैं और गॉव के लोग ये चाहते हैं कि उन बिल्डिंगों में क्योंकि वो बिल्डिंग खण्डहर हालत में है और वहॉ पर बहुत सारे असामाजिक तत्व

बैठते हैं जो नशा करते हैं और आने–जाने वाले लोगों से कई बार छीना–झपटी हुई है और कई बार वहॉ पर चाकूबाजी भी हुई है तो उनका कहना है कि इस खण्डहर को तोड़कर गांव के लिए इसको एक ग्रीन पार्क बना दिया जाए जिससे कि वहॉ बच्चे भी खेल सकें और... भाई साहब, ऐसे इण्टरप्रेटेशन करना तो सारा तुम्हीं कर लो ना। and people are saying that you must built this place as a park and everybody is of the view that if you do not demolish this building which are not proper and which are not in the condition where people can stay or you know… walk around. It will be a big problem and crime also may increase, so everybody is of the view and opinion that there should be a park and I request to the Transport Department and the Minister of the Transport Department to Allocate this particular place for Khan pur gaon as a park. Thank you very much.

v/;{k egksn;% श्री एस.के .बग्गा जी।

Jh ,l-d- cXxk% अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इडीएमसी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी कष्णा नगर विधान सभा और पूरी पूर्वी दिल्ली में इडीएमसी हाउस टैक्स के नोटिस 2004 से 2016–17 तक दे रही है। इडीएमसी अपना रिकॉर्ड चेक किये बिना सबको नोटिस दिये जा रही है। इनके लोग घरों में जाकर सौदेबाजी कर रहे हैं तथा लोगों को तंग कर रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इडीएमसी कमिश्नर को कहें कि पहले वे अपना रिकॉर्ड ठीक करें और पूरा करें तभी उन लोगों को नोटिस दिया जाएं, जिनका बकाया हाउस टैक्स है। इससे लोगों में डर बना हुआ है। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk% अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर और मैं समझता हूँ कि सदन का हर सदस्य स्कूलों में दाखिलों को लेकर के जो नीति पारदर्शिता की बात हुई थी, ऐसा कुछ वहॉ नहीं हो रहा है। कोई पारदर्शिता नहीं है। कोई नियम और कानून नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई कैटेगरी नहीं है जिससे कि अभिभावकों को एक सन्तुष्टि हो कि उनका नम्बर नहीं आया तो क्यों नहीं आया और किसी दूसरे का आया तो क्यों आया। लेकिन सरकार ने बड़े–बड़े दावे किए थे, दाखिले की पारदर्शी व्यवस्था करने की, लेकिन सरकार की नीति पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है। डोनेशन के मामले में भी फीस जो भी विद्यालयों द्वारा ली जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। जिस विद्यालय का जो मन आ रहा है, वो उसको प्राप्त कर रहा है, ले रहा है और मैंने कल भी जो मामला उठाया था, मैं उसको बार–बार उठाता रहूँगा। आज भी 9वीं और 11वीं के अंदर जो रिजल्ट्स को लेकर के जो धांधलियॉ हैं, यहॉ तक होता है कि अगर आप बच्चे को ले जाओगे तो टीसी ले जाइये, पास का बना देते हैं। जब आपने फेल्ड डिक्लेयर कर दिया तो पास का टीसी कैसे बन जाता है, मुझे

आज तक समझ में नहीं आ रहा। तो क्या वो रिजल्ट जो रिकॉर्ड पर आ गया फिर उसके बाद पास का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, यह समझ से बाहर है। और इन्हीं विद्यालयों के अंदर जिस तरह की मानसिक पीड़ा से विद्यार्थी गुजर रहे हैं, क्योंकि अभिभावक तो बोलने की स्थिति में नहीं हैं। अगर अभिभावक बोलेगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है और उसका प्रभाव उसके बच्चे की पढ़ाई पर पड़ता है। बच्चे के साथ होने वाले व्यवहार पर पड़ता है। इसके साथ–साथ टक शॉप की बात भी कल की गई थी। आज फिर मैं टक शॉप की बात करना चाहता हूॅं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी प्रकार का...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% कल विषय बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा में आया था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था।

Jh fot;sUnz xqIrk% अध्यक्ष जी, उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूॅं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद थी कोई कार्रवाई होगी लेकिन टक शॉप्स में जिस तरह किताबों को लेकर, कॉपियों को लेकर, बस्ते को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर के अभिभावकों का हर प्रकार से शोषण हो रहा है, उसके विरोध में मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि सरकार इन पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाएं, जिससे दिल्ली के अंदर 1705 विद्यालय हैं और लगभग 16 लाख विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं। एलकेजी से लेकर 12वीं तक तो 15–16 लाख बच्चे जिस सिस्टम में हों, 40 लाख तो कुल हैं दिल्ली में विद्यार्थी, जिसमें से एक हजार स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, 15 लाख

बच्चे उनमें हैं। तो उससे ज्यादा बच्चे तो उनके पास हैं और अगर ये अंकुश नहीं लगेगा तो मध्यम वर्ग परिवार के अभिभावकों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, इस पर हमारी कड़ी आपत्ति है।

v/;{k egkn;% धन्यवाद। अखिलेशपति त्रिपाठी जी। जो इसमें है, वही पढ़ियेगा। भई, अब नहीं। नहीं है आपके पास? श्री जगदीश प्रधान जी। तैयार हैं, प्रधान जी, बैठिए, दो मिनट। अखिलेश जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh% सर, मेरा भी एक मैटर है।

v/;{k egkn;% नहीं, जो मेरे पास आए हुए हैं... नहीं, प्लीज।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh% माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में जीटी करनाल रोड स्थित त्रिपोलिया गेट के निम्नीकरण का कार्य पिछले डेढ़ सालों से रुका पड़ा है। यहॉ पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। पीछे माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, जिसके बाद एक लेन बहुत तेजी से 15–20 दिनों के अंदर बन गया। पता लगाया गया कि काम चल रहा था, उस बीच में एएसआई वाले आए, ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केन्द्र सरकार की संस्था है, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर करेंगे, आपने यह रोड कैसे बना दी! अब मैं हैरान था कि रोड था, किसी का घर तो बन नहीं रहा था लेकिन उसे जान–बूझकर के वहॉ के कुछ स्थानीय नेता, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा और वहॉ के स्थानीय सांसद द्वारा इस काम को केन्द्र सरकार के द्वारा रुकवाने का काम किया गया। आधा काम शुरू कर दिया गया था, उसमें गड्ढा खुद गया था और आज तक वो गड्ढा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। इसमें दो–तीन मौतें हो चुकी हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूँ सदन के माध्यम से कि यह काम तुरंत शुरू किया जाए और इसकी जॉच की जाए कि किन लोगों की मिली–भगत से यह काम रुक गया, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस गड्ढे को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अध्यक्ष जी को कि मुझे मौका दिया इस मुद्दे को उठाने का।

v/;{k egkn;% श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i/kku% धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

Jh lkeukFk Hkkjrh% सर, 280 में...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आज मैंने 13 ले लिए, जहॉ तक आए हुए थे। अब उससे ज्यादा और नहीं। प्लीज। अब जगदीश जी को पढ़ने दीजिए। प्लीज।

Jh txnh'k i/kku% अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह अस्पताल सरकार की उदासीनता का जीता–जागता उदाहरण है। जिस उद्देश्य को लेकर यह अस्पताल शुरू किया गया था, वह दूर–दूर तक कहीं पूरा नहीं हो रहा है। वह अस्पताल सोसायटी मॉडल पर है, परंतु खेद की बात है कि सरकार की यह योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है और आम आदमी पार्टी सरकार तीन साल से हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इस अस्पताल में आज तक दिमाग, किडनी, लिवर और

पेट से संबंधित विभाग लगभग मृतप्रायः हैं। ह्रदय रोग विभाग के डॉक्टरों की भारी कमी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 200 बिस्तर जंग खा रहे हैं। वेंटीलेटर समेत 10 आइसीयू बंद पड़े हैं। ब्लड बैंक आज तक शुरू नहीं हो पाया है। सरकार ने न तो डॉक्टरों की भर्ती करी है, न कर्मचारियों की।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बीमार अस्पताल को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि वहॉ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, धन्यवाद।

v/;{k egksn;% अंतिम श्री महेंद्र गोयल जी।

Jh egsUnz xks;y% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूॅ कि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया और यह भी बहुत ही अच्छा हुआ कि वित्त मंत्री साहब भी इस समय सदन के अंदर उपस्थित है।

मैं आज जो प्रश्न रखने जा रहा हूॅ यह देश के सभी व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो जब मैं प्रश्न को रखूॅगा तो एक ही कहा जाएगा कि यह सिक्खों के लिए है लेकिन यह देश के हर वर्ग के लिए है क्योंकि यदि कहीं पर भी भूख लगती है तो लोग एक ही बात कहते हैं कि गुरुद्वारे में जाकर रोटी खा लें। हम आंदोलन के अंदर भी थे, जब जंतर–मंतर पर थे और किसी कार्यकर्ता को रसोई लगाने से पहले भूख लगती थी तो वो बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर जाकर रोटी खाता था। आज सीरिया के अंदर युद्ध चल रहा है और उसकी जो पॉजिशन है तो इस समय भी सिक्ख कम्युनिटी ही गुरुद्वारों से रोटी बनाकर सीरिया के हर मैदान के अंदर रोटी

पहुंचाने का काम कर रही है, यह सिक्ख कौम के लिए बहुत बड़ी बात है और जो लोगों का पेट भरती है। लेकिन इस समय में हमारी केन्द्र सरकार ने इन गुरुद्वारों के प्रति जो व्यवहार किया है, जीएसटी उस खाने के ऊपर भी लगा दी है, जिसको फ्री के अंदर बांटा जा रहा है। मेरा इस सदन के माध्यम से यह अनुरोध है... सोमनाथ जी, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो उस बात का सुन लेना चाहिए, यह आग्रह है आपसे। आपकी बात को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि यह एक मुद्दा ऐसा जुड़ा हुआ है कि लोग फ्री के अंदर रोटी बॉटते हैं और उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। मैं वित्ती मंत्री साहब से भी अनुरोध करूँगा, अपने बजट के अंदर आप भी इस बात को अमेंडमेंट करें, बदलाव करें इस चीज के लिए कि गुरुद्वारे के ऊपर जो भी मंदिर में, गुरुद्वारे में क्योंकि खाने का काम, पेट भरने का काम सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे ही करते हैं। तो दिल्ली सरकार के पास भी मान लो कोई जीएसटी आ रहा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको भी लौटाएं और आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि केन्द्र सरकार के पास भी यह अपील जाए कि गुरुद्वारा जो भी जीएसटी के रूप में कर देता है, उन गुरुद्वारों को वो कर वापस होना चाहिए जीएसटी के रूप में, यह मेरा आपसे, सदन से अनुरोध है, जयहिंद, जय भारत। जो बोले सो निहाल।

l|Jh vydk ykEck अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 54 के तहत् मैं आपसे एक गम्भीर मुद्दे के ऊपर चर्चा चाहती हूँ।

अध्यक्ष जी, मेरा महिला बाल विकास मंत्रालय से नियम 54 के तहत्...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% अलका जी, बोलने का नहीं, देखिये 280 है, चर्चा के लिए नहीं होता है।

Jh txnhi flg% अध्यक्ष जी, हमारा समर्थन है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आपका समर्थन हो गया।

Jh vorkj flg dkydkth% एक जरूरी गल करनी है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% मैं नहीं अलाउ कर रहा।

Jh lkeukFk Hkkjrh% मैं बोलना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, बैठिए। प्लीज, बैठिए।

Jh tjuy flg% समर्थन है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आपका समर्थन है?

Jh vorkj flg dkydkth% मैं जीएसटी पर नहीं बोल रहा, गल करनी है...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा हूँ। मैं इसमें और कोई अलाउ नहीं कर रहा, प्लीज। प्लीज मेरी बात को समझ लीजिए। अलका जी, आपका क्या है?

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, हम लोग एंटी स्टॉकिंग के ऊपर जो है, एक बिल लाने की मॉग है, अगर इसकी जरूरत के ऊपर मैं... थोड़ा सा मौका देंगे, आपको समझ आएगा कितना गम्भीर मुद्दा है और यह बिल, इस कानून के ऊपर चर्चा इस हाउस में होनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सदन हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाता रहा है और ये उम्मीद आपसे हम करते हैं कि आप हमें अवसर देंगे। इसके ऊपर चर्चा के लिए थोड़ा सा समय दीजिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे।

/;kukd"k.k ¼fu;e&54½

v/;{k egkn;% मैं कुछ भी... अलका जी क्या बोल रही हैं मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। आपका ठीक है खड़े होकर हॉ कर दीजिए लेकिन उनको बात तो रखने दीजिए।

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, मैं नियम 54 के तहत इस सदन में एंटी स्टॉकिंग बिल महिला सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर एक बिल लाने की मॉग कर रही हूँ। इससे पहले मैं चर्चा करना चाहती हूँ ताकि मेरे साथी सदस्य इससे अगर सहमत हों तो इस सदन में हम लोग महिला सुरक्षा के इस मुद्दे के ऊपर एक बिल लाकर केन्द्र सरकार को भेज सकें ताकि केन्द्र भी इस पर गंभीरता दिखाकर इसकी जरूरत... क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत बदत्तर है अध्यक्ष जी, और आपने अभी देखा कि...

v/;{k egkn;% बहुत संक्षेप में रखिये... क्या है? संक्षेप में रखिये।

lqJh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली में कुछ वारदात ऐसी हुई हैं। ये एंटी स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। शब्द लगता है मनचले हैं पीछा कर रहे हैं कोई नहीं, बहुत छोटा मोटा अपराध है, पीछा ही तो किया है। लेकिन ये पीछा करना किस लेवल तक जा रहा है मैं छह हमारी बेटियों के नाम आपको गिनवाऊँगी जिन्हें पीछा करने के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया है। सबसे पहला उदाहरण, उदाहरण देने के बाद मैं आपके इस पर फाइनल आऊँगी कि अगर जरूरत ये सदन समझे तो इस पर बिल लाया जाए। सबसे पहले मीनाक्षी नाम की हमारी बेटी जो टीनेजर थी। नहीं ये तो वो... सॉरी, अखबारों में उनकी हत्या हो चुकी है। आज निर्भया की मां भी अपनी बेटी का नाम ले रही है क्योंकि ये बेटियॉं अब हमारे बीच में रही नहीं और ये छह की छह बेटियॉं दिल्ली की हैं और इतना ही नहीं चेन्नई, महाराष्ट्रा, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी बेटियॉं ऐसी हैं जो इससे लड़ी और मौत के घाट उतार दी गई। इसकी कितनी जरूरत महसूस की जा रही है, मैं वो बता रही हूँ। अध्यक्ष जी आप इजाजत देंगे मैं नाम लूँगी, वरना मैं नाम नहीं लूँगी।

v/;{k egkn;% नहीं नाम छोड़ दीजिए आप संख्या बता दीजिए।

lqJh vydk ykEck% मैं नाम नहीं लूँगी। अध्यक्ष जी, सबसे पहली वारदात जो है, ये 19 साल की हमारी एक बेटी के साथ हुई। सबसे पहले इसका मनचले लड़के पीछा करते रहे, बहुत ह्रास परेशान हुई, पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बहुत कोशिशों के बाद ये पंजाबी बस्ती आनंद पर्वत का मामला है। अध्यक्ष जी, इसमें एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर

होने के बाद ये जमानती अपराध है। अगर कोई किसी का पीछा करता है, फिजीकली पीछा नहीं कि आप शारीरिक रूप से किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं अगर आप उसे लगातार फोन काल करते हैं, एसएमएस करते हैं, आप उसे ह्रास परेशान कर देते हैं किसी तरह मेल करते हैं, आप उसको किसी तरह उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं, ये सब स्टॉकिंग में आता है। तो इसमे हुआ ये कि पुलिस ने बहुत दबाव के बाद अध्यक्ष जी, एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद जमानती था। मेरी मॉग यह है कि इसे गैर–जमानती बनाया जाए क्योंकि इसकी एफआईआर हुई होने के बाद इसकी जमानत हो गई, जमानत होने के बाद इस लड़के ने आकर हमारी इस बेटी को जो है, जिसने हिम्मत की, हम सब लड़े, एफआईआर हुई उसको मौत के घाट उतार दिया।

दूसरा केस आता है एक और जो 22 साल की हमारी बेटी की है। एक मनचला बहुत समय तक पीछा करता रहा। ये 2016 सितंबर का मामला है अध्यक्ष जी। शादी करना चाहता था लेकिन लड़की ने उसे शादी करने से मना कर दिया। ये बुराड़ी दिल्ली का केस है जिसमें पुलिस ने लड़की के ऊपर दबाव बनाया, 'समझौता कर लो, कोई बड़ा मामला नहीं है, बोल दो, ''मैं शादी नहीं करना चाहती।'' उसने कहा, ''हजारों बार बोला है, मेरा जीना हराम कर दिया है।'' पुलिस ने दबाव में जो एफआईआर नहीं की, केस दर्ज नहीं किया और अंत में वो लड़का जो है, हमारी इस बेटी को भी जो है, वो बिलकुल उसका पीछा करके उसको मौत के घाट उतार दिया।

तीसरा केस करूणा का है, माफी चाहूँगी मैं, फिर नाम नहीं ले रही। क्योंकि ये भी बेटी हमारे बीच में नहीं रही, इसकी भी वही शिकायत थी

कि मनचलों ने इसका जीना हराम कर दिया था। पॉचवॉ केस जो है, उसमें भी यही हुआ। फिर नाम नहीं ले रही। दिल्ली के ही हैं, बेल हुई और हत्या कर दी गई।

एक और बेटी है जिसकी मॉ जो है, उस बेटी के साथ हिम्मत देने के लिए गई कि नहीं, हमें ये सब नहीं बर्दाश्त करना। वो बेटी जो है, थाने तक मॉ के साथ गई बेटी और मॉ को... दोनों पर चाकूओं से हमला कर दिया। बेटी की जान चली गई। मॉ इसमें घायल हो गई। यही नहीं, एण्टी स्टॉकिंग में... पिता के ऊपर भी आती हूॅ।

50 साल के पिता जिनका नाम काशीराम है, अमर कालोनी दिल्ली के ही हैं। उनके साथ भी यही हुआ बेटी को हिम्मत दिखाई कि इनके सामने झुकना मत तुम्हारा हक है आजादी के साथ, सुरक्षा के साथ इस देश में जीने का। पुलिस स्टेशन गई। वही हुआ, बेटी को मौत के घाट उतार दिया और पिता को कम से कम नही तो, 50 बार चाकू से गोद दिया गया। ये सिर्फ फायदा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आज तक ये कानून जो है, वो जमानती है। मेरी ये मॉग है, इस सदन में कानून लाकर इसे गैर–जमानती बनाया जाए। इसकी डेफिनेशन क्या है, उसे पूरी तरह से साफ किया जाए। क्योंकि लगता है कि पीछा ही तो कर रहा है, मनचला तो बहुत छोटा है लेकिन जब अंजाम सामने आते हैं; एक नहीं, दो नहीं... क्योंकि जब पीछा होता है, लड़की को पकड़ लिया जाता है, फिर रेप होते हैं, उसकी हत्या होती है और फिरौती तक मॉगी जाती है। तो एक अपराध से चार अपराधों के दरवाजे खुल जाते हैं और पुलिस पूरी तरह से... दिल्ली की पुलिस मैं कहॅूगी, ये छह अपराध दिखाते हैं कि पूरी तरह से नाकाम

हैं। इन मनचलों पर इस तरह की हत्याएं, हमारी बेटियॉ जो हर रोज हो रही हैं उससे।

मैं 2014 का ऑकड़ा रख रही हूँ। 2014 में दिल्ली के अंदर 4700, 2015 में 6300 और 2016 में 7200, 33 प्रतिशत इस तरह के जो हैं, स्टॉकिंग के... पीछा करने के हत्याओं के मामले में 33 प्रतिशत जो है, वो बढ़ोत्तरी हुई है। ये मैं नहीं, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार का जो डाटा है, वो ये बताता है। अध्यक्ष जी, इसकी गंभीरता को जानते हुए मुझे नहीं मालूम है, इससे पहले भी हम लोग जो है, महिला सुरक्षा कानून लाने की बात की थी। मुझे याद है 2015 में सदन बनते ही महिला सुरक्षा पर हमने बात की, चर्चा की, और हमारा एक बिल यहॉ से पास होकर अभी तक 2015 से 2018 आ गया, केन्द्र की सरकार के पास एलजी के माध्यम से आज तक ठण्डे बस्ते पर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं मालूम फिर ये कहा जाएगा, ये कानून और व्यवस्था का मामला है। ये पुलिस से जुड़ा मामला है। इस तरह के कानून और महिला बेटियों की सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती, आप बिल नहीं ला सकते, पर मुझे लगता है, इस सदन की मंशा, नीयत इस बिल को अगर लाकर साफ हो जाती है दिल्ली के सामने कि अगर केन्द्र सरकार और एलजी यहॉ से बिल पास होने के बाद अध्यक्ष जी, अगर रोकेंगे तो वो बेनकाब होंगे, जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं और हर बार कोई न कोई बहाना करके कि ये कानून बनाना लॉ एंड आर्डर, व्यवस्था के आपके अधीन नहीं आती है, ये बेनकाब होंगे क्योंकि किसी तरह से भी बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है और 8 मार्च अभी गुजरा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। 'रेप रोको' को लेकर दिल्ली महिला अध्यक्ष और अभी आम आदमी पार्टी की महिला

अध्यक्ष ऋचा पांडे भी बैठी हुई हैं। इन लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया और दिल्ली के ही नहीं, बहुत से पिताओं ने, बहुत से भाइयों ने इसको साइन किया है कि वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटियॉ, उनकी बहन, भारत की राजधानी दिल्ली में अगर सुरक्षित नहीं हैं तो कहीं सुरक्षित नहीं होंगी। उन्हीं की मॉग पर मैं चाहती हूॅ कि इस बिल के ऊपर इस सदन में चर्चा हो और एंटी स्टॉकिंग पीछा करने का जो ये कानून की हम बात कर रहे हैं, सदन से पास करके केन्द्र की सरकार को भेजा जाए ताकि केन्द्र भी, जो खाली एक जुमला बना हुआ है, 'बेटी बचाओ' नारे को हकीकत में बदल पाए और हमारी बेटियों को भारत की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित करके एक उदाहरण इस देश के सामने रख पाए कि किस तरीके से हम चाहें तो देश की बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद करती हूॅ, और मैं बिलकुल चाहूॅगी महिला बाल विकास मंत्री जी इसके ऊपर जरूर अपनी बात रखें कि क्या सरकार की तरफ से इस सदन में चर्चा के बाद ये बिल केन्द्र सरकार को एलजी के माध्यम से भेजा जाएगा या फिर उसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है। मैं चाहूॅगी इस सदन में जरूर इस पर बात रखें। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूॅ।

v/;{k egksn;% इसमें बस मैं केवल बंदना जी को अवसर दे रहा हूॅ बोलने का।

Jherh cnuk dqekjh% अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पीछा करने का जो कानून है, ये लगातार बहुत सारी बेटियॉ, खासकर हमारी बहनें, हमारी बेटियॉ जब जाती हैं तो हम सब दिन रात चिंतित रहते हैं के कब क्या

हादसा... कैसे वो घर लौट जाती हैं तब तक हम लोगों को चिंता बनी रहती है तो इस तरह के बहुत सारे दिन रात आते हैं लेकिन पुलिस के पास हम लोग भी जाते हैं, हमारे साथी भी जाते हैं और हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियॉ आती हैं, इस तरह की बात बताती हैं लेकिन हम पुलिस के पास जाते हैं, इसका कोई निदान नहीं निकलता। जब हम इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। इस तरह का कोई हमारे पास सबूत नहीं है। इस तरह की बातें नहीं हैं। बहुत सारे वॉट्सऐप्प पर जो अभी बातें कह रही थी अलका जी, उस पर वॉट्सऐप पर बार बार पिक्चर आती हैं, उनको ह्रास किया जाता है। इसी तरह से मैसेज लिखकर इसी तरह से जब वो जाती हैं कहीं पर, तो दूर तक बाइक से... क्योंकि स्कूटी पर भी हमारी बच्चियॉ जाती हैं तो इस बिल को कानून का रूप दिया जाए और सख्त से सख्त इस पर कानून बनाया जाए।

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, श्री सत्येन्द्र जैन जी।

xg e=h ¼Jh lR;Unz tSu½% माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संजीदा मामला है और मैं सरकार की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूॅ इस सदन को कि ये 354(डी) आइपीसी के अंदर इसमें संशोधन करना होगा। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द संशोधन लेकर आएगी और मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार भी इसको शायद नहीं रोक पाएगी क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया है तो किसी के लिए भी जब तक कि इसका समर्थन न करते हों, कोई भी रोक नहीं पाएगा और ये होगा, जल्द से जल्द सरकार इसके भी ऊपर बिल बनाकर लेकर आएगी।

अध्यक्ष महोदयः एक बार मुझे अलका जी से बात करने दीजिए। अलका जी, माननीय मंत्री जी ने संशोधन का... आप बिल की बात कर रही हैं।

lqJh vydk ykEck% नहीं सर, हम बिल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं उसमें अब देखिये।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% दो मिनट रुक जाइए, विषय को तो खुलने दीजिए।

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, मेरी इस सदन से और सरकार से मॉग ये है, हमारा एक ही मकसद है, ये अपराध रुकने चाहिए। बेटियॉ सुरक्षित होनी चाहिए। आप किस तरीके से करेंगे, ये सरकार को तय करना है। सरकार चाहे बिल लाना है, सरकार बिल लाए। लेकिन मेरी अध्यक्ष जी, ये सरकार के ऊपर मैं छोड़ रही हूॅ, सरकार तय करे। मकसद वो ही है कि अपराध रुकना चाहिए, बेटियॉ सुरक्षित होनी चाहिए। दो मॉगें मेरी हैं, वो कैसे पूरी होंगी। पहली मॉग, जमानती को गैर जमानती बनाया जाए और जो सजा है, एक से तीन साल है और जमानती है, उसमें जमानत पर बाहर आकर ही सारी हत्याएं हुई हैं। तो मेरी ये मॉग है कि कैसे सुरक्षित हो, ये सरकार तय करे।

v/;{k egksn;% सोमनाथ जी और सौरभ जी में से दोनों तय कर लो कौन बोलेगा। एक तय कर लीजिए। आज बजट पर चर्चा होनी है। महिलाओं का विषय है। श्री सोमनाथ जी। सौरभ जी आपको दे दिया। बहुत संक्षेप में करिए। मैं मान रहा हूॅ विषय बहुत गम्भीर है। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो मैं पूरा समय चर्चा करवाता। सोमनाथ जी, प्लीज जल्दी करिए।

Jh lkseukFk th% अध्यक्ष महोदय, ये मामला बहुत गम्भीर है लेकिन मैं चूंकि इसके अंदर कानूनन, इसका एक कानूनन पहलू भी है। मैं उस पर क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा था। एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि जी, इस पर क्या दिल्ली की विधान सभा कोई कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता। जो restricted subject जिस की बात कल एलजी महोदय के जरिए आपके पास पहुॅची थी, ये उसमें नहीं आता।

सीआरपीसी का अमेंडमेंट, आइपीसी का अमेंडमेंट दिल्ली विधान सभा का हक है। दिल्ली विधान सभा अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी का अमेंडमेंट भी कर सकता है आइपीसी का अमेडमेंट भी कर सकता है। लॉ इन्फोर्समैंट अलग है, लॉ मेकिंग अलग है। पुलिस भले ही केन्द्र सरकार के पास हो लेकिन जब भी सदन चाहे कि सीआरपीसी का अमेंडमेट करके बहनों की रक्षा की जाए, एन्टी स्टॉकिंग बिल बनाया जाए या अपने किसी सैक्शन के अंदर 354 (डी) के अंदर कुछ चेंज कर दिया जाए, तो कर सकता है। उसको मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि दिल्ली विधान सभा अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी का अमेंडमेंट करके... जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 354(डी) को चेंज करके, उसको हम नॉन बेलेबल बना सकते हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn;% माननीय मंत्री जी।

xg ea=h% अध्यक्ष महोदय, मैं ये जो बताना चाहूॅगा सदन को कि अमेंडमेंट बिल ही होगा। मतलब बिल कहना या अमेंडमेंट बिल कहना एक ही बात है जिसमें धारा 354(डी) है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा।

वो बिल के बराबर ही है और इस अमेंडमेंट के होने के बाद जो अलका जी ने बात उठाई है, वो लागू हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको केन्द्र सरकार भी रोक नहीं पाएगी... जल्द से जल्द होगा।

v/;{k egkn;% इसका प्रस्ताव रखिए।

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी प्रस्ताव... एक प्रश्न है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसी सरकार ने रेप के बाद फॉसी की सजा का जो है, वो कानून अपने सदन में लाकर पारित कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बिल या अमेंडमेंट बिल के माध्यम से क्या ये भी हो सकता है जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने 'रेप रोको' के तहत ये मॉग की है कि दिल्ली के अंदर भी फॉसी की सजा जो है, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो क्या अगर ये भी हो सकता है तो ये भी प्रस्ताव लाकर अमेंडमेंट अगर हो सके, तो करना चाहिए। कम से कम दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की जो मॉग है 'रेप रोको' और इतना बड़ा अभियान, दिल्ली का सदन... तो इसमें कम से कम ये प्रस्ताव लाकर उसे करना चाहिए, ताकि केन्द्र सरकार भी जागे।

x`g ea=h% अध्यक्ष महोदय, इसको तो एग्जामिन कर लिया जाएगा, उसके बाद में कोई भी वादा कर पाऊँगा सदन से। बट जो पहला मुद्दा था, उस मुद्द के ऊपर मैं फिर से एक बार आश्वासन देना चाहता हूँ। सरकार जल्द जल्द बिल अमेंडमेंट लेकर आएगी और सारा सदन इसको पास करके जल्द से जल्द भेजेगा। केन्द्र सरकार भी इसको...

v/;{k egkn;% अलका जी, प्रस्ताव रखिए इस पर जल्दी। नहीं, सौरभ जी, आप रखिए।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, मैं इस विधान सभा के समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूँ कि दिल्ली सरकार इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अंदर अमेंडमेंट लाए जिससे दिल्ली के अंदर जो स्टॉकिंग होती है, उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जा सके और उसके अंदर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जा सके। इसके साथ दिल्ली सरकार इस विषय को भी देखे कि क्या दिल्ली के अंदर जुवेनाइल रेप्स यानी कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनके विषय में सजा–ए–मौत का प्रावधान तलाशे और देखे कि कैसे दिल्ली के अंदर ये सम्भव हो सकता है कि ये दिल्ली के इंडियन पैनल कोड की अमेंडमेंट के अंदर आ सके।

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगी कि जो बेटियॉ हिम्मत दिखाकर... एफआईआर नहीं होती, उनकी एफआईआर इन्श्योर की जाए।

v/;{k egksn;% वो आ गया, अलका जी, आ गया वो। वो सौरभ जी ने इन्क्लूड कर दिया सब, उसमें हो गया।

lqJh vydk ykEck% और दूसरी बात... जो बेटियॉ हिम्मत दिखा रही हैं एफआईआर लिखाने की, उनकी सुरक्षा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता पुलिस ने सुरक्षा दी थी। यदि सुरक्षा दी होती तो बेल पर आने के बाद वो हत्याएं नहीं होती हमारी बेटियों की।

Jh lkjHk Hkkj}kt% सीआरपीसी के अंदर जो है, एफआईआर का प्रावधान तो है और सुरक्षा का प्रावधान अभी तक नहीं है। वो अगर कोर्ट के अंदर विक्टिम या कम्पलेंनेंट कहता है तो कोर्ट उसको देखकर देती है सुरक्षा।

v/;{k egkn;% अब ये जिस विषय को अलका जी ने लिया है, सौरभ जी प्रस्तावित किया सदन के सामने...

Jh lkseukFk Hkkjrh% इन्होंने जो प्रस्तावना रखी है, उसमें अमेंडमेंट ऑफ आइपीसी ही रखा है। इसका सम्भावना यह भी है कि आपको सीआरपीसी की अमेंडमेंट करना पड़े तो ये सीआरपीसी और आइपीसी किसी, जिस किसी का भी आपको अमेंडमेंट करना पड़े उसको, उस अमेंडमेंट को सदन के आगे लाया जाए।

v/;{k egkn;% अलका जी का जो विषय था, सौरभ जी का प्रस्ताव, उसमें सोमनाथ जी द्वारा अमेंडमेंट, ये सारा सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वो कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;
(सदस्यों के हॉ करने पर)
प्रस्ताव पारित हुआ, पारित हुआ।

lnu iVy ij izLrqr nLrkost

अब माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत वार्षिक बजट 2018 पर आगे... इसमें दो चीजें रह गई हैं, प्लीज चर्चा अभी आरम्भ करेंगे। माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली बिक्री कर अधिसूचना (सूची संलग्न) की हिन्दी अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक तीन के उप बिन्दु एक में दर्शाए गए निम्नलिखित अधिसूचनाओं की अंग्रेजी हिन्दी प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूॅ[1]:

1 पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर.आर.–20492–20545 पर उपलब्ध।

Delhi (State Tax) Notification

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
1	F2(3)/Policy/GST/2017/65 8-69 dated 16.08.2017	01/2017
2	F2(3)/Policy/GST/2017/68 3-94 dated 18.08.2017	02/2017
3	F2(3)/Policy/GST/2017/70 3-14 dated 23.08.2017	03/2017
4	F2(3)/Policy/GST/2017/87 0-81 dated 29.09.2017	04/2017
5	F3(786)/Policy/GST/20111 459-469 dated 30.06.2017	11/2017
6	F3(786)/Policy/GST/20111 470-480 dated 30.06.2017	12/2017
7	F3(25)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-y1/546 dated 22.08.2017	22/2017
8	F3(31)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/675 dated 20.10.2017	27/2017
9	F3(28)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-V1/631 dated 27.09.2017	28/2017
10	F3(38)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-V1/716 dated 08.11.2017	32/2017
11	F3(38)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/717 dated 08.11.2017	33/2017
12	F3(39)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/718 dated 09.11.2017	34/2017

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
13	F3(40)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/719 dated 09.11.2017	36/2017
14	F3(52)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/758 dated 27.11.2017	38/2017
15	F3(68)/Fin(Rev-I)/20I7-18/DS-VI/781 dated 01.12.2017	39/2017
16	F3(53)/Fin(Rev-I)/20l7-18/DS-VI/759 dated 27.11.2017	40/2017
17	F3(41)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/720 dated 09.11.2017	45/2017
18	F3(54)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/760 dated 27.11.2017	46/2017
19	F3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/745 dated 23.11.2017	47/2017
20	F3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 dated 23.11.2017	48/2017
21	F3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/747 dated 23.11.2017	49/2017
22	F3(55)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/761 dated 27.11.2017	50/2017
23	F3(58)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/764 dated 27.11.2017	51/2017

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
24	F3(72)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/826 dated 22.12.2017	55/2017
25	F3(70)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/808 dated 12.12.2017	57/2017
26	F3(71)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/809 dated 12.12.2017	64/2017
27	F3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827 dated 22.12.2017	65/2017
28	P3(74)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/828 dated 22.12.2017	66/2017
29	F3(77)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/37 dated 17.01.2017	70/2017
30	F3(79)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-V1/56 dated 31.01.2017	71/2017
31	F3(80)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57 dated 31.01.2017	73/2017
32	F3(81)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/58 dated 31.01.2017	74/2017
33	F3(78)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/55 dated 31.01.2017	75/2017
34	F3(83)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-V1/74 dated 13.02.2018	01/2018

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
35	F3(82)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/59 dated 31.01.2017	03/2018
36	F3(86)/Fin(Rev-I)/2017-18/ds-VI/92 dated 23.02.2018	04/2018
37	F3(87)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/93 dated 23.02.2018	05/2018
38	F3(88)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/96 dated 23.02.2018	06/2018
39	F3(89)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/94 dated 23.02.2018	07/2018
40	F3(90)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/95 dated 23.02.2018	09/2018
41	F3(96)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/115 dated 1.3.2018	11/2018
42	F2(3)/Policy/GST/2017/99 8-1009 dated 31.10.2017	
43	F3(22)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/515 dated 11.08.2017	

Table No. 2:- Delhi (State Tax-Rate) Notifications

1	F3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/479 dated 31.07.2017	18/2017

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
2	F3(26)/Fin(Rev-I)/2017-l 8/DS-VI/584 dated 06.09.2017	19/2017
3	F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/585 dated 06.09.2017	20/2017
4	F3(27)/Fin(Rev-IV)/2017-18/DS-VI/586 dated 06.09.2017	21/2017
5	F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/587 dated 06.09.2017	22/2017
6	F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-l 8/DS-VI/588 dated 06.09.2017	23/2017
7	F3(37)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/703 dated 06.11.2017	24/2017
8	F3(37)/Fin(Rev-IV)/2017-18/DS-VI/704 dated 06.11.2017	25/2017
9	F3(37)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/705 dated 06.11.2017	26/2017
10	F3(37)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-V1/706 dated 06.11.2017	27/2017
11	F3(37)/Fin(Rev-I)/2017-I8/DS-V1/707 dated 06.11.2017	28/2017
12	F3(37)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/708 dated 06.11.2017	29/2017
13	F3(43)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/743 dated 23.11.2017	30/2017

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
14	F3(44)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/744 dated 23.11.2017	31/2017
15	F3(45)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/749 dated 24.11.2017	32/2017
16	F3(46)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/807 dated 12.12.2017	33/2017
17	F3(47)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/750 dated 24.11.2017	34/2017
18	F3(48)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/751 dated 24.11.2017	35/2017
19	F3(49)/Fin(Rev-D/2017-18/DS-VI/752 dated 24.11.2017	36/2017
20	F3(50)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/756 dated 27.11.2017	37/2017
21	F3(51)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/757 dated 27.11.2017	38/2017
22	F3(56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762 dated 27.11.2017	39/2017
23	F3(57)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763 dated 27.11.2017	40/2017
24	F3(59)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/768 dated 28.11.2017	41/2017

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
25	F3(60)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/779 dated 30.11.2017	42/2017
26	F3(61)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/769 dated 28.11.2017	43/2017
27	F3(62)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/770 dated 28.11.2017	44/2017
28	F3(63)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/771 dated 28.11.2017	45/2017
29	F3(64)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/772 dated 28.11.2017	46/2017
30	F3(65)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/773 dated 28.11.2017	47/2017
31	F3(85)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/97 dated 23.2.2018	01/2018
32	F3(84)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/75 dated 13.2.2018	02/2018
33	F3(91)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/98 dated 23.2.2018	03/2018
34	F3(92)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/99 dated 23.2.2018	04/2018

Sl. No.	File No. and Date of Notification	Notification No.
35	F3(96)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/116 dated 1.3.2018	05/2018
36	F3(98)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/121 dated 7.3.2018	06/2018
37	F3(93)/Fin(Rev-0/2017-18/DS-VI/100 dated 23.2.2018	07/2018
38	F3(94)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/101 dated 23.2.2018	08/2018
39	F3(95)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/102 dated 23.2.2018	09/2018

TableNo 3:- Delhi Other Notifications

1	F3(36)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/702 dated 06.11.2017	
2	F3(17)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/765 dated 27.11.2017	

v/;{k egkn;% अब श्री सत्येन्द्र जैन जी माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित अधिसूचनाओं की हिन्दी अंग्रेजी प्रतियां सदन पटन पर प्रस्तुत करेंगे:

Åtk e=h% माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दु क्रमॉक तीन के उप बिन्दु दो में दर्शाई गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की अंग्रेजी हिन्दी प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ[2]

2 पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 20608—609 पर उपलब्ध।

क) दिल्ली विद्युत विनयामक आयोग आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक प्रथम संशोधन नियम 2018 की अधिसूचना संख्या एफ 1785 डीआरसी 2017—18/5885/20661 दिनांक 15 फरवरी 2018;

ख) दिल्ली विद्युत विनयामक आयोग कोड तथा निष्पादन मानक प्रथम संशोधन

विनियम 2018 के शुद्धिपत्र की अधिसूचना संख्या एफ1785 डीईआरसी विनयम 2017—18/5885/2087 दिनांक 7 मार्च 2018।

okf"kd ctV ¼2018&19½ ij ppk tkjh---

v/;{k egkn;½ बजट पर चर्चा। श्री पंकज पुष्कर जी। दोबारा नाम कैसे आ गया? लक्की हो! पंकज जी।

Jh iadt iq"dj½ माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का और आपका जो मुझे विश्वास मिला है, उसका मैं धन्यवाद देते हुए आज दूसरे दिन बजट चर्चा में शुरूआत करते हुए माननीय फतेह सिंह जी और बाकी सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए, दरअसल सबसे पहले यह अहसास तो करना जरूरी है कि इस दिल्ली विधान सभा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व का काम हो रहा है। मैं सक्रिय राजनीति में आने से पहले एक नागरिक धर्म निभाते हुए और राजनीति शास्त्र के छात्र के तौर पर जो बातें करता हूँ, उसके नाते कम शब्दों में बातें पहुँच जाती है। हमारे एक बड़े प्रिय कवि मित्र आजकल हमसे कुछ नाराज चल रहे हैं तो उस... लेकिन उस परम्परा को बनाए रखते हुए चार पंक्ति में माननीय अध्यक्ष महोदय ये आपकी जो गरिमा है, मैं बहुत सिर झुकाकर सलाम करता हूँ कि आपने खासतौर से

इस सत्र में इस विधान सभा के सम्मान को बहुत बढ़ाया है। हमारे माननीय उप—राज्यपाल महोदय से भी यही अपेक्षा है कि वो संविधान की आत्मा को सशक्त करने का काम करेंगे और हमारे माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे देश में उम्मीद का एक माहौल पैदा किया है। हमारे वो साथी भी जो हम पर बहुत तीखे सवाल करते हैं, कई बार सही करते हैं, कई बार बहुत हल्के भी करते हैं लेकिन उनका भी बड़ा रचनात्मक योगदान है और हम सब लोग... तो मैं चंद पक्तियों में किः

"तुम ही से रोशन हैं चिराग दिल के,
तुम्हीं से आबाद ये बस्तियॉ हैं
भंवर से घिरे हैं, ओझल किनारा,
नाविक नये हैं, नयी किश्तियॉ हैं
नाविक नये हैं नयी किश्तियॉ हैं।।"

मैं एक बहुत बड़ी बात... आज जो बजट भाषण के दौरान माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने कही कि इस बजट का विजन क्या है, एक बात ये कही कि तीन वर्ष से हमने अपने कार्य के आधार पर एक समझ, एक विजन बनाने की कोशिश की है। ये विनम्रता जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उप मुख्य मंत्री महोदय के बजट संभाषण में एक बड़बोलापन नहीं है, एक कर्मयोगी की विनम्रता है कि हमने चल के रास्ते बनाए हैं। हमने किसी अतीत के बोझ को अपने सिर पर नहीं लिया है। ये इस विनम्रता को सलाम करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि सदन में इस पूरे सत्र में छाई रही है, मैं इसको दर्ज करना चाहता हूॅ और बजट पास करना किसी भी विधान सभा का, किसी संसद का वो बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है जिसके चारों ओर पूरा लोकतंत्र घूमता है। आज हमें, बहस इस बात पर

हर रोज हो रही है कि अधिकारी जवाब देंगे, या नहीं देंगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय संकेत करते हैं कि आप इन विषयों पे सवाल पूछते, नहीं पूछ सकते। पूरे लोकतंत्र की बुनियाद में एक सवाल है, एक नारा है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लोकतंत्र का इतिहास खंगालेगे तो टैक्स लेने का अधिकार, नागरिकों का टैक्स देने का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो नागरिकों के उन अधिकार से जुड़ा हुआ है कि नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार है और वो नागरिक धर्म जो है, नागरिक का अधिकार विधान सभाओं में व्यक्त होता है, संसद में व्यक्त होता है तो उसको याद करते हुए एक ऐसा विजन निकाल कर हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय लाते हैं जिसको इन्होंने बहुत सुंदर शब्द दिया ट्रिकल अप, एक पूरे राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लड़ रहा है जो कि अमीरों के लिए कुछ चंद एक दो प्रतिशत लोगों के लिए है। इसको मैंने बहुत गहराई से आकलन किया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, और बहुत ही समय की मर्यादा से बातें तो इतनी ज्यादा हैं कि आप जितना समय देना चाहें, लेकिन एक लियो टॉलस्टॉय नाम के एक वैज्ञानिक, एक विचारक, एक दार्शनिक हुए उन्होंने कहा कि हर कोई गरीबों के भले की बात करता है। आप क्या इतना कर सकते हैं कि गरीबों के जो कंधे पे बैठे हैं, वहॉ से उतर जायें, गरीब अपना भला अपने आप कर लेगा। ये जो सोच है, ये सोच इस बजट में परिलक्षित होती है, यही बजट का मूल एक दर्शन है, उसकी आर्थिक नीति है। ये बहुत अद्भुत तरीके से मनुष्यों में निवेश करने वाला बजट है। ये जो दर्शन है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ संभावनाएं; उत्पादन की संभावनाएं, राजनीति में और आर्थिक संभावनाओं में भागीदारी लेने की संभावनाएं हैं। तो ये एक इस तरह का बजट है जोकि मनुष्यों में निवेश करता है। ये अनूठा बजट

है जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा में आधे से अधिक अपने साधनों का निवेश करता है और यहीं से नारा निकलता है कि 'शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र और समर्थ राष्ट्र।' राष्ट्र जो है किसी तस्वीर का नाम नहीं है, राष्ट्र नारों में नहीं नजर आता। ये आर्थिक दर्शन में नजर आता है।

माननीय महोदय, मैं एक तथ्य आपके सामने रखूँगा। एक न्यू वर्ल्ड वैल्थ की रिपोर्ट है। 2017 में भारत से सात हजार अल्ट्रा रिच अति समृद्ध लोग विदेश में जाके बसे, 2016 में संख्या 6 हजार थी, 2015 में संख्या 4 हजार थी। मगर 7 हजार सुपर अल्ट्रा रिच देश की संपदा लेके या कमाया यहॉ पर और अब विदेश में जाके बस गये हैं। पहले अंग्रेज आते थे देश लूटने, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको लूटने आने की भी जरूरत नहीं, हम इकट्ठा करेंगे और आपके यहॉ जमा कर देंगे। ये उस पूरी राजनैतिक, आर्थिक सोच जोकि देश में साधनों को इकट्ठा करके विदेशों में जमा करना चाहती है उसके बरक्स ये बजट माननीय मनीष सिसोदिया जी एक वो दर्शन लेके आते हैं कि हम जड़ों को सीचेंगे। जिन लोगों की मिट्टी यहॉ की गहराई में जिनकी जड़ें हैं, उनको सीचेंगे, उनको एक समृद्ध नागरिक बनायेंगे, उनको समृद्ध, सम्पन्न नागरिक बनायेंगे। ये कैसी अजीब बात है कि आने वाला वक्त जिस देश के अंदर 60 प्रतिशत युवा रहते हैं, वहॉ पर ये कैसे हो सकता है कि हम युवाओं को लावारिस छोड़ दें, वो युवा जिन बस्तियों से आते हैं उनको छोड़ दें तो एक बजट हमारे सामने है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य उसके केन्द्र में है और हर किसी को आर्थिक भागीदारी देना उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उसका बुनियादी चीज है।

माननीय महोदय, मेरे सामने 2016 का जो इकॉनॉमिक सर्वे है, भारत सरकार का, उसका निचोड़ है। उसमें ये कह रहे हैं इकॉनॉमिक सर्वे स्वयं

कह रहा है, Economic Survey says, "the rich gets implicit subsidy of more than rupees one trillion" . इतने बड़े स्तर पर जो संपन्न एक प्रतिशत, चंद एक प्रतिशत भी न कहें, माननीय महोदय, एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि it is worse that the just the top 30 cases of default account of rupees 1.21 lakh crore which is almost 40 percent of the non-performing assest in bank. केवल अध्यक्ष महोदय, केवल 30 केस ऐसे हैं 30 लोग, 30 परिवार ऐसे हैं जो कि इस देश की 40 परसेंट नॉन परफार्मिंग असैट के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने पूरे बैंकिंग का दिवालिया बना दिया, उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। ये सरकार पहली बार पानी के बुनियादी अधिकार, हर घर में एक पंखा चले, हर घर में एक बिजली का बल्ब जले, उसको सब्सिसडाइज कर रही है। मतलब लोगों को खड़े होने के लिए जगह पैदा कर रही है और जब कि दूसरी तरफ एक ऐसा आर्थिक दर्शन चल रहा है कि 30 लोगों को लुटा दिया पूरा बैंकिंग व्यवस्था। ये बहुत, उस कालिमा के बीच ये बजट कुछ अंधेरे को दूर करने के लिए उस रोशनी की बात करता है।

माननीय महोदय, मैं कुछ तथ्य आपके सामने और रखूँगा। यही जो आर्थिक दर्शन है, केवल देश में सौ, दो सौ, पांच सौ लोगों को सींचने का, केवल 10 लोग हैं जो कि अनिल अम्बानी सवा लाख करोड़, वेदांत अनिल अग्रवाल वन प्वाइंट थ्री करोड़, रूई ब्रदर्स वन करोड़, एक लाख करोड़ का इनके ऊपर देनदारी है, कर्जा है। सवा लाख करोड़ का अनिल अम्बानी के ऊपर देनदारी है, जेपी के ऊपर 75 हजार करोड़। इस तरीके से ये 10 बड़े समूह मिलके इस पूरे देश की संपदा का केन्द्रीयकरण कर रहे हैं, उनको निर्धन बना रहे हैं, उनके हिस्से का संसाधन लूट रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स ये जो ट्रिकल अप की बात है...

v/;{k egksn;% कन्क्लूड करिए पुष्कर जी, अब कन्क्लूड करिए।

Jh iadt iq"dj% माननीय महोदय, मैं पॉच मिनट का समय लूॅंगा।

v/;{k egksn;% नहीं नहीं, और नहीं प्लीज। पुष्कर जी, कन्क्लूड करिए अब। प्लीज।

Jh iadt iq'dj% कल माननीय सदस्य ने...

v/;{k egksn;% एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

Jh iadt iq"dj% माननीय सदस्य ने ये जिक्र किया कि ट्रिकल अप तो उन्होंने शब्द ही नहीं सुना। उन्होंने गॉधी का जिक्र किया, चौ. चरण सिंह का जिक्र किया। ये वो लोग हैं जिसके विरासत के असली लोग इधर बैठे हैं। मैं केवल इतना कहूॅंगा कि उन्होंने अगर किसी को भी ध्यान से पढ़ लिया होता, इस सत्ता पक्ष ने, माननीय मनीष सिसोदिया जी इस का नेतृत्व कर रहे हैं और आर्थिक दर्शन के स्तर पर उन सारे... न केवल चौ. चरण सिंह और गॉधी की परंपरा, बाबा साहब अंबेडकर की परंपरा, वो एक महान आर्थिक, एक अर्थशास्त्री भी थे, उस परंपरा को सींचने का काम किया है जिसमें हम जमीन के नीचे से जमीन पे रहने वाले आम नागरिक को सशक्त करेंगे।

आखिरी बात मैं कहूॅंगा जो आखिरी सैक्शन मेरे हिस्सेदारी का है, वो है शिक्षा की गुणवता के बारे में मुझे अतिरिक्त बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के कमरे बनाना, शौचालयों की स्थिति ऐसी कर देना कि हर बच्चा बहुत सिर उठा के रह सके, भारत के अंदर अलग अलग

देश बना दिए गए थे कि एक इंडिया होगा, एक भारत होगा। ये इस सरकार के बजटीय प्रावधान से संभव हुआ कि आज सब... सर उठा के हर बच्चा स्कूल में जा रहा है। यहॉ पर बालक के सपने छीन लिए गए थे। ये मनीष जी के शिक्षा बजट में संभव हुआ है कि हम बिल्कुल हर बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हैप्पीनैस करीकुलम की बात हो रही है। आज का शिक्षक सिर उठाते ट्रेनिंग ले रहा है। ये नहीं कि कोई नौकरशाह उसको ट्रेनिंग दे रहा है। यहॉ पर बेटियों को सेल्फ डिफेंस की बात हुई, एक रेनबो बजट की बात हुई। यहॉ पर इस बजट में जो बच्चियों को झूठा नारा दे के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं, वो जुमले से बाहर आके हर बच्ची को सिर उठा के एक सशक्त शिक्षा दी जा सके, बहुत मार्मिक मामला है। बच्चियों के स्वाभिमान का मामला है। हर बच्ची को... बहुत आत्मसम्मान के साथ वो लौटे, उसका मामला है। नहीं तो गरीब परिवारों के महिलाएं अपने साथ बच्चे को साथ लेकर कोठियों में काम करने आती हैं।

v/;{k egkn;% पुष्कर जी, आप कन्क्लूड करिए, 15 मिनट हो गये हैं, प्लीज।

Jh iadt iq"dj% मैं केवल ये बात कहके पूरा करता हूँ।

v/;{k egkn;% मैं आपका नाम बोलने को मजबूर हो जाऊँगा।

Jh iadt iq"dj% इसमें भी कमी निकालने के लिए निश्चित रूप से विपक्ष के साथी कुछ सवाल उठायेंगे बात को पूरी करने में, मैं यही कहूँगा, सिर्फ प्रधान जी ही बैठे हुए हैं, बाकी सदस्य तक मेरी बात पहुँचे कि हमें आखिर में वहॉ जवाब देना है, जनता की अदालत में जवाब देना है। तो सच के साथ चलें, इमानदारी की राजनीति के साथ चलें जो इस बजट

का आर्थिक दर्शन है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सशक्त करने का, उसके साथ चलें और झूठ बहुत आगे नहीं चलता। मैं ये पंक्ति कह के बैठ जाना चाहता हूँ कि याद रखें माननीय विजेन्द्र गुप्ता के पास पहुँचे कि सजन रे! झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है, न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।

तो सच के साथ आगे बढ़ें, हैप्पीनेस वाले बजट के साथ आगे बढ़ें, मनीष सिसोदिया जी के उस आर्थिक दर्शन के साथ आगे बढ़ें और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को सक्रिय सहयोग दें, जय हिन्द, जय भारत।

v/;{k egkn;% सुश्री राखी बिड़ला जी।

lqJh jk[kh fcM+yk% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट सत्र पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, 2013 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हरेक सभा में एक ये लाइन जरूर दोहराते थे कि हम दिल्ली में चार सड़कें कम बना लेंगे, चार फ्लाइ ओवर कम बना लेंगे लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को इस कदर बढायेंगे कि जब वो बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या और किसी प्रोफेशन में जायेंगे तो अपने क्षेत्र की सड़कें और पुल खुद बना लेंगे, इनका निर्माण खुद कर लेंगे। एक लक्ष्य शुरू से ही निर्धारित था; शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का प्राइवेटिज्म हो रहा है, व्यापार जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसे खत्म करने के लिये। मुझसे पूर्व... कल से इस विषय पर चर्चा... बजट सत्र पर चर्चा है। मुझसे पहले तमाम सभी वक्ताओं ने जोर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बार बार उन सब चीजों को दोहराने का मुझे कोई औचित्य

लगता नहीं, लेकिन सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ऐतिहासिक हाम कर रही है, ये एक पहलू है लेकिन इसके और भी कई पहलू हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए भी अदभुत काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है।

अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग भारत के वासी, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उसमें भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं। पिछले दिनों अभी हमने नवरात्रों की पूजा की समाप्ति करी है लेकिन अध्यक्ष जी, इस पटल पर, इस सदन में खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कभी भगवान नहीं देखा लेकिन अगर भगवान के रूप में मैं किसी को अगर मानती हूँ तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका मार्ग दर्शन, उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वही बताते हैं कि इस चीज से फायदा होगा, इस चीज से नुकसान होगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, आजादी के आज 70 सालों के बाद इस देश के इतिहास में कभी भी किसी भी जिम्मेदार सरकार ने बुजुगों के बारे में नहीं सोचा। आज 21 वीं सदी के अंदर जहॉ मॉ बाप बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छी नौकरी, अच्छी परवरिश देकर उनको संपन्न जीवन बिताने के लायक बनाते हैं, वहीं आज दिल्ली समेत देश के अलग अलग कोने के अंदर वृद्धा आश्रमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरूआत करी। इस यात्रा के तहत प्रति वर्ष हमारी सरकार लगभग 70 हजार दिल्ली के बुजुर्ग नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवायेगी। ये बहुत ऐतिहासिक जो है, कदम है। इसमें कोई वोटों का लालच नहीं है। अमूमन कोई भी सरकार जब बजट पारित करती

है, तो वो ये देखती है किस समुदाय विशेष के लिए, किस जाति विशेष के लिए बजट को इस तरह से बनाया जाये कि किस तरह से हमें वहॉ से वोट अर्जित हों। लेकिन ये जो एक तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट हमारी सरकार लेकर आई है, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो बुजुर्ग लोग जो अपने आर्थिक कमी के कारण अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में चाहते तो हैं तीर्थ यात्रा करना लेकिन कोई सपोर्ट नहीं होता। लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ बच्चों की पढाई के लिए नहीं, सिर्फ दिल्ली के लोगों के रोग निवारण के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि हमारे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए भी ऐतिहासिक काम कर रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी कड़ी में हमारी दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण के लिए एससी एसटी और अल्पसंख्यक... तकरीबन पिछले तीस सालों के अंदर सात लाख से अधिक छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी है। इतना ही नहीं, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने ''मुख्य मंत्री भीम योजना'' का जो है, लोकार्पण किया, जिसमें हमारे एससी एसटी बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए जो है; आईएस बनना है, या और उन्हें कोई सिविल सर्विसिज की तैयारी करनी है, उन्हें मुफत कोचिंग सैन्टर्स की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। ये व्यक्ति वही सोच सकते हैं जो जमीन से उठे हों। अमूमन ऐसी कमरों में बैठकर बजट बनाया जाता है, किसी भी विशेष वर्ग के बारे में बिना सोचे समझे सिर्फ पेपर काले करने और अपने आप को इस तरह से प्रायोजित करवाना एडवर्टिजमेंट करवाना कि हम इतना बेहतर बजट लेकर आये लेकिन वास्तव में समाज के किस वर्ग को समाज के किस वर्ग में किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, अगर कहीं पर किसी को सीखना है तो वो आकर दिल्ली की सरकार से सीखे, दिल्ली के मुख्य मंत्री, दिल्ली के पूरे मंत्रिमंडल

से सीखे कि किस प्रकार से एक जो क्रमबद्व तरीके से, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो बारहवीं पास कर के हॉयर ऐजुकेशन की और जाने वाला बच्चा हो या फिर विशेष वर्ग से आने वाले बच्चे हों, उनको आगे पढ़ाई किस तरह से मुहैया कराई जाये, वो अपने भविष्य को किस प्रकार से सुनहरा जो है, एक मार्ग दर्शन दे पायें, इस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, इसी प्रकार हम लोग आज तक आजादी के 70 सालों के बाद और हमारे सरकार में आने से पूर्व ऑगनवाड़ियों में किस प्रकार का घोटाला होता था, ऑगनवाड़ियों में किस प्रकार बच्चों के लिए जो भोजन आता था, उसको किस तरह उसमें वितरित किया जाता था, ये किसी से छुपा नहीं है। उसमें किस प्रकार की कालाबाजारी होती थी, किस प्रकार के गोरखधंधे होते थे, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने न सिर्फ बुजुर्गों के लिए, न सिर्फ एससी एसटी समाज के बच्चों के लिए, बल्कि हरेक उस गरीब परिवार के बच्चे के लिए जो है, अपना बजट में अलग से ध्यान दिया है जिनको जीरो से लेकर तीन साल की उम्र में पोषक तत्वों की अति जरूरत होती है। इसके लिए हमारी सरकार ने बारह लाख बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष तौर पर अपने बजट में प्रावधान किया है। अध्यक्ष जी, सिर्फ इतना ही नही, हम लोगों ने अमूमन देखा दिल्ली जैसे राज्य में, मैं बता रही हूँ जो देश की राजधानी है कि ऑगनवाड़ी सिर्फ एक छोटे से कमरे में चलती थी और रजिस्टर में फेक 70–70, 80–80 बच्चों की ऐन्ट्री होती थी, बड़ा मुश्किल था असली डेटा इकट्ठा करना, बड़ा मुश्किल था कि किस प्रकार से ऑगनवाड़ी में बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, खाना अच्छा दिया

जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। सरकार जिस तरह से बजट दे रही है, सरकार जिस तरह से शुद्वता और इमानदारी की उम्मीद कर रही है, वो आखिरी बच्चे तक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ऑगनवाड़ी में पोषण लेने के लिए सफाई कर्मचारी का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ठेला लगाने वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, सिलाई मशीन कढाई करने वाली महिला का बच्चा आता है। वहीं गर्भवती महिलायें ऑगनवाड़ी में आती है तो इसको किस तरह से रोका जाये, इस ऑगनवाड़ी के अंदर व्याप्त काला बाजारी को कैसे रोका जाये! तो एक अदभुत कल्पना, एक अदभुत कार्यक्रम कि इन सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार को देना चाहती हूँ। अमूमन हमारी ऑगनवाड़ी जो वर्कर्स होती हैं, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था। वो काम चोरी करती थी, टाइम पर रिपोर्ट नहीं देती थी। उस सभी पीड़ा को समझते हुए देश में पहला ऐसा दिल्ली राज्य है, जहॉ पर ऑगनवाड़ी वर्कर्स को सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है सिर्फ उसकी सैलरी ही नहीं बढाई दिल्ली सरकार ने, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए एक एक मोबाइल फोन देने का भी प्रावधान दिल्ली की सरकार ने अपने बजट में किया है। मैं इसके लिए दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं कि ऑगनवाड़ी के माध्यम से हमारे मजदूर वर्ग के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, गरीब परिवारों के बच्चों को पोषण मिले, गर्भवती महिलाओं को जो है, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले बल्कि उन बच्चों को बड़े होने के बाद आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए मजदूरों के मिनिमम वेजिज को बढ़ाने का भी ऐतिहासिक काम हमारी दिल्ली सरकार ने किया, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार को देना चाहती हूँ। इसके अलावा...

v/;{k egkn;% कन्क्लूड करिये, राखी जी।

lqJh jk[kh fcMykW% बहुत छोटे छोटे प्वाइंट हैं अध्यक्ष जी, कन्क्लूड कर दूॅंगी मैं बिल्कुल... आपके समय का मैं ध्यान रख रही हूॅं। महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने महिला आयोग का बजट बढ़ाकर कई गुणा करा जिसके माध्यम से देखिये, पिछले ढ़ाई दो साल के अंदर पूरे देश का जो 29 राज्य हैं, 28 राज्यों का महिला आयोग केन्द्रीय महिला आयोग और सिर्फ एक दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग एक तरफ और बाकी पूरे देश के महिला आयोग एक तरफ, उन्होंने कुल मिला कर इतने काम नहीं करे होंगे जितना सिर्फ और सिर्फ हमारी दिल्ली की महिला आयोग की टीम ने किया है। इसके लिए बजट बढ़ाना और वो सारे के सारे संसाधन जुटाने का जो प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हुआ, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूॅं।

दिल्ली की बेटियॉं, जैसे अभी बताया कि पीछा करने पर बेटियों की हत्या की गई, जबर्दस्ती हुई, मना करने पर उनके साथ जो है, मर्डर तक की घटनायें हुई। ऐसे में दिल्ली की बेटियों को मजबूत करने के लिए, निडर बनाने के लिए दिल्ली के स्कूलों के अंदर तकरीबन जो है, हमारी बेटियों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भी बहुत बधाई का कदम, बहुत सराहनीय कदम हमारी दिल्ली सरकार की और से है। उसी में दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा की कड़ी को सुनियोजित तरीके से आगे बढाने के लिए बेटियों में दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए दिल्ली में तकरीबन डेढ़ लाख कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाये जायेंगे ताकि हमारी बेटियॉं जब बाहर निकलें तो अपने आप में एक विश्वास और सुरक्षा की जो भावना है, उसको लेकर निकले...

v/;{k egkn;: राखी जी, अब हो गया, राखी जी...

lJh jk[kh fcM+yk: इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, डीटीसी कर्मचारी जो कि पिछले कई दिनों से लगातार सातवें वेतन आयोग की मॉग कर रहे थे, उन्हें सातवॉ वेतन दिया।

अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में खत्म कर दूंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारी सरकार ने इस वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो ये है कि वर्ष 2018—19 के अंदर 6,903 करोड़ रुपये हमने एमसीडी को दिए। ये कुल बजट का 13 परसेंट है और पिछले बजट में हमने इसे बढ़ाकर वर्ष 2017—18 के अंदर 9.88 प्रतिशत की वृद्धि करी थी। अध्यक्ष जी, इतना बजट का, बजट का 13 परसेंट देने के बावजूद आज भी हमारी दिल्ली की एमसीडी का बुरा हाल है। दिल्ली में आज सिविक सेंटर के अंदर 20 मार्च से सिविक सेंटर पर 5 हमारे सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 27 तारीख हो गई, 7 दिन लगातार, हमारे 5 सफाई कर्मचारी अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मॉगे हैं कि 1/4/1998 से जो लोग पक्के नहीं किए गए हैं, उनको पक्का किया जाए। अध्यक्ष जी, इसको हमारे को मतलब... फील करना बहुत इजी है कि 1998 से लेकर आज 2018 हो गया है, पूरे 20 साल में जो सफाई कर्मचारी 1998 के दौरान आज से 20 साल पहले कच्चे पर लगा था, उसे 20 साल से एमसीडी ने पक्का नहीं करा।

v/;{k egkn;% राखी जी, अब कन्क्लूड करिए, बार—बार राखी जी...

lJh jk[kh fcM+yk% दो मिनट में कर रही हूॅ, अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% नहीं—नहीं, दो मिनट नहीं, अब इसको कन्क्लूड करिए, प्लीज।

l|Jh jk[kh fcMykk% मैं कर रही हूँ, अध्यक्ष जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब पूरे बजट का 13 परसेंट हम एमसीडी को दे रहे है तो ऐसे में क्या कारण हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की तनख्वाह नहीं मिलती? उन्हें पक्का नहीं किया जाता। उनके बकाया एरियर नहीं दिए जाते। जब कोई वीआईपी, अभी 2 अक्टूबर, 2015 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी से 'स्वच्छ भारत अभियान' का नारा दिया था, जब बड़े—बड़े वीआइपियों ने सफाई अभियान चलाया तो उनके ऊपर पूरे मास्क होते, पूरी किट होती है, पूरे साजो सामान के साथ वो अपना अभियान करते हैं लेकिन जो सफाई कर्मचारी अध्यक्ष जी, सड़क पर सुबह 6 बजे जाकर सफाई करता है, पूरी दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी लेता है, आज वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये हमारा सदन एक मत होकर इस बात को पारित करे कि हम इस सदन के अंदर एमसीडी से मॉग करें कि एमसीडी एक 'श्वेत पत्र' जारी करे और इस 'श्वेत पत्र' में बताए कि पिछले 20 सालों के अंदर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एमसीडी ने क्या कार्य किए। पिछले 20 सालों के अंदर सफाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट भी हुई, उनकी मौत भी हुई और दिल्ली की पॉपुलेशन भी बढ़ी, उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो रिक्त स्थान हुए, उनको ध्यान में रखते हुए और जिनकी मौत हुई उनको ध्यान में रखते हुए, एमसीडी ने कितनी नई भर्तियॉ खोलीं क्योंकि अध्यक्ष जी, बहुत दुःखद है 2003 के बाद एमसीडी में कोई भी नई भर्तियॉ नहीं खुली हैं। आप बार—बार समय की पाबंदी लगा रहे हैं, आपको मैं बस, धन्यवाद देते हुए

यही कहना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज हजारों सफाई कर्मचारी सिविक सेंटर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। आप इस सदन के माध्यम से एमसीडी तक ये गुहार जरूर पहुंचाएं कि 'श्वेत पत्र' जारी करके सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई जो है, उस पर जवाब दे, बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

v/;{k egkn;% श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i/kku% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट पर चर्चा के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, चालू वित्त वर्ष के लिए 2017–18 में 48,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित था जिसमें से केवल 44,370 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस प्रकार सरकार अपने अनुमान से 3630 करोड़ रुपये पीछे रही। अध्यक्ष महोदय, वहीं सरकार ने 2018–19 के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। उपरोक्त संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि आगामी वित्त वर्ष में सरकार 8,630 करोड़ रूपया किस प्रकार से खर्च कर पाएगी?

अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं चर्चा करूँगा शिक्षा पर, क्योंकि मेरी विधान सभा और मेरे आसपास की विधान सभा शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्य मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का कि जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे यहाँ विद्यालय नहीं है, मुझे आप वहाँ... तो उन्होंने कहा कि आप जमीन तलाश कर दें, हम आपके यहाँ जमीन खरीद देंगे, पैसा जितना भी लगेगा जमीन का, हम देंगे, उस बात के लिए उनका ध ान्यवाद करता हूँ, आभारी रहूँगा जिदंगी भर... वो भी बता रहा हूँ जी। उसके बाद जब जमीन नहीं मिल पाई कहीं या सरकार खरीदने में असफल रही,

तब मैंने शिक्षा मंत्री से बात की कि हमारे यहॉ एमसीडी की जगह है, आप उसमें से कुछ जगह ले लो, उन्होंने कहा, हम उसका पैसा दे देंगे, आप वहॉ से जमीन दिलवा दो। मैं उनका आभारी हूँ, मैंने वहॉ प्रयास किया जो हमारा ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर हैं, उन्होंने उस पर दो बार ओब्जेक्शन लगाया कि मुझे इस जमीन का 11 करोड़ रुपया चाहिए। उसके बाद मैं भी उनके पीछे पड़ा रहा, दो बार एलजी साहब से उनको कहलवाया गया, उसके बाद आज मुझे खुशी है कि उस जमीन का आज मैंने दिल्ली सरकार को कब्जा दिला दिया है एमसीडी से और वो भी एक रुपये की लीज पर, केवल एक रुपये की लीज पर। वो किराया एक रुपये रहेगा 99 साल का, वो दिलवा दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी ही मेरा 5—4 महीने में स्कूल वहॉ शुरू करा दिया जाए...

v/;{k egkn;% जितने कमरे बना दिए, वो तो बता दो।

Jh txnh'k i/kku% सर, बता रहा हूँ। 76 कमरे बनाए हैं और सरकार ने 500 नए स्कूल खोलने की बात कही थी। उनमें से मात्र... मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मात्र 24 नए विद्यालय बने हैं, कमरे भी बने हैं 6—7 हजार, मैं उसके लिए इग्नोर नहीं कर रहा हूँ सरकार को। तो सरकार जिन विधान सभाओं में स्कूल के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जहॉ एक तरफ हम ढ़ाई से तीन हजार स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। मैं उन विधान सभाओं की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का और उप मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहॉ उन स्कूलों को बंद होने के बाद जहॉ एक—एक विधान सभाओं में उन स्कूलों की संख्या 50 से 100 तक हैं और वहॉ कम से कम 10 से 15—20 हजार बच्चे पढ़ते हैं, यदि वो स्कूल बंद हो जाएंगे

तो क्या सरकार... जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर ऑपरेशन के लिए एक महीन की डेट मिलती है या टाइम नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट अस्पताल से वो अपना इलाज करा ले, हम उसकी पेमेंट करेंगे, क्या सरकार इस तरह का कोई प्रावधान कर रही है कि जहॉ स्कूल बंद हो गए, हम उन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं तो क्या सरकार उसका पैसा व्यय करेगी सरकार?

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूॅं कि जैसे एमसीडी दिल्ली के अंदर किराए की बिल्डिंग लेकर स्कूल चला रही है कई जगह, मेरी जानकारी के अनुसार और मैं जब इस बात करता हूॅं यहॉ कि किराए की जमीन लेकर स्कूल खोल दिए जाएं क्योंकि आज यदि आप जमीन एक्वायर तो कर नहीं सकते क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो एक लैंड बिल लेकर आई थी, उस लैंड बिल के अकार्डिंग किसी किसान की जमीन, किसी दूसरे की जमीन हम एक्वायर नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं जिनके अकार्डिंग जमीन एक्वायर नहीं हो सकती तो उसमें 2015 में नवम्बर में मोदी जी अध्यादेश लाए थे कि जो काम रूके हुए हैं, जमीन के भाव के कारण, उन जमीन को हम एक्वायर कर ले और जहॉ कोई रोड बनना है, स्कूल बनना, अस्पताल बनना है, वो काम हमारे हो जाएं। वो 31 नवम्बर को शायद वो अध्यादेश खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने बिल में संशोधन करने की बात कही। तो मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है कि उसमें हमारी दिल्ली सरकार ने भी मोदी जी की उस बात का विरोध किया। आज मैं सरकार के सामने कहना चाहता हूॅं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूॅं, क्या सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया है कि जहॉ रास्ते चौड़े न होने के कारण, हमारी बसें जाना

बंद हो गई हैं, दिल्ली में जाम की समस्या से हम जूझ रहे हैं, क्या कोई ऐसा बजट में प्रावधान किया है कि हम जमीन एक्वायर कर सकें आज के रेट पर? बहुत सारी विधान सभा ऐसी हैं कि जहॉ स्कूल नहीं है और जिनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी विधान सभा के अंदर बसें नहीं आती। उस समय एक बार माननीय गोपाल जी परिवहन मंत्री थे, तो मैंने जब भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहॉ बसें नहीं जाती हैं तो उन्होंने मुझे उस समय आश्वासन दिया था कि मिनी बसें आ रही हैं। सर, बता रहा हूॅ एक बस आती है वो भी कभी–कभी। सर, मैं वो ही बता रहा हूॅ तो साहब ने कहा था कि हम दिल्ली में बहुत जल्दी मिनी बसें लेकर आ रहे हैं और सबसे पहली वो बस चलेगी तो आपके करावल नगर विधान सभा से मुस्तफाबाद होती हुई चलेगी। हमने धन्यवाद किया गोपाल राय जी का, आज तक उस बस का कोई पता नहीं। फिर मैंने मंत्री जी से पूछा कि कौन सी विधान सभा ऐसी हैं, जिसके अंदर एक बस भी न आती हो तो मंत्री जी ने उस दिन जवाब नहीं दिया। कहने लगे, हम अगले दिन उसका जवाब देंगे। मैं धन्यवाद करता हूॅ कि उन्होंने अगले दिन उसका जवाब दिया और एक बस सुबह 7.50 पर और एक बस 8.20 पर हमारे यहॉ आती है और वो भी बड़े मुश्किल से क्योंकि रास्तों का अभाव है और फिर मैं वही कह रहा हूॅ कि आज दिल्ली सरकार ने तीन–चार हजार बसें खरीदने की बात की है जो तीन साल से कर रही है, अभी तक खरीदी तो कोई गई नहीं है। अब फिर बजट में प्रस्ताव है कि हम तीन हजार बस के आसपास लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूॅ कि बसें तो आप खरीद लेंगे, वो बसें चलेंगी कहां? शास्त्री पार्क जहॉ से आप गुज़रते हो, कई बार दो–दो किलोमीटर लंबा जाम होता है। वहॉ

बसें चलने की कोई जगह नहीं है। क्या वहॉ आज तक कोई फलाइओवर की स्कीम है?

सीलमपुर फ्लाई ओवर की बात करता हूॅ, सत्येन्द्र जैन जी नहीं हैं यहॉ अभी। छः महीने पहले उनके पास गया मैं। सीलमपुर जो एक फ्लाई ओवर बाकी बच रहा है, उसका क्या कर रहे हो? तो उनका जवाब था कि तिवारी जी ने जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के और इस दिल्ली नार्थ से सांसद हैं, कि उन्होंने वहॉ होर्डिंग लगा दिये कि भई हम इस फ्लाई ओवर को बना रहे हैं। इसलिए मैं इस फ्लाई ओवर को नहीं बनने दूॅगा। मैंने तिवारी जी से बात किया कि तिवारी जी आपने ये क्या किया? आपने तो हमारा फ्लाई ओवर रुकवा दिया, तो कहने लगे, भाई मैंकृ वो शुरू करें सत्येन्द्र जैन जिस पर मैं उनके नाम के हार्डिंग लगा दूॅगा। तो मैं कहना चाहता हूॅ कि इस तरह की बदले की भावना से हमें काम नहीं रोकना चाहिए। हमें दिल्ली के विकास की बात करनी चाहिए। भईया मैं... तो आप सुन रहे हैं ना?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% चलो, जगदीश जी अब।

...(व्यवधान)

Jh txnh'k i/kku% अरे! कुछ हमें कहने का मौका तो दें। ये तो भारती जी और वही बात है...

v/;{k egkn;% जगदीश जी, आप ये न कहिये। देखिये, ये मुझे... नितिन जी, एक सैकेंड रुक जाइये। जितना इस सदन में मैं विपक्ष को

समय काक़ृ देख लीजिए तोल कर, बिल्कुल, जितना विपक्ष को समय देता हूॅं। सत्ता पक्ष से मैं काट कर देता हूॅं।

...(व्यवधान)

Jh fotsUnz xqIrk% तो हम नहीं आये? हम ऐसे ही आ गये क्या? अरे! हम जीत के नहीं आये क्या? हम ऐसे ही आ गये हैं?

...(व्यवधान)

Jh fotsUnz xqIrk% अरे! हम आपको जगाने की बात कर रहे हैं। हम दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं। हम पानी की बात कर रहे हैं, बसों की बात कर रहे हैं।

v/;{k egksn;% लेकिन मैं समय देख रहा हूॅं। जगदीश जी, आप कन्क्लूड करिये, प्लीज़।

Jh txnh'k iz/kku% सर, सत्ता पक्ष का काम है तारीफ करना और हमारा काम है दिल्ली की समस्याओं को यहॉ रखना।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% नितिन जी, बैठिये प्लीज़, पुष्कर जी, बैठ जाइये। नहीं–नहीं, बैठिये। नहीं, अभी मैं समय की सुई देख रहा हूॅं बराबर। नहीं, सुई मैं देख रहा हूॅं बराबर, ऐसा नहीं है। आप बोलिये।

Jh txnh'k iz/kku% अध्यक्ष जी, मैं शालीनता के साथ अपनी बात रख रहा हूॅं और दिल्ली की जैनुइन जो समस्या, वो आपके सामने रख रहा हूॅं। अगर आपको इससे कोई एतराज है तो मुझे आप कह दो, मैं बैठ जाता हूॅं।

v/;{k egkn;% नहीं, आप कन्क्लूड करिये, हो गया।

...(व्यवधान)

Jh txnh'k iz/kku% अरे। आप से नहीं मैं बात कर रहा, मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ। आप बोलते बहुत हैं। सुनिये आप।

v/;{k egkn;% नितिन जी, आप बैठिये प्लीज, बैठिये। अब हो गया, कम्पलीट हो गया।

Jh txnh'k iz/kku% अध्यक्ष जी, मैं पानी के ऊपर दो बात और कहना चाहता हूँ और एक सुझाव देना चाहता हूँ कि दिल्ली में पानी की बहुत भारी कमी है। दिल्ली में चार—पॉच... सुनने को तैयार नहीं हैं आप लोग। अरे! मैं सुझाव दे रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा किसी की मैं। आप सुझाव नहीं देते, आप तारीफ करते हैं यहॉ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% पुष्कर जी, ऐसे तो ठीक नहीं है। ये तरीका स्वस्थ तरीका नहीं है।

Jh txnh'k iz/kku% मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में पानी की कमी है। मेरी विधानसभा में 12 कालोनियों में लाइन डाली, उसके लिए धन्यवाद। मगर उस 12 कालोनियों में पैसे लगाने के बाद एक बूंद भी पानी का नहीं है।

v/;{k egkn;% चलिये, कन्क्लूड करिये।

Jh txnh'k i/kku% ओड–इवन में पानी आ रहा था मैं एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वजीराबाद ब्रिज और पल्ला बख्तावरपुर तक जो जमुना बाढ़ आती है उस समय, उसमें एक रिजर्ववॉयर बनाया जाये।

v/;{k egksn;% ये विषय तो आप रख चुके हो भई।

Jh txnh'k i/kku% सर, मैं तो मुख्य मंत्री जी के सामने कहना चाह रहा हूँ।

v/;{k egksn;% कहिये कहिये, चलिये।

Jh txnh'k i/kku% अगर वहॉ कोई रिजर्ववॉयर बन जाये और उसको बनाने के लिए पैसा भी आपको वहीं से मिल जायेगा, जो जमुना में रेती भरी पड़ी है, आप उसको बेच दें और वहॉ एक रिजर्व वायर बना दें दिल्ली की पानी की समस्या खत्म हो जायेगी, धन्यवाद।

v/;{k egksn;% श्री महेन्द्र गोयल जी।

Jh egUnz xks;y% धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मुझे जिस समय ये पार्टी बनी थी उस समय की याद आ गई। उस समय के अंदर इस समय के अंदर हमारे तीन साथी जिन्होंने अनशन किया था, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, इन्होंने ऐलान किया था कि हम पार्टी बनायेंगे। क्योंकि देश के अंदर यदि गंदगी की सफाई करना है तो इस गंदगी के अंदर उतरना पड़ेगा। राजनीति के अंदर आना पड़ेगा। आज मुझे वो साकार होती नज़र आ रही है कि राजनीति के अंदर आकर गंदगी कैसे मिटाई जाती है और

अच्छे काम कैसे किये जाते हैं। उस समय की मुझे पंक्ति याद आ रही है।

'सोच को बदलो, सितारे बदल जायेंगे,
नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जायेंगे।
किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे साथिया,
बस, उसका रुख बदल दो, किनारे बदल जायेंगे।
किनारे बदल जायेंगे।

आज वाकई में आपने किनारों को भी बदल दिया और सही दिशा के अंदर भी जा रहे हैं। मूड में तो हम उसी समय आ जाते हैं जब मुख्य मंत्री साहब के दर्शन हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, अभी मैं हरियाणा में चला गया दो दिन तीन दिन पहले तो हरियाणा में बहुत से बुजुर्ग मिले, बहुत से साथी मिले। बहुत से बुजुर्गों ने कहा भई छोरे ने लट्ठ गाढ़ दिया, मने किस तरह? क्योंकि उन्होंने ये हमारा दिल्ली विधान सभा का बजट को उन्होंने सुना था कि पानी भी फ्री दे रहे हैं, बिजली भी आधे रेट के अंदर दे रहे हैं। हॉस्पिटलों में दवाइयॉ भी फ्री दे रहे हैं और बच्चों की शिक्षा भी फ्री दे रहे हैं। इतने काम करें हैं कि छोरे ने लट्ठ गाढ़ दिया है। मने भइ ये तो वाकई में लट्ठ गाढ़ने वाली बात है। मने हरियाणा में भी गढ़वा लो। बोलूॅगा हरियाणा में भी तैयारी कर दी है और हिसार की रैली को कामयाब करके दिखाया उन्होंने, वो भी अगली... हौर कह रहा हूॅ कि वहॉ पे भी लट्ठ गढ़ गया। अध्यक्ष जी, मैं बजट को देख रहा था... तो 53000 करोड़ का जो बजट पेश किया कितनी खूबसूरती के साथ पेश किया है। और इसमें से खर्च कैसे कर रहे हैं उसके उपर भी आकलन किया। उसमें से मैंने देखा तो शिक्षा के ऊपर जो बजट खर्च कर

रहे हैं, 26.3 परसेंट और देश की 19 स्टेटों का भी इसके अंदर बजट देखा तो टोटल देश के अंदर 16.1 परसेंट बजट खर्च हो रहा है। क्योंकि मुख्य मंत्री साहब की और मनीष सिसोदिया जी की एक ही सोच थी और इस सदन में बैठे हुए सभी साथियों की सोच एक ही है कि देश के बच्चे पढ़ जायेंगे तो देश अपने–आप तरक्की कर जायेगा। इसीलिए शिक्षा के ऊपर जो इतना बजट खर्च किया है, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और हर साल ये बजट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और स्वास्थ्य के ऊपर भी हम देखें तो देश के अंदर जो स्वास्थ्य का बजट खर्च हो रहा है। दिल्ली के अंदर 12.7 परसेंट और देश के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर सिर्फ 4.8 परसेंट कितने शर्म की बात है क्योंकि सोच एक ही है। देश के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, देश के नौजवान स्वस्थ रहेंगे, बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे तो देश अपने आप ही तरक्की कर जायेगा। उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ मैं, देश कैसे तरक्की कर रहा है। देश पूरा का पूरा तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली पूरी की पूरी तरक्की कर रही है। कहीं से भी उठाके देख लो आप। उत्तर से ले के दक्षिण तक और पूर्व से ले के पश्चिम तक। यहॉ नरेला से स्टार्ट हो जाती है हमारी और बदरपुर पे जा के खत्म होती है। तो पूरी की पूरी दिल्ली का आप इतिहास देखोगे तो हर जगह आदमी खुश। हर जगह पानी फ्री, हर जगह दवाइयॉ फ्री, जगह–जगह मौहल्ला क्लीनिक खोल दिये। जहॉ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर दवाई भी इतने महंगे रेटों पे मिलती है और उनको वो फ्री में देने का काम कर रहे हैं। ऊपर से वो टैस्ट फ्री करने का काम कर रहे हैं। ये तो लट्ठ ही गढ़ गया पूरा, दिल्ली के अंदर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि... मैं बहुत सीधी–साधी भाषा के अंदर कह रहा हूँ और अब की

बार तो डीयू के अंदर जो 2000 सीटें बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव रखा है तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी करता हूॅं लेकिन इसके अंदर एक अमेंडमैंट भी चाह रहा हूॅं शिक्षा मंत्री साहब से, कि जब दिल्ली के बच्चे है यहॉ पर, दिल्ली के बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि और स्टेटों केकृ जब और स्टेटों के अंदर कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं और वहॉ पर रिजर्वेशन है तो इसके ऊपर शिक्षा मंत्री साहब से मैं अनुरोध करूॅंगा कि यदि संशोधन हो सके या कानून लाया जा सके कि दिल्ली के बच्चों को यहॉ पर पढ़ने का अधिकार है क्योंकि 12वीं से निकलने के बाद यहॉ पर बहुत कम सीटें हैं, है ना दिक्कत ये? क्योंकि बाहर तो रिजल्ट के पैकेज मिलते हैं, दिल्ली के बच्चों को नहीं एडमिशन मिल पाते, ये एडमिशन मिलते हैं और दूसरी स्टेटों के... किसी का नाम लेंगे तो कहेंगे, ये बुरा मान गए, नकल के पैकेज हैं किसी भी उसके अंदर देख लो आप। और आसपास के तो जितने भी सराउंडिंग के हैं; बीजेपी की सरकारें हैं, इन्होंने तो पैकेज खोल रखे हैं। भई, इतने पैसे दो और ये अपना सीट ले लो। तो इसके अंदर आपसे अनुरोध है कि इसमें अमेंडमैंट हो सके या कोई भी बिल लेके आ सकते हैं तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर ऑगनवाड़ियों में और स्कूलों के अंदर जो आपने सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्दी लग जाएंगे तो इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूॅं।

दुर्घटना से घायल व्यक्तियों के लिए आपने निजी अस्पतालों में योजना के लिए 50 करोड़ का बजट दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही स्वागत करता हूॅं और मैंने पहले भी अध्यक्ष जी, के कहने से एक संशोधन के लिए लिखा

था तो आप दोनों ही बैठे हैं और मुख्य मंत्री साहब भी बैठे हैं कि दिल्ली के किसी भी नागरिक का यदि बाहर भी एक्सीडैंट हो जाता है, तो उसको भी उसका वो हक मिलना चाहिए। आप बाहर के हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर सकते क्योंकि आपका उसके अंदर प्रावधान है कि एफआईआर, एफआईआर तो वहॉ की होगी, वो उस व्यक्ति का, एफआईआर वहॉ की कटी हो और दिल्ली का नागरिक हो तो उसको भी उस दुर्घटना के अंदर वो लाभ मिलना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है।

v/;{k egkn;% महेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh egUnz xk;y% कन्क्लूड तो 2019 में कर दूँगा आपको पहले ही कह रखा है जी, और आप जो 'बुजुर्ग तीर्थ यात्रा' की योजना लेके आए हैं, इसके लिए भी बहुत–बहुत धन्यवाद और ग्रीन बजट भी साथ में आपने पेश किया, आउट–कम बजट के साथ–साथ पहली बार, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूॅ कि 1000 इलैक्ट्रिक नई बसें खरीदी जाएंगी और 905 फीडर बसें खरीदी जाएंगी और 1 अप्रैल, 2015 से 1 मई, 2016 तक जितनी भी ई–रिक्शा है और उनको वो सब्सिडी नहीं मिली थी, तो उसका भी आपने प्रावधान रखा है क्योंकि ये दिल्ली के पर्यावरण को साफ रखने के अंदर बहुत सहायक होती है ई–रिक्शा। तो उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

जैसे कि आपने होटलों के अंदर सीएनजी या बिजली से जो तंदूर चलेंगे तो उसके लिए 5 हजार प्रति तंदूर के हिसाब से आपने सब्सिडी दी है, उसके लिए भी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और सीएनजी लगी हुई नई गाड़ियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है और आपने 50 प्रतिशत की इसके

अंदर छूट दी है तो इससे लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। ये आपने डीजल की और पैट्रोल की गाड़ियों को छोड़कर... वो सीएनजी किट वाली गाड़ी लेंगे तो इसके लिए भी और जो वाई–फाई के लिए है, बच्चों के अंदर इस बात के लिए बड़ी ही... क्योंकि नेट का वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वाई–फाई के लिए जो आपने अब की बार, 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% धन्यवाद, धन्यवाद। श्री नरेश बाल्यान जी।

Jh ujs'k cky;ku% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के उप मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को ग्रीन और क्लीन बजट के लिए बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के लोगों में इस बजट को लेकर बहुत प्रसन्नता है। दूसरे राज्यों की सरकारों से आज सवाल हो रहे हैं कि दिल्ली जैसा 53 हजार करोड़ रुपए का ग्रीन एंड क्लीन बजट आज तक कहीं ओर क्यों पेश नहीं हुआ? बेहतर इलाज, बेहतर शिक्षा, पर्यावरण न केवल दिल्ली के रिहायशी इलाके बल्कि दिल्ली के तीन सौ से अधिक गॉवों में भी आम आदमी की सरकार ने लगातार चौथे साल रखा है, यह बहुत गर्व की बात है। 2015 से अब तक गॉव में हो रहे विकास कार्यों ने दिल्ली के गॉवों की सूरत बदल कर रख दी है। हर बार की तरह इस बार भी गॉवों का विशेष ख्याल रखा गया है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शहरों के साथ दिल्ली के गॉव और निवासियों को भी हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्रीन बजट का पूर्ण फायदा हो, इस बजट से साफ होता है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली और सबसे सस्ता पानी, हर घर तक पक्की सड़क, आधुनिक स्कूल दिल्ली के गॉव वासियों तक पहुॅचाने का काम

आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तकलीफें शायद एक आम आदमी ही समझ सकता है। हमारी सरकार में ऐसा कोई नहीं जो खुद महलों में रहे, दुनिया भर घूमे और केवल भाषण के वक्त दिखाई दे। अच्छे दिनों के वायदे तो काफी किए लेकिन वो केवल बातों में तब्दील होकर रह गए। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर आज देश के ये हालत हैं कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 केवल भारत में स्थित हैं। हमारा ये क्लीन और ग्रीन बजट दिल्ली ही नहीं, दूसरे शहरों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। यह हमारा भरोसा है और हमारा यह प्रयास भी है कि हमारे नारे एजूकेटिड इंडिया, हैल्दी इंडियन, स्ट्रॉग इंडिया को सिद्ध करेगा। इस बजट ने गरीबों की आकॉक्षाओं को नए पॅख दिए है। क्योंकि इसे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। बजट में पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ–साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, इसी के चलते ग्रीन बजट को, एक क्लीन बजट कहलाने लायक है। सरकार ने समाज के हर तबके का ध्यान रखा है और गरीब महिलाओं, छात्रों और मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ पर्यावरण पर भी प्रमुख ध्यान दिया गया है। इस बजट में पर्यावरण, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के 26 कार्यक्रमों और योजनाओं को एक सूत्र में बांधकर एक अभियान चलाने की शुरूआत की है। इसके साथ ही तीन अतिरिक्त चीजें; सड़क, पानी और सीवर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिल्ली सरकार का आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा पहुॅचाने का है। यही वजह है कि सरकार ने पारदर्शी शासन व्यवस्था के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए समय सीमा भी तय की है

कि ये सारी चीजें एक समय सीमा के अंदर कम्पलीट होनी चाहिए। हमने पुराने वायदे के तहत दिल्ली सरकार ने बिजली की दरों में न केवल बढ़ोत्तरी न करने, न केवल मुफ्त पानी देने की योजना को भी बरकरार रखा है, इस बजट का एक ऐतिहासिक पहलू यह भी है कि पिछले चार साल की तरह शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सर्वाधिक 26 प्रतिशत बजट शिक्षा को आबंटित किया है। प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करते हुए 366 नए नर्सरी क्लासिज विद्यालयों के अंदर खोली जाएंगी, छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा सरकार 2018—19 के लिए 12748 नई कक्षाएं, 30 नए स्कूलों के भवन स्थापित करना, एक लाख दो हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे ताकि छात्रों की सुरक्षा में कोई कमी ना आ पाए। इस कदम से साफ होता है कि आम आदमी की सरकार की प्राथमिकता दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा देना। ऐसी योजनाएं बनाने काकृ जो जुमलों से परे जाकर सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए एक नई यूनिवर्सल हैल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है। इसके तहत विस्तृत दिषा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 2018—19 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है। दिल्ली सरकार अपनी मौहल्ला क्लीनिक की लोकप्रिय योजना को लागू करते हुए 760 नए मौहल्ला क्लीनिक अक्टूबर 2018 तक स्थापित करेगी। इसके लिए इसके साथ ही अस्पतालों में बेडों की संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की योजना है। दिल्ली में पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 2018 में ग्रीन बजट में उचित स्थान दिया गया। डीजल के जनरेटरों से बिजली आधारित जनरेटरों को स्विच करने के लिए कंपनियों

को 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी।

v/;{k egkn;% कन्क्लूड करिए बाल्यान जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh ujs'k ckY;ku% इसके अलावा 1000 नई बसें दिल्ली के अंदर इलैक्ट्रीकल बसें चलाई जाएगी। इसके लिए मेरी विधानसभा में भी ककरौला मोड़ से लेकर पंजाबी बाग तक एक ऐलिवेटिड रोड का इस बजट के अंदर प्रावधान रखा है। उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बात के द्वारा अपनी बात खत्म करूंगाः

माना की अंधेरा घना है,
पर दिया जलाना कहॉ मना है
जहॉ सच है, वहॉ हम खड़े हैं,
इसी खातिर
इनकी आंखों में हम गड़े हैं।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% बहुत–बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। श्री गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc flag% धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आज ये सदन इस साल के बजट पर चर्चा कर रहा है और मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया और अलग–अलग तरीकों से पूरी दिल्ली की जनता घर में बैठकर बहुत गंभीरता से इस सरकार से जो उम्मीदें थी, उनको देख रही है और वो उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों को है। आशा भी और उनको विश्वास भी है। हम जब चुनाव जीतकर इस सदन में आए थे तो ये सोचा था कि जो हमने 70 वायदे दिल्ली की जनता से किए हैं, इनको हम शायद पॉच साल कंप्लीट नहीं

होने देंगे और इनको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका अनोथराइज कालोनी के अंदर रहता है। करीबन 50 लाख लोग दिल्ली की 1739 अनोथराइज कालोनी के अंदर रहते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ बजट की और उससे पिछले साल के बजट की बात करूँ, इन दोनों बजट का जो पैसा था, उस पैसे को किस तरह से रोका गया खर्च होने से। इस साल माननीय उप मुख्य मंत्री साहब ने जब बजट बनाया और जब कल परसों किसी साथी ने एक सवाल पूछा कि कितनी बार आपकी और अधिकारियों की और मुख्य मंत्री साहब की इस बजट बनाने से पहले मीटिंग हुई तो उसमें बताया गया कि 40 बार ये एक–दूसरे से मिले हैं। यानी कि कितना गंभीरता से इस बजट को बनाया गया है। 40 बार मीटिंग्स हुई तब जाकर इस बजट को बनाया। 1500 करोड़ रुपये दिल्ली की अनोथराइज कालोनी के लिए रखे गए हैं। पहली बात मैं थोड़ा सा इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सर, थोड़ा सा आपको और इसमें थोड़ी धनराशि और आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि 1300 करोड़ रुपये के हमारे एस्टीमेट ऑलरेडी रेडी हैं और दो ही साल बचे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर आप इसमें कृपा करेंगे, कुछ बजट और बढ़ेगा। तो वो काम हमारे जल्दी पूरे हो सकेंगे लेकिन एक मन में शक भी और मन में संशय भी है, सवाल भी है कि अगर मान लीजिए बढ़ा भी दिया और आज ये 1500 करोड़ रुपये भी हैं, तो क्या ये खर्च हो पाएगा! डीएसआइडीसी विभाग जो दिल्ली के अंदर सड़क बनाने का काम अनोथराइज कालोनी के अंदर करता है, पिछले एक महीने में विधानसभा की जो अनोथराइज कमेटी की जो आपने गठन किया हैं, ऋतुराज जी उसके चेयरमेन है। लगातार हमने मीटिंग की 16 फरवरी... इसी साल 16 फरवरी को एक

मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर डीएसआईडीसी के एमडी साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, यूडी सेक्रेटरी साहब सब उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उसमें सदस्य होने के नाते मैं वहीं मौजूद था। उस मीटिंग के अंदर डीएसआइडीसी फाइनेंस सेक्रेटरी, यूडी सेक्रेटरी सबसे पूछा गया कि भई आप लोग टेंडर फ्लोट क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में जब मीणा जी एमडी थे, इस कमेटी के आदेश पर मीणा जी और पूरा विभाग कालोनियों के अंदर विजिट करने के लिए गया था और उन कामों को जिनको वो कमेटी देखने गई थी, वो अधिकारी जो देखने गए थे, इस साल जब 16 फरवरी को मीटिंग शुरू हुई तो मैंने वहॉ पर कुछ चीजें रखी। सबसे पहला कि किस तरह से कामों को रोकने की कोशिश की गई। तीन—चार इतने बड़े... मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूॅ। एक ए एण्ड जे बिल्डर हैं, जिनको 24/12/2016 को एक काम दिया गया, एक नहीं चार काम मिले, इसको सेम डेट में। 24/12/2016 को चार काम मिले और उन कामों को कंप्लीट होना 2017 में। लेकिन उसके बाद इन्होंने डेट बढ़ा दी कि भई इसको आप 23/12/2017 तक कंप्लीट कर दीजिए। आज की तारीख में भी वो काम... इनकी रिपोर्ट कहती है 67 परसेंट हुआ है बस, अभी तक। ये डीएसआइडीसी की रिपोर्ट कहती है। क्यों रुका ये काम, ये काम क्यों रोका गया, जानबूझकर ऐसे—ऐसे टेक्नीकल कुछ चीजें अड़ाई जाती हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी, इस सबके दौरान एक ऐसा क्लॉज डाला गया कि जितनी भी डीएसआइडीसी या जो भी एजेंसी सड़कें बनाएगी, वो तीन ही कंपनियों से आरएमसी के प्लांट जो उनके होते हैं, वहॉ से गाड़ियॉ मंगाएगी और उसी से रोड बनाएगी। चौथी कंपनी नहीं है कोई भी। अब वो तीन कंपनियॉ उन ठेकेदारों को भी ब्लैकमेल कर रही

हैं, नो–डाउट, उनकी समस्या भी हम समझते हैं। लेकिन ये जो बिल्डर हैं, इसके बारे में हमने कमेटी के अंदर कहा कि जान–बूझकर ये कामों में डिले कर रहे हैं। इनके कामों में लापरवाही है, इनके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया। इनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया डायरेक्टर साहब की तरफ से। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर, ये मैं पिछले साल जुलाई की बात कर रहा हूँ। पिछले साल जुलाई की मीटिंग में ये तय हुआ कि 15 दिन के अंदर यूडी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट डीएसआइडीसी को 280 करोड़ रुपये दे देगा। यकीन नहीं करेंगे हम, अभी जब ये मीटिंग हुई तब पता चला कि सिर्फ 140 करोड़ रुपये दिए गए। 140 करोड़ रुपये की डिमांड! हमने कहा कि भई क्यों नहीं मिले 140 करोड़ रुपये तो यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से था जी, इनसे यूसी सर्टिफिकेट हमें चाहिए। जिसके अंदर ये पूरा ब्यौरा देंगे कि पिछला जो पैसा इनको दिया, वो खर्च किया कि नहीं किया। ये सच्चाई भी है, डीएसआइडीसी ने वो उनको ब्यौरा नहीं दिया। उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले एक हफ्ता–10 दिन पहले 109 करोड़ रुपये डीएसआइडीसी को और ट्रांसफर किए गए। लेकिन कोई टेंडर नहीं लग रहे। इस मीटिंग की जहॉ तक मैं बात कर रहा हूँ 16 फरवरी की। उस मीटिंग के अंदर की कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से ये जो 1500 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की अनोथराइज कालोनी के लिए रखा गया है, हमें डर है कि जिस तरह से पूरे प्लान–वे में अधिकारियों को डराया जा रहा है या अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे सभापति महोदय थे, ऋतुराज झा जी, उन्होंने पूछा

भई बताइए, ये जो 1300 करोड़ रुपये के एस्टीमेट बने हुए हैं। आप इनमें से कितना टेंडर अभी लगा सकते हैं, क्या है? आपके पास फंड की क्या व्यवस्था है? उन्होंने जवाब दिया, डीएसआइडीसी के जो एमडी हैं, वो कहते हैं... पहले तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डवलपमेंट से पूछा गया। वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग ली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगले कुछ दिनों में हम आपको और पैसा दे देंगे और 600 करोड़ रुपये की उन्होंने कमिटमेंट हमसे की है कि आप टेंडर फ्लोट कर दीजिए और हम आपको 600 करोड़ रुपये और दे देंगे। उसके बाद हमने एमडी साहब से पूछा जोकि डीएसआइडीसी के एमडी हैं। उनसे हमने पूछा, ''हॉ जी, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं, आपके सामने बात हुई, बोले हॉ सर, 600 करोड़ रुपये की कमिटमेंट हमको मिल गई है।'' मैं 16 फरवरी की बात कर रहा हूॅ और हमने पूछा, तो बताइए अब ये जो 600 करोड़ रुपये की कमिटमेंट आपको मिली है, आप इनके टेंडर फ्लोट कब तक करेंगे? उन्होंने इस मीटिंग में कहा विधान सभा की कार्यवाही में ये नोट है। उन्होंने ऑन रिकार्ड कहा है कि 15 दिन के अंदर हम 600 करोड़ रुपये के हम टेंडर कॉल कर देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूॅ कि 8 मार्च को, 13 मार्च को बैक टू बैक मीटिंग हुई और डायरेक्टर साहब ने... आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने साफ कहा कि मैं अब ये 600 करोड़ रुपये के टेंडर नहीं करूॅगा। मैं इन 600 करोड़ रुपये के टेंडर करने के लिए अपने शेयर होल्डर से पूछॅूगा। अब शेयर होल्डर कौन है, जानिएगा, शेयर होल्डर है लेफ्टिनेंट गर्वनर साहब। यानी कि दिल्ली के स्टेक होल्डर कह रहे हैं कि जी, वो उनसे पूछॅूगा। यानी कि हमने पूछा कि भई कितनी बार दिल्ली के इतिहास में अनोथराइज कालोनी के लिए टेंडर लगाने के

लिए आपने फाइल एलजी साहब के पास भेजी है? उन्होंने खुद रिकार्ड में कहा कि आज तक कोई फाइल नहीं गई है, लेकिन अब भेज रहे हैं वो। ये सारा का सारा काम दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए एक गहरी साजिष रची गई... एक गहरी साजिश रची गई है तो कैसे यकीन कर लें कि जो 1500 करोड़ रुपये रखे भी गए हैं... और मान लीजिए...

v/;{k egksn;% गुलाब जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh xqykc flag% सर, बहुत मुख्य विषय है, आपको इसमें थोड़ा बोलने का मुझे समय देना पड़ेगा। सर, मैं यह कहना चाह रहा हूॅ कि ये यकीन नहीं हो रहा कि ये 1500 करोड़ रुपया हमारे...

v/;{k egksn;% जगदीप जी।

Jh xqykc flag% इम्प्लीमेंट होंगे, खर्च होंगे।

Jh txnhi flag% गुलाब सिंह जी, एक मिनट रुकिए।

v/;{k egksn;% जगदीप जी।

Jh txnhi flag% सर, एक बहुत सीरियस मुद्दा है जिसमें मुझे बीच में चर्चा रोकनी पड़ रही है। वहॉ पर कुछ सिख लोगों को महेन्द्र गोयल जी ने बुलाया हुआ था और उनमें से कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो यहॉ पर गार्ड्स लगाए गए हैं, उन्होंने उनकी पगड़ियॉं हिला हिला के उनकी पगड़ियों में हाथ डाल डाल के चेक किया है और वो सारे वहॉ पे खड़े हैं, कह रहे हैं, हमें ऑर्डर्स हैं, इस तरीके

से चेक करना है। अगर उनको चेक करना है मेटल डिटेक्टर होता है। मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा सकता है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वहॉ पर बहुत सारे लोग वहॉ इकट्ठे हुए हैं। ये आप एसीपी को बुलाके अभी की अभी संज्ञान लें। ये एक बहुत ही मतलब इन्सल्ट वाली बात है ये कि इस तरीके से अगर यहॉ पर विधान सभा में चेक किया जाएगा। मतलब किसी की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा, बहुत गलत बात है ये।

v/;{k egkn;% मैं देखता हूॅ, इसको देखता हूॅ अभी। अभी संज्ञान में लेता हूॅ इसको।

Jh jkts'k _f"k% ये फ्रांस में होता था। हिन्दुस्तान में हो रहा है ये सब।

v/;{k egkn;% मैं इसको लेता हूॅ जरा। संज्ञान में लेता हूॅ, बैठिए।

Jh txnhi flag% वो लोग अभी भी वहॉ पर एल.जी. गैलरी के पास बने हुए हैं उनके और उनको वहॉ खड़ा किया गया है।

v/;{k egkn;% संज्ञान में आ गया है मेरे। मैं एक्शन लेता हूॅ इस पर, जो भी है।

Jh txnhi flag% आप एटलीस्ट उनको अन्दर बुलाके, अन्दर बैठिए, बस इतना तो ऑर्डर कीजिए।

v/;{k egkn;% कहॉ हैं।

Jh txnhi flag% क्योंकि उनके पास पासिज हैं, वो वहॉ खड़े हुए हैं।

v/;{k egksn;% मुरूगन जी, एक बार देखिए जरा।

Jh xqykc flag% अध्यक्ष महोदय, और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुःख है कि 1500 रुपये का इस बजट में प्रावधान इस साल में रखने के बाद जब बजट पे चर्चा हो रही है तो महोदय, जो एमडी हैं डीएसआइडीसी के शायद देश से बाहर घूम रहे हैं। ये गंभीरता दिखाती है। ये कि किस तरह से ये सदन में जो पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है, क्यों उनके रोड नहीं बन रहे हैं? ये उनकी जो लापरवाही ये दिखाती है। मेरा सदन से ये कहना है कि वो किस को तो जानकारी दे के गए; चीफ सैक्रेटरी सारी को दे के गए, मुख्य मंत्री साहब को दे के गए, उप मुख्य मंत्री साहब को दे के गए या मंत्री साहब को दे के गए, किस को ये दे के गए? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो आज एमडी साहब बैठे हैं यहॉ पर, मैं ये चाहता हूॅ कि इस पूरे मामले की जॉच... ये सारी मिनट्स निकलवा के और ये पूरे मामले की जॉच सब कुछ प्रश्न एण्ड संदर्भ कमेंटी को, पिटिशन कमेटी को ये मामला सौंपा जाए क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल के अन्दर इस तरह की लापरवाही हुई है, जानबूकर कुछ बिल्डर्स के ऊपर जो रोड बनाने वाली एजेंसी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। जानबूकर ऐसे क्लॉज डाले गए कि अंबुजा, एसीसी, से आप प्लांट से आप सीमेंट ले आइए, वहीं ये आप उनसे कंक्रीट खरीदिए, वहीं से सब कुछ कीजिएगा। तो कहीं न कहीं इसके अन्दर कोई न कोई साजिश है जो दिल्ली की जनता के हित में हम काम करना चाहते हैं। ये ऐतिहासिक बात है कि ये पहली सरकार है कि विधायक निधि कोष जो होता है, एमएलए फंड जो होता है, पहली बार... ये सरकार है जिसने ये प्रस्ताव पास किया कि अभी अनॉथराइज कालोनी में भी लगे। ये पहली सरकार है जिसने कई सारी

कालोनियों के अन्दर हाइ टेंशन तारे हटाई है। ये पहली सरकार है जिसने पिछले 15 साल में जो 300 कालोनियों में लाइन डली। लेकिन पिछले तीन साल में 450 अनधिकृत कालोनियों में लाइन डालने का इतिहास रचा, ये पहली वो दिल्ली सरकार है। इसलिए इन कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।

मेरा आपसे पुरजोर ये निवेदन है कि इस पूरे मामले को प्रश्न एण्ड संदर्भ कमेटी को सौंपा जाए, पेटिशन कमेटी को सौंपा जाए और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो एमडी साहब हैं, ये पिछले 15 साल से कहॉ कहॉ रहे, किस किस पोस्ट पर रहे, कितने कार्यों को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, कितनी इसकी विदेश यात्राएं हुई, सारी इनकी जॉच की जाए और सख्त से सख्त कोई भी कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर करके और ऐसे अधिकारी को दंडित करना चाहिए जिससे कि दिल्ली की जनता का भला हो सके और मैं इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक नया जो प्रोग्राम लॉच होने जा रहा है, 'डांस और सिंगिंग कम्पीटिशन' दिल्ली के अन्दर एक जो माहौल बना है पूरी दिल्ली के अन्दर ये पहली सरकार है कि अभी तक स्कूल के प्रॉगण से बच्चे बाहर निकल कर अपना कहीं पे टेलेंट नहीं दिखा पाते थे, लेकिन सरकार ने माननीय उप मुख्य मंत्री साहब को मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं, बच्चों ने एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया है और एक सरकार ने कहा, अगर बेटे आपके अन्दर टेलेंट है तो आओ, और टेलेंट दिखाओ। और ये टेलेंट अगले कुछ दिनों के अन्दर दिल्ली के अलग अलग विधान सभाओं में, दिल्ली के 272 वार्डों के अन्दर आपको दिखेगा और पूरी दिल्ली की जनता में इस चीज को लेकर अब

सभी पैरेंट्स में, अभिभावकों में बहुत जोश है और एक वो समय आएगा जब दिल्ली का कोई स्टार बच्चा आकर माननीय मुख्य मंत्री साहब से इनाम लेगा और दिल्ली का टेलेंट ढूंढने का काम इस सरकार ने अभी किया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि इस अधिकारी के खिलाफ और डीएसआइडीसी के इस सारे जो जितना काम रोकने की कोशिश की है, इसके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए।

v/;{k egksn;% धन्यवाद। भई, मेरे पास बहुत स्लिप आई हैं, समय को बढ़ाने में बहुत दिक्कत है प्लीज, श्री विजेन्द्र गुप्ता।

Jh fotsUnz xqIrk% अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय सदन में कम रखा गया है, इसको ज्यादा रखना चाहिए था। दो ही दिन रखा गया, वो भी एक एक घण्टे। मैं यही कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण मामला है बजट। बजट सत्र है लेकिन बजट सत्र पर जितना समय सदस्यों को मिलना चाहिए, उतना मुझे लग रहा है, नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया...

v/;{k egksn;% आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि अच्छा बजट है।

Jh fotsUnz xqIrk% उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ का इश्यू था, जी...

v/;{k egksn;% आपकी मुस्कुराहट बता रही है, अच्छा बजट है।

Jh fotsUnz xqIrk% हॉ, हॉ, बिल्कुल मैं बहुत ही... मैं तो अध्यक्ष जी, सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा और बजट पर कहूँगा और बजट के अलावा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि दिल्ली सरकार वित्तीय संकट

से जूझ रही थी। मैं अभी बैठा हुआ देख रहा था पिछले 2011–12 से लेकर के और 2015–16 से अगर शुरू करें। 2015–16, 2016–17, 2017–18, तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं कान्सटेंट सी थी क्योंकि जो स्टेट के जो ऑन टैक्सेज हैं विशेष रूप से सेल्स टैक्स और अब जो एसजीएसटी जुड़ा है, तो वो 21 हजार करोड़ के आस पास उसी के आस पास घूम रहा था। लेकिन 2017–18 में एक जम्प होता है। एक जुलाई, 2017 के बाद और मैं देख रहा हूॅ कि ये लगभग 26 हजार करोड़ के करीब इस वर्ष पहुंचा है यानी कि 4750 करोड़ रुपया अतिरिक्त सिर्फ जीएसटी से इस सरकार को प्राप्त हुआ है और ये जो वॉल्यूम बजट का बढ़ा है जिसको अपनी पीठ खुद ठोक रहे थे। अपनी सरकार की पीठ ठोक रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब। 30 हजार करोड़ तक जो सेल्स टैक्स और जीएसटी यानी कि लगभग 23,400 के करीब जीएसटी से आएगा और 6600 करोड़ रुपया जो कॉन्सटेंट चला ही रहा है लगभग लिक्कर और बाकी चीजों से जो सेल्स टैक्स आ रहा है पैट्रोल, डीजल से, तो एक तो... लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं, जीएसटी की तारीफ की। ठीक है, सड़क पर आप विरोध कर रहे हो। लोगों के बीच में आप भ्रम पैदा कर रहे हो। लेकिन जो वास्तविक दिल्ली को उसका लाभ मिला है, जीएसटी से जो 19 परसेंट की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में वो रिमॉर्केब्ल है, उसको बताने में पता नहीं क्यो आप हेजिटेट कर गए और वो 50–50 का जो शेयरिंग हुई है, सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी की, कितना बड़ा शेयर केन्द्र के करों का आपको मिला है और बिना टैक्स वो एनहांस किए। तो अगर इस सदन में आप केन्द्र सरकार की, वित्त मंत्री जी की, देश के प्रधान मंत्री जी की, जीएसटी से होने वाले लाभ को अगर यहॉ कहते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन मैं देख रहा हूॅ,

यहॉ बार बार हमारे सत्येन्द्र जी तो... उन्होंने तो पकड़ ही रखा है, एक बात... कोई एमसीडी की बात आए, हमें तो 325 करोड़ रुपये मिलता है, हमें तो 325 करोड़ रुपये मिलता है। आज वो भी मैं बता दूॅ, आपको कि आपको 325 करोड़ नहीं मिलता है। आपको देखिए जो ग्रॉट मिल रहा है, वो 2017–18 में 4432 करोड़ इसके साथ साथ जो पेंशन एण्ड जीपीएफ जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट पे करती है, वो सरकार पे नहीं करती। 3750 करोड़ रुपया हर साल वो मिलता है आपको। 3750 करोड़ रुपया, क्योंकि वो बजट प्रस्तावों में आप उसको रिफलेक्ट नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। वो होता नहीं है तो इसलिए उसके बारे में आप सदन को नहीं बताएंगे और साढ़े सात हजार करोड़ रुपया आपको इस साल अतिरिक्त जीएसटी के लागू होने से आ रहा है। साढ़े सात हजार करोड़! ये लगभग बनता है 16 हजार करोड़ रुपये। अब मैं... 4432 लीजिए, लिखिए, लिखिए। लिखिए सर, 4432 करोड़, फिर जवाब भी तो देंगे आप। 325 करोड़, 4757 करोड़, पेंशन एंड जीपीएफ से 3750 करोड़, जीएसटी से 7500 करोड़, 16007 करोड़। हालांकि इस बजट में एक बात जो अलार्मिंग है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है और कैपीटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। जिस प्रोपोर्शन में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। देखिये, 2015–16 में आपने जो कैपीटल एक्सपेंडिचर किया वो आपका... सब लिखा है, सब लिखा है मेरे पास। सब लिखा है नहीं तो मनीष जी की किताब में लिखा हुआ है सब। देखिये, जो कैपीटल एक्सपेंडिचर है, वो 2015–16 में 8853 करोड़ था, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 26343 करोड़ था। अब 2016–17, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ कर हो गया 29082, लेकिन कैपीटल एक्सपेंडिचर कम हो गया 8182, फिर और आगे चलिये 36326 रेवेन्यू

एक्सपेंडिचर, कैपीटल एक्सपेंडिचर 8044, फिर और आगे चलिये, अब जो आपने बजट बनाया 43091 और कैपीटल एक्सपेंडिचर 9908, वो तो प्रपोज किया है। जब 8044 आया है तो तब वो प्रपोज 10000 करोड़ किया था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो हो जायेगा क्योंकि बारह, साढ़े बारह हजार रुपये तो आप सैलरी में बॉटेंगे, सेवन्थ पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया है और भी जो आप दे रहे हैं कि जो भी आप दे रहे हैं; कॉलेजेज का दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, रेकरिंग एक्सपेंडिचर सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई सरकार कर रही है तो कोई तीर नहीं चला रही है। अब उसमें कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं, उसको जरूर उप मुख्य मंत्री जी बतायें और जस्टिफाई करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद भी दिल्ली के विकास की गति और उसके फायदे लोगों को किस प्रकार होंगे क्योंकि कैपीटल एक्सपेंडिचर में लगातार गिरावट आना, अभी जितने दावे यहॉ किये गये हैं, अभी यहॉ अस्पतालों के बारे में जो बात हो रही थी, वो भी इस बात को रिफलेक्ट करता है कि हमारा जो इन्फ्रॉस्ट्रक्चर है, दिल्ली का, वो कहीं न कहीं पिछड़ रहा है और अगर कैपीटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो इसका मतलब साफ है कि हम एक जो इन्वेस्टमेंट होती है शहर के अंदर, उस पर ध्यान हमें देने की जरूरत है। वो कहीं न कहीं पिछड़ रही है क्योंकि अगर ट्रैफिक पे कंजेशन आये, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक बहुत से कारण, बहुत दिक्कतें हैं तो कंजेशन को कम करने के लिए आपने क्या किया? अब 31000 करोड़ रुपया... आप 325 करोड़ की बात करते हैं। 31 हजार करोड़ रुपया दिल्ली में कंजेशन को कम करने के लिए एनएच–1, एनएच–2, एनएच–8, एनएच–10, एचएनएनएस–24 और इस्टर्न पैरिफेरेल एक्सप्रेस वे, ये तो मनीष जी जरूर जानते होंगे क्योंकि इस्टर्न का मामला है और जो ये पूरा एक

सरफेस बन रहा है दिल्ली से बाहर, अध्यक्ष जी, पचास परसेंट ट्रैफिक... दिल्ली में जो ट्रक आ रहे हैं, वो 15 अप्रैल के बाद दिल्ली से बाहर हो जायेंगे, दिल्ली में नहीं आयेंगे। दो लाख व्हीकल पर डे दिल्ली में कम एंटर होगा क्योंकि ये गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद, पलवल ये जो कोंडली से ये पूरे का पूरा एरिया बाइपास कर जायेगा दिल्ली को और जो ट्रैफिक दिल्ली एंटर कर रहा था, जो जो सड़क निजामुद्दीन से उत्तर प्रदेश सीमा तक दो हजार करोड़ रुपया खर्च करके तैयार हुई है, नौ किलोमीटर, नया रिंग रोड चार हजार करोड़ रुपये से बन रहा है। धौलाकुआं से एयरपोर्ट... हम सब फंसते हैं जब हम जाते हैं बाहर, सिग्नल फ्री किया जा रहा है। काम शुरू हो गया है। ये जो सारी योजनाएं अगर केन्द्र के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार... अब दिल्ली की सरकार बात करती है कि शुरू की थी तीस हजार बेड होगें, 10 हजार से बढ़कर हम 30 हजार बैड करेंगे दिल्ली में, लेकिन तीन साल में स्थिति ये हैं कि एक नया बैड सरकार जोड़ने में सफल नहीं हुई। अब हैल्थ सर्विसेज पर आ जाइये, अगर आप हैल्थ पर भी बात करते हैं।

v/;{k egkn;% कंक्लूड करिये विजेन्द्र जी।

Jh fotsUnz xqIrk% देखिये, हो गया ना, पॉच मिनट में कन्क्लूड हो गया।

v/;{k egkn;% 15 मिनट हो गया।

Jh fotsUnz xqIrk% मतलब लीडर आफ अपोजिशन बोलेगा और उसको पॉच मिनट में कन्क्लूड कर देंगे आप।

v/;{k egkn;% 15 मिनट पूरे हो गये हैं।

Jh fotsUnz xqIrk% बड़ी अजीब सी बात!

v/;{k egksn;% 15 मिनट।

Jh fotsUnz xqIrk% सर, मुझे मौका दिया जाये।

v/;{k egksn;% मैं पूरी घड़ी देख रहा हूँ।

Jh fotsUnz xqIrk% मैं सरकार को आइना दिखाना...

v/;{k egksn;% विजेन्द्र जी। एक सेकेंड...

Jh fotsUnz xqIrk% 10908 बैड हैं आपके पास, 10908 बेड।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% और मैं चारों को...

Jh fotsUnz xqIrk% लेकिन...

v/;{k egksn;% चारों के नाम आये, चारों को बुलवाया।

Jh fotsUnz xqIrk% 10908 बेड हैं।

v/;{k egksn;% फिर उसके बाद कहें कि समय नहीं मिल रहा है।

Jh fotsUnz xqIrk% सेंट्रल हैल्थ...

v/;{k egksn;% मुझे सोचना होगा इस बात पर।

Jh fotsUnz xqIrk% सेंट्रल गवर्नमेंट के 11110 बेड हैं दिल्ली में। आज भी आपसे ज्यादा बैड सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। फिर आपके पास... आप एमसीडी

की बात करते हैं। चार हजार बैड दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के हैं। 10 हजार आपके चार हजार। अगर आप इसकी बात करें, दिल्ली के अंदर पिछले तीन साल में 2014–15 में 4896 बैड थे, 2016–17 में ये बढ़कर हो गये 53329 बैड, यानी कि लगभग 5300 बैड बढ़े और दिल्ली सरकार ने उसमें से कितने बढ़ाये बैड नहीं बढ़े क्योंकि पूरा हैल्थ सेक्टर या तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, नर्सिंग होम्स की तरफ जा रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्था वहीं की वहीं है, जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, दिल्ली के अंदर बैड बढ़ाने की। अब अगर मैं बात करूँ... कि आप बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर मैट्रो की बात करते हैं आप। मैट्रो आपके लिए एक अपोर्च्युनिटी है। फिफ्टी परसेंट इक्विटी पर। दिल्ली सरकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी रिस्पोंसिबिलिटी है। आपका सहयोग करने के लिए दिल्ली में मैट्रो पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पचास परसेंट इक्विटी के साथ हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि आप बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे सकें, लेकिन आपकी अपनी पब्लिक ट्रॉसपोर्ट की क्या स्थिति है डीटीसी की? मैंने क्वेश्चन लगाया था, ये मेरे पास इसका जवाब है। मैं इन प्रश्नों के उत्तर...

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिये।

Jh fotUn xIrk% संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ।

v/;{k egkn;% भइ इसको कन्क्लूड करिये आप।

Jh fotUn xIrk % इसमें...

v/;{k egkn;% ये लंबा चौड़ा नहीं चलेगा।

Jh fotsUnz xqIrk% ये जवाब में लिखा है, जब मैंने पूछा कि क्या यह सत्य है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट द्वारा डीटीसी के संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें डीटीसी के प्रबंधन की अलोचना की गयी है। तो उत्तर आया, जी हॉ। क्या क्या आलोचना है, क्या रिसर्च कहती है, बसों की भारी कमी है। सबसे बड़ी बात गैर भरोसेमंद बस सेवा, लोगों का विश्वास नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम के अंदर प्रति दिन आप कह रहे हैं कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ये रिपोर्ट कहती है, कम हो रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो संख्या बढ़ी भी, अगर आप कहते हैं तो आपने क्या दिल्ली में एक भी बस जोड़ी तीन साल में? इसी मेरे प्रश्न के उत्तर में। मैंने पूछा यदि हॉ तो तीन वर्षों के कार्यकाल में अब तक सरकार ने कितनी बसें खरीदी हैं। तीन वर्ष के कार्यकाल में अब तक दिल्ली परिवहन निगम ने कोई भी नई बस नहीं खरीदी है, ये मुझे उत्तर मिला है। तीन साल में... ये जब मैंने ट्रॉसपोर्ट मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि तीन साल में हमने एक भी बस नहीं खरीदी है। सवाल ये है कि आपने तीन साल में एक भी बस नहीं खरीदी। दिल्ली के अंदर बसें नहीं हैं।

v/;{k egksn;% विजेन्द्र जी, अभी माननीय मंत्री जी को बोलना है।

Jh fotsUnz xqIrk% दिल्ली के अंदर ट्रॉसपोर्ट व्यवस्था...

v/;{k egksn;% इसको अब कन्क्लूड करिये।

Jh fotsUnz xqIrk% एजुकेशन की अब बात करते हैं। एजुकेशन के अंदर दिल्ली के अंदर...

v/;{k egkn;% भइ विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिये।

Jh fotsUnz xqIrk% कुल 44 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं।

v/;{k egkn;% 20 मिनट पूरे हो गये हैं।

Jh fotsUnz xqIrk% अध्यक्ष जी, लेकिन...

v/;{k egkn;% 20 मिनट का समय।

Jh fotsUnz xqIrk% मैं आपको साकेत, जे ब्लॉक की बात बता रहा हूँ।

v/;{k egkn;% अब मैं रोक रहा हूँ प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk% 44 कमरों वाले स्कूल के कमरे तोड़ दिये।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि बैठ जाइये। बैठिये, प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk% 44 कमरे तोड़कर वहॉ नये कमरे बना रहे है। लोगों ने कहा कि इन कमरों में तो कोई बुराई ऐसी थी नहीं, तो आप अगर कमरे तोड़कर नये बनाके ये कहें कि हमने इतने अतिरिक्त कमरे बना दिये...

v/;{k egkn;% बैठिये, मैं समय को...

Jh fotsUnz xqIrk% इतने क्लासरूम बना दिये, तो इसका बड़े दुःख की बात है।

v/;{k egkn;% चलिये, कोई बात नहीं।

Jh fotUn xIrk आप नेता विपक्ष को नहीं बोलने देते।

v/;{k egkn; नहीं नहीं, ठीक है अब। नहीं, मैं अब कह रहा हूँ। मैं आगे ध्यान रखूंगा भाई। आगे मुझे चारों को समय देना है, दो को देना है, मैं देखूँगा।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; कोई बात नहीं, अब आप बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk उसके अलावा किसानों के साथ दिल्ली में आप कहते हैं कि दिल्ली में खेती नहीं होती। किसान नहीं है। दिल्ली के किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आपने यहॉ पर कहा एन्वायरनमैंट को लेकर के... पहले बजट में मनीष जी ने कहा था। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; विजेन्द्र जी, ये उचित नहीं है। ये तरीका उचित नहीं है।

Jh fotUn xIrk यमुना को ब्यूटीफाई किया जाएगा। यमुना का क्या हाल है आज, आप बता सकते हैं? आपने कहा था कि बिजली वितरण में एक से अधिक कम्पनियॉ लाकर प्रतिस्पर्धा करवाने की बात करेंगे। कहॉ गई वो योजना? 'लास्ट माइल कनेक्टीविटी' आपने कहा था। व्यापारियों को 'सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स' आपने कहा था। आपने कहा था 'वरिष्ठ नागरिक आयोग' बनाएंगे। स्लम मुक्त दिल्ली बनाएंगे। एक स्लम ड्वैलर को अपने घर नहीं दिया। आपने 3113 करोड़ रुपया आपने 2017–18...

v/;{k egksn;% विजेन्द्र जी अब मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ।

Jh fotsUnz xqIrk% ग्रामीण विकास बोर्ड पर...

v/;{k egksn;% विजेन्द्र जी, अब आप बैठिए। अब मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ, बैठिए अब। विजेन्द्र जी, अब बैठ जाइए प्लीज। विजेन्द्र जी, प्लीज, बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, अब मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी। नहीं, विजेन्द्र जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। ये ज्यादती है। ये अतिक्रमण है। हॉ, बैठिए आप।

Jh fotsUnz xqIrk% विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे है आप।

v/;{k egksn;% मैं सदन का समय सदस्यों के संख्या के अनुसार आगे से एलाट करूँगा। आगे से मैं वैसे चलूँगा, बैठिए। आप बार–बार ये कहते हैं एलाट नहीं करते। विपक्ष को बोलने नहीं देते। मैं आगे से सदस्यों की संख्या के अनुसार डेली का समय एलाट करूँगा। बैठिए, प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय श्री गोपाल राय जी।

Jh fotsUnz xqIrk% ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है।

v/;{k egksn;% बीस मिनट पूरा हो गये। बीस मिनट से ज्यादा क्या समय लेंगे? नहीं, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। श्री गोपाल राय जी। सोमनाथ जी, प्लीज। ये एक–एक मिनट सदन का महत्वपूर्ण है प्लीज।

Je e=h ¼Jh xksiky jk;½% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बात रखने का मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बजट पर अपनी बात रख रहे थे तो ऐसा लग

रहा था कि वैसे तो बोलने के लिए समय और मॉग रहे थे लेकिन जिन–जिन बिन्दुओं का उन्होंने जिक्र किया। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कुछ ढूॅढ़ रहे है कि बोलने के लिए कुछ तो मिल जाए। कुछ समय उन्होंने केन्द्र सरकार की तारीफ में गुजारी और कुछ समय जो उन्होंने गुजारा सरकार के इस बजट की आलोचना में जिन तथ्यों को रखा, वो भी आधे–अधूरे रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र जी ने कहा कि केन्द्र सरकार दिल्ली वालों के लिए इतने इतने इतने... पैसे देती है। केन्द्र सरकार आज भी जितनी दिल्ली वालों से लेती है, उतने देने की हिम्मत नहीं रखती है। केन्द्र सरकार अपने जेब से नहीं देती है दिल्ली वालें को। जो देती है, वो दिल्ली वालों का पैसा है और जिम्मेदारी है। ये एहसान नहीं है। विजेन्द्र जी ने कहा, मेट्रो में 50–50 का अवसर मिला है दिल्ली के लोगों को। ट्रॉसपोर्ट व्यवस्था दिल्ली की जिम्मेदारी है। पैसा देना हो तो दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है और दिल्ली का मुख्य मंत्री गिड़गिड़ाता रहे, 'किराया मत बढ़ाओ।' मालिक बनना हो तो केन्द्र सरकार के अधिकारी हैं। एक ही साथ दोनों हाथ से डफली बज जाती है। ऐसा नहीं होता दुनिया में। अगर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है हिन्दुस्तान के अन्दर जो भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र के अन्तर्गत फेडरल स्ट्रक्चर बना, वो इसीलिए बना कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारियॉ राज्य सरकार पूरा करेंगी और जहॉ कमी बचेगी, केन्द्र सरकार उसके साथ खड़ी होगी। राष्ट्र को भी देखने के साथ–साथ राज्यों के विकास का मॉडल भारत के संविधान ने प्रस्तुत किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूॅ, अध्यक्ष महोदय, प्रधान जी ने एक बात उठाई थी कि पिछली बार दिल्ली सरकार ने अपना 48 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था इस सदन के अन्दर लेकिन उसमें से लगभग 3600

करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। मैं तो इस पर गर्व महसूस करता हूँ आज बैठकर के। हमें तो ये लगता है कि जिस तरह से हर 15 दिन पर, पखवाड़े पर दिल्ली सरकार को पंक्चर करने के लिए दिल्ली सरकार के मिशन और लक्ष्य को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, ठप्प करने के लिए षडयंत्र होता है, अगर उसके बार भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार 90 प्रतिशत बजट खर्च कर लेती है, ये छोटी–मोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर शायद... ये सहयोग करते, जैसे हरियाणा के सरकार के साथ सहयोग करते हैं, जैसे महाराष्ट्रा की सरकार के साथ सहयोग करते है, जैसे राजस्थान की सरकार के साथ सहयोग करते हैं, जैसे गुजरात की सरकार के साथ सहयोग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सहयोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल सरकार में इतनी क्षमता है कि 90 परसेंट छोड़ दो... 180 परसेंट बजट खर्च करने की क्षमता रखती है ये सरकार। अगर केवल सहयोग करें तो। विकास क्या होता है, बजट क्या होता है, उसके पैमाने क्या होते हैं। ये रफ्तार हम बता देते। अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र जी ने कहा... इन्होंने प्रश्न लगाया था डीटीसी के अन्दर कितनी बसें आईं। कहा, एक बस नहीं आई, नहीं आई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। दिल्ली के अन्दर दो तरह की बस सर्विस चलती है। सरकार के द्वारा ही। एक डीटीसी के अण्डर में और दूसरा कलस्टर सेवा के अण्डर। डीटीसी के अण्डर में बस नहीं आई है। नई बसें आने का प्रावधान सरकार ने किया है। कलस्टर बस सर्विस में पिछले साल के दौरान, मेरे संज्ञान में जो है, वो संख्या लगातार बढ़ रही है। 600 से ज्यादा नई बसें दिल्ली के अन्दर आई हैं और सड़क पर चल रहीं हैं। विजेन्द्र जी, ये नहीं बताया किसी ने आपको। दस नये डिपो बनके तैयार हुए हैं इसी दिल्ली के अन्दर।

ये आपको नहीं किसी ने बताया और आपको अध्यक्ष महोदय, ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के अन्दर जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, वो समस्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में बॉट करके नहीं देखा जा सकता है। इस दिल्ली के अन्दर केन्द्र सरकार के सारे मंत्री, सारे प्रधानमंत्री से लेकर के सारे अधिकारी इसी दिल्ली के अन्दर रहते हैं। ये दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार जिस तरह से दिल्ली के अन्दर प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इस सरकार ने जिस तरह से ग्रीन बजट में अपना लक्ष्य बनाया है, वो इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि पूरे दिल्ली के अन्दर एक समग्र विकास का मॉडल खड़ा हो रहा है। अगर दिल्ली सरकार की नजर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला अगर मजदूर है, अगर कान्ट्रेक्ट पर मजदूरी करने वाला मजदूर है, अगर दिल्ली की सरकार एक मजदूरों की चिन्ता करती है तो दिल्ली सरकार इस दिल्ली के व्यापारियों की भी चिन्ता करती है। दिल्ली सरकार अगर शिक्षा की चिन्ता करती है तो दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसकी भी चिन्ता करती है। दिल्ली सरकार अगर अनोथराइज कालोनियों की चिन्ता करती है तो दिल्ली सरकार झुग्गी–झोपड़ी की भी चिन्ता करती है। दिल्ली सरकार इसकी चिन्ता करती है कि दिल्ली का विकास हो तो दिल्ली सरकार इसकी भी चिन्ता करती है कि प्रदूषण मुक्त विकास हो और इसके लिए मैं तहेदिल से बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने सरकार बनने के बाद ही हमने प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ी थी। इस पूरे देश के अन्दर हमने जब कार फ्री डे शुरू किया। हम लोग ऑड–ईवन लेकर के आए। हम लोगों ने और सारी तमाम व्यवस्थाएं कीं। आलोचना करने वाले आलोचना करते

हैं, इसलिए करते हैं कि दिल्ली सरकार से उम्मीद है कि यही एक सरकार है। हरियाणा सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो प्रदूषण खत्म करने में सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश की के सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो सहयोग करेगी लेकिन आज ग्रीन बजट प्रस्तुत करके दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली वालों को ये भरोसा दिलाया है कि समग्र विकास के रास्ते पर दिल्ली सरकार चल रही है। आम जनता के, आम आदमी के हित के लिए किसी भी तरह की योजना है, उस पर काम करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है और अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आज जिस तरह से विकास का एक नया मॉडल खड़ा हो रहा है, इस देश के अंदर दो तरह की थ्योरी रही है, पूरी दुनिया के अंदर दो तरह की थ्योरी रही है। आज जिस तरह से तेजी के साथ नीचे से एक आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली लाने का विकास का जो मॉडल खड़ा हो रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि... दिल्ली सरकार की बात छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की अलग–अलग सरकारों के अंदर इस तरह के अध्ययन शुरू हुए हैं कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, हम अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते? और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के अंदर भी इस तरह की टीमें... अंडरग्राउंड टीमें बन रही हैं कि जो दिल्ली सरकार कर पा रही है, इतना परेशान करने के बावजूद, इतने सीमित संसाधन में जो मॉडल खड़ा कर रही है विकास का, वो विकास का मॉडल कैसे कर रही है, इसके लिए रिसर्च हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक नए तरह का आर्थिक सिद्धांत और नया आर्थिक आयाम जो दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए तहेदिल से माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को

धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए बधाई देते हैं कि लगातार चौथी बार ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करके न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक भविष्य का विकास मॉडल दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया है। सफलतापूर्वक इसके लिए तहेदिल से बहुत–बहुत बधाई, बहुत–बहुत शुक्रिया।

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी ने कुल दस मिनट लिए हैं अपनी बात पूरी करने में। बहुत–बहुत धन्यवाद। सदन का एक घंटा समय बढ़ा लिया जाए।

Jh tjuSy flag% जो मामला अभी जगदीप जी ने सदन के सामने रखा था, उसके बाद मैं और जगदीप जी जाकर सिक्योरिटी वालों से मिले हैं, वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूॅ कि लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी अध्यक्ष जी जिनकी पगड़ी के बीच में हाथ डाल–डाल कर, पगड़ी हिला–हिला कर तलाशियां ली गई हैं। अध्यक्ष जी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% कुछ वेट तो कर लो।

Jh tjuSy flag% अध्यक्ष जी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सारे लोग पगड़ी बांधकर बैठे हैं, उनको मालूम है पगड़ी की क्या रेस्पेक्ट है। आज 'रेस्पेक्ट द टरबन' वहॉ पर पूरी कैम्पेन चल रही है और हमारे यहॉ यह हो रहा है!

v/;{k egkn;% जरनैल जी, इसको थोड़ी देर वेट तो कर लो। मुझे एक बार यह बजट की चर्चा पूरी करवा लेने दो। आप मेरे संज्ञान लाए हैं, चार बंधु आकर बैठ गए हैं, मैंने देख लिया है।

Jh tjuSy flag% मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए और इस मामले पर सख्त निर्देश दिए जाएं।

v/;{k egksn;% पहले इसको ले लूॅं। इसको छोड़ दूं? जैसा आप आदेश दें।

Jh tjuSy flag% हमारी इतनी मॉग है कि इस मामले को गम्भीरता से लें।

v/;{k egksn;% माननीय वित्त मंत्री जी।

foÙk ea=h ¼Jh euh"k fllksfn;k½% अध्यक्ष महोदय, दो दिन लगातार चर्चा हुइ है बजट के प्रस्तावों पर और मुझे खुशी है कि हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों ने, इसके डेटा से लेकर इसके प्रस्तावों तक चर्चा की है और मैं देख रहा था, अभी तक 14 सदस्य जिसमें तीन विपक्ष के साथी भी बोले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। माननीय मंत्री जी सहित अभी तक जितने लोग बोले, 14 लोग। यह एक ऐसे समय में जब देश में एक नई परंपरा की शुरूआत हो रही है कि देश की संसद में बजट बिना चर्चा के पास करा दिया जाए, वैसे में दिल्ली की विधान सभा में बजट पर चर्चा होना और चार में से तीन विपक्षी सदस्यों का बजट पर बोलना, यह बताता है कि आपका संचालन कितना लोकतांत्रिक है और कितना विपक्ष की आवाज को और विपक्ष को तरजीह देकर चलते हैं और मैं खुद भी मानता हॅूं, पिछली बार भी... कई बार बोल चुका हॅूं कि अपने जितने भी सत्ता पक्ष के साथी हैं, निश्चत रूप से उनका इशारा जब भी किसी तरफ रहेगा तो वो गलती ठीक करने की तरफ रहेगा और विपक्ष की तरफ से जब भी कोई इशारा आएगा, वो कमी निकालने की तरफ आएगा। अपनी कमियॉ भी पता चलें.

.. पर मैं हर बार सोचता हूँ कि विजेन्द्र गुप्ता जी जब भी कुछ मेरे प्रस्ताव आते हैं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आते हैं, उनमें कुछ ऐसी रिसर्च करके निकाल कर लाएंगे जहॉ से हमें अपनी कमी पता चलें, पर इनकी बात करते—करते मैं एक लाइन पढ़ रहा थाः

मुझे गुनाहगार साबित करने की कोशिश न कर,
बस खबर कर दे, क्या—क्या कबूल करना है।

इतनी सी बात है क्योंकि सरकार आपकी है पूरे देश में, जहॉ आपकी नहीं बनती, वहॉ भी बना ही लेते हैं। जहॉ के लोग नहीं चुनते, वहॉ भी बना ही लेते हो आप तो। इलैक्शन कमीशन आपका, चुनाव आयोग... ...(व्यवधान) मुझे तो कइ बार लगता है आज पता नहीं क्या होगा। आज बेचारे चुनाव आयोग साहब को कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि बीजेपी की स्क्रिप्ट से हटकर उन्होंने एक तारीख में थोड़ा सा ट्वीट कर दिया है शायद। जो इनके प्रवक्ता ने चुनाव आयोग की घोषणा से पहले घोषित किया था, उसके हिसाब से एक डेट थोड़ी इधर—उधर हो गई थी। अब पता नहीं, उसकी सज़ा चुनाव आयोग को कितनी भुगतनी पड़ेगी, यह तो वक्त बताएगा। खैर! ...(व्यवधान) येदुरप्पा वाला कर्नाटक। खैर!

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आपके सोशल मीडिया के इंडिया के, जो देखते हैं उन्होंने डेट चुनाव आयोग के एक घंटा पहले डिक्लेयर कर दी। 12 तारीख को चुनाव होंगे और चुनाव आयोग की प्रैस कांफ्रेंस ठीक एक घंटे बाद हुई। पूरा मीडिया में चला।

foÙk e=h तो कल से बजट प्रस्तावों पर बातचीत करते हुए अलका जी ने सीलिंग का मुद्दा रखा, ग्रीन बजट के बारे में बात की। सोमनाथ भाइ ने आम आदमी को मजबूत करने की कवायद पर बात की। ओम प्रकाश जी नहीं हैं अभी सदन में, उन्होंने जिक्र किया था आईपी यूनिवर्सिटी का पैसा राष्ट्रपति शासन के दौरान आया था। पूछ रहे थे, इसमें आपका क्या योगदान है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, हमारी सरकार बनने से और पिछली 49 डेज की सरकार के बीच में, तो ओम प्रकाश जी की विधान सभा में आईपी यूनिवर्सिटी का, ईस्ट दिल्ली कैम्पस का उद्घाटन हुआ था। मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो राष्ट्रपति शासन का यह फायदा हो गया कि जल्दी—जल्दी ये फैसले हो गए, वरना हो सकता है देरी होती हो और जब सरकार बनी दोबारा से, हमें आकर सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने तुरंत कहा कि इसको तो जल्दी से खड़ा करो, ईस्ट दिल्ली में बड़ी भयानक कमी है। आप भी वहीं से हैं, आपकी और हमारी विधान सभाओं के बीच में यह पड़ता है। लेकिन मुझे दुःख हुआ देखकर और उस पर मुझे एक साल लगा काम करने में कि जिस जमीन पर जाकर नारियल फोड़ दिया गया, नेम प्लेट लगाकर बड़े—बड़े पत्थर लगाकर अनावरण कर दिया गया। बहुत बड़ी—बड़ी स्क्रीन लगाकर उस जमीन का हस्तांतरण तक तब तक नहीं हुआ था, आइपी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद डीडीए से खतों किताबत करके, लड़कर, झगड़कर, लिखकर, एलजी साहब के यहॉ बात करके और फिर दिल्ली सरकार का पैसा खर्च करके तब आइपी यूनिवर्सिटी की जमीन इस सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई जिसका शिलान्यास इस सरकार के बनने से पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान फर्जी तरीके से कर दिया गया था तो आप जो कर रहे हैं, उसका मैं जिक्र करता।

ऋतुराज जी ने भी अनआथोराइज्ड कालोनी पर बात रखी, नितिन त्यागी जी ने एजुकेशन पर खर्च करने को बताया, बड़ी अच्छी टिप्पणियाँ कई तरफ से आईं। मैं नोट कर रहा था कि एजुकेशन पर खर्च करना देश को मजबूत बनाना है। पंकज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में बात रखी कि यह मानवता में निवेश करने वाला बजट है। मुझे उनके... पिछली बार भी जब उन्होंने एक शब्द दिया था कि एक तरफ एक फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है, एक शिक्षित राष्ट्रवाद चल रहा है तो फर्जी राष्ट्रवाद के पैरोकार मुस्कुराते रहे, पता है, कौन हैं? यहॉ शिक्षित राष्ट्रवाद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राखी जी ने आंगनवाड़ी सुधरे, बड़ा अच्छा उसमें बोला कि आंगनवाड़ी सुधरेगी तो गरीब, पिछले वर्ग के परिवारों का भविष्य सुधेरगा। यह बहुत छोटी सी चीज लगती है, आंगनवाड़ी लेकिन इसीलिए आंगनवाड़ी की सैलरी बढ़ाई गई और इसीलिए आंगनवाड़ी पर इस बार कई ऐसी स्कीम इस बजट में हमने रखी है क्योंकि देखने में लगता है आंगनबाड़ी योजना देश की बहुत बड़ी, अलग इतने बड़े फलक्रम पर एक छोटी सी बात है लेकिन जो राखी जी ने बात रखी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑगनवाड़ी सुधरेगी तो गरीब, पिछड़े वर्ग के परिवारों का भविष्य सुधरेगा क्योंकि जिन बच्चों को गली–मोहल्ले में, कोई ठीक से खेलने नहीं देता, उन बच्चों को अच्छे आंगनवाड़ी सेंटर्स में बिठा कर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर काम करना, उनके भविष्य पर काम करना, उनके परिवारों का भविष्य सुधारने की एक बड़ी कवायद है। सदन ने इसको नोट किया, अच्छी बात है। जगदीश प्रधान जी ने तो कई बात रखी पर उनको भी पता है कि उनके क्षेत्र की स्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है। जगदीश प्रधान जी से, अभी बैठे हैं, वहॉ क्या करें! जरूरत हमको लफ्जों के... इनके लिए मैं कहता हूँ कि इनके लिए मैं कहता हूँ कि:

'जरूरत हमको लफ्ज़ो के तकल्लुफ की नहीं होती,
उधर वो समझते हैं और इधर हम कुछ नहीं कहते।'

तो आपके लिए आपको पता है आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जरा डेटा उठाकर देखियेगा कि 1993 से अब तक बजट इस्टीमेट क्या रहे हैं और एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या रहे हैं और उसके बीच का गैप क्या रहा है और उसमें भी जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा। जब दिल्ली का बजट अरूण जेटली जी ने बनाया था, उस वक्त के बजट एस्टीमेट और उस वक्त के एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर देखियेगा। रखूँगा मैं आपके सामने। महेन्द्र गोयल जी ने दिल्ली के बच्चों के लिए हॉयर एजुकेशन की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की। महत्वपूर्ण इश्यू है, मैं बार बार इस सदन में कहता रहा हूँ लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले तीन साल में इस सरकार ने न सिर्फ हॉयर एजुकेशन के नये नये इंस्टीट्यूट खोले हैं बल्कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स थे, उनकी भी सीटों की संख्या काफी बढ़ाई है। मैंनें शायद पिछले सेशन में डेटा रखा था आगे भी कभी अपडेटेड डेटा रखेंगे लेकिन दोनों तरफ से चल रहा है क्योंकि बीच में शायद ओमप्रकाश जी ने या किसी ने जिक्र किया, 'कालेज कहॉ गये?' मैं फिर से रखना चाह रहा हूँ। हैं नहीं, अभी आपकी विधान सभा में खुला है लेकिन उनकी विधानसभा का बॉर्डर है। ईस्ट दिल्ली कैम्पस डीटीयू का एक कालेज है नया, फुल फ्लेज्ड कालेज है; अंबेडकर युनिवर्सिटी का लोदी रोड पर। टीचर्स ट्रेनिंग का फुल फ्लेज्ड कालेज चल रहा है, नया खुला है। अंबेडकर युनिवर्सिटी का कर्मपुरा में कालेज खुला है नया, नया कैम्पस खुला है। फुल फ्लेज्ड चल रहा है, वहॉ पर तीन हो गये। गिन लीजिएगा, बता दीजिएगा आप। नौ बीवो कालेजेज खुल गये हैं, आते

ही खोल दिये थे, 12 हो गये नौ और तीन, सुखदेव कालेज तो फिर भी चलो, पहले चल रहा था, उधर बिल्डिंग दे दी उसको। हम वैसे नहीं गिनेंगे कि एक नया कालेज खुल गया। मैं नयी बता रहा हूँ हालांकि उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। वो संख्या बढ़ने वालों में काफी आता है, उसकी छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। डिप्सारू एक नइ युनिवर्सिटी खुल गई है और आपको याद होगा इसी सदन, में इसी सरकार के दौरान इसी विधान सभा ने, मौजूदा विधान सभा ने ही इस बिल को पास किया था और मुझे खुशी हो रही है कि ये भी लगातार दो साल से चल रही है। डिप्सारू युनिवर्सिटी एशिया की पहली फार्मास्युटिकल रिसर्च युनिवर्सिटी है। तीन नये... इस बीच आइपीयू ने नये प्राइवेट कालेज को भी एफिलिएट किया है आइपी युनिवर्सिटी ने। एनएसयू, डीटीयू, आइजीडीटीयू, आइपी और डीयू में संक्षितों की संख्या बढ़ी है। नये स्किल सेंटर हम खोल रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, महेन्द्र जी ने उसका जिक्र किया था कि हॉयर एजुकेशन के एवेन्यूज बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है और इस बजट में भी हमने जैसा 25 नये स्किल सेंटर खोलने की बात कही है और वो खुल जाएंगे तो उससे बारहवीं के बाद बच्चों के लिए नये नये वेन्यूज आगे बढ़ेंगे। नरेश बालियान जी बहुत कम भाषण देते हैं, कई बार मैंने देखा है लेकिन आज बहुत अच्छा! उन्होंने बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी और बड़ी उम्मीद भरी बात कही कि दिया जलाना कहां मना है। गुलाब भाइ ने फिर से अनऑथोराइज कालोनी की बात कही। विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक लेकिन सवाल उठाया, मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीज लाएं बजट में हो सकता हो, हमसे चूक हो गई है, खूब मेहनत करते हैं। बैठकों पर बैठक करते हैं सब लोग दिन रात काम करके बजट तैयार करते हैं और इसमें हो सकता

है कोई चूक हो गई हो, कुछ निकाल कर लाएंगे। निकाल कर लाए साहब आप, रेवेन्यू बजट आपका क्यों ज्यादा है? सर जी, आप जब ये पूछते हैं कि रेवेन्यू बजट क्यों ज्यादा है, इस सदन में भी हम में से बहुत लोगों को क्योंकि मैं बजट बनाता हूँ तो इसलिए धीरे धीरे कुछ शब्द डिकोड हो गये पर इस सदन में भी और जो हम लोगों को चुनकर भेजते हैं, उनको ये रेवेन्यू कैपिटल फर्क नहीं पड़ता है, ये शब्द हैं। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी के इस सवाल को थोड़ा सा खोलकर बताना चाहता हूँ ताकि ये सदन के रिकॉर्ड में रहे और सदन से बाहर भी जाए तो लोगों की भाषा में जाए। विजेन्द्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं; रेवेन्यू बजट इतना ज्यादा क्यों है? मतलब विजेन्द्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने कर्मचारियों को इतनी ज्यादा तनख्वाह क्या दे रहे हो? इस सवाल का मतलब ये है। सर जी, हम अपने तमाम कर्मचारियों को जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं क्योंकि हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। जिसमें डॉक्टर भी शामिल है क्योंकि हम स्वास्थ्य पर जोर दे रहे हैं और सिर्फ यही नहीं आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल हैं। इसमें हमारे और सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में काम करने वाला, स्कूलों की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी शामिल है क्योंकि मिनिमम वेज बढ़ाकर उसको सेलरी मिल रही है बढ़ी हुई। वहॉ सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। आप पूछ रहे हो उनको तनख्वाह क्या दे रहे हो!

Jh fotsUnz xqIrk% सरकार का विजन क्या है जी?

mi eq[; ea=h% सरकार का विजन ये है, वो आपको समझ में नहीं आएगा विजेन्द्र गुप्ता जी। सरकार का विजन ये है कि कर्मचारियों को सही से तनख्वाह मिलनी चाहिए। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, अध्यापक हो, डॉक्टर

हो और अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सबको सही समय पर और नियम कायदे कानूनों के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। आप मुझे एक सरकार बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की, एक सरकार, मैं बार बार कहता हूँ, जहॉ दिल्ली के बराबर आंगनवाड़ी वर्कर्स को, गेस्ट टीचर्स को, सिक्योरिटी गार्डस को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही हो, एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बता दीजिए ये विजन है सरकार का। वो जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है स्कूल के बाहर। वो जो आंगनवाड़ी वर्कर खड़ी होती है, गरीब लोगों के बच्चों के साथ में खाना खिलाने के लिए। वो जो टीचर है, जो गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको अगर सरकार तनख्वाह दे रही है तो आप कह रहे हैं, इसमें सरकार का विजन क्या है? आप कह रहे हैं सरकार तनख्वाह क्या दे रही है? विजेन्द्र गुप्ता जी, हम लोग पहले शब्द सुनते थे एक बड़ा प्रचलित शब्द था धन्नासेठ। हम न धन्नासेठों के लिए काम करते हैं और न धनियासेठों के लिए काम करते हैं, हम इन मजदूरों और गरीबों के लिए काम करते हैं। नया शब्द आप लोगों ने इजाद किया है इस देश में धनियासेठ। धनिया बेचकर धनिया बोकर 16 हजार परसेंट। धन्नासेठ होता था गॉव में, शहर में, कस्बे में, पैसा कमाया, कुछ लोगों ने मेहनत से कमाया, कुछ लोगों ने शोषण से कमाया लेकिन एक एवरेज लेवल से ऊपर का रईस आदमी जो व्यापार करता था; धन्नासेठ बोलते थे। प्रचलित शब्द है लेकिन धनियासेठ आपकी सरकार यानी केन्द्र सरकार ने दिया है। धनिया बोओ और 16 हजार प्रतिशत कमाओ, तो ये सरकार न धन्नासेठों के लिए... सरकार का विजन बता रहा हूँ मैं आपको। ये सरकार धन्नासेठों की सरकार नहीं है और ये सरकार धनियासेठों की सरकार नहीं है। ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के

बच्चों के लिए शिक्षा देती है। आम आदमी को पढ़ाने वाले बच्चों के अध्यापकों को तनख्वाह देती है इसलिए रेवेन्यू का बजट ज्यादा है। आम आदमी का इलाज करने वाले लोगों को तनख्वाह देती है, आम आदमी के सरकारी स्कूलों को। आम आदमी के ऑगनवाड़ियों में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स को तनख्वाह देती है। तनख्वाह देते हैं इसलिए रेवेन्यू का बजट ज्यादा है किसी को पेट में दर्द होता हो तो अपनी बला से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बात कही, मैं... पुष्कर जी नहीं हैं, उन्होंने मुझे एक दिन लिखकर दी थी किसी दिन कविता।

Jh fotsUnz xqIrk% कविता मैं भी लिखकर लाया हूँ।

mi eq[; ea=h% सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप नहीं सुना पाए। ये जो इनको तनख्वाह मिलती है, आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ ना इनसे, बार बार मुझे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर, कभी पॉच साल इनकी सरकार, कभी 10 साल उनकी सरकार, कभी 15 साल किसी की सरकार। मिलकर इन्होंने जिस राज्य में 15–20 साल शासन किया हो, एक राज्य बता दें जहॉ दिल्ली सरकार के एक्सीलेंट स्कूल जैसा एक सरकारी स्कूल हो आपके पास में, एक राज्य बता दो, मिलकर बता दो। एक राज्य बता दो जहॉ गरीब लोगों को, गरीब कामगारों को, मजदूरों को इतनी मजदूरी देने की व्यवस्था आपने कर रखी हो और मिलते हों। आपका विजन और हमारे विजन में अंतर यही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो 95 परसेंट लोग जिनको आपने खस्ता हाल सरकारी स्कूलों के हाथों छोड़ दिया था... नगर निगमों की आप बात कर रहे हैं। नगर निगमों के स्कूलों की हालत देख लीजिए, उनके हाथों छोड़ रखा है।

उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं, वो स्वस्थ रहें, देश के विकास में योगदान करें, वही देश की खुशहाली में योगदान करें। गोरखनाथ पांडे की कविता मैं आपके लिए पढ़ रहा था।

वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं?तमाम धन दौलत गोला बारूद और पुलिस फौज के बावजूद! है, आपके पास धनिया सेठ भी है, धन्ना सेठ भी है, गोला बारूद भी है। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन–दौलत, गोला–बारूद, पुलिस–फौज के बावजूद, वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर दें! आप इसलिए डरते हो क्योंकि इनकी तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। आंगनवाड़ी वालों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। गरीब मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। ये अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लेंगे और जिस दिन ये पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, उस दिन ये आपकी हेकड़ियों में आना बंद कर देंगे। आपकी फिरकियों में आना बंद कर देंगे। इसलिए आप डरते हो इनसे। इसलिए आप इस विजन से डरते हो। और इस विजन से आपको डरना चाहिए। ये देश का विजन है। इस लिए मैंने उसकी बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं... क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है। मैं तमाम सदस्यों का, तमाम उन तमाम लोगों का जिन्होंने बजट प्रस्ताव तैयार करने में लम्बे समय तक सहयोग दिया। मीडिया के साथियों का भी जिन्होंने दिल्ली की जनता तक इन बजट प्रस्तावों को पहुॅचाने में सहयोग दिया और तमाम सदस्य साथियों का जिन्होंने इस बजट की समीक्षा करने में इस बजट पर अपनी टिप्पणी देने में सहयोग दिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूॅं और मैं उम्मीद करूॅगा कि ये सदन इस बजट को पास करें, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% माननीय मुख्य मंत्री जी।

ekuuh; e|[; e=h% अध्यक्ष महोदय, आज से तीन साल पहले और चार साल पहले इस देश की राजनीति में दो बडे डेवलपमेंट्स हुए थे। आज से चार साल पहले इस देश के लोगों ने केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत देकर जिताया था। आज से तीन साल पहले दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अभूतपूर्व बहुमत देकर जिताया था। दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की उम्मीद थी कि इतना अभूतपूर्व बहुमत दे रहे हैं, ये सरकारें कुछ अलग करके दिखाएंगी। जो जनता की इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालेंगे। तीन साल और चार कोई छोटा समय नहीं होता। इसी लिए ये समय है, ये देखने का कि दोनों सरकारों ने इन तीन साल में और चार साल में क्या काम किया। अगर मैं कुछ भी कहूॅ तो कहा जाएगा कि राजनीति कर रहा है। तो मैंने पिछले दिनों में कई लोगों से बातचीत की। मैने जनता से पूछा, कई लोगों से पूछा पहले और मैने नहीं पूछा, पुछवाया मैंने। भेजकर सर्वे कराया। लोगों से पूछा गया भई केन्द्र की भाजपा सरकार ने क्या–क्या काम किये हैं। और उनसे पूछा गया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या–क्या काम किये। तो जब पूछा गया भाजपा सरकार ने क्या–क्या काम किये। तो जो सबसे पहला जवाब आता है जी, जितने बैंकों के घोटले पिछले तीन चार साल के अंदर हुए हैं आजादी के बाद से आज तक, शायद इतने बैंकों के घोटले आज तक कभी नहीं हुए। ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूॅ क्योंकि इससे दिल्ली की जनता बड़ी त्रस्त है। ये मुद्दा केवल ये नहीं है कि विजय माल्या नौ हजार करोड़ रुपये लेकर भाग गया। और भाग गया नहीं, भगाया गया। नौ हजार करोड़ रुपये लेकर कोई आदमी ऐसे ही थोड़े चला जाएगा! एक रात को हवाई जहाज में बैठकर चला गया। कह

रहे हैं, 'पता नहीं चला।' वहॉ पर कस्टम वाले होते हैं, वहॉ पर स्क्योरिटी वाले होते हैं, वहॉ पर इमिग्रेशन वाले होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई हवाई जहाज उड़कर ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा, तो भगाया गया। नौ हजार करोड़ रुपये लेकर उसको भगाया गया। अब नीरव मोदी ग्यारह हजार करोड़ रुपये लेकर उसको भगा दिया। और अभी किसी ने एक दो दिन पहले मुझे लिस्ट भेजी थी, बड़ी लम्बी। सिम्भोली शुगर लि. 109 करोड़, टोटल इन्फ्रा. 1394 करोड़, कनिष्क गोल्ड 824 करोड़, एसएलसीएल चार हजार करोड, विक्रम कोठारी 3695 करोड़, द्वारका दास सेठी 379 करोड़, जतिन मेहता 6712 करोड़। इतने लोग पैसे ले लेकर और भागते जा रहे हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि कोई इनसे रिश्तेदारी तो थी नहीं कि भई रिश्तेदारी थी, चाचा ताऊ लगता था, चलो, अपना भगा दिया। तो कुछ न कुछ तो... आज फ्री में तो कोई बेटा अपने बाप का काम नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि... खूब लोगों को, हजारों–हजारों करोड़ लेकर इस देश से भगाया जा रहा है। एक तो ये तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है कि. .. यूपीए को जनता ने इसीलिए तो हटाया था। रोज सुनने में आता था कभी 2जी कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी कॉमन वैल्थ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया और अब ये रोज सुनने में आ रहा है कि वो फलाने बैंक का पैसा लेकर भाग गया, वो फलाने बैंक का पैसा लेकर भाग गया! क्या बदला? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है, वो ये कि अमूमन 90 परसेंट जनता एक ही प्रश्न पूछ रही है, कह रहे हैं जी, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के ग्यारह हजार करोड़ रुपये लेकर भाग गया। पंजाब नेशनल बैंक में अब हमारा एक आदमी आया, मेरे पास रिटायर्ड आदमी था, बोला जी, जितनी

जिंदगी की जमा पूंजी थी सारी मैने एफडी करा रखी है पीएनबी में। तो बोले जी, अरविंद जी, आप तो थोड़े जानकार आदमी हो तुड़वा लूँ एफडी, वापिस निकलवा लूँ? मेरा पैसा सेफ तो है। लोग बहुत डर रहे हैं। चारों तरफ डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं किस बैंक में पैसा जमा कराएं और अब बता रहे हैं; कानून ला रहे हैं ये लोग कि अगर कोई बैंक दिवाला हो जाए तो जितने लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं, उनके पैसे जब्त हो सकते हैं। ये कानून लाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक तो कि केन्द्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी, जरा सा जनता को ये बता दें कि किस बैंक में पैसा जमा कराएं, जहॉ पर पैसा सुरक्षित हो जनता का? जनता के अंदर भरोसा हो। कौन सा ऐसा बैंक है; स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहबाद बैंक है, कौन सा बैंक है? किस बैंक में लोग पैसे जमा कराएं जिसमें उनका पैसा सुरक्षित होगा? ये एक ऐसा डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ है जिसका जवाब चाहिए जनता को।

दूसरा, जनता ने बोला कि पिछले तीन साल के अंदर चार साल के अंदर व्यापारियों को बर्बाद करने में केन्द्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले नोटबंदी! बोले नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होएगा। बेवकूफ बनाया! न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ, कुछ नहीं खत्म हुआ। उसके बाद जीएसटी और अब सीलिंग की तीसरी मार! एक साल के अंदर बेचारा व्यापारी! तीन–तीन इतने बड़े उसके ऊपर वार हुए। अब लोगों ने दुकान बंद करके... व्यापार बंद हो गए। मैने कई व्यापारियों से पूछा, मैने कहा, 'ये बताओ, पिछले तीन साल में तुम्हारी क्या ग्रोथ हुई है?; आदमी ग्रोथ के लिए काम करता है कि मेरी 10 परसेंट इस बार ग्रोथ हुई, मेरी 20 परसेंट ग्रोथ हुई। मेरा टर्न ओवर बढ़ा, मेरा मुनाफा

बढ़ा। ये बड़े–बड़े धन्ना सेठ छोड दो, अम्बानी, अडानी। मेरे को भाई साहब, आम व्यापारियेां में एक व्यापारी ऐसा नही मिला जो कहता हो, बोला, 'जी, पहले 10 रुपये कमाते थे तो आठ रुपये बच गए, कोई बरकत नहीं हुई हमारी चार साल के अंदर। उल्टा नीचे जा रहे हैं सारे। पहले कोई चार आदमी अपनी दुकान पर रख रखे थे तो उसने एक हटा कर तीन कर दिये। दिल्ली के अंदर सीलिंग की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी अफरा तफरी मची हुई है! लेकिन केन्द्र सरकार ने इसको मूछ की लडाइ बना लिया, बोले, 'जी, आर्डिनेंस नहीं लाएंगे, बिल नहीं लाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दिल्ली तबाह हो जाए, चाहे सारे व्यापारी बर्बाद हो जाएं, चाहे सारे भुखमरी पर आ जाएं, आर्डिनेंस नहीं लाएंगे।' मूछ की लड़ाई बना ली। ये गलत बात है! तो क्या व्यापारियों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। इसकी वजह से बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से फैल गई कि युवाओं को समझ नहीं आ रहा और मेरे दिल्ली का मुख्य मंत्री होते हुए, मेरी सबसे बड़ी चिन्ता का विषय ये है कि अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर बेरोजगारी फैल गई, लॉ एंड आर्डर की ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसको काबू करने में आपको पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद जितने इंस्टीच्यूशन्स थे, वो सारे मजाक बनकर रह गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक साल तक रुपये नहीं गिने गए। बोले, 'रुपये नहीं गिने जा रहे हमसे। अभी भी गिन रहे हैं, गिनती चालू है। आरबीआई का मजाक बन गया, इलैक्शन कमिशन का मजाक बन गया,/630/ सीबीआई का मजाक बन गया, दिल्ली पुलिस का मजाक बन गया, लोकपाल का मजाक बन गया, आरटीआई का मजाक बन गया, सारी युनिवर्सिटीज का मजाक बना हुआ है! फिर हमने लोगों से पूछा भई तीन साल में दिल्ली की आम आदमी

पार्टी ने क्या काम करा? भाई साहब, चार बातों की तो सारे चर्चा करते हैं। बोले, जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रॉति आ गयी, लोग कह रहे हैं। हम अपनी तारीफ करें, वो ठीक नहीं है, जब जनता कहे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रॉति आ गयी और मुझे आज बड़ी खुशी है कि प्रधान साहब ने भी शिक्षा मंत्री जी की पीठ थपथपाई है, अपोजिशन वाले जब कहें कि अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो हैल्थ के क्षेत्र में... हैल्थ के क्षेत्र में जबर्दस्त काम हुआ है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। बिजली के क्षेत्र में सबसे सस्ती बिजली आज पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है, लगातार तीन साल। चौथे साल में जा रहे हैं और चौथे साल के अंदर भी, पानी के क्षेत्र में इतना काम हुआ, लेकिन आज यहॉ पे मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि अब पानी के ऊपर इन्होंने गंदी राजनीति करनी चालू कर दी। पिछले तीन महीने से दिल्ली को हरियाणा... दिल्ली का अपना पानी है नहीं, दिल्ली के पास हरियाणा से, यूपी से पानी आता है, पिछले तीन महीने से हरियाणा से अमोनिया वाला पानी दिया जा रहा था जिसकी वजह से पानी की बुरी तरह से किल्लत हो रही थी। हम हाई कोर्ट गए, हाइकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अमोनिया वाला तो ठीक कर दिया लेकिन अब उन्होंने पानी का स्तर नीचे कर दिया। लगभग 70 से 80 एमजीडी पानी डेली हरियाणा से कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? अभी तक 10—15 साल में कभी भी ऐसा नहीं किया था। इतना जबर्दस्त पानी का स्तर नीचे कर देना! अब ये पानी की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को प्यासा मारना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। इस तरह की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। मुझे लगता है, राजनीति करनी है, चुनाव के पहले करनी चाहिए, आपको जनता से बदला नहीं लेना चाहिए। जनता के साथ इस किस्म की राजनीति

नहीं करनी चाहिए कि आप जनता को प्यासा मार दो। अगर जनता को प्यासा मारोगे, उनकी ऐसी आह लगेगी, उनकी ऐसी हाय लगेगी, आपको जिंदगी भर कोई नहीं बचा सकेगा उससे! अब राशन, गरीबों का राशन! गरीबों के पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है। राशन में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, हम सब लोग जानते हैं। राजनीति में आने से पहले हम लोग झुग्गी—झोपड़ियों में राशन के उपर ही काम किया करते थे। हमने इसकी पूरी प्लानिंग करी कि भई हम राशन को... अभी लोगों को राशन लेने के लिए दुकान पे आना पड़ता है, दुकानें खुलती नहीं हैं, पूरे महीने में दो या तीन दिन दुकान खुलती है, वहॉ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, राशन वाला कम राशन तोलता है, ज्यादा पैसे लेता है, गंदा राशन देता है, लोगों को ढेरों शिकायतें हैं और उसमें खूब भ्रष्टाचार है। तो हमने ये पूरी प्लानिंग करी कि राशन को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे, आपका जितना राशन बनता है, उसको पैक करके, बोरी में पैक करके आपके घर में कोई देके आएगा। आपको दुकान में आने की जरूरत नहीं है, आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके घर पे राशन पहुॅच जाएगा। मुझे लगता है ये क्रॉतिकारी कदम था। इस किस्म की सोच और उसके बाद उसका कार्यान्वयन, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी हम लोगों ने। लेकिन एलजी साहब ने उसको मना कर दिया। मैंने विजेन्द्र गुप्ता जी के बड़े ब्यान पढ़े हैं अखबारों के अंदर कि ये डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन के खिलाफ हैं? तो मैं अगले हफ्ते से दिल्ली की झुग्गियों में खुद जा रहा हूॅ, एक एक घर में जाऊॅगा दिल्ली के और ये मेरे सारे एमएलए जाएंगे। हम वहॉ जाके कहने वाले हैं कि बीजेपी ने एलजी साहब को कह के ये बंद करा दिया। तो मैं बस दो लाइन में आपसे ये जानना चाह रहा था कि भारतीय

जनता पार्टी की 'डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन' पे क्या ऑब्जेक्शन है? हॉ बोलो, चर्चा तो होनी चाहिए न। माइक खोल दो भाई, माइक खोलो।

Jh fotUn xIrk% गरीबों का राशन पूंजीपतियों को सौंप रहे हो। पूंजीपति साढ़े तीन करोड़ गेहूॅं—चावल गरीबों का ले जायेंगे और गरीबों तक पहुॅंचेगा, नहीं पहुॅंचेगा, कोई आपके पास हिसाब नहीं होगा। क्यों पूंजीपतियों को फायदा पहुॅंचाना चाहते हो आप, मुझे ये सूचना दीजिए।

Ek[; e=h% ये आपको किसने कह दिया?

Jh fotUn xIrk% आप ईस्ट इंडिया कंपनी को पैदा करना चाहते हो दिल्ली में।

e[;e=h% अच्छा एक तो आपका ये कि पूंजीपतियों पे और? बस।

Jh fotUn xIrk% पूंजीपतियों को ई—पोज जब आपने पोर्टेबल सिस्टम लागू कर दिया, कहीं से भी, किसी भी दुकान से राशन लो, वो आपकी मर्जी। दिल्ली में साउथ दिल्ली से लो, नार्थ दिल्ली में लो, ईस्ट दिल्ली में लो, जब इपोज लागू हो गया, चार लाख नकली राशन कार्ड पकड़े गये, 16 लाख नकली लोग पकड़े गये, जब जो डेढ़ लाख परिवार लाइन में लगे हुए हैं, गरीब हैं जो असली, उनको राशन नहीं मिला, वो घर बैठे हैं बेचारे, वो 20 रुपये किलो गेहूॅं खरीद रहे हैं और जिनके बड़े—बड़े मकान हैं, वो राशन लिए जा रहे हैं गरीबों का। इमरान हुसैन जी ने सदन में बयान दिया, बिल्कुल ठीक दिया। इन्होंने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है, जिसका अंगूठा नहीं लगा, वो बिना वैसे ही कागज पे लगा के राशन ले सकता है और दिलवाया इन्होंने। तो ये बहाना करना सरकार का कि जी, लोगों के अंगूठे

नहीं लगे, बिना अंगूठे के जब राशन मिल रहा है और सरकार दे रही है, इपोज को क्यों खत्म कर रहे हो आप? डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर, जब गरीब को डॉयरेक्ट अकाउंट में पैसा पहुॅच रहा है, क्यों खत्म करना चाह रहे हो? आप पूरे देश के गरीबों को डीबीटी से 90 हजार करोड़ रुपया बचा है गरीबों का, दिल्ली के गरीब को डीबीटी नहीं मिलेग... ये विरोध नही, अध्यक्ष जी, ये गरीब की जो असली जरूरत है, ये डीबीटी वो है। क्यों बिचौलियों को पैदा कर रहे हो आप? एक नैरो इंटरफीयरेंस को आप लोग जनरेट कर रहे हो। आप ही बताइए वो राशन पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? 250 करोड़ रुपया खर्च होगा।

e[;e=h% तो आपके तीन...

ekuuh; v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी,

e[;e=h% बोलने दीजिए अध्यक्ष जी, इनकी अगले हफ्ते से बहुत भद्द पीटने वाली है पूरी दिल्ली में। तो इनको सारा बोल लेने दो आज। हॉ।

Jh fotUn xIrk% पॉच किलो आटा जो आज इनको असला मिल रहा है डीबीटी की वजह से। 250 करोड़ की बचत हो रही है, सरकार को। वो धन्नासेठों को दिलवाना चाह रही है। क्यों पूंजीपतियों की जेब भरवाना चाह रही है? गरीबों के गेहूं चावल...

v/;{k egkn;% बैठिए, बैठिए।

Jh fotUn xIrk% आज साढे तीन करोड़ आपको केन्द्र सरकार दे रही है। आप वो ठीक तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। उस पर आप नौटंकी–नाटक कर रहे हो। आप गरीबों तक वो गेहॅू–चावल सही पहुॅचे, आज

800 करोड़ रुपये का गेहूॅं–चावल दे रही है केन्द्र सरकार आपको। और जब वो सारा सिस्टम बन गया, सब पकड़े गये, निकल गये। एक दम बेकार. .. जैसे आपकी चाल इपोज कामयाब हो गया, डीबीटी कामयाब हो गया, बोले, स्कीम बदल दो! क्यों बदल रहे हो आप स्कीम ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा?

e[;e=h% तो मोटे मोटे तौर पे इनके तीन ऑब्जेक्शन हैं, हॉ, वो एलजी साहब ने नोट दिया होगा, एलजी साहब ने ही बुला के बनाया है, बताया है इनको। हॉ, वो, एलजी एक ही बात है एलजी और बीजेपी एक ही बात है। एक इनका ये कहना है भई, धन्नासेठों को... धन्नासेठ से आपका मतलब है भई जो भी ठेका लेगा इसका, जो इंपलीमेंट करेगा।

Jh fotUn xIrk% कोइ न कोई तो करेगा ना। अब बता दो, अगर वो 5000 करोड़ से कम के आदमी हों तो मुझको...

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करो।

Jh fotUn xIrk% 5000 करोड़ जिसके पास होती है, वो गरीबों का गेहूॅं चावल...

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, अब खत्म करो।

e[;e=h% बैठ जाओ, बैठ जाओ।

v/;{k egkn;% जवाब तो ले लो अब शांति से सुन लेना एक बार।

e[;e=h% दिल्ली में लगभग 3000 राशन की दुकानें हैं... एक मिनट रुक जाओ, बाद में कर लेना। तीन हजार लगभग, अब आपका टाइम खत्म

हो गया, अब मेरा टाइम है। दिल्ली में लगभग तीन हजार राशन की दुकानें हैं। हमारी तो नई–नई पार्टी है। हमारी तो नई–नई पार्टी है, हमारे में से तो अभी किसी ने राशन की दुकानें ली नहीं हैं। वो आधी बीजेपी वालों की हैं, आधी कॉग्रेस वालों की हैं। तो वो जो बीजेपी के राशन वाले राशन की चोरी करके इन लोगों को पैसे पहुॅचाते हैं, वो सारे पैसे खत्म हो जायेंगे, तकलीफ इस बात की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूॅ जिन बड़े–बड़े धन्नासेठों की ये एनएचएआई की इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, वो ठेकेदार ही बनाता है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनती हैं, कोई ठेकेदार ही बनाता है या मंत्री जा के सड़कें बनाता है? टेंडर होंगे, टेंडर में जो एप्लाई... एक मिनट, एक मिनट... टेंडर होंगे, टेंडर में जो एप्लाई करेगा जिसका सबसे कम रेट आएगा, वो करेंगे। एलजी साहब ने आपको ये नहीं बताया। एलजी साहब ने जितने उसमें ऑब्जेक्शन लिखे हैं... मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है आज। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं एलजी साहब के पास पर्सनली मिलने दो बार गया। दो बार मैं पर्सनली केवल इसके लिए गया, मिलने के लिए 'डोर स्टैप' दिल्ली राशन के लिए मैंने एलजी साहब से कहा, मैंने कहा, 'सर, आप से मैंने आज तक कुछ नहीं मॉगा, यही शब्द मैंने इस्तेमाल किये हैं, मैंने कहा, 'सर राशन के ऊपर मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने 2006 से दिल्ली की सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम कियाा है। मेरे ऊपर हमले हुए, हमारे कार्यकर्ताओं पर सात बार हमले किये गये। हमारी एक कार्यकर्ता थी, संतोष उसका गला काट दिया गया, हमारा एक कार्यकर्ता था चन्दर उसकी नाक काट दी गई। हमने बहुत हमले सहे हैं इस राशन व्यवस्था के लिए, इस राशन व्यवस्था को मैं दुरुस्त करना चाहता हूॅ। ये डोरस्टैप डिलीवरी... मेरे को राशन की एक एक कानून और एक एक दाव,

उसका पता है, उसकी नस का पता है। ये कहॉं कमाते हैं, क्या करते है। मैंने कहा सर एक ही चीज आपसे मांगने के लिए आया हूॅं इस प्रपोजल को पास कर देना अगर आपकी कोई ओबजेक्शन हो इसको पास करने के पहले अगर आपके मन में कोई शंका हो, मेरे को बुला लेना।' मैं दो बार गया।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई विजेन्द्र जी, अब ये तो कोई बात नही है। नहीं, आप बीच बीच में टोकेंगे क्या?

Ek[; e=h % मुझ्ा कहते हुए बड़ा दु:ख है कि एलजी साहब ने मुख्य मंत्री के कहने के बावजूद उन्होंने इतनी बेसिक कर्टसी नहीं दिखाई कि इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करने के पहले मेरे को बुला लेते। बेहद दु:ख है आज मेरे को, मैं एलजी साहब से कहना...

...(व्यवधान)

e[; e=h% एक मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाइये, चुप हो जाइये. .. मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूॅं कि मरने के बाद जब भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान पूछेगा कि केजरीवाल जब गरीबों को राशन बॉटने के लिए इतनी अच्छी स्कीम ला रहा था, आपने क्यों मना की? वहॉं पर जब आप कहोगे कि मेरे को बीजेपी वालों ने कहा था, भगवान आपको कभी माफ नहीं करने वाला। गरीबों की आह लगेगी बीजपी वालों को और एलजी साहब को! ये गलत... जो आप गलत काम कर रहे हो, ये पूरी जनता देख रही है और हम एक एक घर में जायेंगे, दिल्ली के एक एक घर में जायेंगे,

सारे व्यापारियों को तो तुमने नाराज कर लिया, अब सारे गरीब, 70 लाख लोग हैं दिल्ली के अंदर जो राशन लेते हैं, मजाल एक आदमी जो तुमको वोट दे दे, इसके बाद! हम देखते हैं कैसे वोट देते हैं! जनता तुमको सबक सिखायेगी! अध्यक्ष महोदय, हम केवल पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, हम नेगेटिव राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि राजनीति केवल चुनाव के पहले होनी चाहिए। चुनाव के पहले जो आप लोगों ने कहना है, आप कह लो। चुनाव के पहले आपने जो गाली गलौच करना है, कर लो। लेकिन एक बार अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाये; जैसे जगदीश प्रधान जी हैं, विपक्ष के व्यक्ति हैं लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने ये नहीं देखा कि ये विपक्ष का आदमी है, मैं स्कूल नहीं बनवाऊँगा इसके यहाँ। इन्होंने स्कूल...

...(व्यवधान)

Ek[;ea=h % जमीन दे दी ना! कमरे बनवा दिये ना!

v/;{k egksn;% उन्होंने अभी सदन में कहा है, 76 कमरे बनवा दिये।

Ek[;ea=h% हम पॉजीटिव राजनीति में यकीन रखते हैं। हमें ये लगता है कि अगर कोई देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, उसके अंदर सारी पार्टियों को मिलकर अच्छा काम होने में कंट्रीब्यूट करना चाहिये लेकिन अगर...

...(व्यवधान)

Ek[;ea=h% बाकी दोनों उससे रिलेटिड नहीं हैं ना ओबजेक्शन, डोर स्टैप डिलीवरी से नहीं है, वो तो इपोज को हटा दिया, ये क्यों करा दिया, वो

कर दिया, उसका कोई डोर स्टैप डिलीवरी नही। हम तो जनता को जा के यही कहेंगे, एक एक घर में जायेंगे और उनको जा के बतायेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसको पैसा पहुॅचता था इन राशन वालों से, उसको तकलीफ हो रही है और वो ये नहीं चाहती कि राशन वालों की दुकानें बंद हों और जनता को घर घर पर राशन मिले। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो पिछले तीन साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक नई किस्म की राजनीति ने जन्म लिया है पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। 70 सालों के अंदर जो दूसरी पार्टियॉ नहीं कर पाई, जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा, दूसरी पार्टियों की 70 साल से दूसरी पार्टियों की सरकार है, कोई राज्य ले लीजिये लेकिन एक राज्य ऐसा बता दीजिये जिसके अंदर इतने बढ़िया स्कूल हों, इतने बढ़िया मौहल्ला कलीनिक हों, सारी दवाइयॉ मुफत हो, सरकारी अस्पतालों के अंदर इतना काम किया गया हो और जितनी इतनी स्कीम्स जो तीन साल के अंदर दिल्ली सरकार ले के आई है। कोई ऐसा राज्य बता दो जिसमें 70 साल में इन्होंने इतना काम करके दिखाया हो तो आम आदमी पार्टी जब आई थी, लोगों ने उम्मीद से वोट दिया था और मुझे बेहद खुशी है आज ये कहते हुए कि आज जनता को ये लग रहा है कि यार! हो तो सकता है। अभी तक हमें बेवकूफ बनाया था इन लोगों ने। 70 साल में इन्होंने बेवकूफ बनाया था। हो तो सकता है। स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं, मौहल्ला क्लीनिक भी अच्छे हो सकते हैं, सड़के भी अच्छी हो सकती हैं, बिजली भी अच्छी हो सकती हैं... बिजली भी अच्छी हो सकती है पानी भी अच्छा हो सकता है। नीयत साफ होनी चाहिए, आज साफ नीयत वाली सरकार है। वित्त मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया, इसके लिए

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूॅं और इसके प्रति अपना पूरा समर्थन जाहिर करता हूॅं।

foRr o"kZ 2018&19 gsrq vuqnku ekaxksa ij fopkj rFkk ikj.kA

v/;{k egksn;% अब माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी 2018–19 के लिए डिमांड फार ग्रांट पेश करेंगे।

mi eq[; ea=h% Hon' ble Speaker Sir, I present the Demands for Grants for the Financial Year 2018-19.

v/;{k egksn;% अब सदन डिमांडस फॉर ग्राण्टस वाइज विचार करेगा।

डिमाण्ड नं. – 1 लेजिस्लेटिव एसेम्बली, जिसमें रेवन्यू में 21 करोड़ 71 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉं कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉं कहने पर)
हॉं पक्ष जीता, हॉं पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.–1 पास हुई।

डिमाण्ड नं. – 2 जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवन्यू में 4 अरब 22 करोड़ 68 लाख 75 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉं कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमांड नं.–2 पास हुई।

डिमाण्ड नं.–3 ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें रेवन्यू में 11 अरब 66 करोड़ 47 लाख रुपये और कैपिटल में दो करोड़ रुपये हैं; कुल राशि 11 अरब 68 करोड़ 47 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है ;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.–3 पास हुई।

डिमाण्ड नं.–4 जिसमें रेवेन्यू में तीन अरब 20 करोड़ 61 लाख रुपये और कैपिटल में सात अरब 10 करोड़ 15 लाख रुपये हैं, कुल राशि 10 अरब 30 करोड़ 76 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं. 4 पास हुई।

डिमाण्ड नं.–5 होम जिसमें रेवेन्यू में 6 अरब 66 करोड़ 96 लाख रुपये और कैपिटल में 76 करोड़ 77 लाख रुपये हैं, कुल राशि 7 अरब 3 करोड़ 73 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

पर विचार तथा पारण।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.—5 पास हुई।

डिमाण्ड नं.—6 ऐजूकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 119 अरब 69 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये और कैपिटल में 4 अरब 90 करोड़ 43 लाख 50 हजार रुपये हैं कुल राशि 124 अरब 59 करोड़ 56 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.—6 पास हुई।

डिमाण्ड नं.—7 मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 55 अरब 82 करोड़ 65 लाख रुपये और कैपिटल में 2 अरब 81 करोड़ 73 लाख रुपये हैं, कुल राशि 58 अरब 64 करोड़ 38 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है —

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.—7 पास हुई।

वित्त वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान मॉगों 333 पर विचार तथा पारण। 06 चैत्र, 1940 (शक)

डिमाण्ड नं.–8 सोशल वेल्फेयर जिसमें रेवेन्यू में 57 अरब 21 करोड़ 34 लाख रुपये और कैपिटल में 5 अरब 82 करोड़ 46 लाख रुपये हैं, कुल राशि 63 अरब 3 करोड़ 80 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.–8 पास हुई।

डिमाण्ड नं–9 इन्डस्ट्रीज, जिसमें रेवेन्यू में 4 अरब 43 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये और कैपिटल में 3 करोड़ 27 लाख रुपये हैं, कुल राशि 4 अरब 47 करोड़ 1 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है –

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.–9 पास हुई।

डिमाण्ड नं. 10 डेवलेपमेंट, जिसमें रेवेन्यू में 26 अरब 30 करोड़ 33 लाख 58 हजार रुपये और कैपिटल में तीन अरब 50 करोड़ 55 लाख रुपये हैं, कुल राशि 29 अरब 80 करोड़ 88 लाख 58 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड नं.–10 पास हुई।

डिमाण्ड नं.–11 डेवलपमैंट एण्ड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 107 अरब 25 करोड 92 लाख रुपये और कैपिटल में 57 अरब 21 करोड 58 लाख रूपये, कुल राशि 164 अरब 47 करोड 50 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड न.–11 पास हुई।

डिमांड न.–12 .(ऋण) – जिसमें कैपिटल में 1 करोड 50 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड न.–12 पास हुई।

डिमाण्ड नं. 13 पेन्शन्स– जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 25 करोड रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
डिमाण्ड न.–13 पास हुई।

हाउस ने रेवेन्यू में 397 अरब 96 करोड 55 लाख 33 हजार रुपये और कैपिटल में 81 अरब 80 करोड 44 लाख 50 हजार रूपये, कुल राशि 479 अरब 76 करोड़ 99 लाख 83 हजार रुपये की डिमाण्ड को मंजूरी दे दी है।

fofu;kstu ¼la[;k&02½ fo/ks;d] 2018 dk iqj%LFkkiu] fopkj rFkk ikj.k

Appropriation (No.2) Bill 2018

v/;{k egksn;: अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी Appropriation (No.2) Bill 2018, (Bill No.3 of 2018) को House में Introduce करने की permission मांगेंगे।

mi eq[; ea=h – Hon' ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriaction (No.2) Bill, 2018, (Bill No.3 of 2018) toAuthorize payment and Appropriation of certain sums from and out of the consolidated funds of NCT of Delhi for the financial year 2018-19.

v/;{k egksn;: अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
प्रस्ताव पास हुआ।

v/;{k egkn;: अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में इण्ट्रोड्यूस करेंगे।

mi e[; e=h: Hon' ble Speaker Sir, I introduceAppropriation (No.2) Bill, 2018, (Bill No.3 of 2018) to the House.

v/;{k egkn;: अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड–दो, खण्ड–तीन व शेड्यूल बिल का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;

खंड–दो, खंड–तीन एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए।

v/;{k egkn;: प्रश्न है कि खण्ड–एक, प्रस्तावना और शीर्षक बिल का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
प्रस्ताव पास हुआ,

खण्ड–एक, प्रस्तावना और शीर्षक बिल का अंग बन गए।

v/;{k egkn;: अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No.2) Bill, 2018, (Bill No.3 of 2018) को पास किया जाए।

mi e|[; e=h: Hon' ble Speaker Sir, The House may now please pass the Appropriation (No.2) Bill, 2018, (Bill No.3 of 2018).

v/;{k egkn;: माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता;
प्रस्ताव पास हुआ,

Appropriation (No.2) Bill, 2018, (Bill No.3 of 2018) पास हुआ।

2018–2019 के लिए वार्षिक बजट पास हुआ।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्य जरनैल सिंह जी और हमारे चीफ व्हिप, जो सदस्यों ने ये प्रश्न अभी उठाया था, अवतार जी का भी उसमें सम्मिलित हुआ था, माननीय सदस्यों ने भी जो विषय उठाया था, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सिख आगंतुकों की तलाशी लेने पर आपत्ति की गई थी। सुरक्षा कर्मचारियों ने यह कहा है कि भविष्य में इस बारे में वो पूरा ध्यान रखेंगे।

दरसल माननीय सदस्यों को ये याद होगा कि कुछ समय पहले ही दो आगंतुकों ने जो सदन में पगड़ी पहनकर आए थे, इस सदन में नारेबाजी की थी और पर्चें फेंके थे, वे अपनी पगड़ियों में पर्चे छिपाकर लाए थे इसलिए सुरक्षाकर्मी किसी भी आगंतुक की जॉच में अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। इसके बावजूद हम आश्वासन देते हैं कि भविष्य में सुरक्षाकर्मी पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी, किसी की व्यक्तिगत गरिमा को ठेस नहीं पहुॅंचाएंगे। यह किसी दुर्भावनावश नहीं किया गया था अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुॅंची है तो उसके लिए हमें खेद है। मैं भी अपनी और से, माननीय सदस्यों की और से जो दर्शक दीर्घा में सदस्य आकर बैठे थे, इस घटना के लिए खेद प्रकट करता हूॅं। अब सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

कल भी लंच की व्यवस्था है, हमारे माननीय खाद्य मंत्री इमरान जी की ओर से रहेगी, उनका भी बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, कल जरूर लंच में आएं।

(सदन की कार्यवाही 28 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।